राजस्थान विधान सभा

पन्द्रहवीं बैठक, बुधवार, दिनांक—२४ मार्च, सन १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में (मध्यान्हपूर्व) पर ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(प्रातः कालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४१८

मेड़ता शहर के जल-कष्ट निवारणार्थ लूनी नदी में से बड़ायली के पास एक नहर निकालकर मेड़ता कुन्डल में पानी लाना

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मेड़ता शहर का जल कष्ट दूर करने के लिए सरकार लूनी नदी में में से बड़ायली के पास एक नहर निकाल कर मेड़ता के कुन्डल में पानी भरने का विचार कर रही है ?

(ख) यह कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मन्त्री)—

(क) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भोपालसिंह—अगर विचार किया जावे तो क्या हर्ज है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने कहा कि विचाराधीन नहीं है।

Page No.2

श्री भोपालसिंह—वहाँ के लोगों के जल-कष्ट को दूर करने के लिए विचार किया जाना आवश्यक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह नगरपालिका का काम है। अगर वह हमारे पास यह मामला भेजे तो विचार किया जा सकता है।

श्री भोपालसिंह—पर नगरपालिका भेजे नहीं तो क्या किया जावे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेड़ता में एक योजना पहले बनी थी और वह नगरपालिका के विचाराधीन है। अगर वह अधिक रकम दे तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह—सरकार के पास हजारों योजनाएँ विचाराधीन हैं; इसको भी अगर इनमें शामिल कर लिया जाए तो क्या हर्ज है।

श्री चन्दनमल वैद—एक हजार पहले हैं तो एक हजार एक करने से कोई फायदा नहीं है।

प्रश्न संख्या ४१६

वालड़ी से पादू के बीच में ८ मील सड़क निर्माण

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार पालड़ी से पादू तहसील मेड़ता में एक छोटा ८ मील का टुकड़ा बनाने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—प्राथमिकता की दृष्टि से इसको किसी योजना में स्थान नहीं मिल सका। यह टुकड़ा छोटा अवश्य है पर सांभर से अजमेर और परबतसर के वास्ते छोटा नहीं है।

श्री भोपालसिंह—स्थान नहीं मिलने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—इतनी जरूरी नहीं है जितनी दूसरे योजनाएँ जरूरी हैं।

श्री भोपालसिंह—इस तहसील में कोई भी योजना जरूरी समझी गयी है क्या ?

श्री भोलानाथ—जरूरी अगर हुई तो जरूरी समझी जावेगी।

श्री भोपालसिंह—अगर अबतक कोई योजना नहीं रही तो कोई जरूरी नहीं समझी गई होगी, इसीलिए कोई योजना इस तहसील में जारी नहीं की गई; क्या यही सरकार सोचती है ?

Page No.3

श्री भोलानाथ—यों तो लाखों रुपये बजट में रक्खे जाते हैं और योजनाएँ भी बनाई जाती हैं पर वे तहसीलवाइज़ नहीं रक्खी जातीं ।

श्री भोपालसिंह—यानि तहसील में यह रकम खर्च नहीं की जाने की है क्योंकि यह तहसील राजस्थान का हिस्सा नहीं है ?

श्री भोलानाथ—यह मैंने आपको बतलाया कि कोई भी योजना तहसील के अनुसार नहीं रक्खी जाती ।

एक माननीय सदस्य—चूरू में कौनसी योजना जरूरी नहीं हैं, यह बता सकते हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या ४२०

थांवला से पुष्कर जाने का रास्ता (बाड़ी घाटी) चौड़ा करना

श्री भोपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या सरकार ने थाँवला से पुष्कर जाने का रास्ता, बाड़ी घाटी को चौड़ा करने का विचार किया है ? हाँ, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

क्या बाड़ी घाटी से पुष्कर तक सड़क बनवाने के लिए अजमेर-मेरवाड़ा से लिखा-पढ़ी चालू है ? यह रास्ता कब तक चालू हो जावेगा ? क्या इसके लिए जनता की तीव्र माँग है ?

श्री भोलनाथ (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(१) इस विषय में अभी कोई विचार नहीं किया गया है क्योंकि जब तक अजमेर सरकार पुष्कर से बाड़ी घाटी तक सड़क न बनवाये तब तक इसको चौड़ा करने से कोई फायदा नहीं है ।

(२) नहीं, यह प्रश्न नहीं उठता । सरकार के पास कोई तीव्र माँग की खबर नहीं है ।

श्री भोपालसिंह—अगर सरकार से अजमेर-मेरवाड़ा की सरकार माँग करे तो क्या सरकार उस पर विचार कर सकती है ?

श्री भोलानाथ—जरूर विचार किया जावेगा ।

श्री भोपालसिंह—कब तक ?

श्री भोलानाथ—पहले माँग तो आए ।

एक सदस्य—आपने (श्री भोपालसिंह ने) माँग रखी है, क्या इस पर विचार किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४२१

सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर्स का एकीकरण

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) क्या सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर्स की सर्विसेज़ का एकीकरण हो गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उनके कितने ग्रेड रक्खे गये हैं और प्रत्येक ग्रेड में कितने इन्सपेक्टर रखना तय किया है और ये ग्रेड किस तारीख से लागू होंगे ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) इनके तीन ग्रेड रखे गये हैं। पहले ग्रेड में दस, दूसरे में चौदह व तीसरे में तेबीस। ग्रेड किस तारीख से लागू होंगे, अभी यह तय नहीं हुआ है।

(ग) उक्त ग्रेडों में वर्तमान इन्सपेक्टरों को रक्खे जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अभी इन्सपेक्टरों को नये और पुराने ग्रेडों के अन्तर की रकम नहीं मिली है। अन्तर की रकम इन्सपेक्टरों को उक्त ग्रेडों में रक्खे जाने के बाद दी जायगी।

श्री कंवरलाल जेलिया--तीन श्रेणियाँ जो ये बताई, वे किस तरह से हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जरा जोर से बोलिये।

श्री अध्यक्ष—ग्रेड क्या क्या है उनके ?

श्री अमृतलाल यादव--तीन ग्रेड हैं मैंने अर्ज किया न।

(विराम के अनन्तर)

श्री कंवरलाल जेलिया—मुझे मेरे सवाल का उत्तर चाहिये।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने बताया है कि 'ए' के इतने हैं, 'बी' के इतने हैं और 'सी' के इतने हैं। आपने यह पूछा था कि यदि हाँ, तो उनके कितने ग्रेड रक्खे गये हैं और प्रत्येक ग्रेड में कितने इन्सपेक्टर रखना तय किया है; तो मैंने यह बताया कि तीन ग्रेड रक्खे गये है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is automotically understood as to what are the grade scales......

श्री अध्यक्ष—(श्री यादव को सम्बोधित करते हुए)

"क्या ग्रेड हैं" वे यह चाहते हैं। कितनी कितनी ग्रेड्स हैं, उन ग्रेड्स की सेलेरीज़ क्या-क्या हैं, यह जानना चाहते हैं वे।

श्री अमृतलाल यादव—यह इस प्रश्न में तो नहीं था। सप्लीमेंटरी से पूछते हैं कि ग्रेड्स क्या-क्या हैं। बाद में बता दूँगा, अभी मेरे पास नहीं हैं। यह एकीकरण से सम्बन्ध रखता है इसलिए उसी विभाग से सम्बन्धित है।

श्री मेजर आपजी रघुराजसिंह—I think it automatically means this and the information must be supplied if the Hon'ble Member wants. This is a relevant question and must be repiied to. The Hon'ble Minister must be prepared for a reply. It seems that several times Ministers try to evade replies.

श्री हरिकृष्ण व्यास—एकीकरण क्या पी. एस. सी. द्वारा किया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—सिलेक्शन तो पी. एस. सी. ने किया है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सिलेक्शन के बारे में अपनी राय पी. एस. सी. ने सरकार को प्रस्तुत कर दी है ?

श्री अमृतलाल यादव—जैसे-जैसे मालूम होता है वैसे-वैसे पी. एस. सी. विचार करती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस मामले को सरकार ने पी. एस. सी. को प्रस्तुत किया और पी. एस. सी. ने अपनी राय उस पर सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह जो प्रश्न है वह अपोइन्टमेंट विभाग से सम्बन्धित है इसलिए इसकी डिटेल वही ज्यादा बता सकेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्टीग्रेशन में सिलेक्शन किस डेट से हुआ ?

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रश्न का उत्तर तो मिलना चाहिये। पी. एस. सी. ने अपनी रिकमन्डेशन दी है या नहीं; अगर दी है तो कब ?

श्री अध्यक्ष—Reply has already been given. Next. Shri Trivani shyam sharma.

प्रश्न संख्या ४२२

श्री अध्यक्ष—श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ४२३

मोटे (कोर्स) धान को नियन्त्रण से मुक्त करने पर भी क्रय-विक्रय स्टॉक का हिसाब देना

श्री चांदमल मेहता—क्या रसद मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

१. क्या यह सही है कि कोर्स ग्रेन को कन्ट्रोल से मुक्त करने के बाद भी लाइसेन्स होल्डर्स को उनके क्रय-विक्रय व स्टॉक का हिसाब देना पड़ता है ?

२. क्या कोर्स ग्रेन के लिये अब भी लाइसेन्स सिस्टम का जारी रखना आवश्यक है ।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) हाँ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि राजस्थान के पड़ौसी राज्यों में डिकन्ट्रोल करने के साथ ही लाइसेन्स सिस्टम बन्द कर दिया है और हिसाब देना भी बन्द कर दिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ४२४

सोजत सिटी की कुछ सड़कें तैयार करवाना

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सोजत सिटी की निम्नलिखित सड़कें बनकर कब तैयार हो जायगी ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(अ) राजपोल दरवाजे से सिरे बाजार होती हुई, जैतारण दरवाजे होती हुई, हवाई जहाज के मैदान के पास से चूने के भट्टों के पास, ग्रान्ड ट्रंक रोड से मिलाना ।

(ब) इसी ऊपर की सड़क से दो एप्रोच रोड बाहर व अन्दर की पत्थर की खानियों से मिलाना ।

(ख) क्या सोजत सिटी व सोजत रोड से सब्जी बेचने वालों के बैठने के वास्ते सीमेंट की चबूतरियाँ व टीन के छप्पर बनवाने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद—(क) हाल में राजपोल दरवाजे से करीब २ फर्लाङ्ग तक सड़क एन. सी. सी. केडेट द्वारा तथा जनता की मदद से बनी है । यह सड़क म्युनिसिपेलिटी की है और म्युनिसिपल कमेटी द्वारा पूरी की जानी चाहिये ।

[श्री चन्दनमल वैद्य]

(ख) सोजत सिटी व सोजत रोड में सब्जी बेचने वालों के बैठने के वास्ते सीमेंट की चबूतरियाँ व टीन के छप्पर बनवाने की योजना नहीं बनी है। यह काम नगरपालिका का है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अगर नगरपालिका के पास धन नहीं है तो क्या सरकार सहायता देगी ?

श्री चन्दनमल वैद—इसका विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीराम।

प्रश्न संख्या ४२५

श्री अध्यक्ष—श्री मोतीराम।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२६

चालू वार्षिक वर्ष में जवाई प्रोजेक्ट में संग्रह का मिलान करना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for P. W. D. be pleased to answer :—

(a) Has any physical verification of stocks been undertaken at the Jawai Project during the current financial year ?

(b) If so, when it was done and by whom ?

(c) Was any discrepancy between the book entries and the actual stocks in godown discovered ?

(d) If so, what was the extent of such discrepancy.

(e) What action has the Government taken in the matter ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(a) Yes.

(b) It was conducted by Shri Harsaran Dass, S. D. O. from 1-4-53 to 10-4-53 and test checked by Shri Jai Narain, Executive Engineer, Jawai, from 19-5-53 to 2-6-53.

(c) Yes, certain discrepancies were discovered.

(d) Shortage to the extent of Rs. 5,262/-

[श्री चन्दनमल वैद्य]

approximately and surpluses to the extent of Rs. 9,838/— approximately were detected.

(e) The matter is under investigation and steps are being taken to fix the responsibility for the shortages.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What was the original discrepancy discovered ?

श्री चन्दनमल वैद—This was the original discrepancy.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Government prepared to lay the report of the checking of the officer on the Table of the House ?

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री चन्दनमल वैद—No.

श्री जसवन्तसिह—Why not ? The question was whether the Govmment is prepared to place the report on the Table.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Departmental reports are not placed on the Table.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the original discrepancy is reported to have been larger.

श्री चन्दनमल वैद—I have told that these are the original discrepancies.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then what objection can there be in laying that report on the Table of the House ?

श्री चन्दनमल वैद—The reason has been given by the Leader of the House

प्रश्न संख्या ४२७

पंजाबी शरणार्थियों का श्री अजीतप्रसाद के पास प्लोट्स की मांगों के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Co-operation be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that a deputation of Punjabi refugees waited upon Sri Ajit Prasad Jain on 6-11-53 for securing their demands for plots ?

(b) Is it a fact that they were assured sympathetic consideration and even asked to get their society registered ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) Is the Government aware that an application for the registration of such a society has been made and all formalities been completed by 15-11-1953 ?

(d) Is the Government aware that the said society has so far not been registered without assigning any reason ?

(e) Is the Government aware that the officials of the Department have by verbal order arbitrarily called for further general body meeting and are thus delaying registration ?

(f) Will the Government conduct an enquiry into the whole matter ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मंत्री)—(अ) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ब) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(स) पंजाबी विस्थापितों की ओर से एक गृह-निर्माण-समिति बनाने के लिये पत्रादि सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जयपुर, के पास अवश्य आये थे मगर उनके साथ प्रस्तावित उपनियमों में कुछ त्रुटियाँ रह गई थीं।

(द) समिति की रजिस्ट्री ता० ४-३-५४ को हो चुकी है।

(ह) यह प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

(फ) अब कोई जाँच करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४२८

बैराठ के स्थानीय डॉक्टर के विरुद्ध जनता के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि कस्बा बैराट के स्थानीय डॉक्टर के विरुद्ध जनता के साथ मारपीट, गाली-गलौच व स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने की लगातार गये ४ माह से शिकायतें की जा रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या कोई जाँच की गई और उन पर क्या एक्शन लिया गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कस्बा बैराठ में स्थानीय डॉक्टर के विरुद्ध शिकायत की जाँच की जा रही है।

Page No.10

श्री मुक्तिलाल मोदी—सरकार ने इसकी कई दफा जाँच की और इस डॉक्टर के खिलाफ सरकार ने नोट लगाया था; उसके बावजूद भी वह डॉक्टर उस कस्बे में मौजूद है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—कभी पहले भी इस डॉक्टर के बारे में शिकायतें हो चुकी हैं और सरकार द्वारा जाँच कराई गई फिर भी वह वहाँ है; इसका जवाब दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—जो शिकायतें आई हैं वे जाँच में हैं।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—उक्त डॉक्टर के खिलाफ प्राइमा फेसी प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं फिर भी उसको सस्पेन्ड नहीं किया गया है।

श्री कुम्भाराम आर्य—यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने दिनों से जाँच चालू है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—३ महीनों से।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—अभी और कितना समय लग जायगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—अब बहुत कम समय लगेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कितनी बार जाँच हो रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य--पहली बार।

श्री मुक्तिलाल मोदी—सरकार को यह बतलाता हूँ, इस डॉक्टर के बारे में कि कई दफा जाँच होकर यह नोट लगाया हुआ है कि इस कस्बे के अन्दर यह डॉक्टर नहीं जायगा।

श्री अध्यक्ष—यह पूछिये कि "क्या जाँच होकर नोट लगाया हुआ है या नहीं।"

(हँसी)

He should not presume.

श्री मुक्तिलाल मोदी—नोट लगा हुआ है या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य—मुझसे जिन शिकायतों के बारे में सवाल पूछा गया है तो उसके बारे में मैंने कहा है कि जाँच की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इससे पहले दूसरी शिकायतों के सम्बन्ध में जाँच होकर नोट लगा हुआ है क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य--इसके बारे में अलग से प्रश्न पूछिये।

Page No.11

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--यह रिलेवेन्ट प्रश्न है ।

श्री कुम्भाराम आर्य--किसी की जिन्दगी में कहाँ-कहाँ क्या हुआ, इसकी हिस्ट्रीशीट तैयार करके नहीं लाया हूँ; इन शिकायतों की जाँच हो रही है ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--इस जगह इस डॉक्टर के रहने में कोई शिकायत हुई या नहीं, कृपा करके यह बता दें ।

श्री कानसिंह--मन्त्री महोदय यह भी बतायें......

श्री अध्यक्ष--Order ! Order !! one question at a time.

(चुप्पी)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--Can I expect reply to my question ? Very simple it was.

श्री कुम्भाराम आर्य--इस जगह ३ महीने पहले शिकायतें आई हैं, वे सब एन्क्वायरी में हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह शिकायतें कितने दिन पहले आई थीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य--यह प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि ३-४ महीने पहले, इसकी जाँच हो रही है ।

श्री कानसिंह--क्या इस डॉक्टर की कोई हिस्ट्री शीट भी है ।

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)--आपको मालूम करायें कि यदि उक्त डॉक्टर की हिस्ट्री शीट पर नोट लगा हुआ......

श्री अध्यक्ष--No. 'यदि' । Order ! Order !! No hypothetical question.

(विराम)

श्री धर्मपाल, प्रश्न सं० ४२६

प्रश्न संख्या ४०६

म्युनिसिपल मेहतर कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर का अध्ययन करने के लिए समिति का निर्माण

श्री धर्मपाल--क्या बेकवर्ड विभाग के मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :--

(अ) म्युनिसिपल मेहतर कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई समिति स्थापित करने की योजना है ? यदि है, तो क्या उस समिति का निर्माण हो गया है और उसमें कितने और कौन-कौन मेम्बर लिये गये हैं ?

[श्री धर्मपाल]

(ब) क्या समिति ने अपना कार्य चालू कर दिया है ? यदि हाँ, तो कितनी प्रगति आज तक हो पाई है ?

(स) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा आदि बड़े-बड़े शहरों में मेहतर कर्मचारियों के रहन-सहन को ठीक करने के क्या-क्या कार्य हो रहे हैं ?

(द) क्या यह सही है कि जयपुर में मेहतर लोगों के घर जो शहर पनाह के आस-पास हैं वे बेतरतीब वार झोपड़ियों में बसे हुए हैं ? यदि हाँ, तो उनकी स्थिति क्या है और उनकी उन्नति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)--(अ) समिति का निर्माण विचाराधीन है।

(ब) प्रश्न ही नहीं उठता।

(स) कोई विशेष कार्य नहीं किये जा रहे हैं।

(द) हाँ। नहीं, जयपुर म्युनिसिपेलिटी से चर्चा की जा रही है। एक सर्क्युलर नं० सी० । एस. डी. २० (बी) ता० २४-१२-५३ भी भेजा गया है जिसमें सब म्युनिसिपैलिटीज को ५० प्रतिशत तक सहायता देने का आश्वासन दिया गया है।

श्री धर्मपाल पंवार—क्या सरकार इसकी आवश्यकता को महसूस करती है

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार महसूस करती है इसीलिये तो समिति का निर्माण विचाराधीन है।

एक सदस्य—क्या समिति जिम्मेवार बनाई जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहाँ जैसी आवश्यकता होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या सरकार श्री ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का विचार करेगी ?

श्री भोगीलालपंड्या—यह आप फिर प्रश्न पूछिये तो इसके बारे में जवाब दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी पूछूँ या बाद में ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—यह योजना कितने साल से चालू है और कितने साल से विचाराधीन है ?

Page No.13

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने समय के लिए प्रश्न पूछा तो मालूम करके तारीख और वर्ष आपको बता दूँगा।

श्री धर्मपाल पंवार—यदि सरकार की यही गति रही तो क्या आशा की जा सकती है कि इतने दिनों के अन्दर लोगों का उत्थान हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार चाहती है कि १० वर्ष में हो जाय और आगे के लिए यदि आवश्यकता हुई तो सोचा जा सकता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—तो क्या रिज़र्वेशन भी बढ़ा दिया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सरकार जैसी स्थिति में होगी उस तरह से विचार करेगी।

कुँ श्री जसवन्तसिंह—कम से कम एक शताब्दी में सुधार हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आशा तो जल्दी की ही कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसी प्रश्न के सम्बन्ध में श्री ठक्कर कमेटी की रिपोर्ट २ साल से पहले प्रकाशित हो चुकी है। क्या सरकार उसको लागू करने लिए के विचार करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवश्य करेगी।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार उनके घरों के बारे में विचार करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूँ कि सब म्युनिसिपैलिटियों को लिखा गया है.........

श्री अध्यक्ष—उसकी रिपोर्ट......

श्री भोगीलाल पंड्या (पूर्व उत्तर जारी रखते हुए)—कि नगरपालिकाएँ जो खर्चा करेंगी तो सरकार भी आधा रुपया देगी ऐसा सर्क्युलर निकाल दिया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—सरकार जमीनें मुफ्त देगी या कीमत पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने पहले ही बता दिया है कि म्युनिसिपैलिटियों को सूचित किया गया है कि जहाँ कहाँ लोगों के पास जमीनें हैं वे उनके पास ही रहेंगी।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इसमें भारत सरकार से भी राजस्थान सरकार को सहायता मिलेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माँगेंगे और अगर मिलेगी तो मैं हाउस को बतला दूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लेबर हाउसिंग स्कीम में उनको इन्वलूड किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं लेबर विभाग को पूछकर आपको जवाब दूँगा।

प्रश्न संख्या ४३०

गिलोद (जि० टोंक) की मिटटी एवं सड़क बनवाने में व्यय

श्री लालूराम—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सत्य है कि सड़क गिलोद, जिला टोंक की मिट्टी हटाने एवं सड़क बनवाई में १०,०००) रु० प्रति वर्ष खर्च किये जाते हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार कोई स्थायी प्रबन्ध करने का सोच रही है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—यह सत्य नहीं है कि प्रतिवर्ष १०,०००) रुपया मिट्टी हटाने या सड़क बनवाने में खर्च किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार सड़क को ठीक कराने के लिए आवश्यक रकम खर्च की जाती है।

(ख) बनास नदी के पानी के बहाव को दृष्टि से रखते हुए खुर्रा बनवाने से कोई काम नहीं चल सकता। प्रति वर्ष की मिट्टी हटाने की दिक्कत और उस पर होनेवाले खर्चा का निराकरण पुल बनवाने से ही हो सकता है। इसका खर्चा इसलिये आवश्यक नहीं समझा जाता कि पंचवर्षीय योजना में जहाँ-जहाँ एक नई सड़क बनाने का कार्य शामिल कर दिया गया है। इसके बन जाने से यहाँ ट्रेफिक इतना अधिक नहीं रहेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सत्य नहीं है कि प्रति वर्ष मिट्टी हटाने और सड़क बनवाने में काफी रुपया खर्च किया जाता है। बनास नदी का पानी बहता रहता है और उससे मामूली मरम्मत से काम नहीं चल सकता ?

श्री चन्दनमल वैद—मामूली मरम्मत से इसका निराकरण नहीं हो सकता। इसके लिए पुल ही बनवाना पड़ेगा और पंच-वर्षीय योजना में यह कार्य शामिल कर लिया गया है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—आपने अभी कहा (क) के उत्तर में कि यह ठीक नहीं है। यह किस आधार पर ठीक नहीं है ?

श्री चन्दनमल वैद—५१-५२ में इस पर ४०३१ रु० ५ आ० खर्च हुए, ५२-५३ में ५३०० रु० खर्च हुए और ५३-५४ में ६४६१ रु० ४ आ० ६ पा० खर्च हुए; इस आधार पर कहा कि (क) प्रश्न का (क) भाग सही नहीं है।

प्रश्न संख्या ४३१

जैसलमेर सब डिवीज़न में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सन १९५२,५३ तथा ५४ में विकास कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या सामुदायिक विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या जेसलमेर सब डिवीजन में पंचवर्षीय योजना के तहत कोई डेवलपमेंट वर्क सन् ५२, ५३ तथा ५४ में हुआ ? अगर हुआ तो कहाँ-कहाँ ? नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जैसलमेर सबडिवीज़न में निम्न डेवेलपमेंट के कार्य शिक्षा व निर्माण विभागों द्वारा किये गये।

(१) शिक्षा विभाग

सन् ५३-५४ में निम्नलिखित स्थानों पर नये स्कूल खोले गये:—आसकन्दरा, खईयाला, सेती, सनवारा गाँव, रनजीतपुरा, सेवारा, सिहारा, मांडली।

(२) निर्माण विभाग

१. जैसलमेर पोकरन सड़क लागत १,६००,०००) रुपये। इस कार्य पर इस वर्ष में १,५०,०००) रुपये रखे गये हैं और आगामी वर्ष में ३ लाख रुपये माँगे गये हैं।

इसके अलावा सहकारी विभाग द्वारा उपरोक्त जिले में ३१ मार्च, १९५६ से पहिले ४० समितियाँ बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

चूँकि जैसलमेर उपजिले में कोई सिंचाई के लिए बाँध बाँधने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है, इस वजह से पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। सिर्फ वहाँ पर हरिका पतन सिचाई योजना कार्यरूप में परिणत होने की आशा है जो कि केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

श्री हनवन्तसिंह—क्या जैसलमेर में बाँध बाँधने के बारे में आपने मुलाहिजा किया है कि वहाँ बाँध बांधे नहीं जा सकते ?

श्री चन्दनमल वैद—वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है कि वहाँ बाँध नहीं बाँधे जा सकते।

श्री हनवन्तसिंह—क्या यह बात आपको देखने से मालूम हुई ?

श्री चन्दनमल वैद—देखकर ही यह मालूम किया गया है।

श्री सोहनलाल—हर के बाँध का क्या हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद—सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि जैसलमेर के नजदीक १-२ मील की दूरी पर थोड़ा पहाड़ी इलाका है ?

श्री चन्दनमल वैद—जी हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जाँच करवायेगी कि इस इलाके में बाँध बंधवाने की गुंजायश है ?

श्री चन्दनमल वैद—वहाँ पर सिंचाई होती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—हर के बाँध के सम्बन्ध में राजस्थान में सर्वे कराया गया उसकी क्या रिपोर्ट है ?

श्री चन्दनमल वैद—यह अलग प्रश्न है, इसको अलग पूछिये ।

कुँ० श्री जसवन्तसिह—जैसा कि अभी माननीय मन्त्री ने फरमाया कि वहाँ सिंचाई हो रही है तो क्या पिछड़े हुए इलाके में बाँध से फायदा नहीं पहुँचाया जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद—और भी किया जायगा।

श्री कानसिंह—क्या जैसलमेर में कई जगह उल्लाव हैं, कई जगह पानी निकलता है और.....

श्री चन्दनमल वैद—आप साफ फरमाइये।

श्री कानसिंह—जैसलमेर में कई जगह अच्छे-अच्छे उल्लाव हैं, वहाँ पर बाँध बाँधा जाय तो सिंचाई अच्छी हो सकती है ?

श्री चन्दनमल वैद—आप साफ-साफ फरमाइये कि कहाँ पर ऐसा है ?

श्री कानसिंह—आपल सिड़ा आदि स्थानों पर।

श्री चन्दनमल वैद—इसकी जाँच की जायगी।

एक सदस्य—क्या साँकड़ा में बाँध बनने की गुंजायश है ?

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ४३२

परबतसर तहसील में पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परबतसर तहसील में कितने मील नई पक्की सड़क बनेगी और वे सड़कें कौन-कौन सी हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—इस समय तक प्राथमिकता की दृष्टि से पंचवर्षीय योजना में इस तहसील का कोई कार्य स्थान नहीं पा सका है, न कोई तहसील से विशेष माँग ही डिपार्टमेंट में पेश हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपको यह जानकारी है कि पीलवा एक इंपोर्टेन्ट पुलिस स्टेशन है और वहाँ से ३ मील दूर सड़क है। क्या वहाँ पर एप्रोच रोड बनवाने की माँग नहीं की गई है ?

श्री चन्दनमल वैद—अब तक कोई माँग नहीं की गई। आप अब कहते हैं तो विचार किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—गच्छीपुरा इंपोर्टेन्ट व्यापारिक स्थान है, पुलिस स्टेशन भी है; इसको परबतसर से कनेक्ट करने के लिए कई बार कहा गया, क्या इसको कनेक्ट करने का आपका विचार है ?

श्री चन्दनमल वैद—अभी कोई विचार नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या इसे पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार करेंगे ?

(उत्तर प्राप्त न होने पर)

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने पहले सवालों का निश्चित उत्तर नहीं दिया कि माँग की गई है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद—विचार किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न यह है कि आज तक इसके लिए माँग की गई है या नहीं, इसके लिए आपका निश्चित उत्तर क्या है : हाँ या ना ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने कहा कि कोई विशेष माँग नहीं की गई ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—अविशेष कितनी माँग की गई ?

श्री चन्दनमल वैद—आपका प्रश्न अस्पष्ट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अविशेष कितनी मागें पेश हुईं ?

श्री चन्दनमल वैद—मामूली एक-दो पेश होती रहती है।

श्री वेदपाल त्यागी—सरकार के पास विशेष और अविशेष माँग जाँचने का क्या मापदण्ड है ?

श्री चन्दनमल वैद—वह तो माँग खुद ही बता देती है।

Page No.18

प्रश्न संख्या ४३३-

मीयांपुर (त० परबतसर) के पास रखत से चराई तथा उससे आय

श्री चाँदमल मेहता—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मियांपुर (तहसील परबतसर) के पास रखत से चराई की कितनी आमदनी होती है ?

(ख) इस रखत में कहाँ-कहाँ के मवेशी छूटते है और चराई की शरह क्या है ?

(ग) उक्त रखत में मवेशियों को चरने की इजाजत प्रति वर्ष किस महीने में दी जाती है ?

(घ) उक्त रखत गाँव से कितनी दूर है ?

श्री अमृतलाल यादव—(क] मियांपुर, तहसील परबतसर के पास रखत से चराई की गत वर्ष रू० ३८६) आना चार, की आमदनी हुई।

(ख) इस रखत में माधोपुर व चारनवास गाँवों के मवेशी छूटते हैं। चराई की शरह इस प्रकार है :

बकरी	आठ आना
भैंस	दो रुपया चार आना
गाय	एक रुपया दो आना

(ख) उक्त रखत में मवेशियों को चरने की इजाजत प्रतिवर्ष आम तौर से अगस्त महीने में दी जाती है।

(घ) गाँव से लगभग एक मील दूर है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस रखत की सीमा गाँव के पास ही है और इस वजह से मवेशियों को चरने के लिये और कोई जगह नहीं मिलती ?

श्री अमृतलाल यादव—यह गाँव से १ मील दूर है।

श्री चांदमल मेहता—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो जानकारी दे रहा हूँ उसकी वास्तविकता की जाँच करने की कोशिश करेंगे कि वह १५० कदम की दूरी पर ही है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, मैं जाँच करवाने को तैयार हूँ।

श्री चांदमल मेहता—जब कि इसकी आमदनी ३८६) रु० सालाना है, तो क्या उसे उठाने के बारे में सोचेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—इसे हटाने के बारे में नहीं सोचा जा सकता ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या ३८६) रु० की आमदनी जनता की कठिनाई को देखते हुए छोड़ी नहीं जा सकती ?

श्री अमृतलाल यादव—जनता की कठिनाई मिटाने के लिये हर प्रयत्न किया जाता है ।

श्री चांदमल मेहता—जनता की कठिनाई का निर्णय सरकार करेगी या जनता ?

श्री अध्यक्ष—दोनों ही मिलकर तय करलें ।

प्रश्न संख्या ४३४

जयपुर की चार डिस्पेन्सरीज़ डी. एम. एच. ओ. के अधीन

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

जयपुर शहर की चार डिस्पेन्सरीज़ को किशनगढ़ के डी. एम. एच. ओ. के नीचे रखने से क्या लाभ है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जिले की डिस्पेन्सरियाँ जिले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिर के नीचे ही रखने का प्रबन्ध शासन की सुविधा के हेतु स्वीकृत किया गया है । चूंकि जयपुर डी. एम. एच. ओ. का हैडक्वार्टर किशनगढ़ में है इसलिये इन डिस्पेन्सरीज़ को उनके नीचे रक्खा गया है ।

डिप्टी डाइरेक्टर मेडिकल व हैल्थ केवल प्रशासनिक ऑफिसर है और उनकी आधीनता में सीधे कोई भी डिस्पेन्सरी रखा जाना उचित नहीं समझा गया ।

कुँ० श्री जसवन्तसिह—यह डी. एम. एच. ओ. क्या होता है ?

श्री कुम्भारम आर्य—डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एण्ड हैल्थ ऑफिसर ।

प्रश्न संख्या ४३५

सन् १९५२में हरिजन दिवस में हरिजनों द्वारा सत्रह मन्दिरों में प्रवेश

श्री हरिशंकरसिद्धान्त शास्त्री—क्या दीलितोत्थान मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि तारीख ४ अक्टूबर, सन् १९५२ को हरिजन दिवस के उपलक्ष में सरकार की ओर से भिन्न-भिन्न स्थानों पर १७ मन्दिर हरिजनों के दर्शन करने हेतु खोल दिये गये हैं ?

Page No.20

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(ख) यदि इसका उत्तर हाँ में है, तो कृपया उनकी विगत बतलावें कि कौन-कौन सा मन्दिर किस-किस स्थान पर हरिजनों के लिये खोला गया ? साथ में यह भी बतलावें कि यह मन्दिर प्राइवेट था या सरकारी या खंडहर पड़ा हुआ था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हाँ, यह सही है।

(ख) भिन्न-भिन्न स्थानों से जो रिपोर्ट आई हैं उसके अनुसार निम्न १७ स्थानों पर हरिजनों ने दर्शन किये :—

(१) खाचरियावास, सीकर।
(२) मन्दिर श्री नारायण भगवान, पिडवाड़ा।
(३) ग्राम भीलवाड़ा : जोधपुर डिवीजन।
(४) मन्दिर श्री नरसिंहजी, पचभदरा।
(५) जैसलमेर।
(६) मन्दिर श्री रामजानकीजी, झालावाड़।
(७) मन्दिर श्री चारभुजजी, छावड़ा।
(८) मन्दिर श्रीमहादेवजी, चेचटा।
(९) मन्दिर श्री हनुमानजी, हनुमानगढ़।
(१०) मन्दिर श्री करनीजी, भादरा।
(११) मन्दिर श्री शीतलाजी, रतनगढ़।
(१२) मन्दिर श्री गोविन्ददेवजी, राजगढ़, अलवर।
(१३) मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, बानसूर, अलवर।
(१४) मन्दिर श्री गोपीनाथजी, दांता रामगढ़।
(१५) मन्दिर श्री भूतेश्वर महादेव, कोटकासिम, अलवर।
(१६) मन्दिर श्री गोर्धनजी, करेरा।
(१७) मन्दिर श्री चारभुजजी, शाहपुरा।

ये मन्दिर प्राइवेट थे या सरकारी अथवा खंडहर, इस विषय में सूचना उपलब्ध की जा रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या जयपुर शहर में ऐसा कोई मन्दिर है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री—क्या जयपुर के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हाँ, जयपुर में रिमूवल ऑफ अन्टचेबिलिटी एक्ट हो जायगा तब किया जायगा।

श्री धर्मपाल--क्या जो मन्दिर हरिजनों के लिये खुल चुके हैं वहाँ हरिजन प्रवेश कर सकते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हाँ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री--क्या इन १७ मन्दिरों में से एक भी ऐसे मन्दिर का नाम बता सकते हैं जहाँ हरिजन सैकड़ों की संख्या में घुसे हों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री कँवरलाल जेलिया— क्या इन १७ मन्दिरों में से एक भी ऐसे मन्दिर का नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिसमें हरिजन घुस कर दर्शन कर चुके हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या--१७ के १७ ही मन्दिरों में हरिजन प्रवेश कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं।

श्री भैरूँ सिंह--क्या कुछ हरिजनों को साथ में लेकर स्वयं मन्त्री महोदय ने किसी मन्दिर में प्रवेश किया था ?

प्रश्न संख्या ४३६

श्री अध्यक्ष—Order ! Next. Shri Dharma chand.

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३७

ग्राम तेजाला (फागी) के चमारों द्वारा गांव खाली करना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या बेकवर्ड क्लासेज के मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम तेजाला तहसील फागी के हरिजन (चमार) गाँव वालों की ज्यादती के कारण गाँव खाली करके दूसरी जगह चले गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो अब तक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा हरिजनों की क्या मदद की गई ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उन हरिजनों के घरों से सामान भी चोरी करके लोग ले गये हैं ?

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]

(घ) यदि हाँ, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) और (ग) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एक सदस्य—क्या सरकार इसके बारे में पता (अश्रव्य) लगा रही है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जी, प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ४३८

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३६

खुदियावास (त. परबतसर) के घाटे से निकलने वाले ऊँट इत्यादि से रोड फीस के नाम से टैक्स

श्री चांदमल मेहता—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि खुदियावास (तहसील परबतसर) के घाटे से निकलने वाले ऊँट, घोड़े, बैलगाड़ी आदि से फोरेस्ट के पदाधिकारी रोड फीस के नाम से टैक्स वसूल करते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—जी हाँ।

श्री चांदमल मेहता—यह टैक्स किस बात का और किस कारण से वसूल किया जाता है ? क्या घाटे से पार होने का टैक्स वसूल किया जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो आप (अश्रव्य) तवारीख (अश्रव्य) में देख लीजिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आमदनी किस मद में जाती है ?

श्री अमृतलाल यादव—फोरेस्ट के मद में।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फोरेस्ट के किस कायदे के सिलसिले में यह टैक्स लागू किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—No

Page No.23

श्री हरिकृष्ण व्यास – क्या यह टैक्स राजस्थान के किसी और इलाके में भी लागू है ?

श्री अध्यक्ष—It is a separate question. Next.

प्रश्न संख्या ४४०

सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में १९५३ में रोगी तथा दवाइयें

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

सिटी डिस्पेन्सरी, किशनगढ़ में १९५३ में मरीजों की संख्या कितनी रही और इसी वर्ष इस डिस्पेन्सरी को कितने रुपये की दवाइयें दिलाई गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ में १९५३ में मरीजों की संख्या की औसत प्रतिदिन निम्न प्रकार रही:—

आउट डोर	१८५·३
इन्डोर	·०७६
मेटर्निटी	·०३६

इस वर्ष के लिए इस डिस्पेन्सरी को करीब १६०० रु० की दवाइयाँ दी गई ?

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ की जनता ने बार-बार माँग की थी कि उस डिस्पेन्सरी को एक पैसे की भी दवाई नहीं दी गई थी? तो क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दवाइयें किस महीने में दी गई ?

श्री कुंभाराम आर्य—तिथि और समय के लिए अलग प्रश्न पूछिए।

श्री चांदमल मेहता—दवाइयाँ सिर्फ कागजों में ही दर्ज हैं या वाकई में दी गई हैं।

श्री कुँभाराम आर्य—दवाइयाँ देने के हुक्म कागजों में होते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय इसकी जाँच करने की कृपा करेंगे कि दवाइयाँ दी नहीं गई हैं ?

श्री कुंभाराम आर्य—जाँच होगी तो भी यही रिपोर्ट आयेगी।

श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्रीजी ने जो इस प्रश्न का उत्तर फरमाया वह कोडवर्ड्स में फरमाया, जैसे ·३६, तो यह हरेक के समझ में नहीं आ सकता। कोडवर्ड्स होने की वजह से समझ में नहीं आया, क्या इसे समझाने की कृपा करेंगे ?

श्री कुंभाराम आर्य—मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, से अर्ज करूंगा कि वे मेरी भाषा नहीं समझते इसलिये आप उन्हें समझावें। (हँसी)

श्री चांदमल मेहता—किसकी रिपोर्ट के आधार पर ये दवाइयें दी गईं, डी. एम. ओ. की रिपोर्ट के आधार पर या और किसी की रिपोर्ट के आधार पर ?

श्री कुंभाराम आर्य—महकमे की रिपोर्ट पर।

श्री चांदमल मेहता--इस महकमे के किस ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर ?

श्री कुंभाराम आर्य—महकमा मेडिकल एण्ड हैल्थ की रिपोर्ट के आधार पर।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४४१

सन् १९५२-५३ में चीनी के आयात का जयपुर शहर के लिए ठेका

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) सन् १९५२-५३ में चीनी के आयात का ठेका किस व्यापारी को जयपुर शहर के लिये दिया गया था और उसको क्या कमीशन देना सरकार तय किया था ?

(ख) उस व्यापारी ने कितनी चीनी साल भर में मंगाई व बेची ?

(ग) क्या बिना विज्ञप्ति इसी व्यापारी के चीनी के आयात के ठेके की अवधि पहिले दो माह और फिर उसी को एक साल के लिए बढ़ा दी गई ?

(घ) क्या यह सत्य है कि कमीशन आठ आने से एक रुपया फी मन इस बढ़ी हुई मयाद के लिए कायम कर दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) पवनकुमार एन्ड सन्स को एक रुपया प्रति मन कमीशन पर नियुक्त किया गया था।

(ख) १५७० टन चीनी अलोट की गई थी। इम्पोर्टर ने कुल कोटा मंगा कर बेचा इसमें से ६० टन अब बेच रहा है।

(ग) दिसम्बर १९५३ के बाद भारत सरकार ने कोई भी चीनी का कोटा इस राज्य को न दिया; न उसकी ऐसी पालसी थी कि जिनसे आइन्दा कोई कोटा मिलने की सम्भावना हो। इसलिए कोई नई विज्ञप्ति नहीं निकाली गई क्योंकि ऐसी विज्ञप्ति निकालने में काफी खर्चा होता है, लेकिन एहतियातन इन्हीं ठेकेदारों को जो कि पाँचों डिविजनों में काम कर रहे हैं, जिनमें से पवनकुमार एन्ड

[श्री भोगीलाल पंड्या]

सन्स, जयपुर भी शामिल है प्रोवीजनली उनका ठेका बढ़ा दिया गया। लेकिन जैसा कहा जा चुका है कि कोई शक्कर का कोटा अभी तक न मिला और फिलहाल मिलने की संभावना भी नहीं है।

(घ) यह सही नहीं है। उपयुक्त ठेका शुरू से ही एक रुपया फी मन कमीशन से दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष—तो फिर पूछिए।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि...

श्री अध्यक्ष—सोचने में समय व्यर्थ मत गंवाइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—क्या मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि क्या राजस्थान सरकार के लिए भारत सरकार से चीनी का कोटा मुकर्रर हुआ था कि नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं अपने प्रश्न के उत्तर में इसको बतला चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष—एक बार फिर बतला दीजिये।

(हँसी)

श्री भोगीलाल पंड्या—क्योंकि अध्यक्ष महोदय की आज्ञा है, मैं इसे फिर पढ़ कर सुना दूँ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, वह पढ़ लेंगे। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४४२ व ४४३

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४४

अजमेर से देवली जाने वाली सड़क का वह भाग जिसको बनवाने का उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार पर

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) अजमेर से देवली जाने वाली सड़क के कितने हिस्से की मरम्मत करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है ?

(२) उक्त हिस्से की सड़क की मरम्मत कितने वर्षों से नहीं हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(१) अजमेर से देवली जाने वाली सड़क का निम्नलिखित भाग राजस्थान सरकार को गत वर्ष में दिया गया था ।

मील	फर्लाङ्ग	फीट		मील	फर्लाङ्ग	फीट
१. ४५	४	४६	=	८	६	१६५
	से					
५४	३	२४१				
मील	फर्लाङ्ग	फीट		मील	फर्लाङ्ग	फीट
२. १६	५	४३०				
	से		=	१२	४	२६०½
३२	२	साढ़े तीस				(दो सौ साढ़े साठ)

(२) सड़क के इस भाग की मरम्मत प्रतिवर्ष होती रहती है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली मर्तबा मरम्मत कब हुई ?

श्री चन्दनमल वैद—पिछली साल ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि यह सड़क ऐसी खराब हो गई है और इस पर इतने खड्डे और पत्थर पड़े हुए हैं कि उससे साफ जाहिर है कि कई वर्षों से उसकी मरम्मत नहीं हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद—मैंने बतलाया कि पिछली साल उसकी मरम्मत हुई है ।

श्री चाँदमल मेहता—कागजों में ही मरम्मत हुई है या वास्तव में हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद—वास्तव में मरम्मत हुई है ?

एक सदस्य—इसकी मरम्मत का खर्चा केन्द्रीय सरकार पर पड़ता है या राजस्थान सरकार पर ?

श्री चन्दनमल वैद—जब से राजस्थान सरकार को मिली है तब से इसकी मरम्मत का खर्चा राजस्थान सरकार पर पड़ता है ।

श्री चाँदमल मेहता—कितने वर्षों से यह सड़क राजस्थान सरकार के कब्जे में है ?

चन्दनमल वैद – पिछले साल से ।

चाँदमल मेहता--पिछली साल इस सड़क पर मरम्मत का कितना खर्चा हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद--८३०६ रुपये ३ पैसे ।

श्री चाँदमल मेहता--जो देवली-अजमेर रोड़ पर मोटरें चलती हैं, ये कच्चे रास्ते से पास होती हैं ?

श्री चन्दनमल वैद--मोटरें चलती हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या मरम्मत इसी तरह की करवाते हैं कि मोटरें कच्चे रास्ते पर चलें ?

श्री चन्दनमल वैद--नीचे-ऊपर चलना मोटरों वालों की मर्जी पर है ।

आपजी श्री रघुराजसिंह--आठ हजार और कुछ रुपया आपने बताया, उसमें कितने मील कवर हुए ?

श्री चन्दनमल वैद--कितने मील और कितने फीट पर यह मैं......

आपजी श्री रघुराजसिंह--मेरा मतलब यह है कि ८ हजार में कितने मील सड़क कवर हुई है ।

श्री चन्दनमल वैद--मैंने बताया कि २० मील की सड़क मिली है ।

आपजी श्री रघुराजसिंह--Is it possible to repair 20 miles in Rs. 8,000 ? क्या धूल डालकर सड़क को ठीक किया गया है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या ८ हजार रुपये सड़क की सर्वे के लिये खर्च हुए हैं ?

श्री चन्दमल वैद--नहीं । सड़क की मरम्मत भी हुई है ।

श्री धूलजी भाई--मैं समझता हूँ कि ८ हजार में २० मील तक सिर्फ रेत भी नहीं डाली जा सकती है ।

श्री चन्दनमल वैद--जहाँ जहाँ सड़क की जरूरत थी वहाँ-वहाँ पर सड़क की मरम्मत की गई ।

एक सदस्य--क्या ठेकेदारों के नाम बताये जा सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद--हाँ, बताये जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ४४५

भरतपुर जिले की भूमियें जो वन विभाग के नाम से प्रसिद्ध

श्री तेजपाल—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) भरतपुर जिले में कौन-कौन सी जमीन किन-किन तहसीलों में वन विभाग के नाम से प्रसिद्ध हैं ?

(ख) ऐसी जमीन पर वन विभाग की ओर से क्या कोई वृक्षारोपण हुआ है ? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर ?

(ग) जिन स्थानों पर न कोई झाड़ी है और न वृक्षारोपण हो रहा है और जमीन खाली पड़ी हुई है, वह क्या काश्त के लिए दी जावेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—(वन मन्त्री) १. भरतपुर जिले में निम्नलिखित भूमि भिन्न तहसील में वन विभाग की है:-

तहसील बयाना, बेर, रूपवास, के आधीनः—

गाल का वाडा, सूखा फाला, बरहना, फाँस की बावड़ी, धुनेनी शाहपुर, थाना, सुल्तानपुर, तलहेटी, छेड़सीला, नहराली, खरेरीं, काठा, उमरेड़ ।

तहसील भरतपुर—

घना केवला देव, भजना की गढ़ी, गढ़ी साँवलदास, सेवर परेड, संघ इकरण ।

तहसील डीग—खंद भाटरा, पहाड़ ताल ।

तहसील कुम्हेर—रूँध हेलक ।

तहसील नगर—रसिया ।

(२) वृक्षारोपण किसी भी स्थान पर नहीं हुआ है । केवल देवघना में रेगुलर प्लान्टेशन किया जा रहा है और खाली स्थानों पर करने की योजना है ।

(३) वन रक्षा के दृष्टिकोण से और जमीन वन विभाग की काश्त के लिए देना उचित नहीं है क्योंकि इस तरह वन विभाग की जमीन काश्त पर दे देने से घास, चरागाह और जलाऊ लकड़ी वगैरह की कठिनाई हो जायगी ?

श्री तेजपाल—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहाँ पर कोई वृक्ष नहीं हैं वहाँ पर वृक्षों का प्रबन्ध करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव—ऐसी कोई जमीन वन विभाग में नहीं है जहाँ वन बिलकुल न हों ।

श्री तेजपाल—यदि ऐसी जमीन कहीं पर हो तो ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री तेजपाल—मेरे ध्यान में ऐसी जगहें हैं।

श्री अमृतलाल यादव—यदि आप बतावेंगे तो मैं उसका ध्यान रखूँगा।

श्री तेजपाल—क्या मन्त्री जी उस पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—पहले आप जानकारी ठीक कर लीजिए, फिर बताइए।

प्रश्न संख्या ४४६

श्री अध्यक्ष—श्री चतरसिंह।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४४७

आदिम जाति मंत्रणा परिषद् की बैठकें तथा सरकार को उनके अभिस्ताव

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या दलितवर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) आदिम जाति मंत्रणा-परिषद की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) क्या उक्त परिषद की ओर से सरकार के पास कोई सिफारिशें भी आई हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उन पर कोई अमल किया है ? अगर नहीं, तो सरकार उनको कब तक अमल में लाने के विषय में सोचती है ?

(घ) क्या ऐसा कोई सुझाव आया है कि आदिवासियों के शैक्षणिक उत्थान के लिये आदिवासी क्षेत्र के प्रत्येक तहसील में एक-एक आदिवासी छात्रावास स्थापित किया जावे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) दो।

(ख) हाँ।

(ग) हाँ, उचित कार्य-वाही की जा रही है।

(घ) नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये दो बैठकें कितने वर्षों में हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक वर्ष में।

एक सदस्य—क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है?

श्री भोगीलाल पंड्या— अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री धूलजी भाई भावसार—सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है, बतलाने की कृपा करेगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उसकी एक लम्बी योजना है। यदि आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना दूँ और अगर आप चाहें तो टेबल पर रख दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—टेबल पर रख दीजिये। नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४४८

बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी तक बन रही पक्की सड़क का वह भाग जो बन चुका तथा शेष कार्य की पूर्ति

श्री जगतसिंह झाला—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(अ) बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी तक पक्की सड़क बनाने का काम जो पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, वह अब कितने माइल तक बन चुकी है?

(आ) क्या यह सच है कि यह कार्य कुछ दिन शुरू करने के बाद बन्द कर दिया गया? यदि हाँ, तो क्यों?

(इ) यह काम कब से चालू किया जावेगा व कब तक समाप्त किया जा सकेगा?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(१) ठेकेदार ने २ मील तक मिट्टी का काम तो कर लिया है। इसी तरह सामान भी करीब-करीब इकट्ठा कर लिया गया है। सड़क की कुटाई वगैरह का काम रोड रोलर की कमी से इस वर्ष न हो सका। यह कार्य आगामी वर्ष में जल्दी ही कराया जायगा।

(२) इस रोड के अलाइनमेंट के बारे में स्थानीय जनता की भिन्न-भिन्न राय होने के कारण यह कार्य करीब २ माह बन्द रहा।

(३) यह कार्य ४-१२-५३ से चालू हो चुका है और आगामी वर्ष में जल्दी ही समाप्त होने की आशा है।

एक सदस्य—क्या ४-१२-५३ से अभी तक दो मील मिट्टी ही पड़ी है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.31

प्रश्न संख्या ४४६

कोटा डिवीजन में छोटी सिंचाई योजनाओं में नदी-घाटी-योजनायें जिनको कार्यान्वित करना

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) कोटा डिवीजन में छोटी सिंचाई योजनाओं में किन-किन नदी घाटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार ने अब तक विचार किया है ?

(ख) इन योजनाओं से कितनी एकड़ भूमि, किस-किस क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी व इन पर कितना खर्च होगा ?

(ग) आलनिया नदी के बाँध के बनाने के लिए क्या राजस्थान सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो इसके लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है ?

श्री चन्दनमल वैद—इसकी लिस्ट इस प्रकार है :

(विराम)

यदि आप कहें तो मेज पर रख दी जाए और कहें तो पढ़ कर सुना सकता हूँ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष—मेज पर रख दी जावे।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या सरकार यह बतावेगी कि कितना खसरा होगा और पैदावार का क्या पर्सेन्टेज पड़ेगा ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सब ४ प्रतिशत से ऊपर होगा।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह आप किस आधार पर कह रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद—मैं आँकड़ों के आधर पर कह रहा हूँ। आप चाहें तो आँकड़े पढ़ कर सुना सकता हूँ।

श्री कँवलाल जेलिया—प्रश्न (ग) का उत्तर मुझे चाहिये वह मुझे नहीं मिला।

श्री चन्दनमल वैद—आलनिया की योजना की सरवे की जा रही है। अभी योजना तैयार नहीं है।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह सही है कि ४ परसेंन्ट की रिटर्न जान-बूझ कर बताई जाने का आदेश दिया गया था ?

श्री चन्दनमल वैद—यह सही नहीं है।

एक सदस्य--क्या यह सच है कि कोटा में आलनिया नदी की योजना तैयार हो चुकी है, मगर रोकी हुई है ? क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री चन्दनमल वैद--मैंने यह आपसे कहा कि सरवे की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पहले योजना बनी हुई तैयार होते हुए भी फिर से सर्वे की जा रही है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद--यह बात माननीय सदस्य के ध्यान में है। मगर सरकार के ध्यान में तो नहीं है।

श्री दलीपसिंह--(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद-- जी नहीं।

श्री कँवरलाल जेलिया--छोटी सिंचाई योजनाओं का एस्टीमेट क्या तैयार हो गया है ?

श्री चन्दनमल वैद--तैयार हो गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--(अश्रव्य)

श्री चन्दनमल वैद--जल्दी।

श्री कँवरलाल जेलिया--जल्दी का अर्थ क्या लगाया जावे।

श्री चन्दनमल वैद-- अगले आर्थिक साल तक।

आपजी श्री रघुराजसिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि इसका सर्वे राजस्थान सरकार ने कराया है, पहले कोटा सरकार से भी हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद--सरकार ने करवाया है।

आपजी श्री रघुराजसिंह--क्या यह काम, कोटा स्टेट में सरवे कराई थी, उससे नहीं हो सकता था ?

श्री चन्दनमल वैद--आप सारी चीजों को देखने के बाद कहिये।

आपजी श्री रघुराजसिंह--क्या यह सही है कि किशनगढ़ स्टेट .....

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५०

श्री अध्यक्ष--श्री छतरसिंह।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

Page No.33

प्रश्न संख्या ४५१

पुनःसंस्थापन विभाग द्वारा १९५०-५१ में बीकानेर बैंक से चैक का रुपया उठाना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Rehabilitation be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that an amount of Rs. 5500/- was drawn from the Bank of Bikaner on the cheque of the Rehabilitation Department, Bikaner, during 50-51, which amount was not found entered in the Departmental account ?

(b) Who was the Deputy Director Rehabilitation and the Accounts Officer at Bikaner at that time ?

(c) Is it a fact that the cheque book was to be kept in the custody of the Accounts Officer ?

(d) Was any enquiry conducted in this case ?

(e) Was a Board presided over by the Collector of Bikaner constituted to enquire into the case ?

(f) What is the report of this Board ?

(g) What action has the Government taken against the persons responsible for it ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मन्त्री)—(a) Yes.

(b) Shri Parmanand was the Deputy Director of Rehabilitation and Shri Bodhraj Kapoor, Accounts Officer at that time.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) Yes.

(f) The matter is still under consideration of the Government and hence the content of the report cannot be disclosed.

(g) The matter is still under consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तो इस बीच में परमानन्द को एक्स्टेन्शन दिया गया है या क्या किया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव—यह तो एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट से पूछें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास— आपके कहने से क्या यह समझा जावे कि एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट और आपके डिपार्टमेंट में कोई कोऑपरेशन नहीं है ।

Page No.34

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं, कोऑपरेशन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट, तहकीकात और जाँच होते हुए भी, इस प्रश्न पर खयाल नहीं रखता ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि......

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सूचना एपोइन्टमेंट डिपार्टमेन्ट को आपके यहाँ से भेजी जा चुकी है।

श्री अमृतलाल यादव—यह प्रश्न विचाराधीन है। उसकी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की जा सकती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी जा चुकी है ?

श्री अमृतलाल यादव—इसके बारे में एपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट ही बतला सकेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५२

आदिम जातियों को वन विभाग के ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिये समितियों का निर्माण

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या सहकारी विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने आदिवासी जातियों का जंगलात विभाग के ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए जंगल सहयोग समितियाँ निर्माण करने का कोई कदम उठाया है ?

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ पर और कितनी सहयोगकारी समितियां का निर्माण हुआ है ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—४६ ग्रामों में बहुधन्धी सहकारी समितियां स्थापित की जा चुकी हैं। उनके द्वारा जंगल का कार्य भी यथाशक्ति सम्पादित कराया जावेगा। ४६ ग्रामों की सूची अगर आप कहें तो पढ़कर सुना सकता हूँ और अगर आप कहें तो टेबल पर रख सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष—टेबल पर रख दीजिए, वे देख लेंगे।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री धूलजी भाई भावसार—मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाँसवाड़ा जिले में कितनी सहकारी समितियाँ खोली गई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, बांसवाड़ा जिले में भी इस प्रकार की समितियाँ खोली गई हैं।

श्री अध्यक्ष—वहाँ कितनी हैं, यह पूछ रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव—मैं अभी छाँट कर तो नहीं बता सकता। शिड्यूल एरिया में समितियाँ खोली गई हैं।

श्रीमती यशोदा देवी—ये समितियाँ कहाँ-कहाँ हैं, क्या आप बता सकते हैं?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, बता सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष मुझे पढ़ने की इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आप जल्दी-जल्दी पढ़ दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव—आगीडोरा, बड़ोदिया, घाटोल, दानपुर, बड़वास, हमीरपुर करजी, जालोन, कोपड़ा भीलान, कोपड़ा चमारान, बोरी भीलान, बोरी शिवा, बाड़ली पाडा भीलान, भारी, बांसवाड़ा, कुन्दला, भापोरल सरवण, प्रतापपुर, सियालदारी, मालपुर, बोखला, गांधी अहेडा, झोंथरी माल, करावड़ा, आसपुर, गेंजी, गामड़ी, सीशोद, बांसवासी, भांडा, खेड़ी, गुमानपुरा, रंजिया, चिरौया वासा, बारी हंगरीपाड़ा, बरवास छोटी, सांडलाई छोटी, भगतपुरा, फगहगढ़, खीरोत, डूँगरपुर, रास्ता, फोरी बड़ी, सुराना, रामपुर।

श्री हरिदेव जोशी—क्या इन समितियों ने काम शुरू कर दिया है?

श्री अमृतलाल यादव—ये समितियाँ स्थापित हो चुकी है और काम शुरू होने वाला है।

श्री सोहनलाल भटनागर—इन समितियों से क्या लाभ होगा?

श्री अमृतलाल यादव—ये समितियाँ बहु-धन्धी हैं और कोई भी काम कर सकती है।

श्रीमती यशोदा देवी—यह कार्य कब तक शुरू हो जायगा?

श्री अमृतलाल यादव—यह कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जायगा; हो भी चुका है।

श्रीमती यशोदा देवी—मयाद क्या है?

श्री अध्यक्ष— कुछ नहीं।

(हँसी)

श्रीमती यशोदा देवी—मैं पूछना चाहती हूँ कि मुद्दत क्या है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये आपसे मुद्दत पूछना चाहती है।

(हँसी)

श्री धूलजी भाई भावसार—इन सहकारी समितियों में कितनी समितियां काम कर रही हैं और कितनी नहीं?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये जो समितियाँ हैं उनमें से कुछ तो गये साल बनी थीं और कुछ इस साल बनी हैं। कुछ ने काम शुरू कर दिया है और कुछ करने वाली हैं तथा कुछ काम कर रही हैं ?

श्री अध्यक्ष—Next, Shri Tejmal Bapna.

श्री किस्तूरचन्द—श्री तेजमल बापना ने मुझे कहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूछ लूँ।

श्री अध्यक्ष—No.

प्रश्न संख्या ४५३ व ४५४

श्री तेजमल बापना।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५५

सिघाना, खेतड़ी में द्वितीय श्रेणी का औषधालय तथा नर्स अथवा मिडवाइफ का प्रबन्ध

श्री रघुवीरसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि सिघाना, खेतड़ी सब डिवीज़न में सैकिन्ड ग्रेड का एक औषधालय है लेकिन वहाँ नर्स व मिडवाइफ का कोई प्रबन्ध नहीं है ?

(ख) इस दिशा में सरकार क्या प्रयत्न करने का सोच रही है ?

श्री कुम्भाराम (स्वास्थ्य मन्त्री)--सिघाना, खेतड़ी सब डिवीज़न में जो औषधालय है उसकी स्ट्रेन्थ में नर्स या मिडवाइफ स्वीकृत नहीं है। सरकार ने यह निश्चय किया है कि नर्स ए. तथा बी. श्रेणी के औषधालयों में स्वीकृत की जाँय और सी. श्रेणी के औषधालयों में केवल एक वैद्य और अनुचर ही रखा जाय। चूँकि सिघाना सी. श्रेणी का औषधालय है अतः वहाँ पर नर्स या मिडवाइफ नहीं रखी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री कंवरलाल जेलिया।

प्रश्न संख्या ४५६

अल्प बचत कोष के अन्तर्गत राजस्थान नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स की बिक्री से धनराशि का संग्रह विभिन्न डिवीज़नों से

श्री कंवरलाल जेलिया--क्या अर्थ मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री कँवरलाल जेलिया]

(क) राजस्थान में अल्प बचत कोष के तहत अब तक नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स की बिक्री से कितनी धनराशि जनता द्वारा संचित की जा सकी है ? यह किन-किन डिवीजनों में, किन-किन जिलों में कितनी-कितनी संग्रह हुई है ?

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा अल्प बचत कोष में नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट्स की बिक्री व इसकी एजेन्सी की व्यवस्था किस तरह से की गई है ?

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जन-सम्पर्क स्थापन करने तथा प्रचार के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं तथा उन्हें किस भाँति कार्यान्वित किया जावेगा ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) राजस्थान में अल्प बचत कोष के तहत में नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स की बिक्री से अप्रैल सन् १९५३ से दिसम्बर सन् १९५३ के अन्त तक २५, ८५,५४४ रुपयों की बिक्री हुई है जिसमें से ४, ३०, ०४५ रुपयों के नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स एनकेश करा लिये गये हैं । यह किन-किन डिवीज़नों में व किन जिलों में कितनी-कितनी संग्रह हुई हैं, इस बारे में अंक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) राजस्थान सरकार ने अल्प बचत कोष में नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स की बिक्री व एजेन्सी के लिए एक केन्द्रीय कमेटी कायम की है तथा प्रत्येक जिले में जिला कमेटी है जो इस बारे में पूरी व्यवस्था करती है । इसके अलावा हर जिले में कलेक्टर को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे नियमानुसार authorised agents नियुक्त करें । गवर्नमेंट के कर्मचारी भी authorised agents हो सकते हैं । महिलाओं की एक एक अतिरिक्त कमेटी बनी हुई हैं जो महिलाओं में विशेष रूप से प्रचार कर धन एकत्रित करती है ।

(ग) सरकार में जन-सम्पर्क स्थापन करने हेतु अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय बचत पक्ष ता० १२ मार्च से २६ मार्च, सन् १९५४ तक मनाने का निश्चय किया है और उसी माफिक आज-कल कार्य हो रहा है । कलेक्टरों को भी यह आज्ञा दी गई है कि वे अपने-अपने जिलों में राष्ट्रीय बचत पक्ष मनावें और जनता को इसके बारे में सही जानकारी दें और अधिक से अधिक धन जमा करने के लिये अनुरोध करें । इसके अलावा राजस्थान में प्रसिद्ध-प्रसिद्ध मेलों के अवसर पर विशेष प्रोग्राम किये जाते हैं और जनता से अधिक से अधिक धन जमा करने के लिए अनुरोध किया जाता है । अभी हाल में नागौर के बैलों के मेलों में एक बृहत आयोजन किया गया था । प्रचार के लिए एक Publicity Van की भी समुचित व्यवस्था है तथा नेशनल सेविंग्ज़ ऑफीसर मजदूरों तथा कारखानों के मालिकों से सदैव सम्पर्क में रहता है ताकि अधिक से अधिक धन-राशि इसमेंएकत्रित की जा सकें । समय-समय प्रचार कार्य भी किया जाता है तथा इसका साहित्य राजस्थानी भाषा में भी निकाला गया है ।

[श्री चन्दनमल वैद]

मजदूर सम्मेलनों का भी लाभ उठाया जाता है। पंचयातों द्वारा भी प्रचार कार्य करने का आयोजन किया गया है। सेविंग्ज़ ग्रूप स्थापित किये गये हैं और उनके प्रसार का कार्य भी किया जाता है।

राजस्थानी प्रवासियों से भी अपील की गई है कि वे कुछ धन राजस्थान में जमा करावें।

बहुत सी संस्थाओं से भी प्रार्थना की गई है कि वे इस कार्य में समर्थन दें। कांग्रेस क्षत्रिय महासभा इत्यादि संस्थायें भी अपने-अपने तरीके से प्रचार कर रही हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के फन्ड्स से भी नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स खरीदे गये थे क्या? जैसे देवस्थान डिपार्टमेंट......

श्री चन्दनमल वैद--जी हाँ, खरीद गये हैं। देवस्थान डिपार्टमेंट के फन्ड्स से १ लाख रुपयों के नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट्स खरीदे गये हैं।

कुँ श्री जसवन्तसिंह--और कुछ अन्य महकमों का भी नाम बता सकते हैं क्या?

श्री चन्दनमल वैद--अलग प्रश्न पूछने पर मैं जानकारी दे सकूँगा।

श्री कंवरलाल जेलिया--हमारे पड़ौसी मध्यभारत में जो धन प्राप्त हुआ है उसके मुकाबले में हमारे राजस्थान में बहुत कम प्राप्त हुआ है क्या?

श्री चन्दनमल वैद--यह आप मध्यभारत विधान-सभा से पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इसके लिए कितने अफसर मुकर्रर किये गये हैं?

श्री चन्दनमल वैद--केवल एक।

श्री कँवरलाल जेलिया--डिवीज़न्स में क्या अलग प्रचारक मुकर्रर नहीं किये गये हैं?

श्री चन्दनमल वैद--जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--एक सर्कुलर हमारे पास आया है, तो क्या किसी व्यक्ति ने हमको यों ही भेज दिया है।

श्री चन्दनमल वैद--भारत सरकार के अफसर ने भेजा होगा।

श्री कँवरलाल जेलिया--जिला वाइज़ जो समितियाँ बनाई गई हैं उनका जन-संपर्क इतना क्यों नहीं है?

श्री चन्ददमल वैद--आशा तो यही की जाती है कि जन-सपर्क खूब हो।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री हरिशंकर।

प्रश्न सँख्या ४५७

जोधपुर पॉवर हाउस के लिए ३५० किलोवाट के कुछ डिजल इंजिनों की पूर्ति के लिये आज्ञा देना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि जोधपुर पॉवर हाउस के लिए २५०-२५० किलोवाट्स के तीन या चार डिज़ल इन्जिन्स सप्लाई करने का ऑर्डर किसी फर्म को दिया जा चुका है ?

(ख) यदि हाँ, तो ऑर्डर देने के पहले क्या इस विषय में सील्ड टेन्डर्स भी माँगे गये थे और क्या इसका बाकायदा ऑल इन्डिया पेपर्स में विज्ञापन कराया गया था ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि जिस फर्म को ऑर्डर दिया गया था उसने अब तक उन इन्जिनों की डिलीवरी पीरियड के अन्दर सप्लाई नहीं किया है ?

(ङ) यदि हाँ, तो फिर उस ऑर्डर को केन्सिल क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) हाँ, जोधपुर पॉवर हाउस के लिए पाँच दो-दो सौ किलोवाट के डिज़ल जेनेरटिंग सेट्स का ऑर्डर दिया गया था।

(ख) हाँ। सील बन्द टेन्डर मांगे गये थे और टेंडर सूचना भारत के निम्नलिखित प्रमुख पत्रों में दो अङ्कों में प्रकाशित की गई थी :

(१) हिन्दुस्तान टाइम्स।

(२) टाइम्स ओफ इन्डिया।

(३) स्टट्समेन, न्यू देहली।

(४) हिन्दू, मद्रास।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नहीं। यह सत्य नहीं है।

(ङ) वह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह सरकार बतलायगी कि उसको कितना समय दिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद—इमीजियेट डिलीवरी (immediate delivery) के आधार पर दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--डिलीवरी की सप्लाई क्या स्टिपुलेट (stipulate) की गई ?

श्री चन्दनमल वैद--डिलीवरी हो चुकी थी।

एक सदस्य--क्या यह विज्ञापन राजस्थान के समाचार-पत्रों में भी दिया गया।

श्री चन्दनमल वैद--हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इन्डिया राजस्थान में भी आते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--डिलीवरी की सप्लाई कौनसी तारीख तक आने का स्टिपुलेशन था ?

श्री चन्दनमल वैद--हिन्दुस्तान इलेक्ट्रिक कम्पनी, बम्बई को यह ऑर्डर दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सप्लाई कौनसी तारीख तक देने का स्टिपुलेशन था ?

श्री चन्दनमल वैद--ठीक जिस तारीख को था उस तारीख को दिया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या उस तारीख तक डिलीवरी मिल गई थी।

श्री चन्दनमल वैद--जी हाँ।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४५८

आयुर्वेदिक औषधालयों में काम करने वाले वैद्यों और कम्पाउन्डरों का एकीकरण

श्री तेजपाल--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) आयुर्वेदिक औषधालयों में काम करने वाले वैद्यों और कम्पाउन्डरों का इन्टीग्रेशन कब तक पूरा हो सकेगा ?

(ख) नए स्केल के अनुसार उन्हें वेतन कब तक मिल सकेंगे ?

श्री कुम्भाराम (स्वास्थ्य मन्त्री)--(क) शीघ्र ही।

(ख) अब बहुत देर नहीं।

(हंसी)

श्री तेजपाल--आप बता सकेंगे कि कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट, श्री सन्तोषसिंह।

प्रश्न संख्या ४५९

जोधपुर की उद्योग तथा कृषि प्रदर्शनी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस-किस विभाग ने किन-किन वस्तुओं से काम से व किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कितने दिनों तक इस प्रदर्शिनी में कुल कितने रुपयों तक का काम किया ?

(ख) इस प्रदर्शनी में पाइप लाइन पर सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ ? क्या यह खर्चा प्रदर्शनकर्ता से वसूल किया जायगा ?

(ग) इस प्रदर्शनी में शुरू से आखिर तक कुल कितने गैलन पानी किस रेट से कितने रुपयों का दिया गया ?

(घ) इस विभाग के कुल कितने, किस माप के स्टाल कितने-कितने रुपयों में किराये पर थे ?

(ङ) हर एक स्टाल में बिजली का व अन्य क्या-क्या खर्च हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—(क) जोधपुर की उद्योग एवं कृषि प्रदर्शनी में फर्राश खाने से कुछ सामान व तम्बू दिये गये। पानी महकमे से २४ टूंटी व नल लगाये गये। इमारत व सड़क विभाग ने एक स्टाल जनता की जानकारी व ५ साला योजना के प्रदर्शनार्थ बनाई। इसमें नगर शाखा कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया। स्टाल बनाने में करीब १५०) रु० खर्च हुए। स्टाल में टीन व बांस वगैरह प्रदर्शनी की तरफ से दिये गये थे और बाकी सामान पुरानी स्क्रेप से जो सजावटों के वास्ते पड़ा हुआ है, लिया गया। बिजली विभाग ने प्रदर्शनी के लिए केवल बिजली के कनेक्शन का प्रबन्ध किया जिसका खर्चा प्रदर्शनी के अधिकारी देंगे। सिंचाई विभाग से प्रदर्शनी में जवाई व चम्बल प्रोजेक्ट तथा पार्वती व मुरेल आदि बन्धों के मोडल व चार्ट और उनके प्रदर्शन हेतु ड्राफ्ट्समेन आदि भेजे गये जिसके व्यय का अनुमान २२००) रु० है।

(ख) प्रदर्शनी के पाइप लाइन लगाने का काम सरकार की ओर से किया गया और टूट-फूट का खर्चा प्रदर्शनी संयोजकों से वसूल किया जायगा। लाइन लगाने व हटाने के खर्चे की वसूली का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रदर्शनी में कुल ७१००० गैलन पानी रिपोर्ट आने के समय तक खर्च हुआ जिसकी किमत १) रु० फी हजार गैलन की दर से प्रदर्शनी संयोजकों से वसूल किया जायगा। इसके अलावा मोटर कार किराया भी वसूल किया जायगा।

(घ) जनकार्य विभाग द्वारा एक स्टाल ३०-३० फीट साइज़ का लिया गया। इसका किराया देने का कोई सवाल नहीं है।

(ङ) जनकार्य विभाग के स्टाल में जो बिजली का प्रबन्ध हुआ उसका अनुमान ४०) रु० का है। एक और स्टाल बिजली विभाग के लिये लिया गया था और उस पर कर्मचारियों आदि के किराये पर खर्चे का अनुमान २५०) रु० का है।

Page No.42

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

श्री सन्तोषसिंह--जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें पी. डब्ल्यू. डी. विभाग द्वारा जो तम्बू और डेरे दिये गये, वहाँ रोड बनाने के लिए जो रोड रोलर दिया गया उसका खर्चा क्या प्रदर्शनी करने वालों से वसूल किया गया या गवर्नमेन्ट ने दिया है।

श्री चन्दनमल वैद--पानी के लिए तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। बाकी अन्य सामान के लिए सरकार विचार कर रही है कि यह खर्चा किससे लिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार पहले बिना तय किये ही फेसिलिटीज़ अवेलेबल (facilities available) कर देती है?

श्री चन्दनमल वैद--किसी अच्छे काम के लिए सुविधायें देना जरूरी हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तय किये बगैर ही फेसिलिटीज़ दी गई?

श्री अध्यक्ष--This is evident from the reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Why should he evade?

श्री अध्यक्ष--The question hour is over.

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)--Sir, Under Rule 193 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly I have to report that I have received a petition relating to the Bill to provide for the levy of general tax on the sale of goods in Rajasthan which was introduced in the Assembly on the 11th March, 1954 and I lay it on the Table.

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री, वित्त विभाग)--Sir, I lay on the Table of the House the Finance Accounts for 1951-52 and Audit Report for 1951.

श्री अध्यक्ष--Now we resume our discussions on the Budget. Shri Bhoiron Singh.

माँग संख्या १६--शिक्षा (क्रम में)

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा के विषय में कल कुछ बातें सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की थीं। आज एक दूसरे विषय को लेकर कुछ बातें सदन के सामने जो रखनी हैं वे यह हैं कि शिक्षा के अन्दर जिन पाठ्यपुस्तकों का क्रम जिस आधार पर बनाया जाता है उनसे कितनी दिक्कतें जनता को हो रही है, इस बारे में हमें विचार करना है।

[श्री भैरूँसिंह]

एक माननीय सदस्य ने कल जिस तरीके से पाठ्य पुस्तकों का सिलेक्शन होता है उसके बारे में कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश किये थे, जो कठिनाइयें पेश होती हैं वे सदन के समक्ष रखी थीं। अध्यक्ष महोदय, इनके अन्दर कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी ओर मुझे सदन का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेक्शन होता है उस वक्त जितने भी टेक्स्ट बुक्स के लिखने वाले होते हैं उनको यह लिख कर दिया जाता है कि वे अपना नाम, उस कॉपी की जिल्द, सारी की सारी हटा दें ताकि जितने भी रिव्यूअर्स आते हैं उनको यह पता न चल सके कि अमुक पुस्तक अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई है; ताकि अमुक व्यक्ति रिव्यूअर्स के पास सिफारिश न ले जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गत वर्ष पाठ्यपुस्तको का एक विशाल काण्ड हुआ। उतनी सख्ती के बावजूद भी यह असंभव नहीं कि पाठ्यपुस्तकों के रिव्यूअर्स को पाठ्यपुस्तकें किसके द्वारा लिखी हुई हैं, यह पता न चल सके। वे एक दूसरे ही तरीके से मालूम कर लेते हैं। जिस किसी शख्स द्वारा किताबें लिखी जाती हैं उनसे वे मिल लेते हैं और मालूम कर लेते हैं कि उनका फलां विषय फलां पुस्तक में है; ताकि वह समझ सकें कि यह उनकी पुस्तक है। गत वर्ष जो काण्ड हुआ था उसमें सिर्फ एक क्लर्क को ससपेन्ड किया गया और सारा जिम्मा उस पर डाल दिया गया। पुलिस द्वारा इन्क्वायरी की गई लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि उस इन्क्वायरी के बाद उस सम्बन्ध में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। केवल इसमें एक बेचारे क्लर्क का ही दोष नहीं, किन्तु नीचे से लेकर ऊँचे अधिकारियों तक की जिम्मेदारी थी। यह सारी की सारी इन्क्वायरी की रिपोर्ट सदन के सामने आती तो पता चलता कि किस प्रकार बड़े-बड़े अधिकारियों का इसमें हाथ था। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि **Text books** के Selection में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई जिनका सम्बन्ध राज्य के ऊँचे-ऊँचे अधिकारियों से है। उनको यह कह तो दिया गया कि पाठ्यपुस्तकों पर से आप नाम हटालें, कवर हटा दीजिये लेकिन जो पुस्तक है उसमें १० वां पाठ फलां रख दीजिये ताकि जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जायगा। आप इस बात को अच्छी तरह देखलें कि जब सारी की सारी किताबें रिव्यूअर्स के सामने पेश होती है तो वे उसको देखते हैं और जब एक घन्टा देख लेते हैं तो बाहर आ जाते हैं और वे पब्लिशर्स से मिल लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी किताब का पता नहीं चला, तो फिर वे पब्लिशर्स या बुकसेलर्स बता देते हैं कि मैंने नवां पाठ इस विषय का दिया है, इस तरह से जब वे वापिस अन्दर जाते हैं तो उनकी किताब का सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप इस विषय में कमीशन बैठायें तो इस काण्ड के बारे में आपको पता चलेगा कि केवल एक क्लर्क का ही उसमें हाथ नहीं है बल्कि मैं यहाँ तक स्पष्ट कहने के लिए तैयार हूँ कि एज्युकेशन सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक के क्लर्क लोगो का भी उसमें हाथ था।

(शेम-शेम)

दूसरी चीज़ मैं निवेदन करूँगा कि इतनी दिलचस्पी लेते हुए भी पाठ्यपुस्तकों में जो पाठ होते हैं वे किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं एक उदाहरण की तौर पर कुछ निवेदन करूँगा।

[श्री भैंरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

इसके लिए मेरा निवेदन है कि कई स्थानों पर ऐसी प्रथा है कि एज्युकेशन के जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनको लिख कर दिया जाता है कि इतने प्रकार की बुक्स बनानी हैं। वे खुद लिखते हैं और इसके बाद में एजुकेशन का बोर्ड उसे एप्रूव कर देता है, जो बाद में गवर्नमेंट के प्रेस के ही जरिये से छापी जाती है और बाद में बिकने के लिए बुकसेलर्स को दे दी जाती हैं। यह काफी उन्नत तरीका आज माना जा रहा है। इससे आज का व्याप्त भ्रष्टाचार तो इस विभाग में अवश्य ही कम होता है, पर अगर इसी तरीके को अपनाना है तो अवश्य शीघ्रता की जावे, नहीं तो ये आज के शिक्षा विभाग के अधिकारी और उनके तरीके किसी भी तरह से जनता की सेवा करने के लायक नहीं हैं। इसके प्रणाम में एक पाठ्य पुस्तक मैं सदन के सामने रखना चाहता था और इसे Booksellers से प्राप्त करने के लिए आज का टाइम भी लिया था पर दुर्भाग्य से वह पुस्तक मिली नहीं। पर कॉपी की हुई एक नकल हमें मिल गई। मैं उसी को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसका नाम है स्वास्थ्य तथा गृह विज्ञान। सर्कुलर नम्बर Ed/P/G-1/51 के द्वारा राजस्थान सरकार से यह सारे राजस्थान के लिए पाठ्य पुस्तक स्वीकृत की गई है। इसका एक अवतरण है उसको मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ—

"अध्यापक (कहता है) –बच्चो, ईश्वर ने तुम्हें एक अत्यन्त उत्तम शरीर दिया है इस शरीर में दस इन्द्रियाँ हैं और पाँच कर्म इन्द्रियाँ हैं।"

पन्द्रह तो इन्द्रियाँ बता दीं और इसके बाद मैं लड़का कहता है—

"गुरूजी वे कौन-सी ?"

तो जवाब मिलता है—

"अध्यापकः—आँख, कोन, नाक, जिव्हा, त्वचा (खाल) गुदा और मूत्र, ये पाँच कर्म इन्द्रियाँ हैं। अतः इनकी सफाई के बारे में तुम्हें कुछ लाभदायक बातें बतलाता हूँ।"

ये इन्द्रियाँ हैं पाँच पर गिनती में सात कर दी।

और कर्मेन्द्रियाँ क्या हैं, ज्ञानेन्द्रियाँ क्या हैं इसका ज्ञान नहीं और बता दिया सात कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ।

तो इस प्रकार की बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। तो ऐसे रिव्यूअर हैं हमारे इस विभाग में जिन्होंने इसको देखकर इसे पास कर दिया। लिखने वाले को तो मालूम नहीं यह भी कि इन्द्रियाँ कितनी होती हैं और रिव्यूअर्स भी नहीं जानते कि इन्द्रियाँ कितनी और कौन-कौन सी हैं, इससे तो यही ज़ाहिर होता है। इसी तरह से इस पुस्तिका की भूमिका को पढ़ते हैं तो हमें तरस आता है, इन सरकारी अधिकारियों और सरकारी रिव्यूअरों की बुद्धि पर। ऐसे-ऐसे अधिकारियों से हमारी यह सरकार उम्मीद करती है कि इनसे जनता का और हमारे इस भावी पीढ़ी का कुछ भला होगा। यह बालू में से तेल निकालने जैसी ही बात है।

Page No.45

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

अध्यक्ष महोदय, आज सारा विश्व का इतिहास साक्षी है, सारा इतिहास साफ-साफ यह जाहिर कर रहा है कि जब-जब जहाँ क्रान्तियाँ आई हैं जब कभी किसी के द्वारा क्रान्तियाँ हुई हैं तो वे सब असन्तुष्ट मध्यमवर्ग के बुद्धिजीवियों द्वारा ही हुई हैं और उस असन्तुष्ट बुद्धिजीवी वर्ग का महत्त्व और भी बढ़ जाता है जब उसकी महत्वाकाँक्षा पूरी नहीं होती है। इस सरकार के द्वारा तो इससे तो उस वर्ग में रोष बढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, दो ही बातें मुझे कहनी हैं। दो मिनिट आपसे और चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष—आप वाइन्ड अप (wind up) करिये।

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—शिक्षा की आजकल की जो पद्धति है वह बड़ी दूषित है। इससे शिक्षित वर्ग में जो एक बेकारी फैली हुई है उसी बेकारी को अगर और बढ़ाना हो तो इस शिक्षा की पद्धति को जारी रहने दें, पर अगर बेकारी को दूर करना है और शिक्षित वर्ग में जो श्रम से एक प्रकार से नफरत सी है उसको समाप्त करना है तो जल्दी से जल्दी इस शिक्षा की पद्धति को आपको बदलना होगा। इस बेकारी को रोकने के लिए, सरकार को जल्दी से जल्दी बुनियादी शिक्षा को लागू करने के लिए सोचना चाहिये। इसके बारे में श्रद्धेय महात्मा गाँधी ने भी एक योजना देश के सामने रक्खी थी पर आज इतने वर्ष होने पर भी देश के आजाद हो जाने पर भी हमारी जनता की प्रतिनिधि सरकार समझी जाने वाली ये हमारी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रहीं हैं। वे आज इस वर्तमान शिक्षा-पद्धति के आगे होने वाले और आज प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले दूषित प्रभाव को अच्छी तरह से अनुभव कर रहे मालूम होते दिखाई नहीं देते। आज वे यह कहते हैं कि इस नई प्रणाली को जारी करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं, पर मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मेरे माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर अच्छी तरह विचार करके शिक्षा की, बुनियादी शिक्षा की एक योजना बनाएँ तो इसके बनने के बाद में इस प्रकार की कोई कठिनाई सरकार और जनता के सामने नहीं आने वाली है। पर पहले ही यह मानकर कि कठिनाइयां का मुकाबला कैसे किया जावेगा, तो उन कठिनाइयों से घबरा कर आज की इस शिक्षा की दूषित पद्धति को नहीं बदलें तो मैं तो उनका मष्तिस्क, अज्ञानता का मष्तिस्क बताऊँगा। यदि राजस्थान में बेकारी के जो आँकड़े बताये गये हैं वे सही हैं तो यहाँ पर बीस हजार के करीब जो सालाना बेकार होते हैं, अगर इन बीस हजार बेकारों को काम पर लगाना है और आगे इस बेकारी को बढ़ने से रोकना है तो हमारी सरकार को अविलम्ब इस दूषित आज की शिक्षा प्रणाली को बदल डालना चाहिये। हमें केन्द्र की इन्तजार नहीं करनी है। यह हमें नहीं देखना है कि भारत सरकार से क्या आदेश मिलेंगे और उनके आदेश का पालन कैसे हो। यह तो अभी आदेश आवेंगे तब आवेंगे, इनमें तो अभी काफी वक्त लग सकता है। पर हमें तो अपनी बीमारी का इलाज खुद करना है और फिर शिक्षा सेन्टर का विषय भी नहीं है, यह तो प्रान्त का विषय है। आप इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। हमें जल्दी ही शिक्षा में परिवर्तन करना है जिससे कि बेकारों कि यह संख्या घटे, बढ़े नहीं। इतना ही निवेदन करके माननीय अध्यक्ष मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—I want to know how much time the House wants to take over this Demand ?

श्री वेदपाल त्यागी—It is an important Demand.

श्री अध्यक्ष—That is true, but I wanted to know form the Members who want to speak; so that I can ascertain time.

श्री चाँदमल मेहता—मैं तो दस मिनिट से ज्यादा नहीं लूँगा।

श्री अध्यक्ष—Leave the time to me.

(श्री शम्भूसिंह बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has spoken yesterday.

Once a Member has already spoken he cannot speak twice on the same subject.

श्री शम्भूसिंह—मैं भी श्री बापना के कट मोशन का सपोर्ट करने के लिए बोलना चाहता हूँ, मेरे सबजेक्ट पर तो मैं बोला ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—No, no, that is not the rule.

(श्री शम्भूसिंह के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—Order please ! Order !! Yes Shri Mehta.

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष नये स्कूल खोलने के लिए काफी रकम बजट में रक्खी गई थी और नये स्कूल काफी संख्या में खोले भी गये और इस वर्ष भी अच्छी रकम इसके लिए रक्खी गई है और काफी स्कूल खोलने की योजना है। इसके लिए तो मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी को बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करूँगा कि ये स्कूलें खोलने में भी सरकार की एक निश्चित नीति नहीं है। होना यह चाहिये कि सरकार इसके लिए एक निश्चित नीति निर्धारित करे कि किस हिस्से में कितने मिडिल स्कूल खोले जाएँ; कितनी हाई स्कूलें और कितनी प्राइमरी स्कूलें और कितने कॉलिज खोले जाएँ।

इस तरह की निश्चित नीति नहीं होने की वजह से कई स्थान ऐसे रह गये हैं कि जहाँ वाकई में स्कूल या हाईस्कूल या कॉलेज खुलने चाहिये वे उससे वंचित रह गये हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने एक बात रखता हूँ। परबतसर एक महत्त्वपूर्ण स्थान है नागौर जिले का। वहाँ हाई स्कूल होनी चाहिये थी पर नहीं है, जब कि इससे कई कम महत्त्वपूर्ण स्थानों पर हाई स्कूल कायम हैं और सरकार द्वारा खोले गये हैं। इसके लिए जब सरकार के सामने माँग रक्खी जाती है तो यह कह कर टाल दिया जाता है कि जब तक इसके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं हो जाती गाँव वालों की तरफ से, तब तक वहाँ हाई स्कूल नहीं खोली जा सकती। लेकिन मैं यह भी निवेदन करूँगा कि अगर

[श्री चाँदमल मेहता]

बिल्डिंग की कमी को देखकर वहाँ हाई स्कूल नहीं खोला गया है तो यह उचित ... होगी। यह कोई सरकार की निश्चित नीति का अंग नहीं हो सकता। ... यह बनानी चाहिये कि हर साल इस हिसाब से सब जगह हाई स्कू... कॉलेज आदि खोले जाएँगे, चाहे इनके लिए गाँव वालों द्वारा बिल्डिंग बनाई ...

दूसरी बात मैं और निवेदन करूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ... पीलवा गाँव है। वहाँ के लोगों ने हाई स्कूल के लिए १५ हजार की लागत से ... ली और माँग की तब सरकार से कि अगर इमारत की वजह से आप हाई स्कू... लीजिये हमने इमारतें भी बनवा ली है, अब तो आप हमारे यहाँ हाई स्कूल की ... में तो यह मौका दिया जाना चाहिये था, पर वहाँ भी इसका मौका नहीं आया। तो ... नीति। इसके सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान अवश्य खींचूँगा कि इस सम्बन्ध में सरकार कोई अपनी स्थिर नीति निर्धारित कर दे और फिर उस पर दृढ़ता के साथ चले। यह क्या कि एक जगह तो चूँकि स्कूल के लिए बिल्डिंग नहीं थी तो कह दिया कि बिल्डिंग बनाओ तो स्कूल कायम करें और इसके विपरित दूसरी जगह जब बिल्डिंग लोगों ने बनवाली तो यह कहकर टाल दिया कि अभी नहीं खोली जा सकती।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा मास्टरों की तनख्वाह के बारे में। वह इतनी कम है कि आज कारखाने में काम करने वाला मजदूर भी उनसे ज्यादा तनख्वाह पाता है। कारखाने में काम करने वाले मजदूर से भी उनकी तनख्वाह कम है। एक ... वाला मजदूर स्थायी तौर पर एक जगह रहता है और ५४) रु० कम से कम ... कि इसके मुकाबले में एक मास्टर ५०) रुपया ही तनख्वाह पाता है और फिर ... उसके पीछे लगी है। एक जगह स्थायी रूप से भी तो नहीं रह सकता और इसके ... और भी है कि अगर उसे तनख्वाह लेनी है तो उसे हैड ऑफिस की ट्रेज़री ... जाना पड़ेगा। इसमें उसे वक्त तो लगेगा ही, पर साथ ही खरचा भी करना होगा और वह भी उसको खुद को भुगतना पड़ेगा। तनख्वाह लेने के बारे में सरकार खर्चा भी उन्हें नहीं देना चाहती। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्षजी, आपकी मार्फत सरकार के इन मन्त्री महोदयों की सेवा में यह निवेदन करूँगा कि इन अध्यापकों की तनख्वाह के बारे में वे फिर से विचार करें।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह है अध्यापकों के पठन-पाठन के बारे में। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो अध्यापकगण आगे पढ़ना-लिखना चाहते हैं उनको पूरी सुविधा दी जावे। पर इस वक्त यह सम्भव नहीं। ऐसे अध्यापक मौजूद हैं जिन्होंने आगे इम्तिहान देना चाहा और इसके लिए इजाजत दी जाने के लिए अपने अधिकारियों को लिखा, पर उनको इजाजत नहीं दी गई और अगर कोई बगैर इजाजत इम्तिहान में बैठ गया तो उनको रोक... जाती है। इस सम्बन्ध में यह बताया गया कि इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं कि एक स्कूल में तीन से ज्यादा मास्टरों को इम्तिहान देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पर ऐसा मौका भी कई बार आता है कि जब कि तीन से ज्यादा अध्यापकों ने माँग की है और उनमें से तीन आदमियों को इजाजत

[श्री चाँदमल मेहता]

दे दी गई है पर इन तीनों में से कोई भी इम्तिहान में नहीं बैठा और जिनको इजाजत नहीं दी वे भी ऐसे ही रह गये। इस कानून को बनाने के पहले हम देखें कि जब यह रेस्ट्रिक्शन (restriction) नहीं थी उस समय बहुत बड़ी तादाद में मास्टर इम्तिहान में बैठते थे, पर ऐसी नहीं थी कि उससे उनके बच्चों को पढ़ाने के काम में बाधा पड़ती हो, जैसा कि यह नियम ब[illegible] समय अधिकारीगण ने सोचा है कि ऐसा करने से और उन्हें खुली छूट देने से बच्चों की पढ़ाई में [illegible] होगा। इससे कोई अव्यवस्था भी पहले नहीं होती थी पर आज यह बन्दिशें लगा दी गई हैं कि [illegible] से ज्यादा नहीं दे सकते और अगर देते हैं तो बड़ी-बड़ी सजाएँ दी जाती हैं। तो मेरा निवेदन है वह बड़ी सजाएँ बन्द की जानी चाहिये।

स्कूलों के बारे में मुझे और जो निवेदन करना है वह है खास तौर से इनकी इमारतों के [illegible] में जमीन देने के सम्बन्ध में। दिक्कतें यह आती हैं कि गाँव वाले स्कूलों के बिल्डिंग भी बनाना चा[illegible] हैं पर सरकार उन्हें सहूलियतें नहीं देना चाहती, जमीन नहीं देना चाहती। मैं इसके सम्बन्ध में ख[illegible] तौर से रिड गाँव के बारे में माननीय अध्यक्षजी, कहना चाहता हूँ कि वहाँ उस गाँव के लोगों [illegible] अपने गाँव में स्कूल खोलने के उद्देश्य से १५ हजार रुपये इकट्ठे किये हैं और अब वे यह माँग [illegible] रहे हैं कि अगर सरकार स्वयं मकान नहीं बना सकती तो कम से कम इसके लिए जमीन तो दी जा[illegible] पर जमीन के बारे में भी सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं; जब कि वहाँ के रहने वाले इस हद [illegible] तैयार हैं कि १५ हजार रुपयों की एक निधि इकट्ठी करके रख रक्खी है, पर महज जमीन नहीं मिल[illegible] से वह मकान स्कूल के लिए बनने से रह रहा है। तो अब अगर सरकार ने यह जमीन भी नहीं दी [illegible] यह बड़ी बुरी बात होगी इस सरकार के लिए।

इसके बाद एक बात मुझे निवेदन करनी है अध्यक्ष महोदय, खास तौर से अध्यापिकाओं के चरित्र के बारे में। इस सम्बन्ध में कुछ अध्यापिकाओं के बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित [illegible] किया गया कि इस तरह से कुछ अध्यापिकाएं चरित्रहीन हैं और इसका असर इतना बुरा बालिकाओं पर पड़ता है कि इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाना चाहिये। पर इस सम्बन्ध में जो कि[illegible] जाना चाहिये वह नहीं किया गया। मैं निवेदन करूँगा कि वैसे तो यह चीज़ अध्यापकों के लिए [illegible] आवश्यक है पर अध्यापिकाओं के मुकाबले में अध्यापकों से उतना बुरा परिणाम नहीं होता। प[illegible] अध्यापकों के मुकाबले में अध्यापिकाओं के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक बात है, इसलिए मेर[illegible] निवेदन है कि जहाँ-जहाँ इस तरह की शिकायतें आएँ उनके बारे में उचित कदम शीघ्र उठाय[illegible] जाना चाहिये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, देश के चरित्र-निर्माण के लिए यह आवश्यक [illegible] कि देश की शिक्षा पद्धति सुधरे। देश की तरक्की इस बात पर निर्भर है कि हमारी शिक्षा कि[illegible] प्रकार की हो। पर मुझे अफसोस है कि आज हमें आजाद हुए पाँच वर्ष हो गये पर आज तक हम[illegible] यह तय नहीं कर पाये कि हमारी शिक्षा-पद्धति क्या होनी चाहिए।

यह तो मैं अकसर सुना करता हूँ हमारे राष्ट्रपति और प्रान्तपति और देश के बड़े-बड़े नेता लोगों से और वे जहाँ कहीं भी जाते हैं यही कहा करते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत खराब है

[श्री वेदपाल त्यागी]

और वास्तव में यह बात सत्य भी है कि जिस वक्त मैकॉले ने इस वर्तमान शिक्षा-पद्धति का निर्माण किया था उस वक्त कहा था कि हमें क्लर्क चाहिये, हमें इस देश को गुलाम बनाने में, हमारी मदद करने के लिए क्लर्कों को पैदा करने लायक शिक्षण-संस्थाएँ चाहिए जहाँ से हम ऐसे गुलाम पैदा कर सकें जो हमारा राज कायम रख सकें। पर खेद है कि, यह जानते हुए भी कि आजाद होने को पाँच वर्ष हमें हो गये पर आज भी हमारे कॉलेजों से और हमारी युनीवर्सिटियों से उसी गुलाम मनोवृत्ति को लेकर लोग निकल रहे हैं और आज भी वही गुलाम प्रथा और गुलाम-शिक्षा-पद्धति जारी है।

यह जो बजट बना है राजस्थान सरकार का इसको देखने से पता लगता है कि राजस्थान सरकार का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है कि हमारे यहाँ शिक्षा का किस तरह का प्रसार करें। अगर बजट के आँकड़े देखे जाँय तो इनसे मालूम होगा कि युनिवर्सिटी और सेकन्डरी एजुकेशन पर जितना रुपया खर्च कर रहे हैं वह आधे से ज्यादा रुपया इसमें खर्च कर रहे हैं और कहा गया है कि हम नये-नये स्कूल खोल रहे हैं, हम ग्रामीण जनता को शिक्षित बनाने का पूरी तरह प्रयत्न करेंगे; लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब मैं बजट को देखता हूँ तो क्षोभ होता है कि यह बात कहाँ तक सत्य है। पिछले वर्ष टीचर्स की संख्या ८०७२ थी और इस वर्ष वह संख्या ७२२३ करदी गई है.....

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—यह फीगर्स करेक्ट कर दिये गये हैं, गलत थे।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या हैं करेक्ट फीगर्स ?

श्री भोलानाथ—आठ हजार के करीब हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—यह पिछले साल से बढ़े हैं या कम हुए हैं ?

श्री भोलानाथ—बढ़े हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—अगर जैसा कि यह कहा जा रहा है कि यह संख्या गलत थी, अब ठीक कर दी गई और पिछले साल से बढ़ी है तो भी, माननीय अध्यक्ष, जिस प्रकार से होना चाहिए था उस अनुपात से शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है। हमारा ज्यादातर रुपया युनिवर्सिटी और सेकन्डरी एजुकेशन पर खर्च होता है। वहाँ से लोग ग्रेजुएट बनते है और ग्रेजुएट बनने के बाद उनके सामने सिवाय एक उद्देश्य के 'नौकरी चाहिए' और कोई उद्देश्य नहीं रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूँगा कि यदि सरकार यह चाहती है कि देश का निर्माण हो, देश का चरित्र बहुत जल्दी बने, तो बहुत जल्दी ही इस शिक्षा-पद्धति को बदलना चाहिए। हमारे शिक्षक लोग इस बात के लिए कहा करते हैं कि इस देश का हरेक व्यक्ति शिक्षित हो। एक जर्मनी के बहुत भारी विद्वान हमारे यहाँ आये थे। वे एक गाँव में गये और गाँव के पनघट पर जाकर दो औरतों की बातचीत सुनी। एक औरत का बच्चा मर गया था तो दूसरी औरत उससे कह रही थी कि जितने दिनों का सम्बन्ध होता है उतने ही दिनों का सम्बन्ध रहता है। इस बात को सुनकर उसने अचम्भा किया कि यह कैसा देश है, उसको इन शब्द में बयान किया:—

"India is a nation of philosophers where every individual man knows philosophy."

[श्री देदपाल त्यागी]

तो, हमारी वह कल्चर (सभ्यता), हमारी वह फिलॉसोफी की शिक्षा-पद्धति बिल्कुल मिटती जा रही है। उसके पुनरुत्थान के लिये, उसको उठाने के लिये हमारे शासक लोग इस बात की कतई चिन्ता नहीं करते कि किस प्रकार की पद्धति हमारे देश में लानी चाहिए और किस प्रकार से हमारी पद्धति को हम बदलें। हम अपनी संस्कृति और लिटरेचर (साहित्य) से बहुत कुछ दूर होते जा रहे हैं। उस संस्कृति और लिटरेचर की आज हमें जरूरत है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमने अपने पूर्वजों से जो चीज हासिल की है उसको भुला नहीं सकते हैं। हमारी संस्कृति एक बहुत ऊँची संस्कृति रही है, उसकी हमारी वर्तमान पद्धति से जो दशा रही है तो जब तक हम अपने पुराने लिटरेचर का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे वह ठीक नहीं हो सकेगा। अभी थोड़े दिन हुए संस्कृत की माँग हो रही है लेकिन हमारे राज्य के जो शासक हैं उन्होंने इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया है। मैं यह समझता हूँ कि शायद उनको ख्याल है कि शिक्षा की मिनिस्ट्री सेन्टर में कायम है, तो वह इस तरह समझें नहीं। मैं यह निवेदन करूँगा कि शिक्षा स्टेट का विषय है, इसलिए स्टेट के शासक लोगों को इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि वह किस पद्धति को अपनाये और किस प्रकार की शिक्षा-पद्धति स्कूलों में शुरू करे जिससे कि हमारा चरित्र-निर्माण हो। हमारे लिये यह जरूरी नहीं कि लोगों को लिटरेट बनायें बल्कि वास्तविक रूप से लोगों को शिक्षित करें। इसलिए तब तक वास्तविक शिक्षा लोगों को प्राप्त नहीं होगी जब तक कि हमारी संस्कृति को ऊँचा उठाने के लिए, हमारे पुराने लिटरेचर का ज्ञान हमें नहीं कराया जायगा और तब तक जो कि शिक्षा दी जा रही है उसमें तमाम रुपया बेकार जा रहा है।

आप देखेंगे कि चीन और रूस में जब क्रांतियाँ हुई हैं तो सबसे पहले शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया है। उन्होंने कॉलेजों और पुरानी शिक्षा संस्थाओं को बन्द कर दिया। कॉलेजों से उन्होंने समझा कि वे अभी तक पुरानी पद्धति पर चलने वाले कॉलेजेज़ से निकलने वाले जो लोग हैं वे सिर्फ नौकरी की तलाश में इधर-उधर मारे-मारे फिरेंगे। यही कारण है कि आज आपके यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है उन लोगों की जो नौकरी की तलाश में हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज भी बेकारों के सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण रखता है कि वही अनएम्प्लॉयड आदमी है जो कि सिर्फ नौकरी की तलाश में आता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि अनएम्प्लायमेंट के जाँचने का यह तरीका नहीं होना चाहिए। जाँचने का तरीका यह होना चाहिए कि शिक्षा पाने वाले व्यक्ति जो हैं वे अपनी शिक्षा का उपयोग किस तरह से राष्ट्र के निर्माण में करते हैं। इसकी जाँच का कोई तरीका राजस्थान सरकार के पास नहीं है। अभी श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर बहस हो रही थी जिसके जवाब में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी इस सम्बन्ध में यह बात कही थी कि हमारी शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करना है, उसकी पद्धति को बदलना है। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि शिक्षा-पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, उसे बढ़ाने की जो योजना हो रही है उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है; लेकिन यहाँ के जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं उनको कॉन्फीडेंस में क्यों नहीं लिया जा रहा है। क्या मैं यह जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ कि शिक्षा पद्धति को बदलने के लिए वह लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें जो व्यक्ति शिक्षा के प्रबन्ध से वाकिफ नहीं हैं उनको बुलाया जा रहा है!

[श्री वेदपाल त्यागी]

आज आप देखेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर को दूसरे महकमे भी दे दिये जाते हैं जिससे उनको एजुकेशन की तरफ ध्यान देने की कतई फुरसत नहीं मिलती है । सेक्रेटेरियेट में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कि शिक्षा का विशेषज्ञ कहा जा सके । मैं यह निवेदन करूँगा कि आपको उसमें ठीक ढंग से निर्णय करना चाहिए । उस शिक्षा पद्धति का निर्माण करने के अन्दर राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के शिक्षा के विशेषज्ञ जो हैं उन लोगों की राय लेकर उस पद्धति का निर्माण करें । उसके बाद शिक्षा में ज्यादा रुपया व्यय करने का गर्व करें । बस, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष मैंने कटमोशन जो भेजा है श्रीमन् उसको पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—Should I read it out ? (कटौती प्रस्ताव ढूंढ़ते हैं)

श्री गोपीलाल यादव—मैंने तो कट मोशन इस वजह से रखा है·······

श्री अध्यक्ष—I may read out your cut-motion.

"That the Demand for Grant No. XVI Major Head 37-Education be reduced by Rs. 1,000/ (to discuss an all round deterioration in Education, lack of planning and the inadequacy of funds in the Department-the General Policy".

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, एजुकेशन पर मैं अधिकार के सहित कह सकता हूँ; क्योंकि तमाम जीवन मेरा एजुकेशन से ही संबंध रहा है । मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि यह शिकायतें जैसी कि मेरे मित्र कल श्री जसवन्तसिंहजी कर रहे थे कि बच्चों में डिसीप्लिन नहीं है, पत्थर फैंके जाते हैं । मेरा यह विश्वास है कि जिस संस्था के टीचर्स और प्रोफेसर्स बच्चों को नहीं उकसायेंगे ऐसा काम करने को वहाँ कोई इनडिसीप्लिन नहीं होगा । अगर आप इसकी पूरी तरह से जाँच कराना चाहें तो करा सकते हैं । मैंने ऐसी हालत वाला स्कूल देखा है कि जहाँ १५ दिन तक लड़के स्कूल नहीं गये और लाठियाँ लेकर फिरते रहें और उन लोगों ने जब मेरे पास एप्रोच किया कि आप चलकर इस स्ट्राइक को तुड़वा दें तो मैंने कान्फीडेन्शल मीटिंग उन टीचर्स की करके उनसे कहा कि मेरा विश्वास है कि आप लोगों का इसमें हाथ है और कमेटी से मैंने पूरा अधिकार ले लिया है कि आप में से हरेक को निकाल दूँ, अगर मुझे शुबा हो गया तो । मैं आपको बताऊं कि दूसरे दिन ही स्ट्राइक खत्म हो जाती है । अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी इन्डिसीप्लिन की मिसालें मिलती हैं उसकी सारी जिम्मेवारी स्टाफ पर है ।

इसके बाद दूसरी चीज यह है जिसकी तरफ आप ध्यान दें । हमारे टीचर्स यह नहीं जानते हैं कि बच्चों को किस तरह से डील विथ करे । यह बड़ी इम्पोटन्ट चीज है । हमारे टीचर्स, हमारे अफसरान और हमारे मन्त्री इस चीज को नहीं जानते कि बच्चों की छोटी-छोटी शिकायतों को कैसे दूर करें । इन छोटी-छोटी शिकायतों पर सख्ती शुरू हो जाती है, जिद शुरू हो जाती है । आप अगर शिकायतों को दूर नहीं कर सकते हैं तो अपनी सिंसियरिटी (sincerity) और अपनी ईमानदारी को

[श्री गोपीलाल यादव]

इम्प्रेस कीजिए कि आप चाहते तो हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं तो वह हरगिज आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। अगर आप कर सकते हों तो उसको कर दीजिए।

तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि जो इसमें डिटीरियोरेशन (deterioration) एजुकेशन में हो रहा है वह सबसे पहले इनडिसीप्लिन (indiscipline) से होता है। उसके बाद में डिटीरियोरेशन उनकी शिक्षा के अन्दर है, उनकी सेहत के अन्दर है, उनके मोरल्स के अन्दर है और वह इस तरह से बढ़ रहा है। आज आप स्कूलों में चले जाइये तो आप क्या देखेंगे कि स्कूलों की एक-एक क्लास में १०० बच्चे होते हैं, ८० बच्चे होते हैं, ५० बच्चे होते हैं। माननीय अध्यक्ष, छोटे बच्चों को कहीं भी अगर आप शिक्षा दें तो एक टीचर के सामने ५० लड़कों को बिठा दीजिए। अगर उनको लिखना-लिखाना है तो हरगिज वह (अध्यापक) ५० लड़कों को कलम पकड़कर बता नहीं सकता। जब तक क्लास में बच्चों की तादाद थोड़ी नहीं होगी वह टीचर हर बच्चे को इन्डिवीजुएली अटेन्ड नहीं कर सकता, यह नहीं होने पर शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं उठेगा। आज मेट्रिक के लड़कों की वह योग्यता है जो २० वर्ष पहले छठी क्लास वाले की थी, आज ग्रेजुएट्स की वह योग्यता है जो कि २० साल पहले मैट्रिक वाले की होती थी। ग्रेजुएट्स युनिवर्सिटी से निकलते हैं उनकी एजुकेशन देखेंगे तो जो वह लिखते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स (spelling mistakes) होती हैं ग्रामर का सेन्स नहीं होता है और कुछ जानते नहीं हैं। इस तरह से हमने शिक्षार्थियों का मास प्रोडक्शन (mass production) करना शुरू कर दिया है। एक कॉलेज है जिसमें तीन हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। फेक्टरियों की तरह तीन-तीन शिफ्टें चल रही हैं। रात में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को आप ५०), ५०) रुपये मासिक वेतन देते है। एक अच्छा प्रोफेसर एक लड़के की ट्युशन के लिए ५० रु० में नहीं मिल सकता तो क्या आपको योग्य आदमी इतनी कम तनख्वाह में मिलेगा? यदि आपके टीचर्स योग्य नहीं हैं तो बच्चों की योग्यता और चरित्र कैसे ठीक हो सकेगा? आपका प्लानिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें यह ध्यान रहे कि टीचर और टॉट (Teachar and taught) में पर्सनल कांटेक्ट (निजी-सम्पर्क) ज्यादा से ज्यादा हो सके। आज कोई स्कूल ऐसी नहीं मिलेगी। मैं कहूँगा एज्युकेशन मिनिस्टर महोदय से कि वे जा कर कॉपियाँ देखें कि टीचर्स ने साल भर में क्या चार ऐसेज़ भी लिखवाकर करेक्ट किये है, हिन्दी में या अँग्रेजी में? नतीजा यह होता है कि लड़कों को कुछ आता नहीं है। इस तरह की शिक्षा से कोई फायदा नहीं है और हमारे एज्युकेशन की हालत दिन पर दिन गिर रही है। मैं निवेदन करूँगा कि एज्युकेशन की नीति सुधारिये, अच्छे टीचर्स रखिये, अच्छा वातावरण पैदा कीजिये। टीचर्स पर सारी जिम्मेदारी है। बच्चों का मोरल, बच्चों की शिक्षा सब टीचर्स पर निर्भर है। आपही के शहर में एक बड़ी इमारत खड़ी है सेन्ट जेवियर्स स्कूल की। वहाँ पर ज्यादा बच्चे की भरती होने का कारण यह है कि वे डायरी मेन्टेन करते हैं। उसमें सारी दिनचर्या बच्चे की लिखी रहती है। बच्चा अगर लेट गया है तो उसमें लिखकर आ जायगा कि आज आपका बच्चा लेट क्यों आया? बच्चे ने अगर काम नहीं किया तो उसमें लिखा जायगा कि आज बच्चे ने काम नहीं किया। बच्चों को जो काम करना है वह सब डायरी में लिखा हुआ होगा। गवर्नमेंट इन्स्टीट्युशन्स में कितनी ऐसी है जिनमें यह प्रणाली फोलो (follow) की जाती है। उसके पास डायरी है या नहीं? कल उसको क्या करना है यह सब डायरी में लिखा

[श्री गोपीलाल यादव]

हुआ होना चाहिये। इससे टीचर्स और होम में कॉंटेक्ट पैदा हो जाता है, जो एज्युकेशन में जरूरी है। यदि पेरेन्ट स साथ नहीं देते तो शिक्षा नाकामयाब होगी और अगर टीचर्स साथ नहीं देते तो भी वही बात होगी। इन दोनों का साथ नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा।

प्लानिंग का काम इस तरह का हो कि जो काम हो रहा है वह वाकई सफल हो रहा है या इतना रुपया व्यर्थ जा रहा है, यह मालूम होना चाहिये। मैं यह चाहता हूँ कि आप एक कमेटी, जो इस सदन के सदस्यों की हो या और सदस्यों की हो, बनाई जाय, जो यह निश्चय कर ले कि आपको ५ साल में या १० साल में एज्युकेशन को इस तरह से करना है या इतने अर्से में कंपलसरी एज्युकेशन सारे राजस्थान में करनी है। यह निश्चय हो जाने के बाद कुछ स्कूलें एक एरिया में पहले खोलें, इसके बाद दूसरे एरिया को लें और फिर तीसरे एरिया को लें। यदि इस तरह का कार्य करेंगे तो १० साल में सारे राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा कंपल्सरी हो सकेगी।

आपकी इनकम (आय) फीस से भी है। कहीं एक लाख होगी, तो कहीं कुछ कम या ज्यादा होगी। अभी आपने कश्मीर के बारे में सुना होगा कि बख्शी गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कॉलेज़ों तक की शिक्षा मुफ्त करदी है। आप २-४ लाख रुपये इस फीस से बचा पाते होंगे। अगर फ्री एज्युकेशन (निःशुल्क शिक्षा) करदें तो गरीब लोगों को, देहात के लोगों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। यदि इतना नहीं कर सकते तो कम से कम किसानों के ऊपर से तो आप बिल्कुल ही फीस हटा दीजिये क्योंकि उन पर दूसरे टेक्स का बोझा इतना ज्यादा है कि वे कपड़े नहीं पहनते। यदि आप उनके साथ जाते होंगे तो आपको शर्म आती होगी कि उनके कपड़े पहने हुए नहीं हैं, यदि वे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते भी है तो अपना स्टेन्डर्ड लो (निम्नस्तर) करके बच्चों की पढ़ाई के खर्च का इन्तजाम करते हैं। आप उन बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री कर दीजिये।

एज्युकेशन का फंड बहुत कम हैं। इस बात की खुशी है कि यह महकमा भोलनाथजी के हाथ में है। इन्होंने लड़ाई लड़ कर इसका बजट ३ करोड़ ३५ लाख का कर दिया है क्योंकि उनको एज्युकेशन से मोहब्बत है। ३ करोड़ ३५ लाख की रकम इतने बड़े इलाके के लिये कुछ भी नहीं है। अपने बजट को देखते हुए भी यह कुछ नहीं है। दिल्ली जैसी छोटी स्टेट में भी शिक्षा के लिए कुल आमदनी का ४४ परसेन्ट रखा गया है, जहाँ पर कि हजारों प्राइवेट इंस्टीट्युशन्स चलते हैं। फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी रकम शिक्षा के लिये रखी है। तो फिर क्या कारण है कि आप आमदनी का २५ प्रतिशत भी शिक्षा में खर्च नहीं करते। यदि इतना ही देते तो साढ़े पाँच करोड़ रुपये हो जाँय।

मुझे यह देखकर भी दुःख हुआ कि एज्युकेशन का जो बजट है उस राशि के मुताबिक वह रकम भी पूरी खर्च नहीं की जाती। किसी स्कूल में टीचर्स की जगह यदि खाली है तो कई महीनों तक वह खाली ही पड़ी रहेगी, कोई टीचर वहाँ नहीं भेजा जायगा। बच्चे स्कूल में यों ही बैठे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। इससे क्या फायदा? आपका प्लानिंग यह होना चाहिये कि जितने

[श्री गोपीलाल यादव]

आदमियों को ट्रान्सफर करना है उसका पता मई मास में हो जाना चाहिये ताकि जिनकी ट्रान्सफर की जाय; वे नये सेशन से जुलाई में अपने-अपने स्थानों पर पहुँच जाँय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि किसी की ट्रान्सफर दिसम्बर में कर रहे हैं तो किसी की नवम्बर में, ऐसा नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आपको टीचर्स अच्छे क्यों नहीं मिलते? इसका कारण यह है कि टीचर्स को आप जो तनख्वाह देते हैं वह बहुत थोड़ी देते हैं। उनका सम्मान उतना नहीं होता जितना दूसरे सरकारी कर्मचारियों; जैसे तहसीलदार, सब इन्सपेक्टर आदि का होता है। उतना सम्मान एक स्कूल के हेड मास्टर का भी नहीं होता। यही कारण है कि योग्य आदमी एज्युकेशन में नहीं आना चाहते और आपको अयोग्य आदमियों की भरती करनी पड़ती है। आपको टीचर्स को वेतन ठीक देना चाहिये और सोसाइटी में उनका सम्मान भी अफसरों के बराबर होना चाहिये। गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्टी है जो उसमें सेक्रेटेरियट के अफसरों को या अन्य विभागों के अफसरों को तो बुलाया जायगा लेकिन स्कूलों के हेड मास्टरों को नहीं बुलाया जायगा। इससे वे यह समझते हैं कि हमारा कोई स्थान ही नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि टीचर्स को वेतन अच्छा दीजिये, उनका सम्मान कीजिये और अच्छा स्टाफ रखिये। यदि आप इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो एज्युकेशन अच्छे ढङ्ग पर आ सकता है और वह राजस्थान के बच्चों का चरित्र-निर्माण कर सकता है। डेमोक्रेसी की कामयाबी बच्चों पर ही निर्भर है। यदि उनका चरित्र अच्छा नहीं हुआ तो उससे आपको हमेशा खतरा रहेगा। इसलिये आपका सबसे ज्यादा ध्यान स्कूल के बच्चों की ओर जाना चाहिये। सी. आई. डी. पोलिटिकल नेताओं के पीछे लगी हुई है या नहीं, इसको देखने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत आपको यह देखने की है कि स्कूलों की क्या हालत है। यदि ऐसा करेंगे तो एज्युकेशन सफल होगा। मैं समझता हूँ भोलानाथजी (शिक्षा मन्त्री) इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे क्योंकि वे इस काम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, यह मैं जानता हूँ।

श्री लाल बहादुर—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने एज्युकेशन के मुताल्लिक कट मोशन पेश किये थे, पर वे नहीं आए। इस बजट में देखने से मुझे ऐसा महसूस हुआ और मैंने शिक्षा मन्त्रीजी से भी बातचीत की कि कोटा जिले के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए वैसा नहीं किया गया है। कोटा में डेढ़ हजार स्टूडेन्ट्स हैं, दो-तीन पाली (shifts) चलती हैं पर उनमें एम. एस. सी. की क्लासेज़ नहीं हैं। साँगोद, माँगरोल और अन्ता इन तीनों जगह हाई स्कूल खुलने की आवश्यकता है। इसके मुतअाल्लिक लिखा-पढ़ी की गई, कई दफा शिक्षा मन्त्रीजी से डेपुटेशन मिला और यह भी कहा कि वे बिल्डिंग देने को तैयार हैं और यदि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मंशा के माफिक उस बिल्डिंग में तरमीम करा सकती है, खर्चा देने को तैयार हैं, परन्तु वहाँ अभी तक एक भी हाई स्कूल उन तीनों जगहों में से एक भी जगह नहीं खुली है। बारां में हाई स्कूल है, वहाँ इन्टर कॉलेज होना चाहिए। जहाँ १०-१०, १५-१५ लड़के मैट्रिक पास करते हैं, वहाँ इन्टर कॉलेजेज़ हैं, परन्तु बाराँ में १५०-१७५ लड़के मैट्रिक पास होते हैं फिर भी वहाँ पर इन्टर कॉलेज नहीं खोला गया है।

मोशन ऑफ थैंक्स के समय में कहा गया था कि कॉलेजों में शिक्षा देने से देश में बेकार

[श्री लाल बहादुर]

बढ़ती है। अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी ऐसे ही ख्याल जाहिर किए थे। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके ज़रिये सदन से यह निवेदन करूंगा कि विद्या पशु को भी मनुष्य बनाने वाली चीज है। जो आदमी जितनी ज्यादा हाई एज्युकेशन प्राप्त करेंगे उतना ही उनका दिमाग तेज होगा और देश के उत्पादन को बढ़ाने के विषय में मालूम करने के लिए उस ओर अपना दिमाग लगावेंगे, न कि ४०) रुपए की क्लर्की के पीछे-पीछे फिरेंगे। पढ़-लिख कर केवल नौकरी के पीछे फिरेंगे, ऐसा कहना गलत है। अभी-अभी हमारे यहाँ कोटा के एम. ए. पास करके लड़के निकले हैं। उन्होंने एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दिया है और फार्म चला रहे हैं। और भी कई ऐसी मिसालें हैं। केवल यह कह कर कि कॉलेजों से बेकारी फैलेगी, शिक्षा को रोकना महज गलती होगी। मेरा तो यही निवेदन है कि एज्यूकेशन पर और भी ज्यादा रुपया खर्च किया जावे।

बाराँ में जो कन्या पाठशाला है उसकी लड़कियाँ बाहर बैठकर पढ़ती हैं, प्राइमरी स्कूल के लड़के बाहर धूप में बैठते हैं और इसी तरह मिडिल स्कूल में भी लड़कों के बैठने के लिए इन्तजाम नहीं है। आप खुद ख्याल फरमा सकते हैं कि उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं इस सदन को उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए सरकार को महकमे के थ्रू (through) बराबर बार-बार रिपोर्ट दी जाती रही हैं पर अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि साँगोद, जो कि मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी है वहाँ की पब्लिक हाई स्कूल के लिए बिल्डिंग भेंट करने को तैयार है, इसके चारों तरफ मिडिल स्कूल्स मौजूद हैं। वहाँ अच्छी तरह हाई स्कूल चल सकता है। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वहाँ पर हाई स्कूल अवश्य खोला जावे।

श्री धूलजी भाई—शिक्षा के बारे में मैं अपने विचार सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूँ। आज कल की जो शिक्षा प्रणाली चालू है उसके बारे में हमने अनुभव किया है कि शिक्षा पाकर जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनसे बेकारी में अपना नाम लिखवाने में बढ़ोतरी हो रही है। उनको इस तरह की औद्योगिक शिक्षा नहीं दी जाती कि वे स्वावलम्बी बन सकें। आज शिक्षा देहाती जनता के लिए महान् आवश्यक है परन्तु उनकी शिक्षा का प्रबन्ध राज्य की ओर से समुचित ढंग से नहीं हो रहा है।

जहाँ-जहाँ प्राथमिक पाठशालायें हैं और काम किया है उसके लिए धन्यवाद है, परन्तु जहाँ-जहाँ प्राथमिक पाठशालायें, मिडिल स्कूल आदि हैं वहाँ ऐसे मास्टर भेजने चाहिये जो कि लड़कों को योग्य बना सकें और हाथ की दूसरी कारीगरी का काम सिखा सकें। इस प्रकार की कई त्रुटियाँ जो हैं उन्हें दूर करना चाहिये।

हमारे जिले में इन पिछले दो-तीन सालों में कोई विशेष प्रगति शिक्षा में नहीं हुई है। घाटोल समुचित तहसील में मिडिल स्कूल एक ही है तथा देरानों के छात्रों के पढ़ने की समुचित व्यवस्था नहीं

[श्री धूलजी भाई]

होने के कारण वहाँ पर आदिवासी मिशनरियों के अड्डों में जाकर अपने धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जिले में विशेष कर छात्रावासों का अभाव होने के कारण शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इस प्रकार के देहाती गाँवों में अवश्य छात्रावास होने चाहिए और विद्यार्थियों के रहने-पढ़ने आदि का समुचित प्रबन्ध होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षा विभाग की मौजूदा प्रणाली है उसमें समूल परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि जनता में शिक्षा की ओर रुचि बढ़े और पढ़ाई खत्म करने पर विद्यार्थी स्वावलम्बी बन सकें।

जो अध्यापक आजकल पढ़ाने आते हैं वे ऐसे आते हैं कि लड़कों को बिल्कुल विदेशीपन की तथा विलास प्रियता की शिक्षा देते हैं। शहरों के रहने वाले विलासीपन की ओर जा रहे हैं, उनमें श्रम का नाम नहीं और श्रम के लिए उत्साह नहीं। उनको सुधारा जाय और इस दिशा की ओर जाने से रोका जाय। अध्यापक ऐसे भेजे जाँय जिनमें श्रम के प्रति उत्साह हो और शिक्षा के साथ ही साथ विद्यार्थियों को उद्योग-धन्धे सिखाये जाँय जिससे कि देहातों की बेकारी समाप्त हो।

इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के अध्यापकों का चुनाव किया जावे जो देहात के लोगों के साथ हिल-मिल कर औद्योगिक शिक्षा का प्रसार करें, ग्रामोद्योगों को बढ़ावें, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे जैसे लुहारी, सुथारी, रंगाई, छपाई आदि में (ग्रामोद्योग से) उन बच्चों को निपुण बनावें। ऐसा करने से सरकार के ऊपर जो बोझा बढ़ रहा है कि शिक्षा पाने के बाद उनको सर्विसेज़ में लेने का प्रश्न है, बेकारी का प्रश्न है यह सरकार के सामने नहीं होगा और इन विद्यार्थियों का जीवन भी इस प्रकार स्वावलम्बी बनेगा। मैं माननीय मन्त्रीजी से प्रार्थना करूँगा कि देहातों की जनता के लिए इस प्रकार की शिक्षा और उद्योग-धन्धे सिखाने का प्रबन्ध होना चाहिए। इस तरह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए।

श्री कंवरलाल जेलिया—अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी कहा है। मैं भी इस विषय पर चन्द बातें दो शब्दों में कह कर माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। आज शिक्षा विभाग प्रैक्टिकल शिक्षा के लिए जोर दे रहा है और यह आदेश इसके लिए दिए गए हैं। मगर मैं सरकार की जानकारी के लिए यह बतला देना चाहता हूँ कि अलग-अलग डिवीज़नों में अलग-अलग टैक्निकल शिक्षा लोगों को प्राप्त हो रही है, फिर भी कई जगह इसकी कमी है। मिसाल के तौर पर कोटा; कोटा में एम. एस सी. की शिक्षा के लिए माननीय शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। महाराजा साहब कोटा ने एक लाख रुपया इस कार्य के लिए दिया है, कोटा में कॉलेज खोलने के लिए। वहाँ पर जगह की कमी है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से यही कहूँगा कि वे कोटा में एम. एस सी. की क्लासेज़ खोलने का ध्यान देंगे।

इसके अलावा मैं शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान, अभी श्री लाल बहादुरजी ने जो बातें कहीं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूँ। बाराँ एक ऐसा स्थान है जो हाड़ोता के बीच में आता है। वहाँ पर इन्टर कॉलेज खोला जाय। हाई स्कूल के लिए सामोद में वहाँ की जनता बिल्डिंग देने को तैयार है और माँगरोल भी एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कस्बा है। इसलिए उनकी माँग गैर वाजिब नहीं

[श्री कंवरलाल जेलिया]

हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि सरकार को उन्हें मन्जूर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान अध्यापकों की ओर दिलाऊँगा। एक अध्यापक को एकीकरण के बाद तनख्वाह दी गई थी। उनको जो तनख्वाह दी गई वह तनख्वाह अब यह कह कर कि पैसे अनुचित दे दिए उनसे वापिस लेने का नोटिस दिया गया है। इतना कम वेतन पाने वाले अध्यापक अब वह पैसा वापिस किस तरह से लोटावेंगे। इस पर शिक्षा मन्त्रीजी खास तौर से ध्यान दें।

एक बात खास तौर से मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उपाधियें हैं, जैसे विशारद, साहित्य रत्न इत्यादि की ओर भी ध्यान दें। मैं माननीय डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का ध्यान खास तौर से आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने मैट्रिक और बी. ए. आदि अध्यापकों के लिए ग्रेड रखे हैं उसी तरह विशारद, साहित्य रत्न पास किए हुए अध्यापकों के लिए भी ग्रेड रखिए और यह रखना शिक्षा विभाग द्वारा बहुत जरूरी है। यदि हम हिन्दी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि इस योग्यता के जितने भी मास्टर हैं उनको प्रोत्साहन दें। यदि आप इस योग्यता वाले मास्टरों को मिडिल और दूसरी क्लासेज में रखेंगे तो मैं यह सकता हूँ कि वे सही तरीके से साथ दे सकेंगे। यह बात गैर वाजिब नहीं है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—श्री कपिलदेव अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, शिक्षा के सम्बन्ध में काफी मित्रों ने कल से अपने विचार-विनिमय किए हैं और वास्तव में शिक्षा क मद इतना प्रमुख है जिस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि हमारे शिक्षा मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और समय-समय पर एम. एल. ए. से इस पर वाद-विवाद और विचार-विनिमय भी करते रहते हैं और जो सुझाव उनके पास आते हैं या वे लेते हैं, उनको वे महज लेकर ही नहीं रख देते बल्कि उन सुझावों को कार्यान्वित करने में भी पूरी दिलचस्पी लेते हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा मिनिस्टर साहब को अर्ज करूँगा कि वर्तमान समय में मास्टरों और लड़कों में चरित्रहीनता की जो लहर चल रही है यह एक ऐसी लहर और इल्जाम है जिसके लिए देश के बड़े-बड़े नेता व दूसरे सन्त लोग भी परेशान हैं और वे भी यह सोच रहे हैं कि इसको रोकने के लिए क्या किया जावे। आज सब जगहों से बच्चों के चरित्र-निर्माण की माँग है। मैं आपके सामने अपने कॉलेज के निजी अनुभव की बात बताता हूँ, ये आँखों देखी बातें हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि आजकल जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह चरित्र बिगाड़ने वाली प्रणाली है। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि होस्टलों की क्या हालत है ? होस्टलों में रात को क्या-क्या नहीं होता है ? आप ताज्जुब करेंगे, लड़के होस्टलों में

[श्री श्रीदास गोयल]

कमरे का दरवाजा बन्द कर लेते हैं और बन्द कमरे में रात को जूआ खेला करते हैं। मौका मिलने पर बोतलों के कोर्क भी खुलते हैं और कहीं-कहीं ऐसे कार्य भी होते हैं जिनका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता। यदि जिक्र किया जावे तो आपको दाँतों तले अंगुली दबानी पड़ेगी। इसलिए मैं गम्भीरतापूर्वक यह अर्ज करूँगा कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया गया और यही शिक्षा प्रणाली कायम रही तो आगे चलकर हमारा यह देश जो सर्वतोमुखी उन्नति करने की ओर जा रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य बनने जा रहा है उसके लिए यह प्रथा कितनी लाभ पहुँचाने वाली होगी, यह आप खुद सोच सकते हैं।

मैं यह निवेदन करूँगा कि राम के चरित्र को बनाने वाले वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। लव और कुश का नाम संसार में न होता अगर बाल्मिकि न होते, हमें फिर से उसी प्रकार के गुरु, जो राम के जमाने में वशिष्ट और विश्वामित्र थे, लाने होंगे और शिक्षा विभाग में यदि हम उसी प्रकार के गुरु लावेंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी। आज हम मास्टरों की दयनीय दशा देखते हैं क्योंकि वे लोग मामूली वेतन पर नियुक्त किए जाते हैं। मगर सरकार को यह समझ कर चलना चाहिये कि ग्रामीण जनता और समाज के अन्दर जो ८५ प्रतिशत बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके चरित्र निर्माण की जिम्मेवारी उन्हीं मास्टरों पर है; इसलिए ऐसे मास्टर रखें जो उनके चरित्रों को और नागरिक जीवन को उन्नत बना सकें।

दूसरी बात यह है कि हमारे इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स जो ग्रामों में दौरा करने के लिए रखे जाते हैं वे इतने इनएफिशिएन्ट (अयोग्य) हैं कि उनके हल्के में १०-१५ प्राइमरी स्कूलें, जिनको उन्हें प्रतिवर्ष देखनी पड़ती हैं, उनको भी अच्छी तरह से नहीं देख पाते। ग्रामों में १०-१५ दिन तक स्कूलों को मास्टर बन्द करके घर पर पड़े रहते हैं और कोई देखने वाला ही नहीं है कि मास्टर स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं या घर पर ही आराम करते हैं। नए-नए मास्टर नियुक्त किए जाते हैं जिनकी आयु १६-२० वर्ष की होती है। उनके न तो कोई चरित्र होते हैं और न वे अपनी जिम्मेदारियों को ही महसूस करते हैं क्योंकि वे स्कूल से निकले हुए होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार उन पर किस प्रकार विश्वास कर लेती है। विश्वास सब पर करना पड़ता है, विश्वास से ही सारे काम होते हैं किन्तु साथ ही साथ यह भी देखना है कि बच्चों का विकास उन्हीं से शुरू होता है। यदि उनके मास्टर अच्छे चरित्र के हुए तो वे अच्छे लड़के बनकर स्कूलों में आगे जावेंगे और खराब मास्टर हुए तो उनके चरित्र खराब हो जावेंगे। इसलिए मैं यह कहूँगा कि चरित्र निर्माण की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय और मैं तो यह कहूँगा कि हमारे मंत्रीजी यदि इस ओर रात-दिन एक कर देंगे और काम करेंगे तो यह काम अच्छी तरह से होगा और तभी कुछ सुधार हो सकेगा और शिक्षा में भी तरक्की होगी, अध्यापकों की भी उन्नति होगी और देश का भी कल्याण होगा। इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि जयपुर में २०-२५ साल से जो मास्टर काम करते हैं और जिनका चरित्र बड़ा उज्ज्वल रहा है और जो अपने जिम्मेदारी को भी महसूस करते रहे हैं, आज उनको ५५) रुपए तनख्वाह मिलती है जबकि उनके पढ़ाए हुए लड़कों को जो नौकरियें करते हैं ७०), ८०), १००) रुपए मिलने लग गए हैं। माधोपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आज उनकी रोटी का

[श्री श्रीदास गोयल]

प्रश्न हल नहीं हो रहा है। सन् १९५२ में शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन निकला था कि उन अध्यापकों को, जिन्हें २५ साल नौकरी करते हो गए हैं, १० प्रतिशत के हिसाब से तरक्की दी जावेगी; मगर अभी तक उस नोटिफिकेशन को कार्यान्वित नहीं किया गया है। बहुत मुमकिन है लोअर स्टाफ ने उसे डिपार्टमेंट में जिस प्रकार मामूली कागजात निकलते हैं उसी तरह से समझ कर भेज दिया हो और वहाँ के लोगों ने उसको इम्पलीमेंट (implement) करने के लिए जो जिम्मेदारियाँ उन पर हैं उनको न समझा हो और उसी कारण वह कहीं पड़ा रहा होगा। मैं निवेदन करूँगा कि शिक्षा विभाग को, शिक्षा मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में जल्दी कार्यवाही करने के लिए कोई नोटिस जारी करा देंगे। इसका असर क्या होगा यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्मचारी यह सोचेंगे कि अधिकारी और ऑफिसर हमें कुछ चाहते हैं और जो काम करने के लिए राजस्थान सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है वे उसे ज्यादा जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। आज अगर आप छोटी-छोटी स्कूलों में जाकर देखें और अगर कोई महानुभाव तशरीफ ले जावें तो उनको मालूम होगा कि छोटे-छोटे बच्चे किस प्रकार कुटेवों के शिकार बन गए हैं। गाँवों में क्या है, बाहर क्या है, कालेजों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अगर उनके (कॉलेजों के) सदृश्य गाँवों में भी हो जाय तो फिर देश की क्या हालत होगी! हमारे मुख्य मंत्रीजी ने श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के बाद जवाब देते हुए कहा कि हमारी शिक्षा-पद्धति किस प्रकार की हो, किस प्रकार चरित्र का निर्माण किया जाय, इस पर विचार किया जा रहा है और यह बात देश के बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों के हाथ में है। अंग्रेजों ने हमारे देश को दो सौ वर्ष तक गुलाम रखा। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति कायम की और एक जहर घोला। हमने उस जहर का पान किया। मैं निवेदन करता हूँ कि श्रीभोलानाथजी भी जहर पीने के लिए ऐतहासिक प्रमुखता रखते हैं। वे उस जहर को पीवेंगे और अपने गले में उसको रखकर नीलकण्ठ शब्द को सुशोभित करते हुए हमें आभूषित करेंगे।

मैं आपको निवेदन करूँगा कि विद्यार्थियों में ही नहीं बालिकाओं में किस प्रकार की फैशन चल रही है, यह एक सोचने की बात है। नाखूनों को बनाना, होठों को किस प्रकार रंगना और एक अजीब वेश-भूषा रखना, आज के माता-पिताओं के लिए समस्या बन गई है। जो विद्यार्थी कॉलेजों में पढ़ने वाले हैं उनके विषय में तो यू० पी० में जो कुछ विद्यार्थियों ने किया वह आपके सामने है। माता-पिताओं की तरफ से माहवारी किश्तें भेज दी जाती हैं, वे सोचते हैं कि लड़के हमारी सेवा करेंगे। वे नागरिक होकर माता-पिताओं और देश की क्या सेवा करेंगे, यह आपको विदित है। अतः मैं आपको निवेदन करूँ कि इस प्रकार कन्याओं का भी सवाल है और उस पर खास तौर पर विचार करना है। वे मातायें थीं, जिन्होंने शिवाजी जैसे रत्नों को पैदा किया। मैं अर्ज करूँ वह बातें जिनको रवीन्द्रनाथ टैगौर ने इस्टर्न और वेस्टर्न पद्धति के लिए व्यक्त किये हैं, जो कि विचारणीय हैं। यह पद्धति भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं है। यह वेस्टर्न नेश्नेलिज्म पर आधारित है और हमारे देश का इससे किसी प्रकार चरित्र-निर्माण होना सम्भव नहीं है। मेरे मित्रों ने सेन्ट जेवियर की तारीफ की है। जिस प्रकार का वहाँ का इन्तजाम है शिक्षा देने के लिए वह सराहनीय है और हमारे जो दूसरे स्कूल्स हैं, संस्कृत आदि की पाठशालाएँ हैं जहाँ सेकेन्डरी एजुकेशन है वह उनको शिक्षा लेनी चाहिये। हमारे एक मित्र ने ठीक कहा है कि ये लोग क्रिश्चियनिटी की ट्रेनिंग देते हैं और देश में

[श्री श्रीदास गोयल]

साइलेन्ट अन्डरग्राउन्ड एटमोसफियर (silent underground atmosphere) बना रहे हैं। अतः हमको इससे सचेत रहना है। आज हमको हमारे विद्यार्थियों और कन्याओं के चरित्र-निर्माण की जरूरत है। अध्यापक और प्रोफेसर दृढ़ चरित्र हों और उनको विद्यार्थियों के साथ सम्पर्क हो। क्या इस प्रकार की कॉलेज़ में हफ्ते में, पन्द्रह दिनों में और महीनें में कभी डिबेट्स इस विषय पर होती है? इस प्रकार की डिबेट्स जरूर होनी चाहिए जिनमें हम अध्यात्मिक, चरित्र-निर्माण और चरित्रवान व्यक्तियों की बातें करें। यदि हम इस प्रकार की बातें शुरू करेंगे तो साढ़े तीन करोड़ का जो बजट शिक्षा के लिए दिया जा रहा है वह बुद्धि के निर्माण में उपयुक्त होगा। बुद्धि के लिए साफ कहा है कि सारे शरीर को चलाने वाला यह बहुत बड़ा सारथी है। यदि उसका निर्माण हो जाता है तो सब का निर्माण हो जाता है। समाज में जो उच्छृङ्खलता है वह इससे खत्म हो जाती है। यू० पी० में जिस प्रकार से कॉलेज वगैरह बन्द हो गये यदि बुद्धि का निर्माण हुआ होता तो यह उच्छृङ्खलता पैदा नहीं होती। मुझे आशा ही नहीं परन्तु विश्वास है कि हमारे शिक्षा मन्त्रीजी चरित्र-निर्माण की शिक्षा देने में सफल होंगे और अगले वर्ष शिक्षा सम्बन्धी बजट पर बहस करते समय सारा सदन एक आवाज से मुक्तकंठ से आपकी सराहना करेगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, हमारे सामने आज के कट मोशन्स की जो लिस्ट है उसमें लिखा है कि "To be moved on 24 th" उसमें मेरा कट मोशन है। यह बात सही है कि कल मुझे अवसर दिया गया था बोलने का, मैं कल दूसरे सब्जेक्ट के कट मोशन पर बोल पाया था। परन्तु जो कट मोशन मैंने अपने सब्जेक्ट का पेश किया था वह आज आया है और आज की फहरिस्त में लिखा हुआ है, "To be moved on 24 th"। मैं, माननीय अध्यक्ष, प्रार्थना करूँगा कि कम से कम दो-चार मिनिट तो मुझे अपने सब्जेक्ट पर बोलने का अवसर अवश्य प्रदान किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो कल हो चुका है।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ मिनिट के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा अर्ज करना है कि मेड़ता में जो हाईस्कूल है उसके ७ कमरे हैं और वहीं हाई स्कूल चलाई जा रही है। लड़के बाहर बैठते हैं। कई प्रार्थना-पत्र भेजे जा चुके हैं और मैंने क्वेश्चन किया था जिसका जवाब दिया गया था कि कोई जरूरत नहीं है। जो लड़के पढ़ते हैं वे बाहर बैठते हैं और यदि उनके पढ़ने के लिए मकान बनाने की जरूरत नहीं है तो फिर क्या है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मेड़ता में हाई स्कूल के कमरे और बनाने चाहिए।

कई गाँव ऐसे हैं जहाँ स्कूल्स कायम हैं किन्तु स्कूलों के लिए मकान नहीं हैं और गाँव वाले रकम भी देने को तैयार हैं। एक लिस्ट भी बना कर मन्त्री महोदय को दी गई थी, उसका उत्तर दिया गया था कि यह डेवेलप्मेन्ट स्कीम में रख दी जावे। डेवेलप्मेन्ट से तो कुछ बनाया जावेगा किन्तु कुछ शिक्षा विभाग से भी मदद दी जावे।

[श्री भोपालसिंह]

एक बात और अर्ज करनी है और वह यह है कि पाठशालायें खोल दी जाती हैं, किन्तु मास्टर भेजे जाते हैं वे बिल्कुल नाकाबिल होते हैं। इसलिए गाँव वालों की अर्ज यह रहती है कि पहले जो प्राइवेट मास्टर लड़कों को पढ़ाया करते थे वे ही पढ़ाया करें; उनकी ज्यादा माँग है। अगर उनको उन गाँवों में रखा जावेगा तो अच्छा रहेगा। सरकार को भी मास्टरों को रखने की सुविधा रहेगी। वे ही मास्टर रखे जावें जिन पर कि गाँव वालों को पूरा भरोसा है। वे डिग्री पास तो होते नहीं हैं फिर भी वे लोग पढ़ाते अच्छा हैं और गाँव वालों को उन पर भरोसा है। इसलिए उनको खास तौर पर लिया जाना वाजिब हैं। यही कह कर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री सन्तोषसिंह।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा-माननीय उपाध्यक्ष, मैंने भी अपना एक कट मोशन पेश किया था वह किसी वजह से आज पेश नहीं हुआ है। सदन के अन्दर शिक्षा विभाग के लिए काफी कुछ कहा गया है और कल शाम को हमारे विरोधी दल के नेता ने विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के ऊपर काफी कुछ बताया है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आज भी विद्यार्थियों के डिसिप्लिन यानि चरित्र पर काफी कुछ कहा गया है। लेकिन उनके चरित्र का किस तरह से निर्माण किया जाय इस पर किसी ने खास तौर से बताया नहीं है। इसके लिए मैं माननीय उपाध्यक्ष, यह कहूँगा कि स्कूलों के अन्दर जब तक कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी तब तक विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। मैं यह मानता हूँ कि हमारी सरकार धर्म के मामले में बहुत परे रहती है। ऐसा मालूम होता है कि धर्म से यह डरती भी है। इसलिए मेरा कहना फिजूल सा ही है कि वह धर्म पर कहीं विश्वास करेगी। लेकिन फिर भी यह कहूँगा कि जब तक स्कूलों के अन्दर विद्यार्थियों के चरित्र को अगर बनाना है तो वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाय और उससे ही विद्यार्थियों के चरित्र का अच्छा निर्माण हो सकता है। विद्यार्थियों का शिष्टाचार भी उससे अच्छा हो सकता है, अन्यथा यह काम हमेशा होता रहेगा और जो विद्यार्थी बड़े होकर हमारे सदन में मेम्बरों की हैसियत से, मिनिस्टरों की हैसियत से आवेंगे और उनमें चरित्र नहीं होगा तो यह जो रोज-मर्रा का झगड़ा है वह बढ़ता जावेगा। सरकार ने करोड़ों रुपयों का बजट लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन (To maintain Law and order) करने के लिए सेन्कशन किया है लेकिन मैं दावा करता हूँ कि कुछ वर्षों के बाद सारी की सारी आमद ही लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए खर्च कर दी जावेगी, तब भी वह काम नहीं होगा क्योंकि जो काम चोरियों और डकैतियों को बन्द करने के लिए सरकार कर रही है अगर एक डकैत मर भी जावेगा तो भी क्या? हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हजारों डकैत रोज पैदा हो रहे हैं। अगर सरकार इनको बन्द करना चाहती है तो हमारे हर एक स्कूल के अन्दर धार्मिक शिक्षा का घंटा जरूर खुले और धार्मिक शिक्षा दी जावे।

विद्यार्थियों का चरित्र-निर्माण अच्छी तरह से हो, शिष्टाचार बढ़े और अनुशासन हो। उसके लिए आवश्यक है कि हमारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये ताकि जो हम शिष्टाचार का अभाव, अनुशासन का अभाव आज के छात्रों में देख रहे हैं वह नहीं रहेगा।

[श्री सन्तोषसिंह]

दूसरा, मेरे एक माननीय सदस्य ने बताया कि सारी की सारी शिक्षा की फीस माफ कर दी जावे। मैं आज राजस्थान की आर्थिक हालत को देखते हुए यह तो नहीं कहना चाहता किन्तु इतनी प्रार्थना अवश्य करना चाहता हूँ कि यदि आठवीं कक्षा तक ही माफ कर दी जाय तो भी गरीब बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी क्योंकि आजकल शिक्षा बहुत मँहगी पड़ रही है क्योंकि पुस्तकें जो ५ या ६ पेज की होती हैं उनकी कीमत भी एक रुपया, दो रुपया तक देनी पड़ती है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे किताबों की कीमतों पर भी विचार करे। इसके लिए पुस्तकों को बनाने वालों से कह दिया जाय कि जितना रुपया उनका इसमें लगा है उससे आधे कीमत में वह पुस्तकें दें ताकि बच्चों को पुस्तकें सस्ती मिल सकें और हरेक विद्यार्थी उसको खरीद सके।

दूसरी बात यह है कि आज कल लड़के और लड़कियों की जो हम सह-शिक्षा देखते हैं तो उससे बड़ा दुख होता है। आजकल बड़े-बड़े कॉलेजों में जो सह-शिक्षा दी जाती है उससे लड़के लड़कियों के चरित्र बिगड़ने का बहुत अन्देशा रहता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऊँची कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियां के लिए अलग से कॉलेज खोले जायं। बड़े-बड़े शहरों में; जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि में और लड़कियों के लिए, फीस बिल्कुल माफ होनी चाहिये ताकि लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। वैसे ही हमारे यहाँ लड़कियों में शिक्षा बहुत कम है। यदि उनकी फीस बिल्कुल माफ कर दी जायगी तो उनको आगे पढ़ने का बराबर प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल केडेट कोर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में दी जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकारी स्कूलों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय।

इसके बाद मैं अपने मतलब की बात पर आता हूँ। भोपालगढ़ में हाई स्कूल बनाने के लिए हमने माँग की थी। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्रीजी इस बात पर भी अवश्य ध्यान देंगे।

बिलाड़ा में हाई स्कूल बना दिया गया है, लेकिन वहाँ ड्राइङ्ग कक्षा और साइन्स की कक्षा खोलने की प्रार्थना करूँगा। वे यथाशक्ति इसको बढ़ाने की कोशिश करें।

एक बात यह भी कही जाती है कि जहाँ कहीं भी जनता स्कूल खुलवाना चाहे वहाँ बिल्डिंग बनाकर दे। अगर कहीं प्राइमरी स्कूल के लिए कोई झोंपड़ा या मकान बनाकर नहीं दे सके तो सरकार को यह कम्पलसरी नहीं रखना चाहिये कि मकान बनाकर दे तो वहीं प्राइमरी स्कूल खोली जाय। जब सरकार शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है तो उसको बिल्डिंग आदि बनाने के लिए जनता को नहीं कहना चाहिये। सरकार के इस रवैये को बदलना चाहिये। जब की आप बड़ी-बड़ी कॉलेजों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो इन छोटी-छोटी प्राइमरी स्कूलों के लिये भी सरकार को ही मकान बनवाने चाहिये। इस रवैये से आगे (पहले से) ही जनता शिक्षा के अभाव में पिछड़ी हुई है। फिर यदि

[श्री सन्तोषसिंह]

यह कह कर दिया जायगा कि मकान बना दिया जायगा तभी स्कूल खोले जायेंगे तो हमेशा जनता पिछड़ी हुई रहेगी।

मैं आशा करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय, मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर गौर करेंगे। (घंटी)

चूँकि अब घंटी बज गई है इसलिये मैं इतना ही कहकर अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(बोलने को खड़े होते हैं)

श्री उपाध्यक्ष—इस माँग पर काफी डिस्कशन हो चुका है, मिनिस्टर महोदय अब इसका जवाब दें।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से शिक्षा विभाग पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ चर्चा तो शायद इसलिये हुई कि बहुत सी बातों के बारे में सदस्य महोदय जानकारी प्राप्त करने की कृपा नहीं करते। शिक्षा विभाग अपनी एक निश्चित नीति के अनुसार इस समय काम कर रहा है जिसको जानने की कोशिश करनी चाहिये। जहाँ तक आज को शिक्षा पद्धति व प्रणाली का सम्बन्ध है इसमें कोई शक नहीं कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है; परन्तु जिस तरह से हमारे देश में शिक्षा को अनिवार्य समझा गया इसके मुताबिक यह आवश्यक नहीं कि सब लोगों को, जिस प्रकार का नक्शा है उसे सामने रखते हुए वह पूरा हो जाय। यह असल में शिक्षा का विषय सारे मुल्क के सामने है। हमारी भारत सरकार ने इसके लिए सेन्ट्रल एडवाइज़री एज्युकेशन बोर्ड बना रखा है जिसकी मीटिंग्ज़ बारबार हुआ करती हैं। उसमें देश के ऊँचे-ऊँचे विद्वान ही केवल नहीं होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले; जैसे हाई कोर्ट में बैठने वाले न्यायाधीश, वाइस चान्सलर, एज्युकेशन के डाइरेक्टर, सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स आदि हैं, वे सब शिक्षा के इस विषय को देखते हैं और अलग-अलग विषयों पर ध्यान दिया जाता है। इससे जाहिर होता है कि भारत सरकार का शिक्षा विभाग इस विषय में अपनी नीति को काफी बदल रहा है और वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपने देश की काया-पलट हो जाय।

कुछ मित्र महाराज राम-कृष्ण की बातें करते है लेकिन में उनसे कह सकता हूँ, ऐसा जमाना कभी नहीं रहा होगा कि एक सरकार ने कम्पल्सरी प्राइमरी एज्युकेशन का किसी डाइरेक्टिव के जरिये वादा किया हो चाहे वह राम का जमाना हो और चाहे वह कृष्ण का जमाना हो। उन जमानों में कुछ व्यक्ति बड़े-बड़े मठों में जाकर, ऋषि आश्रमों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे। किन्तु आज किसी भी वर्ग के बच्चों को चाहे वह गरीब हो या अमीर सबको तालीम देना चाहते हैं। जब इस शिक्षा के बारे में सोच-विचार करें तो हमें साफ नजर आयगा कि भारत सरकार और स्थानीय स्टेट्स की सरकारें इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि कोई भी १४ साल से कम का बच्चा बिना शिक्षा प्राप्त किये हुए न रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने देहातों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खोलने का इरादा किया है और यह प्रयत्न जनता के सहयोग से इसलिये किया जा रहा है कि हर एक गाँव के

[श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)]

लोगों को, जनता के हरेक आदमी को अपने बच्चों को तालीम दिलाने में दिलचस्पी हो और इसी दिलचस्पी को बनाये रखने के लिए यह कोशिश की गई है। हमने जनता के सहयोग के लिए यह शर्त रखी है कि जनता लड़कों की स्कूल के लिए मकान बनाकर दे, मास्टर के रहने के लिए मकान बनाकर दे ताकि वहाँ के अध्यापक का और जनता का प्रेममय सम्बन्ध स्थापित हो सके। श्री गोपीलालजी यादव ने कहा कि अभिभावकों और माता-पिताओं का सम्बन्ध अध्यापकों से हो। उनका आपस में सम्बन्ध होना आवश्यक है इसलिये हमने वहाँ के लोगों पर पाठशाला के लिए मकान बनाने का भार डाला है। अगर वे पाठशाला को बनाने और खोलने में सक्रिय सहयोग दें तो न तो अध्यापक भागेगा और न उसे बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई होगी। इसलिए जब सरकार ने यह विचार किया कि नये-नये प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिये तो उनको देहातों में अधिक खोलने का तय किया क्योंकि हमें अपने कॉन्स्टीट्युशन के डाइरेक्टिव्ज़ को पूरा करना है और अगर ये अधिक से अधिक खोलने हैं तो इसमें जनता से सहयोग माँगना चाहिये; तभी सफलता से ये स्कूल काम कर सकेंगे। हमारा यह एक्सपेरीमेन्ट बहुत हद तक कामयाब रहा। ६० फी सदी देहात के लोगों ने हमें सक्रिय सहयोग दिया और उन्होंने अपने स्वयं के भवन बना दिये। जैसी उनकी अपनी हैसियत थी उसके अनुसार कुछ ने ये पक्के मकान भी बना लिये हैं और कुछ लोगों ने छप्पर भी बनाये हैं; पर सहयोग सबका रहा, यह मुझे खुशी है। पर हम इससे भी आगे बढ़कर उनके कोऑपरेशन के मूल्य की बहुत बड़ी कीमत समझते हैं। कीमत इस वजह से ज्यादा हो जाती है कि पेरेन्ट्स और अध्यापक दोनों पास-पास आ जाते हैं और यह सम्बन्ध स्वतः ही ऐसा है कि शिकायत फिर इस विभाग के बारे में कम से कम होती है।

दूसरी बात जो हम करना चाहते हैं और जिसके बारे में सबसे बड़ी शिकायत है कि यह तालीम किस प्रकार की दी जावे और उसकी पद्धति में क्यों न परिवर्तन किया जावे, तो इस सम्बन्ध में माननीय त्यागीजी ने भी यह बात कही, एक सैद्धान्तिक बात कही कि खर्चे का बजट सैकंड्री एज्युकेशन का ज्यादा है और प्राइमरी का कम है। तो इस बारे में मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी मार्फत उनको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार का बजट इस साल नहीं रक्खा गया है। सेकन्ड्री को तो हम कुछ देना भी चाहते हैं पर कॉलेजों के लिए बहुत थोड़ी रकम रक्खी है। ज्यादा रकम तो इसी बात के लिए रक्खी गई है कि देहातों में हमें अधिक से अधिक स्कूलें खोलें। पर कुछ लोग कॉलेज-शिक्षा पर जोर देते हैं। कोटा में एम. एस सी. क्लास खोली जावे और एक नहीं, कई सदस्यों का दबाव आया। इसी तरह यह भी दबाव आया कि बारां में भी इन्टर कॉलेज हो।

श्री वेदपाल त्यागी—दबाव तो इस वास्ते आता है कि दूसरी जगह क्लासें आदि खोल दी जाती हैं और इधर नहीं खोली जाती इसलिए।

श्री भोलानाथ—तो बात तो मतभेद की यही है। एक दूसरे से भिन्न रायें होती हैं इस विषय में। इस बात के उन्होंने इल्जाम भी लगाये कि कोटा के लिए कम रुपया लगाया गया है।

[श्री भोलानाथ]

इसके बारे में मैं और निवेदन कर दूँ कि इस वर्ष बायोलोजी की डिग्री तक कक्षाएँ कोटा में खोली गई हैं, जो एक बड़ी चीज़ है। यह सब जो कुछ काम किया गया इसकी सराहना नहीं की गई, पर काम आगे नहीं हो रहा है इसकी उलाहना देना वे जरूरी समझते हैं। तो इस तरह से यह छोटे-मोटे जो काम आ जाते हैं इन कॉलेजों के हाई स्कूल आदि के तो इनके खर्च की रकम भी बढ़ती चली जाती है। यह जरूर है कि यह एक साथ बड़ी रकम नहीं बनती पर, फिर भी थोड़ा-थोड़ा खर्चा होता ही जाता है। पिछले साल खानपुर में हमने हाई स्कूल खोल दिया तो इसमें खर्चा हुआ, पर इसके लिए नाराजगी जाहिर करना उचित नहीं है। हो सकता है अधिक नहीं खोले जा सकते हों; दस हाई स्कूलों में से एक हाई स्कूल मिल गया, चाहे फिर वह साँगोद, माँगरोल या अटरू में हो या और कहीं हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विचार हम सभी जगह के लिए करते हैं और जहाँ हमें आवश्यक कोऑपरेशन मिलता है वहाँ हम काम प्रारम्भ कर देते हैं। मैंने साफ कहा कि यह हमारी पूरी इच्छा है कि जनता अगर शिक्षा के काम में दिलचस्पी लेती है, शिक्षा के काम में ही नहीं, किसी राष्ट्रनिर्माण के काम में दिलचस्पी रखती है और उसमें जनता अपनी सक्रिय दिलचस्पी रखती है तो निश्चितरूप से सरकार की ओर से हर सम्भव योग इसमें दिया जाता है। जनता के सक्रिय सहयोग और दिलचस्पी रखने से एक चीज़ यह होती है कि विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों में एक अच्छा सम्बन्ध स्थापित होता है और दूसरी बात जो हमारी विभागीय नियन्त्रण की दिक्कत की है वह भी पूरी होती है। इसलिए इस चीज़ को अपनाया गया और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हर तरफ इसमें हमें काफी सफलता मिली है, चाहे फिर हम परीक्षण के तौर पर हाई स्कूल खोलें, मिडिल स्कूल खोलें, सेकेन्डरी स्कूल खोलें या प्राइमरी स्कूल खोलें।

कॉलेज पिछले साल नहीं खोलें हैं। आगे परिस्थितियाँ ऐसी हों तो हो सकता है कि हम इस पर विचार करें। पर यह जरूर है कि प्राइमरी की तरफ हमारा पूरा-पूरा ध्यान जावेगा।

अब सवाल यह है कि पद्धति में क्या परिवर्तन होना चाहिये। इसमें दो बातें हैं। एक तो युनिवर्सिटी की ऊँची तालीम है। इस तालीम को कैसे उपयोगी बनाया जावे कि सेकेन्डरी की पढ़ाई समाप्त करके युनीवर्सिटी में पहुँचने पर विद्यार्थी किसी विषय का एक्सपर्ट बन सके; किसी ऐसे काम में, किसी ऐसे विभाग में वह जा सके जहाँ से तरक्की करके वह सफल नागरिक साबित हो। इस पर विचार करने के लिए युनीवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बैठा है। सेकन्डरी एजुकेशन पाने के बाद और सेकेन्डरी एजुकेशन पाकर युनीवर्सिटी में जाकर, वहाँ की एजुकेशन पाने के बाद भी दोनों अवस्थाओं में विद्यार्थी अपना विकास कर सके और किसी एक विषय का एक्सपर्ट बनकर सुयोग्य नागरिक साबित हो सके, यह हमारा लक्ष्य है। इससे हम यह भी चाहते हैं कि सेकेन्डरी एजुकेशन भी इटसैल्फ एक कम्पलीट एजुकेशन (secondry education itself a complete education) हो जानी चाहिये। अभी इस कन्टेक्सट में सोचा जा रहा है कि सेकेन्डरी एजुकेशन का डिप्लोमा पास करने के बाद अपनी जिन्दगी में स्वतन्त्र पेशे में वह जा सके तो इसकी कोई स्कीम होनी चाहिए और इन्हीं सारी बातों पर विचार करने के लिए एक सेकेन्डरी एजुकेशन कमीशन भी बिठाया गया है जिसमें न केवल हिन्दुस्तान भर के वल्कि अमेरिका, रूस जैसे देशों के लोगों से भी सलाह ली गई है और दूसरे

Page No.66

[श्री भोलानाथ]

मुल्कों में भी गये हैं और वहाँ के कालिजों और स्कूलों की शिक्षा-पद्धति का भी सूक्ष्म अध्ययन इस दृष्टि से किया गया है और किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की खामी हमारी इस सेकेन्डरी शिक्षा में न रह जावे। इसका हमारा लक्ष्य किस प्रकार सही तौर से पूरा उतरे इसकी पूरी जाँच के लिए वे गये, सारे आर्कटेक्ट स उन्होंने अध्ययन किये और इसके बाद जो रिपोर्ट आई उसके खास-खास मुद्दे में आपके सामने रख देना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है कि डाइवर्सिव फाइव ईयर्स कोर्स इस प्रकार शुरू किया जावे कि इसमें दस-बारह वर्ष पढ़ने के बाद वह स्वतन्त्ररूप से अपनी आजीविका चलाने लायक सुयोग्य नागरिक बन सके। ग्यारह-बारह साल के बाद में बच्चा पढ़कर निकले तो किसी न किसी लाइन में चला जावे। उसके लिए यह डाइवर्सिव फाइव ईयर कोर्स में यह सम्मलित किया जावे कि कोई रेडियो का काम, बिजली का काम, पॉवर्स, प्लान्टस आदि का काम शुरू से सीखे। यदि ऐसा करना है तो इसके लिए हमें अच्छे वर्क-शॉप भी चाहियेंगे, ट्रेन्ड टीचर्स और मकान आदि भी चाहिये। इन सबकी भी हमें तजवीज करनी है इसलिए क्वेश्चन आवर्स के वक्त भी प्रश्नों के उत्तर में बताया गया था कि इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी (implementation Committee) भी बिठाई है और वह इस बात का विचार करेगी कि किस जगह कौन सा कोर्स शुरू किया जा सकता है। यदि यह तय हो जाता है तो इसके बाद में यह जरूरी होगा कि एक सेकेन्डरी एजुकेशन बिल लाया जावे और वह इस हाउस में डिस्कस होगा और इसके हाथ ही साथ हमें युनीवर्सिटी का कोर्स भी बदलना पड़ेगा ताकि इस सेकेन्डरी एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद अगर कोई और भी आगे जाना चाहे तो युनिवर्सिटी की एजुकेशन में और इस एजुकेशन में सामन्जस्य स्थापित हो सके। वैसे इस हालत में सेकेन्डरी एजुकेशन अपने आप में एक पूर्ण शिक्षा होगी। युनिवर्सिटी का कोर्स इसलिए भी बदलाना होगा क्योंकि वह ग्यारह साल का कोर्स जब समाप्त करता है तो युनीवर्सिटी को तीन साल का कोर्स करना पड़ेगा और युनीवर्सिटी के कोर्स में भी इस प्रकार की तब्दीली करनी पड़ेगी जिससे सेकेन्डरी की शिक्षा भी वहाँ फिट हो जावे।

तो ये दो बड़े काम हैं। सेकेन्डरी और युनीवर्सिटी, दोनों की शिक्षा का समन्वय बिठाना है। खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन के साथ में, जिसको बेसिक एजुकेशन के नाम कहा जाता है और इस बेसिक एजुकेशन के बारे में भी सबकी एक राय है, ऐसा तो मैं नहीं कहता पर कुछ राज्यों में इस तरफ काफी ठोस कदम उठाये गये हैं और इसमें किन्हीं अंशों में सफलता भी उन्हें मिली है, पर पूरी सफलता वह भी नहीं कही जा सकती है। पर फिर भी ऐसा समझा गया है कि जो एक तबका यहाँ हमारे ऐसा बन गया है जो काम से परहेज़ करता है और कॉलेज की शिक्षा आज भी इस परहेज की दिशा की ओर बढ़ रही है तो इस परहेज़ को दूर करने के लिए यह सभी द्वारा सोचा गया है कि पाठ्यक्रम ही हमारा कुछ ऐसा हो कि जिससे हमारी हाथ से कुछ काम करने की आदत बने। इसलिए ऐसे कार्य पाठ्क्रम में ही रख दिए जाएं। श्रीमन् राजप्रमुख का जो भाषण हुआ और उसके बाद वित्त-मन्त्री का भी जो भाषण हुआ इन सब में यही कहा गया है कि हमारे यहाँ भी इस तरह के बेसिक स्कूल काफी मात्रा में खोले जावें और सरकार का ध्यान भी इस तरफ है; यह मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ।

[श्री भोलानाथ]

फिर जैसा मैंने आपको अर्ज किया कि किसी भी पद्धति को कामयाब करने के लिए किस प्रकार जन-सहयोग की अपेक्षा रहती है वैसे ही ट्रेन्ड टीचर्स भी चाहिये इस समय जो अध्यापक हैं वे यह काम शुरू कर सकें, ऐसी सम्भावना नहीं है। इसलिए इस वर्ष हमने सोचा है कि हमारे जो ट्रेनिंग स्कूलस हैं उन्हें बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों में बदल दिया जावे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो एक हजार अध्यापक हम हर साल तैयार कर सकते हैं और वे जो ट्रेनिंग पास करके बेसिक स्कूलों में जावेंगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं वे वहाँ पर जरूर किसी न किसी प्रकार का काम, श्रम-का काम भी शुरू कर सकेंगे, बच्चों से श्रम ले सकेंगे और जो एक मनोवृत्ति श्रम से भागने की हम में बन चुकी है, आज की इस दूषित शिक्षा प्रणाली के प्रभाव के कारण वह धीरे धीरे दूर होती जावेगी और इस प्रकार हमारा सारा कार्यक्रम और पाठ्यक्रम ही दूसरी तरह का बन जावेगा। बड़े हो कर ऐसे नागरिक देश की समृद्धि में पूरा योग देंगे, ऐसी हमारी आशा है। तब ऐसी स्थिति में इन बेसिक स्कूलों से निकल कर ये बच्चे सेकेन्डरी स्कूलों या कॉलेजों में जब जावेंगे तो जैसा कि हम सोच रहे हैं इन सेकन्डरी स्कूलों और कॉलेजों में डाइवर्सिव पोइन्ट कोर्स का लागू होगा। अगर वह कोर्स लागू हो गया तो उस कोर्स की शिक्षा में ये फिट हो सकेंगे।

अभी मैंने एक सर्कुलर भेजा था, उसमें निवेदन किया था कि हमारे माननीय सदस्यगण जिस प्रकार देहातों में स्कूलों के लिए सहूलियत पैदा करते हैं इस शिक्षा विभाग के लिए उसी तरह वे सहयोग का वातावरण भी देहातों में बनावें। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत हाउस को भी निवेदन करूंगा कि इन सब बातों में वे हमें सहयोग दें। आगे कहा गया कि बेसिक स्कूलों को शुरू करने के लिए थोड़ी जमीन भी दें तो उसके लिए भी हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। आखिर जो लोग अपने बच्चों को खास तौर की तालीम देना चाहते हैं, और अगर वे कोशिश करें तो २-४ बीघा जमीन वहाँ पर मिल जाय तो उसके वहाँ उस ढङ्ग की तालीम शुरू कर सकते हैं। खास तौर से अपने यहाँ एग्रिकल्चर ही बड़ा धन्धा है और एग्रीकल्चर ही हमारे यहाँ बेसिक कोर्स बन सकता है और यदि जमीन मिलती है तो वहाँ पर अध्यापक को तो सहूलियत होगी। सरकार को भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है कि वह जमीन एक्वायर की जाय, पानी निकलता है या नहीं आवश्यक एक्सपेरीमेंट किये जाँय। खैर यह ठीक है कि शुरूआत में यह सब दिक्कतें मालूम होती हैं, लेकिन आपका पूरा सहयोग मिलता है, ऐसा वातावरण बनाने में मदद करते हैं तो वह ठीक होगा।

मैंने अर्ज किया कि ट्रेनिंग स्कूलों में और कॉलेजों में, बेसिक में बदल जाने पर, उनके शिक्षा प्राप्त अध्यापक उस गाँव में जायेंगे और बेसिक तालीम शुरू कर देंगे। गाँवों की स्कूलों की शिकायतें आती हैं कि न मकान हैं न बैठने की सुविधा है; तो फिर इन स्कूलों की तीसरी माँग आयेगी जमीन की। अगर आप जमीन दिलवा दें उन लोगों से और नये स्कूल खुलवाने हैं और जहाँ इस पद्धति के स्कूल नहीं चाहिये और बेसिक स्कूल चाहिए तो निश्चत रूप से आप मदद कीजिये। यदि आपकी माँग आयेगी और यह सूचना आपकी आयेगी कि जमीन प्राप्त करने की कोशिश की जायगी तो उसको प्रिफरेन्स दिया जायगा। जल्दी से जल्दी एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

[श्री भोलानाथ]

लाना चाहता है लेकिन आम जनता और आपका सहयोग प्राप्त किये बिना ऐसा संभव नहीं है।

जहाँ इस प्रकार के स्कूल कायम होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत कठिनाई होती है । आज भी ऐसे लोग हैं कि जो नई चीजें काम में लाई जाती हैं उनको शक की निगाह से देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि राजाजी की स्कीम की भी लोगों ने बुराई की और कड़ा विरोध किया है। उसमें अध्यापक पढ़ाता है ३ घन्टे। बाद में बच्चों को मौका दिया जाय कि कुछ भी काम कर सकें, तो वे कहते हैं कि बच्चों को मजदूर बना रहे हैं, हमको इन्हें पार्लियामेंट के सदस्य बनाना है, मिनिस्टर बनाना है। तो मिनिस्टर तो वह भी बन सकते हैं लेकिन हिन्दुस्तान में ५०, १०० या १५० ही मिनिस्टर बन सकते हैं, बाकी को तो काम करना ही होगा। मैंने अर्ज किया कि किसी भी इम्पोर्टेन्ट से इम्पोर्टेन्ट स्कीम का विरोध किया जाता है और यह कहा जाता है कि यह कोई मुमकिन नहीं है। बेसिक एजुकेशन के बारे में राजाजी ने कोशिश की कि बच्चे काम करेंगे और निश्चित रूप से थोड़ी अड़चन होगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए कहते हैं कि छोटी उम्र है और उनसे सरकार मेहनत लेगी। इसके लम्बे-लम्बे स्टेटमेंट निकलते हैं अखबारों में। पिछली बार यहाँ पर श्री मिर्जा स्माइल ने युनिवर्सिटी के कन्वोकेशन पर एड्रेस दिया तो उस एड्रेस में कितनी ही बातें बेसिक के बारे में तालीम की कहीं, उनकी सारे देश में निन्दा हुई है।

मैंने पहले बताया कि बेसिक स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं, यह सरकार के लिए एक प्रकार से दुविधा की बात होती है लेकिन मैं दो दिन की सदन की डिबेट से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और सब माननीय सदस्यों का इस बात के लिए आभारी हूँ कि वे बेसिक तालीम की बहुत जरूरत समझते हैं। अगर वे इसे जरूरी बात समझते हैं तो उनसे कोऑपरेशन की आशा करता हूँ। अगर वे नये स्कूल खुलवाना चाहते हैं तो वह अध्यापक के लिए स्थान की बात सोचें, जहाँ स्कूल की बात सोचें तो कुछ जमीन के बारे में सोचें। ऐसा वातावरण बनायें कि किताबी ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ बच्चा थोड़ा बहुत काम भी सीखे। इस प्रकार की प्रेरणा हो कि वह देश का बड़े से बड़ा आदमी बने, लेकिन जो अपने काम को चलाना चाहते हैं, अपने पेशे को नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों को सेल्फ साफिशियन्ट (self sufficient) बनाना हो तो इस प्रकार की स्थिति बनाई जाय। इसमें आपका सहयोग चाहिए। आशा है वह सहयोग मिलेगा।

अभी यह भी कहा गया है कि कुछ प्लानिंग नहीं है, स्कूलें किसी भी प्रकार खोल दी जाती हैं। हमारा यह प्लानिंग है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के पढ़ने चाहिए। इसलिए यह सोचा गया कि पोपुलेशन बेसिस पर स्कूलें खोली गई और तहसीलों में स्कूलों का एलॉटमेंट (allotment) पोपुलेशन बेसिस पर हुआ। इस साल भी एलॉटमेंट पापुलेशन बेसिस पर होने वाला है; इसलिए आप सूचना दीजिए कि इसमें क्या कमी रही, तो उसको करेक्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। दूसरी शर्त रखी है कि जो पॉपुलेशन बेसिस पर स्कूल्स हों, वह २ हजार और एक हजार तक के हों, ५०० या ७०० की आबादी के लिए अगले वर्ष तक स्कूल दे सकेंगे। इस स्कीम से २ हजार तक का कोई गाँव नहीं रहेगा, फिर भी अगर कोई रह भी जायगा तो वहाँ सबसे पहले स्कूल खोला जायगा। फिर एक हजार और

[श्री भोलानाथ]

५०० के बीच में प्राथमिकता मिलेगी। तो उस बीच में स्कूलों के नाम दे देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी माँग पूरी होगी, उसमें कोई तरमीम नहीं होगी। हम चाहते हैं कि इस प्लान से आने वाले दो साल में ५०० तक की आबादी वाले गाँवों में स्कूलों की जरूरत पूरी हो जानी चाहिए। ट्रेन्ड बेसिक अध्यापक तो उसी हालत में पहुँचेंगे जहाँ आपका ज़मीन के लिए कोऑपरेशन होगा।

आज यह सवाल जरूरी हो गया है कि अध्यापक कुछ इस प्रकार के जरूर भेजने चाहिए जिनको अध्यापन का ज्ञान हो। इसके लिए यह तय किया है कि नया अध्यापक कम से कम ६ हफ्ता हमारे पास तालीम लेगा। आपने देखा होगा कि नई भरती जो की गई है अनएम्पलायमेंट के सिलसिले में उनको बेसिक की तालीम यानी कुछ काम सिखाने की कोशिश की गई है, हालाँकि कोई तालीम ६ हफ्ते में पूरी नहीं होती है, लेकिन ६ हफ्ते में हम उनको बतलाते हैं कि किस तरह की तालीम देनी चाहिए, कुछ न कुछ काम बताया जाता है। उन्हें थोड़ा सा पढ़ाने की पद्धति के बारे में, थोड़ा सा स्कूलों के बारे में, थोड़ा सा गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में बताया जाता है जिससे कि जाने के बाद वे एकदम से नये-नये नहीं रहें; इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रहती है कि कोई बिल्कुल नया रहे बल्कि कुछ पढ़ाकर भेजते हैं।

दूसरी बात आम तौर से यह कही जाती है कि नए अध्यापक किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर या दूसरी जगह से भेज दिये जाते हैं। ऐसी बात भी अब नहीं है। पिछले एडवर्टाइज़मेंट में लिखा है कि आवश्यकता तहसील से पूरी की जायगी। अगर अधिक लोग उसी गाँव या तहसील में ही रिक्विज़िट क्वालिफिकेशन के मिल जाते हैं तो उनको उसी तहसील में नियुक्ति मिल जाती है। तो वह वहाँ रहेंगे, वहाँ से भागेंगे नहीं। उनको भी ६ हफ्ते तक अपने पास रखेंगे, कुछ सिखायेंगे और नए अध्यापक घबराकर नहीं भागेंगे। और यदि अध्यापक को कोआपरेशन वहाँ पर मिलेगा तो कोई वजह नहीं कि वह वहाँ से भाग जाये। इसलिए आपने जो शिकायतें की हैं उन शिकायतों का समाधान इस पद्धति से किया जा सकेगा।

अब मैं हाईस्कूलों के बारे में बताना चाहता हूँ। सरकार चाहती है कि ५० हजार की आबादी वाली एक तहसील में कम से कम एक हाई स्कूल जरूर होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस काम में सफलता मिलेगी, यदि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा मकान दिलाने की कोशिश करें। आपके कट मोशन आते हैं रुपया काटने के लिए। सिर्फ यादवजी ने कहा कि एजुकेशन का बजट बढ़ा देना चाहिए, उसको ५ करोड़ का बजट कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप बजट बढ़ा देते हैं तो जगह-जगह स्कूलें खोलने में कोई असुविधा नहीं होगी। तरक्की का जो क्रम है, उसको बढ़ाने में सुविधा पैदा होगी। इसलिए हाउस से निवेदन करूँगा कि इस काम में मेरी सहायता करें।

[श्री भोलानाथ]

संस्कृत के बारे में मैं समझता हूँ जितना राजस्थान में इस बात का ध्यान दिया गया उतना और जगह नहीं। हमारे यहाँ छठी से लेकर आठवीं क्लास तक कम्पल्सरी संस्कृत की तालीम की गई है। वह किसी राज्य में नहीं है। उसके लिए भी शुरूआत में विरोध हुआ कि जबरदस्ती बच्चों पर इतना भार नहीं डालना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमने संस्कृत को कम्पलसरी रखते हुए भी उसमें इम्तिहान पास करने की जरूरत नहीं समझी है, इससे क्वालिफाइड और संस्कृत के उच्च विद्वान बनने में उनको लाभ पहुँचेगा और ऊँचे स्कूलों और कॉलेजों में जाने पर वे अच्छे संस्कृत के स्कॉलर बन सकेंगे। इसके लिए यह प्रारम्भिक कोशिश की जा रही है।

आज संस्कृत की परीक्षाओं में इस बात की कमी अवश्य है कि जो सर्टिफिकेट वगैरह दिये जाते हैं वे युनिवर्सिटी के नहीं हैं। इसके लिए मैं बराबर युनिवर्सिटी से निवेदन कर रहा हूँ और युनिवर्सिटी भी तैयार हो गई मालूम पड़ती है। लेकिन जैसा भी उनका प्रोसीज़र है, प्रोसेस में से गुजर जाने से ही वह कमी पूरी हो सकती है। संस्कृत के जो एक्ज़ामिशनस होते हैं वे युनिवर्सिटी के ज़रिये से जल्दी ही होने लगेंगे और उनकी संस्कृत की शिक्षा जो है वह युनिवर्सिटी के सेटेन्डर्ड पर आ जायेगी और आजकल उस संस्कृत की तरक्की में जो कमी दिखाई देती है वह दूर हो जायगी और अगर बढ़ाने की आवश्यकता हुई तो बढ़ाई भी जायगी।

जो विद्यार्थी सर्विस में आने के इच्छुक हैं उनके लिए ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि उनको नहीं लिया जाय, लेकिन जो पुराने ढङ्ग से संस्कृत पढ़ाते हैं वे केवल संस्कृत का ही ज्ञान रखते हैं; कुछ मैथेमेटिक्स, भूगोल इतिहास व जनरल साइन्स की कमी है—वह पढ़ाने की आवश्यकता है।

यदि अब इसमें पास होने वाले संस्कृत के विद्यार्थी मिलेंगे तो उनको अपोइन्टमेन्ट देने में जरूर ध्यान रखा जायेगा। अब पाठ्यक्रम को बदल दिया गया है, जिसके अनुसार अध्यापकों को और विषयों की जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है।

बड़ी चर्चा कभी-कभी पाठ्यपुस्तकों के बारे में हो जाती है। मैं अर्ज करूंगा कि अब जो पाठ्य पुस्तकें रखी गई हैं वे ३ वर्षों के लिए निश्चित कर दी गई हैं, इसलिए अब जल्दी-जल्दी बदलने की नौबत नहीं आयगी। जो पहले गड़बड़ी आ गई वैसी अब नहीं होगी। श्री एच० के० व्यास ने कहा कि सीक्रेसी कैसे आउट हो गई? आप जानते हैं कि जो बड़े-बड़े अच्छे काम होते हैं उनको बिगाड़ने वाले भी पैदा हो जाते हैं। जो गड़बड़ी हुई उसको सुधारने की कोशिश की गई है। सिलेक्शन में गड़-बड़ी इन्ट्रेस्टेड पार्टी ने मुनाफा कमाने के लिये की है तो उनको सजा दी जायगी। एहतियात काफी रखी गयी है। चार-चार दफे छनने के बाद भी कोई कमी रहती है तो इसमें अपना ही दुर्भाग्य मानना चाहिये, देश की कमजोरी माननी चाहिये। इतना होते हुए भी लोग गड़बड़ करते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे देश में मोरेलिटी की कमी है। एहतियात जितनी बरती जा सकती है उतनी बरती जाती है। मैं समझता हूँ मैंने सभी पोइन्टस कवर करने की कोशिश की है। प्राइमरी एज्युकेशन के बारे में बयान कहा। सेकन्डरी एज्युकेशन कमीशन की रिपोर्ट पर अमल किया जाता है तो सारे देश में

[श्री भोलानाथ]

एक सी नीति पर चलना होगा। इसके विपरीत यदि हम राजस्थान में कोई और ही नक्शा बनाते हैं तो आगे चलकर विद्यार्थियों के लिये कठिनाई उपस्थित हो सकती है क्योंकि दूसरी जगह एकसी पढ़ाई होगी और अपने यहाँ दूसरी तरह की होगी, तो वे विद्यार्थी किसी दूसरी युनिवर्सिटी में भरती नहीं हो सकेंगे। इसलिये खाली राजस्थान के लिये अलग नीति पर चलना संभव नहीं है। साधारण प्राइमरी और बेसिक स्कूल में फर्क होता है। एक प्राइमरी स्कूल को बेसिक स्कूल करने में दूना खर्चा हो जाता है। सरकार बेसिक स्कूलें खोले, इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आपका सहयोग मिलेगा।

एक सदस्य—मिलिटरी एज्युकेशन के बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री भोलानाथ—आपने इन्फॉर्मेशन माँगी थी, मैं देना भूल गया। हमारे यहाँ एन. सी. सी. चल रही है। इस साल राजस्थान सरकार ने ए. सी. सी. की ट्रेनिंग शुरू की है। इसमें कंपल्सरी तौर पर बच्चों को जाना पड़ेगा। यह एन. सी. सी. की मोडिफाइड फोर्म है। बच्चों को ज्यादा सहूलियतें देना तय किया गया है। माथुर साहब ने कहा कि एक्सट्रा एक्टिविटी की तालीम नहीं दी जाती और टूर्नामेन्टस आदि नहीं होते। मैं उनसे कहूँगा कि टूर्नामेन्टस ज्यादा से ज्यादा होते हैं और डिग्री कॉलेज तक के होते हैं। अभी हैदराबाद में स्काउटस की जंबूरी हुई थी। उसमें भी हमारे यहाँ के स्काउटस ने काफी नाम कमाया है। एन. सी. सी. को काफी प्रोत्साहन दिया गया है। उनकी कम्पनियें बढ़ाई गई हैं। इस साल से एन. सी. सी. का कार्यक्रम रखा जा रहा है। कुछ लोगों को शंका है कि इस बहाने फौज में भरती की तो तैयारी नहीं की जा रही है; ऐसा प्रचार भी कहीं-कहीं किया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, क्या सदन में किसी विशेष सदस्य को सम्बोधित करके कहा जा सकता है या अध्यक्ष को!

श्री भोलनाथ—अध्यक्ष महोदय की मार्फत ही कहा गया है।

स्काउटिंग के बारे में मैं कहना चाहता था कि हैदराबाद में जो जंबूरी हुई उसमें जो हमारे यहाँ के छात्रों ने काम किया उससे भी राजस्थान की शान बढ़ी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा राइट ऑफ रिप्लाई रह जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—एक एक करके कट मोशन लिये जायेंगे।

(श्री एच० के० व्यास के खड़े होने पर)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, he has risen and it is due to him that he should give a reply. My point will come later. First his point of order may be decided. I think his point of order appears to me to be in order. It is for you to decide whether it is in order or not.

Page No.72

श्री उपाध्यक्ष—मेरा डिसीजन यह है कि जिस तरह से कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनको सिलसिलेवार लिया जायगा। व्यास के कटौती प्रस्तावों का नम्बर बाद में आयगा, पहले आपका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस वक्त मेरा राइट ऑफ रिप्लाई है।

श्री उपाध्यक्ष—एक एक करके कटमोशन्स लिये जायेंगे।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैंने दो कट मोशन्स मूव किये थे, मैं कुछ समय के लिये सदन से बाहर था इसलिये मैं नहीं कह सकता कि मन्त्री महोदय ने उनका क्या जवाब दिया। मैं आशा करता हूँ कि वे संतोषजनक थे। यदि संतोषजनक जवाब नहीं था तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा।

श्री भोलानाथ—उनका जवाब दिया गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जवाब तो दिया होगा लेकिन वह सन्तोषजनक है या नहीं?

एक सदस्य—आपको यहाँ रहना चाहिये था।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—यह जरूरी नहीं है।

यदि सदन मुझे इजाजत दे तो मैं अपने कट मोशन्स वापिस लेना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की आज्ञा है कि श्री जसवन्तसिंह अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री तेजमल बापना—मैं भी अपने कटमोशन्स वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन श्री बापना को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान करता है।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजमल बापना—मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री तनसिंह—मेरे दो कटौती प्रस्ताव थे, जिनमें से एक के बाबत भी अपने जवाब में दो शब्द खर्च करने की माननीय मन्त्रीजी ने उदारता नहीं दिखाई।

श्री भोलानाथ—प्राइमरी एज्युकेशन के बारे में मैंने जवाब दिया था।

Page No.73

श्री तनसिंह—मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की उदारता दिखा सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री तनसिंह अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री खेतसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा शिक्षा मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि जहाँ की आबादी ५० हजार से ज्यादा है वहाँ हाई स्कूल खोली जायगी तो मैं आशा करता हूँ कि १ लाख की आबादी जहाँ है वहाँ तो हाई स्कूल जरूर खोली जायगी। इसलिये मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री खेतसिंह अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लें।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री खेतसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री हरिदेव जोशी।

(अनुपस्थित)

क्योंकि श्री हरिदेव जोशी उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनके प्रस्ताव के पक्ष में जो हैं वे 'हाँ' कहें और जो विपक्ष में है वे 'ना' कहें।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री गोपीलाल यादव।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री गोपीलाल यादव के कटौती के प्रस्ताव स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

श्री गोपीलाल यादव के कटौती के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, जब मैं मन्त्री महोदय की बातें सुन रहा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सेकिन्डरी एजुकेशन में हमारे ऐसे संस्कार (अश्रव्य) लिए जा रहे हैं पर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

किसी -किसी कट मोशन का और करीब-करीब मेरे जितने कट मोशन्स थे उनमें से एक को छोड़कर किसी का जिक्र नहीं किया गया । लेकिन स्टडी सरकल और सेकेन्डरी एज्युकेशन के लिए, जिस सेकेन्डरी एज्युकेशन कमीशन का यहाँ इतना लम्बा-चौड़ा जिक्र किया गया उसको जो सिफारिश है उसे मैं पढ़ कर सुना दूँ ।

"A fixed percentage of Cantral and provincial revenues about 10% of the Central, and 20% of the provincial should be earmarked for the education by the respective Governments."

तो जितना आग्रह इस कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देकर इधर बैठे लोगों की आलोचना करने का था उतना आग्रह, अगर राजस्थान सरकार की २० प्रतिशत आय एज्युकेशन में प्रोविजन करने के विषय में, होता तो ज्यादा अच्छा होता ।

दूसरी चीज जो जरूरी थी वह बेसिक एज्युकेशन के लिए बेसिक अध्यापक ट्रेन्ड करने की की थी । इसके लिए कहा गया है कि बेसिक एज्युकेशन देकर बेसिक शिक्षक तैयार करेंगे, परन्तु उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं इसका कोई जिक्र नहीं किया ? सारी ही चीजों के बेसिक को तो तय कर दिया गया, पर मन्त्री महोदय ने इसके लिए कुछ नहीं कहा कि शिक्षक की बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं ।

टेक्स्ट बुक्स के बारे में जो इतनी गड़बड़ी हुई उसमें आपको कुछ नजर नहीं आया । जब टेबुलेटर यहाँ आया था और गवर्नमेंट होस्टल में ठहरा था तो पब्लिशर्स मिलने जाते थे, एज्युकेशन विभाग के जितने नये-पुराने, नये स्पुरियस पब्लिकेशन्स की जयपुर में ११ दूकान खोल रखी हैं, उनको देखते तो पता चलता कि शिक्षा विभाग सौदेबाजी का, लेन-देन का अड्डा बना हुआ है । इसके बाद फिर यह कहना कि एहतियात बरती गई; उनको संतोष हो सकता है परन्तु हकीकत किसी से छुपी नहीं है । हकीकत जो है वह हरेक पब्लिशर, हर एक ऑथर, राजस्थान के अखबार और उन अखबारों के जरिये राजस्थान की जनता जानती है । मन्त्री महोदय नहीं जानते हों तो वह एक दिलचस्पी की बात हो सकती है ।

हर चीज़ में रेड रेग (red rag) नजर आता है । सेंट जेवियर स्कूल के बारे में मैंने कल पढ़ कर सुनाया, शायद माननीय मन्त्रीजी के ध्यान में आया या नहीं, कुछ नहीं कह सकता । बेसिक शिक्षा में मैं यह मानता हूँ कि पोली-पोली टेक्निक्स तैयार हों और उनके साथ बेसिक स्कूलों का समन्वय जोड़ा जाय तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं । ऐसी सिर्फ न मेरी राय है और न राजाजी की ही, जिन्होंने एज्युकेशन स्कीम तैयार की है; बल्कि सबसे ऊँचे शिक्षा विशेषज्ञ जो १३ साल तक महात्मा गाँधी के सेवाग्राम में रहे, उन आर्यनायकम् की भी यही राय है । आप सुनें तो......

श्री भोलानाथ—इसका समन्वय बैठाया जा रहा है । यह मैंने इन्फोर्मेशन के लिये कहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—राजाजी के जो इतने बड़े हामी हैं, उनकी स्कीम के बारे में तो समन्वय बैठा नहीं और पोली टेक्निक्स की बात उनके खयाल में आ गई।

पर, फिर ऐसे नागरिक बनाने में यह भी ट्रेनिंग जरूरी है कि राजस्थान का मन्त्री-मंडल जैसे सेकेन्डरी एज्युकेशन के मुतल्लिक टेक्स्ट बुक्स में गड़बड़ी हुई, और जिस तरह उसमें हमारी सरकार का हाथ दिखता है, तो क्या आप इसी तरह के नागरिक तैयार करेंगे।

यह कहा गया कि हमने कॉम्युनिज्म के विरूद्ध रोक करने के लिये यह कार्य किये हैं। अमेरिकन मिश्नरीज यहाँ आये और (अश्रव्य) कहा कि यह घोड़ा है, इसका टिकट लेओगे। इसके खिलाफ तो आपने कुछ नहीं किया।

इसका सीधा तात्पर्य यह है कि कोई तात्विक बात पर, किसी तात्विक आधार पर आपकी एज्युकेशन नहीं चल रही है।

डा० अर्नायकम् (Dr. Arhaya Kam) की राय यह है :

"It is a hybrid between the scheme of basic education and the scheme of thé Macauleán clericel education."

नतीजा यह होता है कि मेरे एक भी कटौती के प्रस्ताव का जिक्र नहीं होता है। फिर भी श्री तनसिंहजी की तरह भलमनसाहत रखते हुए; सिवाय इसके कि चारा ही क्या है, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच. के व्यास के कटौती के प्रस्ताव...

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब एक साथ ले रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष—हाँ सब एक साथ। (कुछ विराम के अन्तर) प्रश्न यह है कि श्री व्यास के कटौती के प्रस्ताव स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

श्री व्यास के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

(विराम)

श्री शम्भूसिंह।

श्री शम्भूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करने की भी इजाजत नहीं दी, तो फिर वापिस लेने का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सदन में प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत आसानी से मिल सकती है, पेश करने की नहीं।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री वेदपाल त्यागी के कटौती के प्रस्ताव स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

(विराम)

श्री भैरूँसिंह।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये। यदि इजाजत हो तो बिना प्रस्तुत किये ही वापिस ले लूँ।

श्री उपाध्यक्ष—पेश नहीं हुए।

श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—अब भी इजाजत हो तो उन्हें मूव करूँ। (हँसी)

श्री उपाध्यक्ष—

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 3,35,20,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XVI, Major Head 37- Education."

(मतदान के पश्चात्)

The Ayes have it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The Noes have it,

राज्य पक्ष—Ayes have is.

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 3,35,20,000/- be granted to H H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XVI, Major Head 37- Education.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I am glad that the whole House is complete now.

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—अब तो दर्शन हो गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बार-बार दर्शन करने की इच्छा है।

श्री चन्दनमल वैद—इसके लिये धन्यवाद।

माँग संख्या २७—विद्युत की रसीदें

श्री उपाध्यक्ष—Shri Tikaram Paliwal.

श्री चन्दनमल वैद—The Demands have been taken as moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The ruling of tha Chair cannot be questioned by any Hon' ble Member. When the name is called out the motion has to be moved.

श्री उपाध्यक्ष—श्री टीकाराम पालीवाल।

(श्री चन्दनमल बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—How do you ask questions which are to be asked by others.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am always for my friends. That is what I generally do.

कु० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, is the Hon'ble Member Mr. Tikaram Paliwal ?

श्री चन्दनमल वैद (उप मन्त्री)—I am moving on his behalf.

(विराम)

I beg to move, "That a sum not exceeding Rs. 1,51,23,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXVII, Major Head XLI—Receipts from Electricity—working exp. etc."

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—List No. V, serial No.110. All the cut-motions at one time, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But Economy cuts and other cuts to be moved separately.

श्री उपाध्यक्ष—Naturally you will speak one thing at a time.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह— On a point of order, Sir, the point is that the token cuts and the economy cuts cannot be taken together under the Constitution. I am afraid, Sir, that the Economy cuts will have to be taken first and when they have been disposed of, the token cuts can be taken into consideration

श्री उपाध्यक्ष—List No.V serial No, 110

श्री हरिकृष्ण व्यास—(Economy--Reduction and saving in expenditnre on Coal, Oil, lubricants, spares and stores.) माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इस आशय का एक कटौती का प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान के अलग-अलग बिजलीघर जो हैं उनमें कोयला, तेल, स्पेअर पार्टस आदि के खरीदने में जो रकम खर्च होती है और बताई जाती है, इसमें कमी होने की गुंजायश है और कम से कम सात लाख की कमी इसमें की जानी चाहिये। इस प्रकार का कटौती का प्रस्ताव देने का बहुत ही मोजू और कुछ हद तक टेक्नीकल कारण मैं सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

एक कारण तो, माननीय उपाध्यक्ष, यह है कि हकीकत में जो रकम आज इन सभी मदों के लिये रखी गई है वह वास्तव में बिजलीघरों के काम में ही खर्च हो रही है। इसके बारे में कोई निश्चित मत कोई इमानदारी से नहीं दे सकता। इसलिये नहीं दे सकता कि न तो आज तक इस विभाग में प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्टस (Profit and loss accounts) हैं और न पिछले पूरे चार वर्षों में क्लोजिंग स्टोक तैयार करके वेरीफाइ किया गया है। इसलिये तसल्ली की जा सकती है केवल दिल को संतोष करने के लिये। लेकिन एक जो तसल्ली का तरीका है वह यह है कि या तो प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्टस हो तो पता लगाया जा सकता है कि ज्यादा खर्च हो रहा है या कम अथवा क्लोज़िंग स्टोक तैयार होता। ये दोनों तरीके अभी तक सरकार ने इस्तेमाल नहीं किये। पहला कारण तो यह है।

दूसरा कारण, माननीय उपाध्यक्षजी, जिस वजह से इस पर बोल रहा हूँ वह यह है कि यदि आप देखेंगे कि राजस्थान के विभिन्न बिजलीघरों में कहीं कोयले से काम होता है, कहीं ऑयल इन्जिन से काम होता है, कहीं नई मशीनें हैं, कहीं पुरानी मशीनें हैं; लेकिन अगर आप आँकड़े देखें कि एक युनिट के जेनरेशन के लिए कितना कोयला कहाँ-कहाँ खर्च होता है तो वह आँकड़ा पाँच हजार, छः हजार, सात हजार, आठ हजार से लगा कर (अश्रव्य) हजार तक गया है। जयपुर में अलग है, जोधपुर में अलग है, और बीकानेर में तो विशेष ज्यादा है, और शायद पलाना का कोयला इस्तेमाल करने की वजह से हो गया हो। इसका समाधानपूर्वक उत्तर कभी आज तक नहीं मिला कि कोयला एक ही युनिट को जेनरेट करने के लिए अलग-अलग बिजलीघरों में इतना कम-ज्यादा क्यों खर्च हो रहा है। कुछ पर्सेन्टेज पुरानी और नई मशीनों की वजह से हो सकता है लेकिन तीन-तीन और चार-चार गुना क्यों? यही हाल है इन्जिन्स का, जिनमें ऑयल इस्तेमाल होता है और पिछले चार महीनों

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से तो माननीय उपाध्यक्षजी, अलवर से, टोंक से और कई जगहों से यह शिकायत आई है कि तेल के पीपे के पीपे गायब हो गये हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह मामला तफतीश के किस स्टेज में है। अलबत्ता यह जरूर कहा जाता है कि तफतीश की जा रही है। जहाँ लाखों रुपयों का प्रोविजन है उसमें से इतना रुपया इस प्रकार से सालाना चाहे चला जाने वाला मिला दें यह भी कहना कठिन है और जो वारदातें रोज होती रहती हैं उससे कम से कम सालाना लोस का प्रोवीजन इसमें रखा गया है। दूसरा कारण माननीय उपाध्यक्षजी यह है कि आँकड़े उपलब्ध हैं पर जानकारी नहीं है। उसमें इतना फ्लक्चुऐशुन (fluctuation) कि एक बिजलीघर और दूसरे बिजलीघर के बीच में यदि कम्पेरिजन (मुकाबला) किया जाय तो मालूम होगा कि भारत के दूसरे विभिन्न बिजलीघरों के मुकाबले में कम से कम जोधपुर बिजलीघर की तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ कन्ज़म्पशन तीन गुना है, दूसरे बिजलीघरों के मुकाबले में।

तीसरा कारण और बताऊँ, माननीय उपाध्यक्षजी, जो यह है कि आज लोगों से छः आना युनिट बिजली का चार्ज किया जाता है, पॉवर का दो आना चार्ज किया जाता है, तीन आना चार्ज किया जाता है और टेम्परेरी कनेक्शन्स जो बड़ी तादाद में दिये जाते हैं उनका बारह आना युनिट चार्ज किया जाता है। दो-दो तीन-तीन साल तक टेम्परेरी कनेक्शनस रहते हैं और उनका भी बारह आना युनिट चार्ज किया जाता है। मीटर का खर्चा भी कन्ज्युमर से चार्ज किया जाता है तथा मीटर का किराया और अलग वसूल किया जाता है। यह विशेषता तो शायद राजस्थान में ही है। मीटर नया लगावें तो मीटर की पूरी रकम जमा करानी पड़ती है उस आदमी को जो एप्लीकेशन करता है और बाद में मीटर का किराया हर महीने अलग वसूल किया जाता है और इतना वसूल करने के बाद भी घाटा जा रहा है, ब्याज का रुपया देना तो दूर रेवेन्यू के माने में भी घाटे में जा रहा है। आखिर यह क्यों? यहाँ राजस्थान में ऐसी मिसाल मौजूद है कि एक मील अपने पड़ौसी पॉवर हाउस को दो आने युनिट से पॉवर सप्लाई करने को तैयार था और एग्रीमेंट भी हो गया था, यह पाली का केस है। मिल वहाँ के किसी व्यक्ति का है और बिजलीघर सरकार का है। पहले दो आने युनिट से ही बिजली दी जा रही थी किन्तु सरकार ने तीन आना, चार आना कर दिया; फिर भी सरकार को घाटा गया। अतः इसकी छान-बीन होनी चाहिए। इसमें बचत की काफी गुँजाइश है। यह भी प्राइमाफेसी केस बचत का बनता है और इसीलिए मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है।

और अन्त में मैं माननीय उपाध्यक्षजी, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है व जो कटौती के प्रस्ताव को मंजूर करने में आशातीत (कारण) है, बताना चाहूँगा। सरकार को सूचना मिल चुकी है कि इसमें बचत की काफी गुन्जाइश है और वह सूचना देने वाले सदन में तकरीर करने वाले लोग नहीं, वह सूचना देने वाले सरकार द्वारा नियुक्त अफसर जिनका नाम श्री यादराम चतुर्वेदी हैं और जिनकी रिपोर्ट को ऐसा दबा-दबा कर रखा जाता है कि मेरा खयाल है कि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, जो अन्य देशों से संधि करता है, वह भी इतनी सिक्योरिटी से नहीं रखी जाती होगी और प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के जो हुक्म होम डिपार्टमेंट से निकाले जाते हैं वे भी ताले में नहीं रखे जाते होंगे जितने कि पी. डब्ल्यू डी. के सिलसिले में श्रीमान् यादरामजी की जो रिपोर्ट आई है वह ऐसी दबा-दबा कर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रखी जाती है कि बार-बार पूछने पर भी जवाब मिलता है कि पता नहीं लगता और बाद में कहा जाता है कि यह कॉन्फिडेन्शियल है, सीक्रेट है । अगर यह रिपोर्ट सामने आ जाय तो पाकिस्तान की जैसी हालत हो जायगी, हमारे सिक्रेट्स के पता लगाने की ओर देश को बहुत भयंकर खतरा महसूस हो जायगा । यह तो बहुत बड़ी सिक्रेट है । क्या सिक्रेट है ऐसी ? मैंने सुना है, उपाध्यक्ष महोदय, वह संकट इस प्रकार का है कि उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा है कि ऑइल और दूसरे सामान को खरीदने का तरीका आज तक अख्तियार किया गया है, और यह शायद एक-डेढ़ साल से पहले की रिपोर्ट है, गलत है, गैरवाजिब है, इससे भ्रष्टाचार हुआ है और इससे कम से कम सरकार को ४५ लाख रुपयों का नुकसान हुआ है । अब जब कि सरकार को यह सूचना मिल चुकी, अपने अधिकारी द्वारा मिल चुकी कि ऑइल की खरीद में, सामान की खरीद में और मीटरों इत्यादि की खरीद में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पाँच हजार से ज्यादा का सामान हो तो उसकी मंजूरी सरकार से लेनी पड़ती है और शायद उच्चाधिकारी से लेनी पड़ती है । उसके ऑर्डर को स्प्लिट करके हर दो महीने में सात सौ, पाँच सौ रुपयों का सामान खरीदा गया है । उस ऑर्डर को स्प्लिट किया गया है; ऐसी शिकायत सुनी है कि श्री यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट में वह मौजूद है । तो माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार के अपने विभाग के इन्तजाम की यह हालत है; स्टोर्स के अकाउन्ट नहीं, बिजली का वेरिफिकेशन नहीं । सरकार ने जाँच कराई तो पता चला कि ४५ लाख रुपयों का घाटा है । जनता से बिजली की युनिट की कीमत ज्यादा चर्ज होती है और उसके साथ-साथ महकमे का घाटा अलग चलता है और अलग-अलग बिजलीघरों में चोरियाँ रोज होती हैं इसलिए कम से कम दस पर्सेन्ट रिडक्शन हो सकेगा, ऐसा मान कर मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे मन्त्री महोदय को मान लेना चाहिए । इतना ही मुझे इस कटौती के प्रस्ताव में कहना है, माननीय उपाध्यक्षजी ।

श्री उपाध्यक्ष—दूसरे कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी बता दें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—(Economy-retrechment of engineers)

जैसा कि आदेश मिला है इकोनोमी के सिलसिले में दूसरा कटौती का प्रस्ताव है, उस पर भी मुझे जो अर्ज करना है वह अभी अर्ज कर दूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो कट मोशन मैंने रखा है उसका आशय यह है कि इन्जिनियरों की तादाद जो जरूरत से ज्यादा है उसको कम किया जाय । यह मानते हुए कि टैक्निकल ज्ञान मेरे पास बहुत कम है, फिर भी मैंने सरकारी आँकड़ों से इसे अध्ययन करने की कोशिश की है । उन आँकड़ों के मुताबिक जोधपुर में जो बिजलीघर है वहाँ जितनी किलोवाट बिजली पैदा होती है उसकी मात्रा जयपुर से कुछ ही कम है......

(श्री अध्यक्ष १२ बजे पुनः पदासीन)

लेकिन वहाँ एक सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर है और दो असिस्टैंट इन्जीनियर हैं । इस तरह से कुल मिलाकर वहाँ पर इन्जीनियरों की संख्या तीन और चार से ज्यादा नहीं है और वहाँ जो इंजीनियर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

काम करते हैं वे ठीक करते हैं। वहाँ की जनता को किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, जिससे यह जाहिर होता है कि उनका काम ठीक है। लेकिन जब जयपुर के बिजलीघर में इन्जीनियरों की तादाद को देखते हैं तो वह तादाद अचानक बढ़ी हुई नज़र आती है और यह मान ा कि यहाँ वाटर वर्क्स का महकमा बिजलीघर के मातहत है फिर भी एक दो इन्जीनियरों की बढ़ती हो सकती है, लेकिन जयपुर के पाँवर हाऊस में इन्जीनियर की संख्या जोधपुर से तीन गुणा अधिक है। यहाँ इतनी ज्यादा तादाद क्यों है? बीकानेर में इन दोनों की बीच की हालत है। बाकी के स्टाफ की भी वही हालत है। जोधपुर में वर्क्स की संख्या ज्यादा है और जयपुर में कम, फिर भी यहाँ इन्जीनियरों की संख्या ज्यादा है। वहाँ इतनी ज्यादा संख्या क्यों है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यह देखकर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि स्टेन्डर्डाइजेशन ऑफ वर्क केवल छोटी तनख्वाह पानेवालों तक ही सिमित रहता है, ऊँची तनख्वाह वालों के लिए कोई भी वर्क की सीमा नहीं है। इसलिए जोधपुर के कार्य को देखते हुए जयपुर के इन्जीनियरों में दो तिहाई की कमी हो सकती है और बीकानेर से एक चौथाई इन्जीनियरों की कमी की जा सकती है। इसी आशय से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रक्खा है। उम्मीद है कि सदन इस पर अवश्य सम्मति प्रदान करेगा।

श्री अध्यक्ष—Have you moved all your cut-motions ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was ordered to move only those cut-motions which relate to economy, and the rest were to be taken after the economy cuts have been disposed of.

श्री अध्यक्ष—So you move other also.

श्री हरिकृष्ण व्यास—At this moment, Sir.

श्री अध्यक्ष—Yes, but you have taken more than 20 minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the original order was different, otherwise I would have moved all of them together. I was told to move the economy cuts first.

श्री अध्यक्ष—You now go on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—1. "That the Demand No. XXVII relating to XLI Receipts from Electricity and 52- Interest etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss Government's letting the Jodhpur Power House deteriorate to a dangerous condition.)"

2. "That the demand No. XXVII relating to XLI- Receipts from Electricity and 52 - Interest etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the failure to recover dues from rulers)."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

3. "That the Demand No. XXVII relating to XLI—Receipt from Electricity and 52—Interest etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the failure in rooting out corruption in the matter of purchase and disposal of stores)."

4. "That the demand No. XXVII relating to XLI—Recipts from Electricity and 52 - Interest etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discess the failure of the Government to concede the demands of its employees)"

5. "That the demand No. XXVII relating to XLI—Receipts from Electricity and 52-Interest etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the failure to get its stores and stocks physically verified)."

6. "That the demand No. XXVII relating to XLI—Receipts from Electricity and 52-Interest etc. be reduced by Rs. 1000/-(to discuss the failure in preparing a profit and Loss Account)."

7. "That the demand No. XXVII relating to XLI—Receipts from Eletricity and 52-Interest etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the gross negligence in regard to protection of its staff from accidents)."

8. "That the Demand No. XXVII relating to XLI—Receipts from Electricity and 52-Interest, etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the highly preferential concession given to the National Bearing Company, Jaipur)."

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे जितने भी कटौती के प्रस्ताव हैं उनको प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, इनमें सबसे पहले जिसका जिक्र करना चाहता हूँ वह एक ऐसी चीज़ है जिससे सरकार की काफी बचत हो सकती है; वह है जयपुर में एक कम्पनी जिसको नेशनल बॉल बियरिंग के नाम से पुकारा जाता है और जिसके अधिष्ठाता है श्री घनश्यामदासजी बिड़ला। सरकार इस कम्पनी को एक विशेष रियायत दे रही है जिसके विरोध में राय व्यक्त करने के लिए कटौती का प्रस्ताव रखा है। सबसे पहले मैं इस सिलसिले में बताऊँ कि दूसरे-दूसरे पॉवर कन्ज्यूमर्स को दो आना, तीन आना प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और शहर के लोगों को ६ आना यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और इस कम्पनी को ६ पाई प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है। यह जो पॉवर सप्लाई की सहूलियत दी गई है मैंने ऐसा सुना है कि इस विषय का कोई एग्रीमेंट हो रखा है जयपुर गवर्नमेंट के जमाने का या राजस्थान गवर्नमेंट के जमाने का। वह एग्रीमेंट किन शर्तों पर हुआ उसकी तफसील से तो मुझे जानकारी नहीं और न वे शर्तें आज तक हमारे सामने आई हैं, लेकिन यह जरूर है कि इसकी वजह से लाखों रुपये का सालाना नुकसान राजस्थान सरकार को रहा है। एक तरह से इस नुकसान का भार जनता का उठाना पड़ रहा हैं। एक तरफ तो बेचारे जो दिन रात के कन्ज्यूमर्स हैं उनको तो आप बिजली महंगी दे रहे हैं और उधर एक बहुत बड़े उद्योगपति को रियायती रेट पर बिजली दे रहे हैं, यह एक कितनी दुख की बात है। यदि आप लोकल कन्ज्यूमर को बिजली सस्ती देते तो सदन के किसी भी मेम्बर को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन रियायत किनको दी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जाती है, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिनके हिन्दुस्तान में कई कारखाने चल रहे हैं। इस तरह से आम लोगों पर उसका बोझ पड़ता है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव जो है उसके सपोर्ट में मैं पहले ही काफी निवेदन कर चुका हूँ।

तीसरी जो कटौती का प्रस्ताव जो है वह है इस विभाग के मुलाजिमों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके बारे में। इसी बात को साबित करने के लिए मैं जयपुर के बिजली घर की एक मिसाल, जो पिछली साल जुलाई और अगस्त के महीने या समझ लीजिए कि सितम्बर की शुरूआत में इन तीन महिनों में चार मुलाजिम इस बिजली की वजह से मारे गये, रखता हूँ। चार आदमियों की मृत्यु हो गई। कारण इसका यह था कि इनमें से दो को मना करने के बावजूद भी, बिजली के खम्भों पर चढ़ने का आदेश दिया गया। जिस समय ये लोग खंभोंपर चढ़े उस समय जितने प्रोटेक्शन (रक्षा-साधन) की आवश्यकता थी वह नहीं दिया गया; जैसे इन्सूलेटिंग मेटीरियल, रबड़ आदि का जो प्रबन्ध करना था वह नहीं किया गया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद जो इसकी जाँच की गई, वह जैसी होनी चाहिए थी वह जाँच नहीं हुई। आज तक भी ऐसे जो काम करते हैं उनको प्रोटेक्टिव मेटीरियल देने का इन्तजाम नहीं किया गया।

दो आदमियों की कूओं में उतरने में मृत्यु हुई। उनको उतरने का आदेश देने के पहले उसके लिए कोई प्रिकॉशन्स (precautions) नहीं लिए गये। इस प्रकार वे व्यक्ति प्रोटेक्शन्स के अभाव में मर गये। यह है बिजली विभाग के अधिकारियों का वहाँ के कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार का नमूना।

दूसरी खेद-जनक बात मैं और आपके सामने रख रहा हूँ। अभी-अभी इन कर्मचारियों का संगठन राजस्थान बिजली घर फेडेरेशन के नाम से है। जब सरकारी अधिकारियों ने घोषणा की कि हम तुम्हारे लिए प्रोवीडेण्ट फंड की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन १८ और २० साल से जो काम कर रहे हैं, जिनकी १८ और बीस साल की सर्विस हो चुकी है, जिनको एक या दो साल बाद ग्रेचुएटी या पेन्शन के अधिकार मिलने वाले हैं, अब जब कि उन पर प्रावीडेण्ट फंड लागू किया जायगा तो उनको बेचारों को १५–२० साल जो सर्विस की है उसका तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं और सिर्फ दो-तीन साल का प्रोवीडेण्ट फंड उनको मिल सकता है। यह उनके लिए कितनी बुरी बात होगी कि जो व्यक्ति २० साल से नौकर था और कुछ साल के बाद जब वह रिटायर हो जायगा तो उसको केवल इतने से प्रोवीडेण्ट फंड के पैसे दे दिये जाँय। जब यह बातें सरकारी अधिकारियों के समक्ष रखी गई तो उनको जवाब मिलता है कि इसके लिए कानून में कोई गुँजाइश नहीं है, लेकिन फिर जोर लगाया गया तो आखिरकार यह जवाब मिला कि इस बारे में अकाउन्टेन्ट जनरल को पूछा जायगा इत्यादि। पूछने की बात कहकर एक प्रकार से उन कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। जिस आदमी को नौकरी में लेते वक्त आपने जो शर्तें उनसे की थीं, उनके साथ भी किसी प्रकार का वादा था, वे भी किन्हीं नियमों के अनुसार लिये गये थे; आज जब उनकी २२ साल की

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सर्विस हो चुकी है तो आप उनको जो सहूलियतें भरती होते वक्त मिल रही थी उनसे उनको क्यों वंचित किया जाता है ? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने राजप्रमुख, उपराजप्रमुख और राजाओं के साथ जो वायदे किये हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते और दूसरी तरफ आप बेचारे गरीब मजदूर लोगों के साथ, जिनके साथ भी आपने कुछ वादे किये थे वे आज तोड़ते वक्त आपको कुछ भी ख्याल नहीं आता। जब आपके द्वारा राजप्रमुख, महाराजप्रमुख के वादों को सुरक्षित रखा जाता है तो क्या वजह है कि इस मजदूर वर्ग के साथ अपने जो वादे किये उनको आप क्यो तोड़ रहे हैं ? जब आप महाराज प्रमुख के लिए एक प्राइवेट सेक्रेटरी, जो १५००) रुपये लेता है उसको नहीं बदल सकते तो इन बेचारे ५०) और ६०) रुपये पाने वाले गरीब कर्मचारियों के साथ जो वायदा किया था उसका क्यों पालन नहीं किया जाता। मेरा कटौती प्रस्ताव पेश करने का यही आशय था और मेरी सदन से प्रार्थना है कि इस कारण मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए।

बाकी जो कुछ भी कटौती के प्रस्ताव हैं उन पर न बोलकर वे सदस्यों की जानकारी और उनकी अक्लमन्दी के भरोसे छोड़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष—We take all the cut-motions as moved.

श्री भैरूँसिंह (१६)—(That the Demand for Grant No. XXVII, Major Head 52- Interest on capital outlay etc., be reduced by Re. 1/-(to discuss the inefficiency of the department and failure of the Government in making proper electric arrangements in Sikar).

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपना कटौती का प्रस्ताव रक्खा है उसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान सरकार द्वारा सीकर जिले में बिजली का उचित प्रबन्ध न करना।

अध्यक्ष महोदय, आज चारों तरफ से इस तरह की आवाजें सुनने में आ रही है कि राजस्थान में भाखरा डेम से और चम्बल डेम से सारे राजस्थान के क्षेत्रों में बिजली पहुँचाई जावेगी, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह योजना इस प्रकार की हो सकती है कि सीकर डिस्ट्रिक्ट को भाखरा डेम से कवर कर लिया जावेगा परन्तु काम की प्रगति के आधार पर यह कह सकता हूँ कि यह योजना महज कागजों तक ही सीमीति रहेगी। इसको कार्य रूप में परिणत करना राजस्थान सरकार के लिए बिल्कुल असम्भव सी ही बात होगी।

आज हम यह कह सकते हैं कि कलकत्ता और बम्बई या और भी अन्य देश के भाग, जिनमें मारवाड़ी हैं और जिनके आधार पर बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे और देश का बहुत बड़ा व्यापार और उद्योग धन्धे चलाये जा रहे हैं, उनमें से अधिकतर बड़े-बड़े व्यवसायी इसी सीकर जिले के निवासी हैं। जब इस विषय में उनसे बात-चीत की जाती है कि जब आप देश के अन्य प्रान्तों को अपने व्यापार, कुशल-बुद्धि से और अपने उद्योग-धन्धों से समृद्ध कर रहे हैं तो अपने मातृभूमि स्थान, इस राजस्थान में भी व्यापार-धन्धे क्यों नहीं जारी करते, जिससे यह पिछड़ा प्रान्त भी समृद्धि

[श्री भैरूँसिंह]

की ओर अग्रसर हो; आप इसी अपनी मातृभूमि में पैदा हुए हैं और इसकी ओर भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान दें। तो उनकी ओर से यही आवाज हमें सुनने को मिलती है कि सीकर और झुँझुनू या उसके आसपास के इलाके में बिजली का प्रबन्ध न होने के कारण से हम कोई भी व्यापार या इसी प्रकार के उद्योग-धन्धे आदि यहाँ नहीं चला सकते; जिसके कारण लोगों को कारबार भी मिल सके, सुख और सुविधा भी प्राप्त हो और इसके अतिरिक्त और भी अन्य सामग्रियाँ प्राप्त हो सकें। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की योजना की बात जब उनके समक्ष रक्खी जाती है तो वे स्पष्ट कहते हैं कि यह योजना महज कागजों में ही सीमित है, यह राजस्थान सरकार इतनी समर्थ नहीं है कि इसे कार्यान्वित कर सके। इस योजना में सीकर जिला कवर नहीं हो सकेगा। सीकर में एक इलेक्ट्रिक कम्पनी इस समय भी है पब्लिक की तरफ से और इसमें सीकर ठिकाने के सबसे ज्यादा शेयर (Share) हैं। पर जिस वक्त से कम्पनी काम कर रही है तभी से लगातार सीकर की जनता को शिकायत रही है कि इस कम्पनी के द्वारा सीकर में बिजली की सुविधा का सीकर की जनता विशेष रूप से फायदा नहीं उठा सकती। इसके विरोध में इस बिजली कम्पनी की धाँधलीबाजी के विरोध में और इसकी घोर अव्यवस्था के खिलाफ वहाँ की जनता ने कई बार हड़तालें कीं, आम सभाओं में इसके विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किये, सरकार से कई बार निवेदन किया गया, राजस्थान के उच्च अधिकारियों से, मन्त्रियों से भी मिले और उन सबसे यही आश्वासन मिलता रहा कि जब भाखरा योजना से बिजली मिलने की योजना सफलीभूत हो जावेगी तो उस वक्त सीकर को उसका फायदा अवश्य मिलेगा और यदि इस योजना से सीकर का एरिया कवर नहीं होगा तो दूसरी योजना बनाई जावेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमें चिन्ता यह है कि हमारा जितना भी मारवाड़ी समाज है, जो दूसरे-दूसरे प्रान्तों में व्यापार कर रहे हैं और अपनी व्यवसायिक-बुद्धि-कौशल से उन प्रान्तों को समृद्धिशाली बना रहे हैं और वहाँ के लगभग सभी प्रमुख व्यवसायों को अपने नियन्त्रण में ले रक्खा है, वे जरा अपनी तवज्जो राजस्थान की ओर दें और उन लोगों के लिए कुछ रोजगार और धन्धों का प्रबन्ध करें, जो आवारों की तरह इधर-उधर भटक रहे हैं; पर उनकी विवशता बिजली के अभाव के कारण ऐसी है जिसकी ओर सरकार उचित ध्यान नहीं दे पा रही है। आज सैकड़ों की तादाद में हमारे राजस्थानी भाई जो इतने बड़े-बड़े व्यवसायी नहीं हैं वे नौकरियों की फिराक में बम्बई, कलकत्ता और दूसरे-दूसरे बड़े-बड़े नगरों में इन व्यवसायियों के आश्रित होकर पड़े हैं। वे बड़ी तादाद में मिलेंगे और जिनमें से बहुत से सीकर डिस्ट्रिक्ट के निवासी भी हैं। लेकिन एक ही कारण से इन सब लोगों के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम इनके लिए उद्योग-धन्धों के लिए यहाँ व्यावस्था नहीं कर सकते और आजकल के मशीनरी के युग में इन उद्योग-धन्धों के लिए बिजली का होना अनिवार्य है और इसके अभाव में सीकर में कोई व्यवसाय चालू नहीं कर सकते। सीकर ऐसी जगह है कि जहाँ इस प्रकार की सुविधाएं अगर प्रदान की जावें तो सीकर ही नहीं उनके कारण सारे राजस्थान के लिए इस प्रकार के उद्योग धन्धों का काफी विस्तार हो सकता है। इस विषय में माननीय मन्त्रियों से डेपुटेशन भी मिले और जब डेपुटेशन लेकर आये और बात-चीत की तो महज आश्वासन देकर बात टाल दी गई, कह दिया गया कि हम जल्दी से जल्दी

[श्री भैरूँसिंह]

विचार कर रहे हैं इस पर । जब कि हम दूसरे शहरों में सुने रहे हैं कि सरकार पॉवर हाउस के लिए मदद भी दे रही है तो सीकर के विषय में जब हम कोई मदद नहीं दिये जाने की बात सुनते हैं माननीय अध्यक्षजी, तो हमें बड़ा खेद होता है । अभी-अभी भी चर्चा चली थी तो अभी भी कह दिया गया कि म्युनीसिपैलिटी अपना खर्चा सारा का सारा बर्दाश्त करके, भाखरा डेम की योजना के प्रारम्भ होने तक, यह पॉवर हाउस चलाना चाहे तो चलाए और अगर योजना सफल हुई तो ठीक ही है, नहीं तो फिर सरकार कोई और योजना के बारे में सोचेगी । पर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास इतना धन नहीं है कि सीकर के पॉवर हाउस को वह अपने कब्जे में ले सके और सरकार को यह निवेदन मुझे करना है कि वह अगर इसके लिए कुछ आर्थिक सहायता सीकर को दे तो इस प्रकार की योजना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह होता कि जिस प्रकार सरकार द्वारा दूसरे पॉवर हाउसेज़ को मदद दी जाती है, उसी प्रकार की मदद भी हमें दी जाती और इतनी दी जाती कि सीकर में ही बिजली का प्रबन्ध हो, ऐसी बात नहीं; पर आसपास लक्ष्मणगढ़, रामपुर, दाँतारामगढ़ आदि तक बिजली सप्लाई की जाती और इसके साथ-साथ काफी सारे उद्योग-धन्धे भी चालू हो सकते और इन उद्योग-धन्धों के लिए सीकर और झुँझुनू के रहने वाले लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, तो अच्छा रहे । जितनी बेकारी की समस्या वहाँ है उसके लिए उद्योग-धन्धों की योजना के लिए जितना पैसा चाहिये उतना लगाने को वे तैयार हैं। पर जब सरकार की ओर से जरा सा भी सहयोग इसके लिए नहीं मिलता, तो मजबूरी आ जाती है।

जिस प्रकार कि दूसरी जगह सहूलियतें देकर मारवाड़ियों के पैसे का उपयोग किया जाता, है उसी तरह अगर इस पैसे का उपयोग हमारी सरकार को लेना है तो सीकर डिस्ट्रिक्ट के मारवाड़ियों से वे अपील करें कि कम से कम वे अपनी मातृभूमि होने के नाते अपने इस पैसे का कुछ सदुपयोग करें और इसके लिए सरकार उसको कुछ सहूलियतें अवश्य दे । यह हो सकता है कहने को कि यह विचारधारा संकुचितता लिये हुए हो पर इस विचारधारा में से कोई आदमी अपने ही स्थान पर बढ़े और यदि व्यवसाय और उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान देकर वहाँ के लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए कुछ किया जाता है तो यह संकुचितता नहीं होगी, बल्कि उपयोगी व्यवसाय बढ़ाने के लिए एक अपील होगी ।

अभी-अभी एक मन्त्री महोदय का वहाँ दौरा हुआ । उस वक्त सारे शहर की जनता ने वहाँ के पॉवर हाउस के खिलाफ हड़ताल की थी, सार्वजनिक सभाएँ की थीं । राजस्थान सरकार के पास अपील लिखकर भेजी गई उसके प्रबन्ध के खिलाफ, पर जब मन्त्री जी का दौरा हुआ तो उस एक दिन के वास्ते पॉवर हाउस ने सारे शहर में लाइट कर दी । इससे माननीय मन्त्रीजी को सन्तोष हो गया । हमने सोचा अगर थोड़ा बहुत काम और किया जावे तो यह १५-२० रोज और चालू रह सकता है पर इसके बाद जैसे ही मिनिस्टर साहब वापिस रवाना होते हैं कि शाम को शहर में देखा जाता है तो वही अन्धेरा था । लोगों को इससे फौरन यह खयाल हुआ कि इसको महज इस वास्ते आज चालू किया गया है और शहर में बिजली इसलिए आज एक दिन के लिए चालू की गई है कि

[श्री भैरूँ सिंह]

यह पॉवर हाउस चालू अवस्था में है, यह बता दिया जावे उन मिनिस्टर साहब को और इसके कारण थोड़ी मदद सरकार से मिल सकती है, वह भी न मिले; पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मन्त्रीजी को यह बताना चाहता हूँ कि यह पॉवर हाउस अब बिल्कुल बेकार है, इस पर आप चाहे जितना रुपया खर्च कर दीजिये पर इसको ज्यादा दिन नहीं चलाया जा सकता।

इसका तो प्रबन्ध यही हो सकता है कि या तो राजस्थान सरकार इसे अपने कब्जे में ले ले और अगर नहीं ले तो इतना धन एकत्रित कर दे कि सारी मशीनें नई खरीद कर चालू की जावें। इसका तो सारा का सारा ही प्लान्ट खराब है और इसमें क्या चीज़ उपयोगी हो सकती हैं, इसकी जाँच किसी अच्छे इन्जीनियर से करा लें और फिर सौदा करना ठीक हो सकता है। अगर यह सब म्युनीसिपैलिटी के ज़रिये काम कराया जावे और रकम की मदद दे दी जावे तो इसमें कामयाबी हो सकती है और इसी कारण मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री चाँदमल मेहता—[To discuss the failure of the Government in providing sufficient sum for the Kishangarh Power House) अध्यक्ष महोदय, मैंने भी किशनगढ़ पॉवर हाउस के सम्बन्ध में कटोती प्रस्ताव रखा है। किशनगढ़ का पॉवर हाउस सन् ५० में सरकार के अधिकार में आया था। इस पॉवर हाउस के सरकार के अधिकार में आने के बाद में इसमें कितनी बढ़ोती हुई, कितना वह आगे बढ़ा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ। जहाँ जनता को फ्लेट रेट चार्जेज़ १ या १॥ रुपये के हिसाब से देना पड़ता था तो आज लाइट चार्जेज़ के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक २-२-२॥ रुपया देना पड़ता है। कनेक्शन फीस और टेस्टिंग फीस (Connection and testing fees) दोनों मिलाकर ७ रुपये देने पड़ते हैं; जबकि पहले सिर्फ २) देने पड़ते थे। जहाँ जनता को फ्री ऑफ चार्ज लाइन दी जाती थी, वहाँ पर स्थिति यह है कि ५० फुट से ज्यादा लाइन देने पर उनसे उसके पैसे चार्ज किये जाते हैं और उस लाइन पर मालिकाना हक पॉवर हाउस का माना जाता है। यह तो हुई जनता की कठिनाइयाँ। जहाँ तक जनता को सुविधा पहुँचाने का सम्बन्ध है वहाँ की स्थिति यह है कि १५-१५ दिन तक के लिए बिल्कुल लाइट नहीं मिलती है और कई बार ऐसा मौका आता है कि कभी इतनी तेज लाइट होती है कि जिससे रेडियो के बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं और कभी लाइट इतनी डिम होती है कि पढ़ भी नहीं सकते। इन सारी चीजों के बाद सरकार की स्थिति आर्थिक दृष्टि से यह है कि सरकार को २५-३० हजार रुपये का घाटा देना पड़ता है। अभी हमारे सामने बजट आया है उसमें ५३–५४ के बजट में खर्च किये हुए मद में जो नये आइटम बतलाये गये है उसमें ४७ हजार हैं। उसमें एक एन्जिन २५ हजार का नया खरीदा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पॉवर हाउस में सही मायने में कोई नया एन्जिन नहीं खरीदा गया है बल्कि जो एन्जिन अन्य स्थलों पर खारिज हो गये या बेकार हो गये हैं और जिन एन्जिनों को शायद वहाँ स्थान नहीं मिला है तो उन्होंने देख लिया हो कि ऐसे एन्जिन किशनगढ़ में भेज दिये जाँय, वहाँ पर पर्याप्त जगह हैं इनको रखने के लिए। २५०००)

[श्री चाँदमल मेहता]

रुपये किशनगढ़ पॉवर हाउस में नये एंजिन के खरीदने में जो बताए गए हैं सम्भव है दूसरे स्थानों से आये हुए पुराने एन्जिनों का मूल्य हो और नया एन्जिन दूसरी जगह खरीदा गया हो। दूसरा नया आइटम ५३-५४ में जो खर्च बताया गया है वह है १५ हजार रुपये का। जिसके बारे में यह बताया गया है कि यह पुराने एन्जिन की मरम्मत के लिए खर्चा किया गया है। अगर आप देखेंगे कि १५ हजार रुपये एक एन्जिन की मरम्मत के लिए खर्च किये जायेंगे तो बहुत गलत बात होगी, उससे दुगुनी कीमत में तो एक नया एन्जिन खरीद सकते हैं। मरम्मत के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि मरम्मत करके ज्योंही उस पर लोड डाला गया तो वह एन्जिन बर्स्ट हो गया, वह खत्म हो गया। इस प्रकार १५ हजार रुपये बेकार हो गये। तो इस तरह से ५३–५४ के वर्ष में ४७ हजार की मद रखी गई है, लेकिन सही मायने में किशनगढ़ पॉवर हाउस में वृद्धि नहीं की गई है। इससे जनता की कठिनाइयाँ बढ़ी हैं, सरकार की कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। वहाँ जनता की सुख-सुविधा के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा ५४–५५ के बजट में एक पैसे का भी प्रोवीजन नहीं रखा गया है।

घाटे की पूर्ति के लिए नये साधन भी निकाले गये हैं। वह साधन यह हैं कि वहाँ कुछ कर्मचारियों की जगह खाली रखी जाती है, ३–४ कर्मचारियों की जगह खाली हैं और एक्स्ट्रा काम दूसरे आदमियों से लिया जाता है और उनको इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। पहले तो ओवरटाइम एलाउन्स मिलता था, लेकिन अभी दो एक आदमियों का ओवर टाइम एलाउन्स बन्द कर दिया गया है। उन कर्मचारियों को जिनको कि वीकली (साप्ताहिक) अवकाश मिलना चाहिए, वहाँ चपरासी को साप्ताहिक अवकाश बन्द कर दिया गया है। इस तरह वहाँ के कर्मचारियों की कठिनाइयाँ भी बढ़ी हैं।

अभी वहाँ सिर्फ एक एन्जिन काम कर रहा है। उसके बारे में भी यह खतरा है कि किसी भी टाइम वह एन्जिन बर्स्ट हो सकता है और वहाँ पॉवर हाउस बन्द हो सकता है।

एक फिर तरक्की की है और वह है वहाँ के इन्जीनियर साहब के व्यवहार के सम्बन्ध में। यह एक ऐसा महकमा है कि वहाँ पब्लिक के आदमी आते हैं, लेकिन वे हुकूमत के मद में इस तरह से मस्त रहते हैं कि वे प्रत्येक आदमी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। एक बहुत बड़े आदमी के बारे में निवेदन करूँगा कि माननीय मुख्य मन्त्री के निवास स्थान में बिजली लगवाने के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी जाता है तो उसके साथ भी जैसा व्यवहार किया है वह आमतौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर हमारे इन्जीनियर साहब कहते हैं कि मैंने कितने बड़े आदमी के साथ कैसा व्यवहार किया है, मैं कैसा बोल्ड (bold) आदमी हूँ। यह उनके व्यवहार की बात है।

माननीय अध्यक्ष, जिस हद तक कठिनाइयाँ आगे बढ़ रहीं हैं और जिस हद तक सरकार को नुकसान हो रहा है तो उन को आगे बढ़ने से रोकिये और ५४–५५ के बजट में ऐसा प्रोवीजन रखिये कि जिससे यह पॉवर हाउस तरक्की कर सके। बेकार एन्जिन जो ४–५, कोटा, उदयपुर, अलवर से आये हुये हैं, पुराने ३–४ साल से पड़े हैं, तो सरकार इन इंजिनों को डिस्पोज़ ऑफ कर दे, और इन एन्जिनों से मेरा ख्याल है १ लाख रुपया आ जायगा। इससे जो पैसा मिले

[श्री चाँदमल मेहता]

उनकी कीमत से नया एन्जिन खरीद कर इस तरह से किशनगढ़ की जनता को सुविधा पहुँचाने की कृपा करें ।

श्री मानसिंह महार—मेरा कटौती प्रस्ताव तो नहीं है । इसके सपोर्ट में बोलना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—एक और मूव हो जाने दीजिये फिर उसके बाद में बोलिए । श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—माननीय अध्यक्ष, my cut-motion is, "to discuss the failure on the part of the Government to electcrify Rajgarh and Bandikui towns".

अध्यक्ष महोदय, बान्दीकुई अपने राजस्थान में सबसे बड़ा रेलवे जंकशन है और साथ ही उसकी आबादी १२-१३ हजार के करीब है। बाँदीकुई में बिजली सप्लाई किये जाने के बारे में वहाँ जनता की ओर से एक लम्बे अरसे से माँग की जा रही है । आशा तो की जाती थी कि निकट भविष्य में वह पूरी की जा सकेगी । राजस्थान सरकार यदि अपने सामान्य खर्चे को नॉर्मल बजट में उसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं कर सकती थी तो समझ में आने की बात थी कि इतने बड़े डिपार्टमेंट के मेन्टीनेन्स का खर्चा सरकार को चलाना पड़ता है, इतने बड़े खर्चे की तरफ तवज्जह देनी पड़ती है; बाँदीकुई कस्बे के अन्दर पावर हाउस लगाने में रुपये की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यहाँ के पावर हाउस के लिए और बिजली की सप्लाई के लिए करोड़ों रुपये राजस्थान सरकार को उसी काम के लिए अलग दिया गया है तब मैं यह नहीं समझ सकता हूँ कि बाँदीकुई और बसवे जैसे कस्बों के लिए राजस्थान सरकार बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझती । मैं यह कहता हूँ कि बाँदीकुई कस्बे के २ भाग हैं, एक भाग रेलवे कोलोनी है और एक है स्टेट कोलोनी, माधोगढ़। राजाशाही के जमाने से उस कस्बे का वह हिस्सा जो रेलवे कोलोनी कहलाता है वहाँ करीब-करीब सारी सुविधाएँ और एमिनिटीज़ सिविक लाइफ (amenities of civic life) की जो होनी चाहिये, वह हैं । वहाँ बिजली भी है, नल भी हैं; और जब कि उसके मुकाबले में यहाँ देखते है जो स्टेट कोलोनी हैं, और जिसके लिए जिम्मेवरी राजस्थान सरकार की है, न बिजली की व्यवस्था है और न सड़क की । सारी एमिनिटीज़ में बराबर के कस्बे के मुकाबले में पिछड़े हुए हैं तो बड़ी दिक्कत महसूस करनी पड़ती है । एक ही कस्बे के एक भाग में जिसकी जिम्मेवरी केन्द्रीय सरकार पर है वहाँ की जनता के लिए तो सरकार सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है और सारी बातों को उपलब्ध करती है, लेकिन जिसके शासन की राजस्थान सरकार की जिम्मेवरी है वहाँ बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है, न सड़क जैसी होनी चाहिये वैसी है ! मैं यह कहना चाहूँगा कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन, कमी, अनुभव होती है मुकाबला करने पर । वह ख्याल करने की बात है सब लोगों के ।

फिर मैं यह कहना चाहूँगा कि पंचवर्षीय योजना में हिन्डौन से दौसा को शायद बिजली की लाइन ले जा रहे हैं वह बाँदीकुई से ६ मील दूर होकर सिकन्दरा की सड़क के पास होकर जा

[श्री बिशम्भरनाथ जोशी]

रही है। मेरे निवेदन करने का मकसद यह है कि वह लाइन सिकन्दरा से राजगढ़ को एक्स्टेन्ड की जा सकती है और यह विजिब्ल प्रोपोजिशन (visible proposition) है। सरकार का पूरा खर्चा भी निकल जायगा। वहाँ कन्ज़म्पशन (Consumption) बिजली का इतना है कि जिससे किसी तरह के घाटे का सवाल सरकार के लिए नहीं रहेगा। रास्ते में सिकन्दरा के कस्बे को भी पूरी बिजली दी जा सकती है जो कि ६–७ हजार की आबादी का कस्बा है। बाँदीकुई से सिकन्दरा होती हुई व राजगढ़ तक लाइन ले जा सकेंगे। जैसा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को पता होगा राजगढ़ का पॉवर हाउस एक प्राइवेट कम्पनी का पॉवरहाउस है और वह घाटे में चल रहा है। मेरा खयाल है कि ज्यादा लम्बे अरसे तक उसकी व्यवस्था नहीं चल सकती है और अन्त में सरकार यह फैसला करेगी और उसको सरकार को अपने नियन्त्रण में लेना पड़ेगा। तो सरकार इस बात को महसूस करेगी कि बिजली की लाइन राजगढ़ तक एक्स्टेन्ड की जा सकती है क्योंकि राजगढ़ को बिजली से महरूम रखना मुमकिन नहीं होगा। जिन घरों में कनेक्शन लिए हुए हैं, पॉवरहाउस जब बन्द हो जायगा तो अन्तिम उपाय सरकार को जरूर करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन करने का मकसद था और सरकार के सामने आर्थिक दृष्टि से बहुत ही प्रेक्टिकेब्ल और व्यवहारिक सुझाव है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान पहले से ही चला जाना चाहिये था। हिन्डौन से सिकन्दरा, बांदीकुई से बसवा होकर राजगढ़ तक कनेक्शन मिला देना चाहिये जिससे बसवा-सिकन्दरा, बसवा और बाँदीकुई सबों को बिजली दी जा सके और वहाँ के लिए यह एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है जिसकी कमी को लोग लम्बे अरसे से अनुभव कर रहे हैं; वह पूरी की जा सके। यह मैंने टोकन कट मूव किया था इस विभाग पर मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, बिजली घर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं जो इस बारे में खास चीज़ कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस विभाग के अन्दर सामान जो खरीदा जाता है और जिस प्रकार से अलग-अलग जगहों पर लगाया जाता है उसका कोई हिसाब इस विभाग के पास नहीं है कि कौनसा सामान कहाँ दिया गया है। मैं बिजलीघर के कुछ आदमियों से मिला और उनसे पूछा कि उनके यहाँ क्या हिसाब-किताब है तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के बड़े इन्जीनियर बड़े शरीफ आदमी हैं। मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? तो वे बोले कि हम सामान ले जाते हैं, यदि रास्ते में २-४ बल्ब टूट जाते हैं या उठा ले जाते हैं तो हमको वे कुछ नहीं कहते सिवाय इसके कि आयन्दा मत गुमाना और फिर दुबारा दे देते हैं। इस प्रकार से इस विभाग द्वारा राजस्थान की धन-राशि को बरबाद किया जाता है।

दूसरी बात यह है कि मेरे मित्र ने कटौती प्रस्ताव रखा है कि राजाओं को जो बिजली दी गई है उसकी कंपेन्सेशन फीस वसूल की जानी चाहिये। इस सिलसिले में कुछ खास बातें निवेदन करना चाहता हूँ, जो यह है कि बिजली घर में हिसाब ऐसा गोलमाल है कि दर असल में राजाओं को कितनी बिजली दी गई है, यह मालूम नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ से १८-२० मील की दूरी पर मेरी कॉंस्टिटुएन्सी का एक गाँव है जमुआ रामगढ़। उस गाँव में जयपुर रियासत के समय से बिजली लगी हुई है और रोज जलती है, मगर बिजली घर को २ वर्ष पहले

[श्री मानसिंह महार]

तक यह मालूम नहीं था कि इसका खर्चा कौन देने वाला है। वहाँ पर बिजली ७ वर्ष तक जलती रही और उसके बाद डिपार्टमेंट का ध्यान गया कि बिजली का पैसा आता है या नहीं; यदि नहीं देते हैं तो वहाँ का कनेक्शन काट दो और कनेक्शन काट दिया गया। गाँव वालो ने उनसे निवेदन किया कि बिजली का पैसा हमसे लिया जाय और बिजली दी जाय। तब वे कहते हैं कि ७ वर्ष से जो बिजली जल रही है और उसमें जो खर्चा हुआ है वह पहले जमा कराओ तब हम बिजली देंगे। गाँववालों को और पूछे वहाँ बिजली लगाई गई थी। जयपुर रियासत के समय यह काम हुआ था और अब कहते हैं कि पुराना खर्चा दो तो बिजली चालू करें। गाँववालों ने कहा कि अब से माहवारी खर्चा ले लो और बिजली जलने दो, हम इसके लिये तैयार हैं; लेकिन इस कस्बे की ऐसी हालत नहीं है कि १० वर्ष की बकाया तक दी जाय। लेकिन बिजलीघर वाले कहते हैं कि जब तक पुराना खर्चा नहीं दोगे तब तक नहीं चालू की जायगी। यदि इस मामले को ठीक कर दिया जाय तो बड़ी महरबानी होगी।

किशनगढ़ के पॉवर हाउस की बात कही गई। वहाँ के बिजलीघर के इंजिन को ठीक करने के लिये १५०००) रुपये नहीं लगावेंगे तो क्या २ या ४ हजार में ठीक होगा?

श्री चाँदमल मेहता—शायद आपको यह पता नहीं है कि नया इंजिन २७,०००) रु० में खरीदा गया है।

श्री मानसिंह महार—शायद छोटा इंजिन ले लिया होगा।

श्री चाँदमल मेहता—शायद आपको पता नहीं है कि किशनगढ़ बहुत बड़ी बस्ती नहीं है।

श्री मानसिंह महार—(भाषण जारी रखते हुए) बिजली घर की मरम्मत के लिये १५०००) रु० जरूरी नहीं है इसलिए वे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेलें तो अच्छा हो।

एक छोटीसी बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि आधी बाँदीकुई में बिजली है और आधी में अँधेरा है। इस बारे में मैं यह कहूँगा कि इस इलाके में दौसा तक बिजली पहुँच गई है और राजस्थान बहुत बड़ा है, इसमें कई इलाके ऐसे हैं जो बांदीकुई से ज्यादा महत्व रखते हैं। इसलिए मैं आपके जरिये यह कहूँगा कि जब आधे इलाके में बिजली है और बचे हुए आधे इलाके में कोई अपने प्रभाव के कारण बिजली ले जाने की कोशिश करे, तो उचित नहीं है। बांदीकुई कोई इतना इंपोर्टेन्ट टाउन नहीं है जहाँ किसी प्रभाव के कारण या असरवाले महाशय के कारण वहाँ पहले बिजली ले जाई जाय। जब तक बांदीकुई से अधिक इंपोटेन्ट टाउन्स में बिजली पहले नहीं दे दी जाय तब तक वहाँ बिजली नहीं देनी चाहिए।

श्री हजारीलाल शर्मा—क्या इससे अधिक इम्पोर्टेन्ट कस्बा अचरोल है?

श्री मानसिंह महार—आपका ध्यान सीमित है। अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई में ले जाने से पहले कई ऐसे कस्बे हैं जो पहले रियासतों की राजधानियें थीं और जो बिजली से बहुत दूर हैं, वहाँ पहले

[श्री मानसिंह मझार]

बिजली ले जाने की अधिक आवश्यकता है। बांदीकुई में इसकी कम आवश्यकता है। उसका कारण यह है कि आधी जगह में तो बिजली मौजूद है। कुल १२ हजार की आबादी वहाँ की बताई है उसमें से बिना बिजली के ३-४ हजार की आबादी रह जाती है। इतनी ही आबादी से ज्यादा आबादीवाले जो कस्बे हैं उन में पहले लगनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि पहले वहाँ न लगाकर किसी असरवाले महाशय के कारण राजस्थान सरकार पक्षपात करे। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम बाँदीकुई की बात मन्जूर नहीं की जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, श्री एच. के व्यास ने कोयले के बारे में जो कटोती प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में बोलना चाहता हूँ। राजस्थान के अन्दर करीब ४० लाख रुपये का कोयला सरकार सालाना खर्च करती है और दूसरे प्रान्तों में टेन्डर न लेकर डाइरेक्ट कोयले की खानवालों से कांट्रेक्ट किया जाता है। यू० पी०, सी० पी० में जितने पॉवर हाउस चलते हैं उनमें डाइरेक्ट कॉंट्रेक्ट करके कोयला मंगाते हैं और पॉवर हाउस में काम लेते हैं। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में हर चीज के लिये टेन्डर कॉल किया जाता है और जिसका टेन्डर लोएस्ट होता है उसका टेन्डर मन्जूर किया जाता है लेकिन कोयला डाइरेक्ट खानवालों से कॉंटेक्ट करके मंगा लिया जाता है। एग्रीमेंट में 'ए' क्वालिटी दिखाई जाती है और माल आता है बी. या सी. क्वालिटी का। राजस्थान सरकार जो कोयला खरीदती है उसमें कुछ लोग नाजायज स्वार्थ साधने के लिए 'ए' क्लास के टेन्डर के स्थान पर 'बी' क्लास का चला देते हैं। इसकी आज तक सरकार ने कोई जाँच नहीं करवाई है। तीसरी बात यह है कि उसमें कमीशन कितना मिलता है इसका किसी को ध्यान नहीं है, १ रु० फी टन के हिसाब से टेन्डर देनेवाले को कमीशन मिलता है। यह पता नहीं कि यह जो कमीशन टेन्डर देनेवालों को मिलता है उसमें से कितना कमीशन अफसरों की जेब में जाता है और टेन्डर देने वाले के पास कितना बचता है। इसकी यदि जाँच करावें तो आज ५ लाख रुपये की सालाना बचत गवर्नमेंट को हो सकती है। जितना सामान सरकार खरीदती है वह टेन्डर्स के जरिए खरीदा जाता है। दूसरे दूसरे प्रान्तों में अधिकतर माल भारत की स्टोर्स परचेज (stores purchaese) विभाग की मारफत खरीदा जाता है, उसी प्रकार हमको भी उक्त डिपार्टमेंट की मारफत खरीदना चाहिए। इसके विपरीत राजस्थान सरकार टेन्डर लेकर सामान खरीदती है और जिस तरह के सामान के लिए टेन्डर में वादा होता है उस तरह का सामान न आकर उससे घटिया किस्म का सामान आता है और उसका पेमेन्ट कर दिया जाता है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से टेन्डर मन्जूर हो जाता है। जब तक वे लोग इन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग शान्ति की तरफ नहीं जा सकेंगे और सरकार के पास जो अब पैसे की कमी हो रही है वह भी दूर नहीं हो सकेगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज तक बिजली घरों के स्टोर्स की कोई जाँच नहीं हुई है और न इसके लिए कोई पोस्ट मुकर्रर की गई है। पी. डब्ल्यू. डी. में जो स्टोर है उसका चेक करने के लिए एक अफसर नियुक्त किया गया है लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए राजस्थान में आज तक इसके स्टोर को चेक नहीं किया गया है। एक दिन हमारे मन्त्री महोदय साहब भी स्टोर चेक करने

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

पधारे थे और उन्होंने पूछा कि क्या आपका स्टोर चेक होता है या नहीं, तो जवाब मिला कि हमारे यहाँ ऐसी कोई पोस्ट ही नहीं है।

तो जिस बिजलीघर में स्टोर चेक नहीं होता हो वहाँ कितनी गड़बड़ी हो सकती है? उस बिजलीघर में कितनी तरह का कितना सामान आता है और कितनी तरह के सामान के कितने टेन्डर लिये जाते हैं, उनका क्या पता है? करोड़ों रुपयों का सामान आता व जाता है, उसका कोई पता नहीं। इसलिये सरकार से मैं निवेदन करूँगा कि इस बिजलीघर के स्टोर का चेकिंग होना चाहिये और सामान के लिये जो टेन्डर लिये जाते हैं वह टेन्डर न लिये जाकर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का जो स्टोर-डिपार्टमेंट है उसके द्वारा सामान लिये जाने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सरकार को काफी रुपयों का फायदा होगा।

आज हम इधर बैठने वाले आपको कुछ कहते हैं और आपको बुरा मालूम होता है, परन्तु अगर आप ऐसे काम करेंगे ही नहीं तो फिर कहने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? परन्तु जब खराब काम होते हैं तो चिल्लाते हैं और अगर आप यह समझते हैं कि चिल्लाते हैं तो हमारा क्या लेते हैं चिल्लाने दो, तो यह तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप याद रखिये कि एक वक्त आयेगा जब कि जनता आप से इन सब बातों का जवाब पूछेगी।

श्री अध्यक्ष—We now adjourn till 4.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Shall we meet today ?

श्री अध्यक्ष—Yes; today, tomorrow and day-after tomorrow. We shall have to meet both, during morning and evening. It depends upon the anxiety of the members to take part in the discussions.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We have select committee meeting in the evening.

श्री अध्यक्ष—Those who want to speak will speak and others may...

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—We have still two days more. We might have two sittings tomorrow and day after tomorrow.

श्री मानसिंह महार—खतम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—All right.

श्री मानसिंह महार—फिर भी खत्म नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—We will meet at four.

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३० मिनिट (मध्यान्होत्तर) पर सायं ४ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—२४ मार्च, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

Page No.95

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर देखिये)

(१) बागीडोरा (२) बढ़ोदिया (३) घाटोल (४) दानपुर (५) बड़वास (६) हमीरपुर (७) करजी (८) जोलाना (६) कोपड़ा भीलान (१०) कोपड़ा चमारान (११) बोरी भीलान (१२) बोरी शिवा (१३) बाड़ली पाढ़ा भीलान (१४) भारी (१५) बांसवाड़ा (१६) कुन्दला (१७) भामोर (१८) सरवण (१६) प्रतापपुर (२०) सियालदारी (२१) मालपुर (२२) बोखला (२३) गाँधी अहेड़ा (२४) भोहथरीमाल (२५) करावड़ा (२६) आसपुर (२७) गेंजी (२८) आमड़ी (२६) सीसोद (३०) बाँसवासी (३१) भाँडा (३२) खेड़ी (३३) गुमानपुर (३४) रंजिया चिरैयावास (३५) बारी (३६) हेंगरी पाड़ा (३७) बरवास छोटी (३८) साँडलाई (३६) भगतपुरा (४०) फतेहगढ़ (४१) खीरोत (४२) डूँगरपुर (४३) रासा (४४) फोरीबड़ी (४५) सुरानता (४६) रामपुर ।

परिशिष्ट २

(वे प्रश्न तथा उत्तर जो कि प्रश्न-काल में न लिए जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

४६० (१२५/एफ. एम.) श्री संतोषसिंह कछवाहा, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १३६—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

जोधपुर के पावर हाउस की बिजली की रेट्स (पावर लाइट, व टेम्परेरी लाइट्स की) क्या-क्या है ?

उत्तर

(उपलब्ध नहीं हुआ)

प्रश्न

४६१. (५७/एम. एच. एम.) श्री भैरूसिंह, एम. एल. ए. डिवीजन नम्बर १६—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि डाक्टर वी. एन. कनसल Eye Specialist को जयपुर लाया जाकर जोधपुर में Eye Specialist का स्थान हटा दिया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो इस समय जोधपुर में Eye Specialist कौन है और डा० कन्सल का स्थानान्तर क्यों हुआ ?

उत्तर

(क) जी नहीं।

(ख) रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न विचाराधीन है। डाक्टर वी. एन. कन्सल का स्थानान्तर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया।

प्रश्न

४६२. (१४२/एफ. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४७—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या चित्तौड़गढ़ में पाइप लगाने की योजना है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस वक्त तक इस योजनानुसार कितना कार्य हुआ और इसमें जो नल ३ साल से लगे हुए हैं वह कार्य अब तक क्यों नहीं पूरा हुआ और आगे कब तक पूरा होने की उम्मीद है ?

उत्तर

इस योजना पर इस समय तक २७८२२ रुपये का कार्य हुआ है, इसमें अधिकतर पाइप लाइन फिट करने का कार्य है।

द्रव्य की कमी के कारण यह काम अभी तक पूरा नहीं हो सका। यदि आवश्यकतानुसार द्रव्य मिल गया तो सन् १९५५-५६ तक इस कार्य के पूर्ण होने की आशा है।

प्रश्न

४६३. (१४७/एफ. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १४७—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या चित्तौड़ के पास गम्भीरी नदी का बाँध बांधने की योजना है?

(ख) यदि हाँ, तो कब तक इसका काम चालू होगा?

उत्तर

(क) हाँ, है।

(ख) उम्मीद है तीन-चार महिने में काम चालू कर दिया जावेगा।

प्रश्न

464 (58/M. H. M.) Shri Hari Dutta, M. L. A., (Div. No. 54)—Will the Minister for Medical and Health be pleased to state :—

(a) Has the Government taken any step towards integration of Vaids working in Aushdhalayas of various covenanting States?

(b) If not as yet, is the Government intending to do so at an early date?

उत्तर

(अ) सरकार वैद्यों के एकीकरण के प्रश्न पर तत्परता से विचार कर रही है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा।

(ब) जी हाँ।

प्रश्न

465 (151/F. M.) Shri H. K. Vyas. M. L. A., (Div. No. 160)—Will the Minister for Public Works be pleased to answer :—

(a) At what rate is power supplied to the National Ball Bearing Company of Jaipur by the Power House ?

(b) Who is the owner of the above mentioned company ?

(c) What is the rate at which power is supplied to other consumers in the city ?

(d) Why has a preferential rate been fixed for the above noted company ?

(e) What is the average annual consumption of this Company ?

(f) How much more income would it have meant to the Govt. had this company been charged at the same rate as other power consumers ?

(g) Will the government take steps to stop this discrimination in favour of such a big financier ?

(h) Will the Government place a copy of the agreement entered into by the company and the Government on the Table of the House ?

उत्तर

(a) Power is supplied to the above cited concern @ Rs. 0-0-10 per unit.

(b) It is a limited Company and Birla Brothers are the Chief Directors of it.

(c) Power is supplied to other consumers in the city @ Rs. 0-3-0 per unit.

(d) The preferential rate has been fixed as per the Original Jaipur Government's agreement with the Company.

(e) Average annual consumption of energy of the Company is about 78480 units (year 1952-53).

(f) Had the Company been charged at the rate at which other consumers are supplied, Rs. 106637-14-8 more would have been realised annualy as shown below :—

787480 Uns @ -/-/10 per unit	Rs. 41,014- 9-0
—do— units @ Rs. -/3/- per unit...... ...	Rs. 1,47,652- 8-0
Difference......Rs.	1,06,637-14-8

(g) The matter is under consideration of the Government.

(h) The copy of the agreement in question is as under.

"MEMORANDUM OF AGREEMENT MADE THIS 13th day of December, 1948, between the GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE MAHARAJA OF JAIPUR hereinafter referred to as "The Jaipur Government" (which expression will include the Authorities of Power for the time being vested with the Administration of the territories governed by the Jaipur Government) of the one Part and NATION BEARING COMPANY LTD., a Company registered in Jaipur, and NATIONAL BEARING COMPANY LTD. incorporated under the Indian Companies Act and having its Registered Office at No. 64, Pathuriaghat street in the town at Calcutta hereinafter referred to as the Companies' (which expression shall include their successor) of the other Part. WHEREBY IT IS AGREED AS FOLLOWS :–

1/- That the Jaipur Government hereby agree to grant to the compauies permanent lease in respect of 62 Acres of land near Rawalji ka Bund and which is called old Polo Ground and nearby land as shown on the site plan attached here to and also described in the Schedule below at a ground rent of Rs. 1,500/- per year for the construction of Factory buildings, officers, and Godowns, Stall, Residential quarters, workers colonies, and for other purposes of the Companies. If any further land be required for purpose of the Companies the Jaipur Government may in case of Government owned land grant permanent leases therefor on reasonable terms or if the land in question be private owned the Government will take steps for acquisition thereof.

2/- That the Jaipur Government will allow the Companies to import raw materials for manufacturing purposes and all such materials for manufacturing purposes and all such materials as may be required for construction, maintenance or working of the factory including building materials, stores, spares, machinery plants, coal, fuel oils, lubricants, cool plants, etc. and also to export and sell all manufactured articles by the Companies or their authorised Agents free of any customs and/or excise duty, Toll, Octroi Sales's Tax, etc.

3/- That no tax on income, profits, or gains, or capital, such as income tax, supertax, corporation tax, excess profit tax business profit tax, capital gains tax or capital tax, or any other tax or any sales tax, or excise duty will be levied for 15 yeas from the date of these presents on the Companies or their products or on the profits or gains or capital resulting from the distribution of Companies products. Even upon expiry of the said period of 15 years, the Companies will still be considered entitled to such half and protection as may be considered reasonable in the opinion of the Jaipur Government. In any case

or any tax or duty which may be imposed or the Companies may, be subjected to will as far as possible be lower than and in no case higher than these prevailing in any part of the dominion of India.

4/- That the Jaipur Government undertakes to provide supply of electrical power at the rate of 10 pies per unit at 45% the companies will get proportionate benefit, as in the schedule of Calcutta Electric Supply Corporation Ltd., above will apply upto 500 K. W. load. If the load is more, the companies will also get the benefit of a reduced rate according to the Calcutta Schedule mentioned above. The Jaipur Government will bear the cost of any wiring, transformers etc. that may have to be put up inside the companies premises upto the Companies main Distribution Boards for the purpose of giving them the electric power.

5/- That the Jaipur Government undertakes the supply to the Companies water for drinking and constrnction and manufacturing and any other purposes of the Companies. The Government will bear the cost of construction of any open or tube well or Installation of pipe connections or pumping plants, that may be necessary for the said purpose. The Government will be entitled to reasonable charge for the actual amount of water supplied such charge will be 4 to 5 annas per thousand gallons and the supply will be arranged within two months.

6/- In the event of any dispute or disputes arising out or in any way relating to or touching or concerning these presents or any matters or dealings affecting thereto, the same will be referred to the arbitration of two persons one to be appointed by each of the parties hereto. The arbitrators will appoint one umpire to whom the disputes will be referred to in the event of differences amongst the arbitrators. The award of the Arbitrators or Umpire appointed thereby shall be final and binding upon both parties.

IN WITNESS WHEREOF the parties to these presents have here into set and subscribed their respective hands at Jaipur this the 13th day of December, 1948.

Sd/- Chandra pal Singh.
Chief Secretary to the Government
of Jaipur.

Signed, seal and delivered by the Government of Jaipur State in the presence of :—

Sd/- G. N. Gupta.

Signed and delivered by and on behalf of the National Bearing Co. Ltd. in the presence of

Sd/- Narain Singha.

Schedule of land given to National Bearing Co. Ltd.

No. of Khasras.	Bigha.	Area Biswa.
94/1	13	18
94/2	10	5
94/3	20	5
94/5	16	9
98/	0	6
84/216/1/2	1	7
94/233/1	1	1
94/4 94/216/2 94/219/1 94/232/2 94/217 94/222/2	33	0
94/6	0	3
94/233/2	1	11
	99	2

Ninty-Nine Bighas and Two Biswas Sixty-two Acres.

Sd/- R. D. Paliwal.

Sd/Chandra Pal Singh
Chief Secretary to the
Government of Jaipur,
Jaipur

प्रश्न

४६६. (१६०/सी. एम.) श्री भैरूँसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १६— क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) मासी बाँध की योजना के संबन्ध में क्या क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना को कार्यरूप में न लाने का सरकार ने निश्चय कर लिया है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्यों और इसमें अब तक सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

उत्तर

(क) सरवे का बहुत-सा काम हो चुका है।

(ख) नहीं।

(ग) सरवे पर लगभग ढाई हज़ार रुपया खर्च हो चुका है।

राजस्थान विधान सभा

सोलहवीं बैठक, बुधवार, दिनांक–२४ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ४ बज कर २० मिनट (मध्यान्होत्तर) पर प्रारम्भ हुई

(सायंकालीन बैठक)

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग संख्या २७–विद्युत से

प्राप्तियें (क्रम में)

श्री अध्यक्ष—We resume discussion on Demand No. XXVII.

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय अध्यक्ष, इलेक्ट्रिक पॉवर हाउसेज़ जितने हैं उनमें जो कोल का खर्चा आता है सरकार यदि चाहे तो उस खर्चे में काफी कमी कर सकती है। मैं जोधपुर के पॉवर हाउस के मुतल्लिक बता सकता हूँ कि वहाँ जो कोल आता है उसको क्रश करने के लिए एक महीने में ७ हजार रुपया खर्च आता है। इस तरह से १२ महिने में ८४ हजार रुपये केवल कोल के क्रश में खर्च हो जाते हैं। किसी ने वहाँ पर इस काम के लिए टेन्डर दिया था; एक टन के क्रश के लिए सवा सात आने भरे थे। वह टेन्डर न मालूम माननीय मन्त्रियों ने मन्जूर क्यों नहीं किया? इसके अलावा जो कोल आता है, पॉवर हाउस के लिए जो कोल दिया जाता है उसका एक कम्पनी को मोनोपोली दे दी गई है। इससे न मालूम कितने सीन का कोयला दिया जाता है; १२ से १६–२० सीन का कोयला आता है। एक कम्पनी को मोनोपोली देने की वजह से वह कोयला बारह और १८ रुपये के बीच के हिसाब से आता है। इसकी वजह यह है कि एक कम्पनी को मोनोपोली देने की वजह से कोयला महँगा पड़ता है।

जोधपुर में अभी दो टरबाइन थे वे टूट गये, लेकिन इसके बाद में कोई व्यवस्था ठीक नहीं हुई। २५० किलोवाट के दो ऑइल इन्जन लगाये गये; फिर भी कई दफा बिजली फेल हो जाती है। उस बिजली से कई मजदूर-पेशा लोग मामूली मशीनें चलाकर अपना गुजारा करते हैं; जैसे आटे की मशीन चलाकर, उनको पॉवर बराबर नहीं मिलता है। चक्कियों को पॉवर नहीं मिलता

[श्रीसन्तोषसिंह कछवाहा]

है, पम्पिंग सेट के लिए पॉवर नहीं मिलता है। इससे जनता को काफी हानि होती है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जाय और नये टरबाइन की भी व्यवस्था की जाय, ताकि बिजली की सप्लाई अच्छी हो सके।

अब मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, पॉवर हाउस का काम जिस प्रकार पिछले दिनों में चला है वह काफी सन्तोषजनक रहा है और मैं यह मानता हूँ कि अगर माननीय सदस्य इनको समझने की कोशिश करते तो शायद हमारे इन्जीनियरों को बधाई देते। कोई चाहे कितना ही काम करे कुछ मित्रों का यह ख्याल रहता है कि कोई भी ऐब उसमें निकाला जाय। मैं देखता हूँ कि पिछले समय इस इन्टीग्रेशन के बाद हमारे राजस्थान में उन रियासतों का एकीकरण हुआ, उन रियासतों के इन्जीनियरों को उसी प्रकार रखा गया और उनको वे ही तनख्वाहें दी गईं और उनसे वही काम लिया गया जो उनके सुपुर्द रियासतों के जमाने में था, जो उनकी योग्यतायें थी, जो जिम्मेदारियाँ वे निभा रहे हैं; लेकिन जब वे इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं कि जो उनके अपने-अपने इलाके से कई गुना बढ़ी-चढ़ी हैं फिर भी उन्होंने यहाँ पर बड़े साहस के साथ काम किया और काम को आगे बढ़ाने में मदद दी। राजस्थान की नई स्टेट बनी और उन्होंने भी उसके मुताबिक पावर हाउस को खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि इन सर्विसेज़ के लोगों की, जिनको हमने पुराने राज्यों से लिया, सेवाओं की कद्र करते ताकि उनकी हिम्मत बढ़ती और उनके लिए ज्यादा अच्छी बात होती। आप किसी भी महकमें को देखने की कोशिश करें। सिविल वर्क्स के बारे में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इन्जीनियरों ने जितनी सड़कें बनायीं जितने मकानात बनाये, उनकी तारीफ की जानी चाहिये थी। हमारे यहाँ जहाँ पॉवर हाउसेज़ करीब १६–२० हैं; छोटे-छोटे राजाओं के जो छोटे पॉवर हाउसेज़ थे जो उनके महलों की शान-शौकत को बढ़ाने के लिये रखे गये थे उनमें से कुछ पॉवर हाउसेज़ बड़े भी थे जैसे बीकानेर, जयपुर और जोधपुर के, वे भी इतने बड़े पॉवर हाउसेज़ नहीं कहे जा सकते जितनी कि जिम्मेदारी आज इन पावर हाउसेज़ पर है। उनको पूरा करने के लिए हमारे वे ही इन्जीनियर जो इन्टीग्रेशन में लिए गये थे और रियासतों में काम करते थे, एक छोटी सी तनख्वाह जो उनको रियासतों के जमाने में मिलती थी वही तनख्वाह हम भी उनको दे रहे हैं। आज वे ही १६–२० पावर हाउसेज़ उनके अधीन हैं। यह कोई कागजी फाइल का काम नहीं जो इधर से उधर जल्दी हो जाय। यह इतना आसान काम भी नहीं कि जो आसानी से देख लिया जाय। हरेक मशीन ठीक ऑर्डर में चलती है या नहीं, बाकायदा इन पर एक्स्पेन्डिचर होता है या नहीं; यह सब इनको देखना पड़ता है। आज भी कई जगह पुराने रूलर्स को जो सहूलियतें प्राप्त थीं वे ही आज भी दे रहे हैं। परचेज़ेज़ के नये सिस्टम आ जाने से और कितनी ही दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऑडिटर जनरल के कारण भी कई दिक्कतें महसूस हो रही हैं, लेकिन जिन सदस्यों ने सब तरफ बेईमानी का दृश्य उपस्थित करने का नियम बना लिया है उनसे हम क्या आशा करें कि किसी की वे तारीफ करेंगे।

मैं आपके सामने कुछ फिगर्स और फैक्टस रखना चाहता हूँ। जब से राजस्थान बना है पॉवर हाउस बराबर तरक्की करते जा रहे हैं। यह स्पष्टतया इस बात से जाहिर होता है कि जितनी

[श्री भोलानाथ]

बिजली हम उस समय पैदा करते थे आज हमारे पास उससे दुगनी बिजली की उत्पादन हैं। हमने कनेक्शन दुगुने और तिगुने दिये हैं। अगर आमदनी को भी देखा जाय तो हमें पता चलेगा कि सन् ५०—५१ में जहाँ हमारी आमदनी ६५ लाख ६३ हजार ५६२ थी वहाँ आय ५३—५४ में १ करोड़ ४ लाख के करीब बढ़ गई है। तब से अब तक लगभग हमें ४० लाख का फायदा हुआ है। यह हमने ४० लाख की आमदनी किसी की जेब से तो नहीं निकाल ली, किसी ने जबरदस्ती इकट्ठी तो नहीं कर ली गई। पुराने—राजा-महाराजाओं के साथ जो वायदे किये हुए हैं उनको भी हम निभा रहे हैं जैसा कि यहाँ नेशनल बॉल बियरिंग के लिए कहा गया। पहले भूतपूर्व जयपुर. राज्य के वक्त में इस कम्पनी की बड़ी आवश्यकता समझी गई कि यहाँ कोई फेक्ट्री चालू की जाय। यह कोई छोटी-मोटी फेक्टरी नहीं है। इस फेक्टरी का महत्व कम नहीं। यह एक लिमिटेड कम्पनी है। इसमें आपके भी शेयर्स हो सकते हैं। उनका फायदा आपको भी मिल सकता है, केवल बिड़लाजी की मैनेजिंग एजेन्सी होने से यहाँ यह शोर किया जाता है। बिजली कम रेट पर दी जाती है यह कहना वाजिब नहीं, यह न्यायोचित ही है। यह कम्पनी एशिया भर में बॉल बियरिंग बनाने में सबसे बड़ी है। अगर इसको कुछ रियायतन बिजली दी जाती है तो इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यहाँ के पहले शासन ने अपने शहर की रौनक बढ़ाने के लिए और अपने यहाँ के लोगों को मजदूरी मिल जायगी इस नीयत से इस कम्पनी को कम रेट पर बिजली सप्लाई करने का वादा किया था इसलिए इस काम की तारीफ करनी चाहिये। राजस्थान गवर्नमेंट आज भी यह चाहती है कि इन्डस्ट्रीज़ को बिजली सस्ते दर पर दे, ताकि हमारे यहाँ उद्योग-धन्धे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पनपें। पहले भी यहाँ कई प्रकार की सुविधायें प्राप्त होती थीं; जैसे कस्टम की रियायतें उस जमाने में दी जाती थी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम और 'ए' स्टेटों के मुकाबले में नहीं आ सकते। हमारे यहाँ कॉम्युनिकेशन की दिक्कतें हैं, आबहवा व क्लाइमेट की दिक्कतें हैं इसलिए जिस तरीके से पुराने काम चल रहे हैं वे चलते जाँय तो अच्छा है। उनकी बुराई करने की जँचती नहीं।

कहा जाता है कि तेलका कन्ज़म्पशन बहुत बढ़ गया है। जहाँ हमारे यहाँ ५१-५२ में ५३ लाख रुपया खर्च होता था आज करीब वह साठ लाख रुपये करीब बताया गया है, इसमें से तीन लाख रेलवे फ्रेट बढ़ा दी है। ३ लाख डी. जी. आई. एस. के पुराने बकाया थे, ४५-४६ के देने बाकी थे वे भी इसमें मिला दिये गये हैं। इस तरह से ६ लाख कम कर देते हैं तो वह रकम ५४ लाख के करीब रह जाती है। जो यह कहा जा रहा है, जो कन्जम्पशन बढ़ाया जा रहा है, ठीक बात नहीं।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो एन्जिन हमें मिले हैं, उनका तेल-कोयले का खर्च इतना नहीं कि आज के अपटूडेट एन्जिन लाये जाँय तब होगा। नई मोटर का कन्ज़म्पशन भी कुछ दिनों में बढ़ता चला जाता है। जोधपुर के इन्जिन सन् १८ के हैं, वहाँ पर एक एन्जिन सन् १४ का भी है। आप यह देख सकते हैं कि जो एन्जिन सन् १४ और १८ के हैं वे कितना कोयला खाते होंगे?

यह भी कहा गया कि इसके कन्ज़म्पशन में फर्क बहुत है। पर कोई ऐसी बात नहीं कि इसमें ऐसा कोई जबर्दस्त फरक दिखाई देता हो। जोधपुर में फरक की बात कही गई। जयपुर में जहाँ

[श्री भोलानाथ]

नये एन्जिन लगाए गए हैं ३.८ और बीकानेर में ५ (अश्रव्य) खर्च आता है। बीकानेर का जो कोल है वह घटिया क्वालिटी का है इसलिए वहाँ खर्चा भी अधिक पड़ता है। पिछले दिनों में वहाँ पर पुरानी कोल माइन्स में गड़बड़ी होने के कारण वहाँ से कोयला निकाल नहीं सके, इसलिए बाहर से मँगाना पड़ा। इसलिए वह थोड़ा महँगा भी पड़ा।

इसके बाद स्टाफ ज्यादा रक्खा गया, ऐसा कहा गया। इसका अनुमान कभी जोधपुर से और कभी बीकानेर से कर लिया गया है और इस तरह से, हर तरह से तोड़-मरोड़कर बात रखने की कोशिश की गई है। जोधपुर में इस समय एक एग्जीक्युटिव इन्जीनियर और ३ असिस्टेन्ड इन्जीनियर्स रक्खे गए हैं। इसी प्रकार बीकानेर में एक एग्जीक्युटिव इन्जीनियर और तीन उनके साथ में असिस्टेन्ड इन्जीनियर्स रखे गये हैं और दो बढ़ा करके रखे गए हैं; क्योंकि वहाँ पर बीकानेर का जो सिस्टम है बिल्कुल दूसरी तरह का है। जोधपुर और जयपुर में तो जो कुछ भी बिजली का प्रबन्ध होता है ज्यादा-तर शहर तक ही सीमित रहता है, पर बीकानेर में बिजली २१ कस्बों में १४० मील के करीब घेरे को दी जाती है। कारखाने पर इसलिए हमको दूसरे असिस्टेन्ड रखने की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर जोधपुर में तो हमारा वाटर वर्क्स पी. डब्ल्यू. डी. के पास है, और स्थानों में बिजली विभाग के पास है। इसलिए भी ज्यादा आदमी रखने की आवश्यकता हो जाती है।

जयपुर की पोजीशन बिल्कुल अलग है। वैसे तो बिजली सप्लाई का ही काम अकेला यहाँ हो तब भी कोई बात नहीं पर वाटरवर्क्स भी अलग साथ में है और वर्कशॉप भी इसका है। वैसे वर्कशॉप जोधपुर-बीकानेर में भी है लेकिन यहाँ पर और जितने भी डीजल एन्जिन्स जो छोटे-छोटे केपिटल टाउन्स में तथा डिस्ट्रिक्ट हैड क्वाटर्स में लगे हैं उनकी मरम्मत यहाँ होती है। आवश्यकता पड़ती है तो असिस्टेन्ट इन्जीनियरों को बाहर भी भेजना होता है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से स्टाफ रखा जाता है।

क्लर्कों और बाबुओं की बात भी इसी प्रकार से बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है। पर मैं निवेदन करूँ कि हम कभी ज्यादा नहीं रखते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतने ही रखे जाते हैं।

एक बात बहुत जोर से कही जाती है कि श्री यादरामजी को नियत किया गया था अकाउन्ट वगैरह की जाँच करने के लिए। तो, यह तो डिपार्टमेंट का अपना काम है, इस तरह की डिपार्ट-मेंट में कोई न कोई कार्यवाही होती ही रहती है। अकाउन्ट रखने के कई तरीके हैं, नया हैं, पुराना है; यहाँ अभी तक पुराने तरीके से हिसाब रखने का रिवाज था उसको किस तरह से सही लाइन पर लिया जावे इसके बारे में सरकार ने सुझाव देने के लिए कोई काम किया तो जो किया, विभाग ने वाजिब किया। अमल करने लायक कोई बात होगी तो उस पर अमल किया जावेगा। उस रिपोर्ट के बारे में यह कहा जावे कि किसी एक आदमी को दी जावे, वह जो चीज विभाग की अपनी फाइलों पर है उसे इस सदन के सामने रख दिया जावे तो यह तो कोई चीज नहीं है। वह कोई पब्लिक एन्क्वायरी नहीं थी कि जो माँगे उसे सरकार दिखाती रहे। जैसे सरकार के और काम होते रहते हैं, साधारण काम

[श्री भोलानाथ]

की दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके लिए छोटे-मोटे प्रबन्ध जरूर हुआ करते हैं डिपर्टमेंट की तरफ से। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि विभाग में जो होता है वह हर कोई बात हर किसी को बता दी जाती रहे।

अब यह कहा जाता है कि जो स्टोर की पर्चेजेज़ होती है उनमें गड़बड़ी होती है। इसका भी हम काफी इन्तजाम करते हैं। आजकल जो स्टोर पर्चेज़ होता है गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के डी. आई. एस. विभाग से पूछ करके, उनकी रेटों से कम्पेरिजन करके किया जाता है; बल्कि उसकी सलाह से जो मशीनरी खरीदी जाती है उसका कमीशन ओर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि यहाँ पर जो कुछ खरीद होती है उसमें कोई भी सही तरीके से काम नहीं होता, यह उचित बात नहीं मालूम पड़ती है। इससे अधिक और क्या अर्ज करूँ।

श्री चाँदमल मेहता को तो इतना ही विश्वास दिला देना काफी होगा कि लगभग ३ लाख ६० हजार रुपयों का प्रोवीजन रखा गया है किशनगढ़ पॉवर हाउस को ठीक करने के लिए। इसके लिए नई मशीनें भी खरीदनी है तो यदि ये सारे रुपये वहाँ इस पॉवर हाउस पर खर्च हो जाते हैं तो सारी स्थिति ठीक हो जाती है।

श्री बी. एन. जोशी चाहते हैं कि बाँदीकुई में बिजली का प्रबन्ध होना चाहिए। पर वहाँ की यह माँग मन्जूर करना सरकार के लिए मुश्किल है। बाँदीकुई को अपने आपको सौभाग्यशाली समझना चाहिये कि चम्बल प्रोजेक्ट की बिजली सप्लाई योजना के अन्तर्गत आ गई है और इस प्रकार वहाँ भी बिजली पहुँचाई जावेगी। श्री मानसिंहजी की भी राय है कि बाँदीकुई में बिजली नहीं भेजी जावे, तो उनकी राय की कद्र की जावेगी और जमुवा रामगढ़ में पेमेन्ट नहीं हुआ इसके लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेन साहब ने आश्वासन दे दिया है कि अगर इसके मुताबिक बात ठीक पाई गई तो इस पर भी उचित कार्यवाही की जावेगी। अभी श्री मोदीजी ने कहा कि अभी जो पर्चेजेज़ की गई हैं इस विभाग में, उनमें पूरा-पूरा ध्यान नहीं रक्खा गया है। इसके लिए टेन्डर्स माँगे गए हैं वे भी रिकग्नाइज्ड ढंग से नहीं लिए गये हैं। इसके लिए मैं श्री मोदी जी को और अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत इस सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है वह पूर्ण संतोषजनक है। वे सभी शामिल है जो इस धन्धे से सम्बन्ध रखते हैं और उन सभी लोगों ने करीब-करीब टेन्डर दिये हैं और उनसे सबसे लिए गये हैं। इसके अलावा भी एक ऐसी परचेज़ कमेटी मुकर्रर कर दी गई है जो इन सबकी देखभाल करती है। इतने प्रिकॉशन लेने के बाद मैं मानता हूँ कि इसमें आपको कोई शिकायत का अवसर नहीं रहेगा।

स्टोर की चैकिंग नहीं हुई है, यह भी कहा गया। तो; पुराना स्टोर जो है उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ जिससे सन्तोष हो जावेगा। जोधपुर में स्टोर का कम्प्लीट वेरीफिकेशन हो चुका है, जयपुर में ६ हजार आइटम्स में से चार हजार का और बीकानेर में ५० प्रतिशत का चेकिंग हो चुका है। तो अब मैं ऐसी स्थिति में उम्मीद करता हूँ कि शिकायत की बात अब नहीं रह गई है और इस डिमान्ड को यह सदन सर्व सम्मति से पास करेगा।

श्री भैरूँसिंह—सीकर पॉवर हाउस को सहायता दी जा सकती है, यह आश्वासन मिल जाने पर मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री चाँदमल मेहता—मैं भी अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की, अध्यक्ष महोदय, सदन से अनुमति चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(श्री हरिकृष्ण व्यास से) आप कोई जवाब देना चाहते हैं क्या ?
आपको तो इन्वेरिएबली कहना ही चाहिए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं खुद ही दो मिनिट लेने का इरादा रखता था इसलिए कि जवाब देने की अब जरूरत हो गई है। मैं अब केवल दो शब्द कहकर अपना कथन समाप्त कर दूँगा।

एक तो यह कि अगर श्री यादरामजी चतुर्वेदी की रिपोर्ट इतनी इनऑस्पिशियस और इनओकुअस है तो माननीय मन्त्रीजी उसको इस सदन की मेज पर या किसी कमेटी के सामने प्रस्तुत करने का आश्वासन दें तो इस आधार पर ही मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हूँ।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने आँकड़ों से खुद ही यह साबित कर दिया है कि पिछले तीन साल में बिजली का कन्ज़म्प्शन बढ़ा, पर साथ ही यह भी कहा कि स्टोर का कन्ज़म्प्शन नहीं बढ़ा। अगर इतना बड़ा चेन्ज राजस्थान तीन सालों में कर पाया तो फिर अब बिजली का कन्ज़म्प्शन थोड़ा-सा बढ़ा तो ६-७ की वृद्धि क्यों नहीं की जा सकती ? तो इसलिए खुद ने उन्होंने यह साबित कर दिया कि बहुत कुछ गोलमाल इसमें है।

तो अब यादराम की रिपोर्ट के बारे में माननीय मन्त्रीजी सफाई कर दें तो मैं निर्णय कर लूँ अपने कटौती प्रस्ताव के बारे में।

श्री भोलानाथ—कोई सफाई की आवश्यकता नहीं है। हरेक कागज माँगे तो पेश नहीं किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Chand Mal Mehta to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

(विराम)

The question is that the two cut motions moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The motions fail.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The question is that 4, 5, 6, 7 and 8; these cut motions moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motions fail.

Cut motions by Shri Jawan Singh, Shri Kapil Deo Agrawal and Shri Sohan Lal Bhatnagar have not been moved.

(विराम)

The question is that the cut motion by Shri Bhairon Singh be accepted.

श्री भैरूँसिंह (वि० सं० १६)—मैं वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhairon Singh to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut motion moved by Shri B. N. Joshi be accepted.

(अस्वीकृत)

The Cut-motion fails.

(विराम)

Now the question is, "That a sum not exceeding Rs. 1,51,23,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXVII, Major Head XLI—Receipts from Electricity, Working Expenses etc."

(स्वीकृत)

The demand is granted.

माँग संख्या ८—सिंचाई कार्य इत्यादि

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 83,13,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. VIII, Major Head XVII-Irrigation Works etc.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

There are various cut motions over this demand. What I wanted to place before the House is that the general discussion on the Budget is meant mostly to lay a general criticism of the budget and the policy of the Departments, and if certain members want to raise a discussion on certain issues, they can move cut-motions. But moving the cut motions in 10 or 20; this practically raises a general discussion on the Departments. Any way. The opportunity of speaking or criticizing on the Rajpramukh's Address as well as the general discussion on the Budget involves a general criticism and it is intended that when the cut motions on demands are put, they raise specific issues for discussions. But when, by one Hon'ble Member of the House, such cut motions in the number of 10 or 15 are issued, I will have to put some time-restriction on them. So we take these cut-motions They are by Shri H. K. Vyas. They are 5. Then Shri Shambhu Singh, Shri Kapil Deo, Shri Tejmal Bapna, Shri Sohan Lal Bhatnagar, Shri Udai Lal Bardia, Shri Bhairon Singh and Shri Damodar Vyas. We take all these cut-motions as moved. We take first the economy cut moved by Shri H. K. Yyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I may forego this cut motion in favour of the other cut motions ?

श्री अध्यक्ष—Yes, any way.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Shall I move the other motions ?

श्री अध्यक्ष—Yes, if you want to move.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, I want to move only three cut-motions to conserve time on some important ones; No. 124, No 126 and No. 127.

श्री अध्यक्ष—That is all right. The rest I can take as not moved ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

124. "That the demand No. VIII, relating to XVII-Irrigation and Works etc. be reduced by Rs. 1000/- (to discuss the unjustified increase in irrigation rates in Ganganagar)."

126. "That the demand No. VIII, relating to XVII —Irrigation etc. be reduced by Rs. 1000/- : (to dicuss the discriminatory policy followed by the Government in charging higher irrigation rates from non-khalsa area in former Jaipur and Jodhpur units)."

[श्री हरकृष्ण व्यास]

127. "That the demand No. VIII. relating to XVII-Irrigation etc. be reduced by Rs 1000/- (to discuss the failure to get estimates sanctioned before taking up works)."

माननीय अध्यक्ष, सबसे पहला जो कट मोशन है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वह इस सिलसिले में है कि एक बहुत ही गलत रूप अपनाया जा रहा है वर्क्स के बारे में। बगैर एस्टीमेट तैयार किये हुए ही और बगैर डिटेल्ड एस्टीमेट्स के मन्जूर कराये हुए ही काम शुरू कर दिया जाता है, किया जाता है और किया जा रहा है। खास तौर से चम्बल की जो योजना है उस योजना के सिलसिले में डिटेल्ड एस्टीमेट्स बगैर तैयार किये हुए काम की शुरुआत की जा रही है। इससे यह कोई पता नहीं चल सकता है कि आया एस्टीमेट के मुताबिक काम हुआ या अगर रिवीजन करने की आवश्यकता पड़े तो वह क्यों, किस हद तक और कोई चेक नहीं रहता है खर्चे के ऊपर। जो पहला कट मोशन मेरा है वह इसके निस्बत है।

दूसरा कट मोशन, माननीय अध्यक्ष, इसलिए है कि राजस्थान में जो भी जागीरी एरिया है, उसमें और खालसा एरिया में अलग-अलग इरिगेशन चार्जेज लगाये जाते हैं; न सिर्फ जयपुर में बल्कि और दूसरे कई इलाकों में। मसलन, जवाई की जो योजना है उससे पानी मिलता है, और उसकी सिंचाई की दर खालसा इलाके के लिए ५) रु० है और जागीरी इलाके के लिए ७ रु० है। जयपुर में भी जयपुर डिवीजन में फुलेरा और दूसरी जगह जहाँ-जहाँ सिंचाई के लिए कुछ पानी दिया जाता है तो खालसा में उसकी दर डेढ़ रुपया है और जागीरी इलाके के अन्दर उसी की दर ढाई रुपया है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या जागीरी इलाके की जमीन ज्यादा पानी सोखती है या वहाँ के किसानों को पानी की आवश्यकता कम है या कारण क्या है? जो सरकार हरेक नागरिक की समानता के सिद्धान्त को कबूल करती है उस सरकार के मातहत में इस प्रकार का एक दूसरा बर्ताव कि जागीरी इलाके के अन्दर जो किसान भूमि की सिंचाई के लिए पानी लेते हैं उसके लिए ज्यादा दर लगाये, यह अत्यन्त ही अन्यायपूर्ण चीज है और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में स्पष्ट कारण देंगे और उन किसानों को राहत मिल सके, ऐसा एलान माननीय मन्त्रीजी जरूर करेंगे। इसके डिफेन्स में शायद ही कोई बात कही जा सकती है।

तीसरा मेरा कट मोशन है अध्यक्ष महोदय, जिसका ताल्लुक है गंगानगर के इलाके के अन्दर जो सिंचाई की दरें बढ़ाई गई हैं उससे। पिछले साल सरकार ने गजट के अन्दर ऐलान किया और गजट में ऐलान करके दरें बढ़ाई। गंगानगर के नहरी इलाके में जो आबपाशी की दर या सिंचाई की दर किसानों से ली जाती है अबतक उसकी बढ़ौती का अन्दाज ऐसे किया जा सकता है कि कुल मिलाकर करीब १०० पर्सेन्ट बढ़ौती की दर करदी गई है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, अभी २ महीने पहले, सुनते हैं कि कोई सम्मेलन हुआ उसमें सलाह-मशविरा हुआ और उसमें जितनी दर बढ़ाई थी उसमें से कुछ दर को कम कर दिया गया। अब भी यहाँ पर यह समस्या मौजूद है कि इस इलाके के काश्तकारों को इस इलाके से नहरी पानी लेनेवाले लाखों आदमियों को चढ़ी-चढ़ी सिंचाई की दर देने के लिये मजबूर किया जा रहा है और आज मुझे यह सूचना मिली है तार द्वारा कि इस तरह के प्रयत्न के विरोध में वहाँ के लोगों ने प्रदर्शन आदि के जरिये राय जाहिर करने की कोशिश की थी और इसके फलस्वरूप ११ कार्यकर्त्ताओं को एरेस्ट किया जा चुका है। ऐसा दिखता है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कि यह मामला और भी गंभीर स्थिति धारण करेगा क्योंकि यदि यह दर देनी पड़ी तो यह जमींदारों पर बहुत भारी पड़ेगी। यह निर्णय ऐक्सपार्टी किया गया है; बगैर किसी जाँच के, बगैर किसी आधार के सिचाई की दर बढ़ादी गई है। मैं यह पूछना चाहता हूँ मन्त्रीजी से और उच्च अधिकारियों से कि सिंचाई की दर बढ़ाने से पहले क्या इस इलाके के किसानों की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन (cost of production) की या पैदावार की सारी एवरेज निकाल कर खर्च काटने आदि की सारी चीजों की जाँच की गई है? क्या दर बढ़ाने के पहले इस चीज की जाँच की गई है कि आज टोटल आमदनी कम होती है तो इसका कारण यह है कि इसमें चोरियें होती हैं? यह इलाका ऐसा है जिसमें पानी की चोरियें होती हैं। वे इस प्रकार होती हैं कि पानी के मेजरमेन्ट के लिये कोई मीटर नहीं है। इसके लिये निश्चित डाइमीटर के मोखे बने हुए हैं। इसमें भूतपूर्व बीकानेर रियासत के समय और उसके बाद कई लोगों ने इस मोखे का एरिया बढ़ा लिया है और अब यदि १ घण्टा पानी चले तो कायदे से जितना पानी जाना चाहिये उससे ज्यादा जाता है। मोखे बड़े बनाने के कारण जितना जाना चाहिये उससे दुगुना जाता है और इस वजह से आमदनी सरकार को कम होती है। जो मेन हैड है, जहाँ से राजस्थान में पानी आता है उसका नाम शिवपुरी हैड है या क्या है, वहाँ पानी की मिकदार तो बढ़ी लेकिन न तो सिंचाई का आँकड़ा बढ़ा और न सरकार की आमदनी बढ़ी और इस कम आमदनी का कारण भ्रष्टाचार है। उसकी कोई जाँच नहीं की जाती और क्योंकि दूसरे इलाकों में सिंचाई की दर बढ़ी है इसलिये यहाँ भी बढ़ा दी जाती है। जहाँ-जहाँ सिंचाई की दरें बढ़ी हैं, वहाँ-वहाँ के किसानों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। लखनऊ में दर बढ़ाई थी तब उसके खिलाफ किसान संगठित हुए थे। आप यह तय मान लें कि इस इलाके के किसान भी बढ़ी हुई दर देने के लिये तैयार नहीं हैं चाहे आप गिरफ्तारियें करें, लेकिन यह चीज नहीं मानी जा सकती। मैं इस कटौती प्रस्ताव के जरिये सदन से प्रार्थना करूँगा कि बढ़ौती की दर रोक दी जाय।

श्री शंभूसिंह—(To discuss unsatisfactory works constructed and services rendered by the Department) माननीय अध्यक्ष, मेरा भी इस डिमान्ड के अन्दर एक कटौती प्रस्ताव है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो तालाब, बाँध आदि बनाये जाते हैं और उनके लिये जो एस्टीमेट तैयार होता है वह काम अक्सर ठेकेदारों से तैयार कराया जाता है। नतीजा यह होता है कि सरकार का जरूरत से ज्यादा पैसा अपव्यय हो जाता है। देखते हैं कि तालाब, बाँध आदि काम के लिये सरकार का जो एस्टीमेट बनता है और काम ठेकेदारों को ठेके दे दिया जाता है वे इस काम में, सरकार जितना रुपया देती है, उससे कहीं कम रुपये में दूसरे ठेकेदारों को ठेके देते हैं और इस प्रकार से वह काम होता है। नतीजा यह होता है कि उस काम से फायदा नहीं होता और वह बहुत कम अर्से में टूट जाता है, नष्ट हो जाता है और सरकार को बार-बार व्यय करना पड़ता है। इसमें एक दलील यह दी जा सकती है कि सरकार के पास उतना स्टाफ नहीं है इसलिये उतना सुपरविजन सरकार नहीं कर सकती। यदि ठेकेदार सुपरविजन कर सकते हैं तो इससे कहीं कम पैसों में तो कोई वजह नहीं कि सरकार सुपरविजन नहीं कर सकती हो और यह काम खुद न कर सकती हो। यदि यह काम सरकार खुद अपने आप करवा ले तो सरकार को पैसों की बचत होगी और फायदा होगा और जो शिकायत बारबार आती है वह भविष्य में नहीं आवेगी और उसके अतिरिक्त

Page No.112

[श्री शम्भूसिंह]

इरिगेशन के लिये जो डेवेलपमेन्ट की स्कीम है वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से फाइनेन्सड है, इसके लिये योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत से ऐसे अच्छे-अच्छे मौके यहाँ आये और काम जल्दी शुरू हो जाना चाहिये था, लेकिन न मालूम क्यों उसे खटाई में डाल दिय गया ? मैं आपके सम्मुख एक जगह का दृष्टान्त उपस्थित करूँगा। वह जगह है भीलवाड़ा जिले में देवरिया गाँव। उसमें एक नाला, जो नदी कहलाता है वह उस गाँव के पास होकर गुजरता है। उस नाले से एक तालाब बनवाने के लिये मेवाड़ गवर्नमेंट के समय सरवे करवा दिया था। मगर दुर्भाग्य है कि सरवे होने के बाद मेवाड़ गवर्नमेन्ट राजस्थान में मर्ज हो गई और कोई काम नहीं हो पाया। उसके बाद वर्तमान राजस्थान सरकार ने उस पर गौर किया और तक्मीना बनवाया और हाल ही में दिसम्बर या जनवरी में यह तखमीना बनकर पेश किया गया, मगर न मालूम क्या वजह हुई कि इस एरिया का तालाब अब तक खटाई में पड़ा हुआ है। वह इतनी अच्छी आमदनी देने वाला है कि उसके पीछे १५०००बीघा जमीन की सिंचाई हो सकती है। जिस तालाब से १५००० बीघा जमीन का इर्रिगेशन हो सके उसको खटाई में डाल देना उत्पादन के लिये कितना नुकसानकारी है। आज देश में सबसे बड़ी आवश्यकता अन्न उपजाने की है। यदि ५ मन अन्न १ बीघे में उपजे तो उस जमीन से ७५ हजार मन अन्न उपज सकता है और इरिगेशन की आमदनी यदि १ रु० फी बीघा भी ली जाय तो १५००० रु० की आमदनी सरकार को हो सकती है। ऐसी पेइंग स्कीम अब तक न मालूम क्यों अमल में नहीं लाई जा सकी। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूँ कि ऐसी स्कीम को जल्दी से जल्दी अमल में लाया जावे। इसके अलावा दूसरे मौके भी हैं। डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा की तहसील सहाड़ा में पोटलाँ नाम का गाँव है, वहाँ तालाब बनने वाला था पर वह भी काम नहीं हो पाया है। वहाँ भी बहुत सा अन्न का उत्पादन हो सकता है व आबपाशी से सरकार को लाभ हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस बजट में इन दोनों कामों के लिये धन-राशि नियुक्त करके ये काम पूरे करें, वहाँ तालाब बन जाने से वहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, अन्न का उत्पादन बढ़ेगा और सरकार को भी लाभ होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और जनता को बहुत बड़ी राहत पहुँचायेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री कपिल देव

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर!

श्री सोहनलाल भटनागर—(To discuss negligence of the Government toward Jai Samand Lake.) माननीय अध्यक्ष, हमारे राजस्थान में खुशकिस्मती से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मौजूद है और उसका नाम है जय समन्द। आज पंचवर्षीय योजना का जमाना है और हम देखते हैं कि लाखों-करोड़ों रुपया विकास योजना के लिए, माइनर इरिगेशन के लिए उधार मिल रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिससे करीब ५०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है उसके विकास की तरफ हमारी राजस्थान सरकार उपेक्षा कर रही है, इसका हमें दुख है।

मेवाड़ में रामा मूर्ति दीवान बन कर आये और इस बात की ओर ध्यान दिया। उन्होंने १०,००० एकड़ जमीन की सिंचाई करवाई। जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो मेवाड़ की जनता की आशाए थीं कि इसका विकास होगा और विद्युत योजना और सारी योजनाएं वहाँ हो सकेंगी परन्तु राजस्थान सरकार का जो उपेक्षापूर्ण रवैया इस ओर रहा है उसको देखकर मेवाड़ की जनता को बड़ा दुख हो रहा है।

गत वर्ष भी ढाई लाख रुपया इसकी नहरें बढ़ाने के लिए रखा गया था जिसे काम में नहीं लिया गया। आज अगर उसकी नहरों का निर्माण हो जाय तो उन नहरों से बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है जिससे अन्न के उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। जहाँ नहर बनी है उसका भी आधे से ज्यादा पानी यों ही बर्बाद होता है, खराब जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि सभी नई बनने वाली योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है और उनसे रिटर्न भी नहीं होने वाला है। तो ऐसी सूरत में करोड़ों रुपया नई बड़ी योजना पर खर्च करने के बजाय अगर इस पर कुछ लाख रुपये ही खर्च किये जाँय तो जल्दी ही बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। जय-समन्द जैसे पानी के भंडार का तो इससे बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। गत वर्ष जो एक नहर खोदी (गहरी की गई) थी उसका रिटर्न भी १० परसेंट से कम नहीं बैठ सकता। इसके बारे में मन्त्री महोदय से और सरकार से निवेदन किया, पर कुछ नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को अपनी नीति को बदलना चाहिये और सिंचाई के बारे में उन कामों को प्रायोरिटी (प्राथमिकता) देनी चाहिये जिससे कम पैसे से ज्यादा रिटर्न बैठ सके।

श्री उदयलाल बरदिया—(To discuss the negligent attitude shown by the Government towards Lasadia tehsil in respect of irrigation works) माननीय अध्यक्ष महोदय, सिचाई की डिमान्ड पर कटौती प्रस्ताव पेश करके मैं उदयपुर जिले की सिचाई के बारे में कहूँगा।

लसाड़िया तहसील एक ऐसी तहसील है कि जहाँ आदिवासियों की आबादी है और वहाँ दूसरे-तीसरे साल अकाल पड़ते रहते हैं और जहाँ अकाल की वजह से लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। कई जगह फूटे तालाब पड़े हैं, जिनकी संख्या ३५ हैं। कई नये बांध बाँधने की जगहें हैं जो बँध जाने पर एक एक बाँध से १०-१०, २०-२० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई कर सकते हैं और इनसे सारी तहसील की पैदावार बढ़ सकती है। इस बारे में बार-बार स्कीम देने पर भी आज तक सर्वे नहीं

[श्री उदयलाल अरदिया]

हुई है। वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बांध भी बहुत कम बांधने पड़ते हैं, पैसा भी बहुत कम खर्च होता है और उससे लाभ बहुत अधिक होता है।

पिछले दिनों जब वहाँ अकाल की समस्या थी, मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी से कई बार सब लोगों ने लिखा, गाँव-गाँव से किसानों की दरख्वास्तें पेश की गईं; कई ऐसे थे जो श्रमदान से मदद करना चाहते थे, परन्तु बदकिस्मती है कि वहाँ सर्वे तक नहीं हो पाई है और आदिवासी उस क्षेत्र को बिल्कुल छोड़ कर जा रहे हैं। अतः इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जावे। बस, मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़) (To discuss the inefficiency and corruption in the department) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने से पूर्व मैं सिंचाई मन्त्री को दो बातों के लिए धन्यवाद अवश्य दूँगा। एक तो राजस्थान बनने के बाद से अब तक इस डिपार्टमेंट द्वारा पैसा खर्च करने में काफी प्रगति की गई और दूसरा धन्यवाद इस बात का देना पड़ेगा कि राजस्थान बनने के बाद से अब तक सिंचाई की दरें (rates) बढ़ने में भी सरकार ने काफी प्रगति की है।

जहाँ तक सरकार की प्रगति का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी को अवश्य धन्यवाद अर्पण करूंगा; परन्तु अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अर्पित करने से पूर्व इन दोनों बातों से राजस्थान की जनता को काफी नुकसान इस डिपार्टमेंट की इनएफीशियेंसी और इस डिपार्टमेंट में फैले भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। जब उन दोनों बातों को, मुकाबला करके एक माँप-दण्ड पर रखते हैं तो मुझे थोड़ी देर के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मैं जो मन्त्रीजी को धन्यवाद देने का साहस करता हूँ उसे देने के लिए थोड़ी सी देर के लिए बन्द हो जाऊं। अध्यक्ष महोदय, आज जगह जगह पर यह बात सुनने को मिलती है कि राजस्थान के फलाँ हिस्से में बाँध बन्ध रहे हैं और उनके नीचे कई नहरें सिचाई के लिए खुदवाई जा रही हैं, जिनसे कई एकड़ बीघा जमीन की सिचाई होगी। इस प्रकार की योजना समाचार पत्रों में पढ़ने से लोगों को संतोष होता है और वे आशा लगाते हैं कि इन नहरों से पानी मिलेगा। लेकिन जब इसको कार्यान्वित नहीं होता देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। आज राजस्थान में इस प्रकार के कई बाँध है और उनको बनाने में काफी रुपया व्यय किया गया लेकिन पानी उसमें एक बूँद भी नहीं टिकता, क्योंकि दरारे हैं। अगर किसी में पानी टिकता है तो उस बाँध में ताकत नहीं कि उसमें जो पानी आये उसको रोक सके। बांध बनने से पूर्व बांध से नहरे निकालना अधिकारी बहुत आवश्यक समझते हैं। परन्तु नहरें बनाने से पहले वे लोग यह नही सोचते कि पानी कितना इकट्ठा होगा, कितने पानी की योजना है और वह पानी बाहर तो नहीं निकल जावेगा। यह विचार करते हैं महज कागजों पर। कोई मौके पर जा कर नहीं देखते और हजारों लाखों रुपयों की नहरें बना दी जाती हैं, सिर्फ यह देख कर कि बांध बन गया है सिचाई होगी और वह नहरों द्वारा ही हो सकती है, इसलिए नहरें बना दी जाएँ। अध्यक्ष महोदय, बाँध बन गया, नहरें भी बन गईं और अखबारों में भी इसकी सूचना निकल गई कि पानी किसानों को दिया जावेगा। किसान नहर पर खड़े-खड़े इन्तजार करते हैं कि अब पानी आवेगा और

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

हम गेहूँ और चने की खेती करेंगे । कई दिन वे इन्तजार करते रहते हैं, मगर न तो पानी आता है और न वे खेती कर पाते हैं । इस तरह से वे किसान परेशान होकर और असन्तुष्ट होकर बैठ जाते हैं ।

मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टांक में एक बाँध है जिसको दाखिया का बाँध कहते हैं । मुझे बहुत अच्छे सोर्सेज़ से इत्तिला मिली है कि उस बाँध में दरारें पड़ गई हैं । इसका कारण यह है कि जिस वक्त टेन्डर माँगे गये थे, उस समय योजना बनाई गई थी कि इतने पत्थर लगाये जावेंगे और इतनी मिट्टी इस बाँध में दी जावेगी; इसका डिज़ाइन (design) इस प्रकार का होगा, चौड़ाई इतनी होगी आदि-आदि । लेकिन, बाद में किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया उस समय उस ठेकेदार को कुछ रियायतें दी गईं और उसने रियायत में पत्थर की जगह रेत काम में ली और जिससे रेत की तादाद ज्यादा बढ़ गई और पत्थर बहुत कम लगाए गए । इस वजह से पानी टिकने का कोई रास्ता ही नहीं रहा ।

दूसरा बाँध राउवास का है । उसकी मोरियां सरकार ने बनाईं । उस बाँध में पानी मोरी के लेवल तक नहीं आता । पिछले साल पानी ज्यादा बरसा और ज्यादा पानी बरसने पर भी पानी मोरियों के मौखों तक नहीं आया । मोरियें ऊँची बनाई गई हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता । इसलिये वे नहरें जो बनाई गई हैं बिल्कुल बेकार पड़ी हैं । चाहिये तो यह था कि पानी को देख कर उसके मुताबिक मोरियें बनाते । मगर आजकल होता यह है माननीय अध्यक्ष, कि सिंचाई विभाग में जो ठेके टेन्डर के बाद दिये जाते हैं और जो डिज़ाइन पास की जाती है उसके अनुसार कभी कोई काम नहीं हो पाते, इसीलिये पानी टिक नहीं सकता । अगर डिजाइन के माफिक ही काम किया जावे तो अवश्य पानी टिक सकता है । इसलिये मैं माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा और उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूँगा कि जो लाखों रुपयों की योजना बनाई जाती है उनको कागजों में ही देख कर इतमिनान न कर लें । ये पब्लिक के लाखों रुपये हैं इसलिये उन्हें चाहिये कि एक-एक पैसे को खर्च करने के लिये और खास तौर से जिससे नहरें बनाई जाती हैं, जिसमें हजारों और लाखों रुपयों की योजना की मन्जूर करते हैं, वे मौके पर जावें और देखें कि यह सारा का सारा-काम हो रहा है या नहीं । उनको चाहिये कि वे योजना बनने के बाद और काम शुरू करने से पहले मौके पर जा कर देखें । जब कि वे सिंचाई. इरिगेशन (Irrigation) आदि से सेस वसूली करना चाहते हैं और लोगों को पानी नहीं मिलने से उनका विरोध सहने के लिये तैयार रहते हैं तो उनको चाहिये कि वे मौके पर जा कर देखें । अभी हाल ही में भीलवाड़ा में भेजा का डिस्ट्रिक्ट है, उसके लिये जयपुर से लाला भगवानदासजी साहब का ट्रान्सफर हुआ । उनके ट्रान्सफर के साथ-साथ जो पेटेंट (patent) ठेकेदार थे वे भी सीधे भीलवाड़ा पहुँच गये और सारा का सारा काम लाला साहब ने उनको ठेके पर दे दिया । लाला साहब इन्जिनीयर हैं, जिनके लिये पब्लिक सर्विस कमिशन ने यह लिखा है कि ये काम करने के काबिल नहीं । इन्हीं लाला साहब के खिलाफ एन्टीकरपशन ने भी अपनी राय दी है । लाला साहब के बदलते ही कई ठेकेदार जयपुर से भीलवाड़ा पहुँच गये और उन्हीं को

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

ठेका दिया गया। इसका नतीजा यह होता है कि रेत ज्यादा और दूसरा सामान कम कर दिया जाता है जिससे पब्लिक के सारे के सारे रुपये बरबाद होते हैं। मगर इसका कौन ध्यान देता है ?

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि आज इस प्रकार की प्रवृत्ति बन गई है कि जो व्यक्ति जहाँ से आता है उसी डिवीजन का ज्यादा ध्यान रखता है और आज हम देखते हैं कि किसी एक ही डिवीजन में काम होता जा रहा है और दूसरे डिवीजनों की उपेक्षा की जा रही है। जैसे सिंचाई मन्त्रीजी उदयपुर डिवीजन से हैं तो आप उदयपुर को देखें, उसकी क्या हालत है ? दूसरी जगहों पर जहाँ कि राजस्थान बनने से पहले की योजनाएं थीं उनको तो कार्य रूप में लाने का कार्य अवश्य किया गया होगा मगर दूसरी नई जगहों के लिये कोई योजना नहीं बनी। आज शेखावाटी का प्रान्त हमारे मन्त्रीजी की ओर देख रहा है। मगर यह कह कर कि शेखावाटी में पानी नहीं है, इसलिये कोई योजना ही नहीं बनाई जाए, यह तो उचित नहीं है। मैं यह कहूँगा कि शेखावाटी में कई ऐसे स्थान हैं पहाड़ों में जहाँ पर पानी रोका जा सकता है। शेखावाटी में दो-तीन साल से अकाल आता है और इससे बचने के लिये भी पानी का रोकना अकाल से बचने का मार्ग बन सकता है। यदि अकाल से बचाया जा सकता है तो भी वहाँ की गरीब जनता को फायदा होगा। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चहता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वे उदयपुर डिवीजन से आये हैं इसलिये केवल उसकी ही ओर ध्यान न दें, उन्हें चाहिये कि वे विशाल हृदयता से काम करें। आप उदयपुर का ही हित नहीं सोचें, आप सारे राजस्थान के सिंचाई मन्त्री हैं इसलिये सारे राजस्थान का हित सोचें। आज पब्लिक यह देखना चाहती है कि हमारे सिंचाई मन्त्री उदयपुर के होते हुए भी दूसरे प्रान्तों के लिये भी उतने ही चिन्ताशील हैं जितने कि उदयपुर के लिये। यदि इस प्रकार की भावना से काम किया गया तो मैं समझता हूँ कि योजनाओं में अवश्य प्रगति होगी और पब्लिक का सहयोग मिलेगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश होने के कारण ऐसी बातों पर गम्भीर चिन्ता करता है। मैं समझता हूँ कि चिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी यदि सिंचाई मन्त्रीजी पूरा ध्यान देंगे।

आज टैक्सेज़ बढ़ाने की बातें दूसरे प्रान्तों के आधार पर भारत सरकार के आदेशानुसार की जा रही हैं; ऐसा कहा जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

डेवलपमेंट, charges, इरिगेशन, charges व अन्य सेस हमें बढ़ाने हैं, यह कहा जाता है। मगर टैक्स बढ़ाने से पहले आप राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखें और आर्थिक स्थिति को ठीक करें, कोस्ट ओफ प्रोडक्शन (उत्पादन व्यय) पर ध्यान दें और उसको आँके और उसके बाद देखें कि पब्लिक की क्या हालत रहती है। जब तक उनकी आर्थिक स्थिति न सुधरे तब तक उस पैसे को जो ऐसे मदों पर खर्च हुआ है, टैक्स लगाकर वसूल न करें, आप अपने पास से उसे खर्च करें। आप आमदनी के जरिये निकालें, काश्तकारों को सहूलियतें दें और बाद में उनसे कहें कि फलाँ टैक्स दो। कृषकों पर जितना कम टैक्स हो, लगाये जावें। यदि आप ज्यादा

[श्री भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)]

टेक्स लगावेंगे तो उनका आर्थिक जीवन संकटमय बनेगा जिससे वे किसी प्रकार अपने आपको सुखी अनुभव नहीं कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की बात मैं बताना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। हर आदमी पैसा कमा सकता है। मैंने खुद ने दो-तीन नहरों का काम देखा है। यह काम पटवारियों के हाथ में दिया गया है कि फलाँ वक्त तक फलाँ खेत में पानी दिया जावेगा और इसी बात के चार्जेज़ उन लोगों से लिये जाते हैं। मगर होता यह है कि पटवारी कह देता है कि इतने समय से इतने समय तक ही तुमको पानी दिया जावेगा और उसके पैसे लेना है। यदि कोई पैसा नहीं देता तो वह पानी समय पर नहीं देता। उनसे भी रिश्वत इस बात की ली जाती है कि आज पानी यदि लेना है तो इतने रुपये जमा कराने पड़ेंगे। यदि बरसात की कमी होती है, पानी की खास आवश्यकता अनुभव की जाती है और उस किसान की खेती के लिए यदि आधी दोपहर भी निकल गई तो जो ईल्ड (yield) होगी, क्रोप का जो प्रोडक्शन होगा उसमें कमी आजायगी और काफी तादाद में अनाज कम होगा। तो इस प्रकार की विकट परिस्थिति जब किसानों के सामने हो जाती हैं तब मजबूरन रिश्वत देनी पड़ती है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के अधिकारी किसानों को परेशान करते हैं कि इतना रुपया जमा कराओगे तब ही पानी मिल सकेगा। अतः इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए माननीय मन्त्री महोदय को काफी प्रयत्न करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—श्री दामोदर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज।

श्री हंसराज—माननीय अध्यक्ष, अभी सिंचाई के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले मुझे यह अर्ज करना है कि अभी पिछले दिनों जयपुर शहर के अन्दर भाखरा और चम्बल के बारे में एक प्रदर्शनी हुई। प्रदर्शनी जयपुर शहर के अन्दर थी और उसका मतलब शायद यह होगा कि इसके द्वारा किसानों को यह बताया जाय कि इन नहरों के आने से किसान कितना फायदा उठा सकेंगे, उसके खेत किस तरह से हरे-भरे होंगे। मैंने शुरू से आखीर तक बड़े गौर से देखा तो वहाँ एक भी ऐसा आदमी दर्शक नहीं था यानी किसान नहीं था जो जमीन काश्त करने वाला हो और उनको फायदा होने वाला हो। वह प्रदर्शनी शहर तक ही सीमित थी या यों कहें कि कुछ ही आदमियों तक सीमित थी। वास्तव में श्रमजीवी वहाँ कोई नहीं था। इस प्रचार से सिवाय इसके कि गवर्नमेन्ट को हजारों रुपयों का खर्चा हो गया और सिंचाई करने वाले किसानों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। वही प्रदर्शनी अगर भाखरा-नांगल, जवाई, चम्बल क्षेत्रों में होती तो किसान फायदा उठाते,

[श्री हंसराज]

महज यह प्रचार मात्र के लिए ही थी। इसका प्रचार पत्रों द्वारा अन्य स्थानों में पहुँचेगा और सिंचाई विभाग को वाह-वाही मिलेगी, सिवाय इसके उस प्रदर्शनी से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की प्रदर्शनी दूसरी जगहों में की जाय और ऐसे क्षेत्रों में की जाय जहाँ सिंचाई होने वाली है, जहाँ किसान काश्त के लिए पानी लगाने वाला है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है, वह है भाखरा के बारे में। यदि यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा कि उसका काम इस तरह से चलता रहा है कि मानों पति-विहीन पत्नी। हमने आँखों से देखा है कि उस नहर को कोई देखने वाला ही नहीं है। एक बार नहीं, अनेक बार यह कहा गया कि भाखरा में बिलकुल सुस्ती से काम चल रहा है और लाखों रुपया बेकार जा रहा है। दूसरी तरफ पत्रों में पढ़ते रहे हैं कि जून सन् ५४ में पानी आ जायगा। माननीय अध्यक्ष, अगर मौके पर जाकर देखा जाय तो कोई भी नहीं कह सकता है कि यहाँ पानी सन् ५४ में आ सकता है। आज भी वहां बीच-बीच में कहीं दो फर्लांग नहर खुदी हुई है तो चार फर्लांग बाकी पड़ी है और अगर चार फर्लांग खुदी हुई है तो दो फर्लांग नहीं खुदी है तथा यदि आठ फर्लांग में खुदी हुई है तो १ फर्लांग बीच में पड़ी हुई है। मैं नहीं समझता कि वहाँ किस तरह से पानी पहुँच जायगा। पंजाब वालों की महरबानी हुई और उन्होंने पानी छोड़ भी दिया तो हो सकता है कि खुदे हुये हिस्सों में पानी आजाय और उस पानी को बहता हुआ देखकर किसान नहर काट कर खेतों में ले जाने की कोशिश करें और उससे एक के साथ दूसरे के झगड़े चलें जिससे कत्ल और खून हो जांय और दिखता है कि ऐसा ही होगा। उस नहर में क्या हो रहा है, किस तरह की धांधली चल रही है यह कुछ वर्णन करने की बात नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई उसको आंखों से जाकर देखे। मैं नहीं कह सकता कि जयपुर में प्लान क्या है, क्या हो रहा है, क्या क्या बताया जा रहा है लेकिन मौके पर नहीं के बराबर है और उसमें जितनी धांधली चल रही है उसका तो मैं विशेष वर्णन न करूँ तो अच्छा है क्योंकि इसके जिम्मेदार हम भी हैं। उधर के साथी कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अतः ज्यादा वर्णन न कर इतना ही कहदूँ तो ठीक है।

तीसरी बात गंग नहर के बारे में कहनी है। इस इलाके में वहाँ के किसानों पर अभी आबियाना (सिंचाई-कर) बढ़ाया गया है। उस आबियाने को बढ़ाने के कारण पहले हमने बहुत ज्यादा गवर्नमेन्ट से पुकार की, बहुत बार मिले, डेपुटेशन के रूप में मिले। किसानों ने दरख्वास्तें पेश कीं, सब कुछ किया। उसके बाद माननीय पालीवालजी ने एक मिटिंग बुलाई जिसमें हम सब एम. एल. एज़. मौजूद थे। बहुत ज्यादा विरोध किया कि यह जो आबियाना बढ़ाया जा रहा है वह उस इलाके के मुकाबले में बहुत ज्यादा है; जोकि इसके पास पंजाब में है, क्योंकि यह नहर पंजाब से आयी है और उस क्षेत्र में, उस नहर में आज तक जितने कानून लागू रहे हैं वे पंजाब के मुताबिक रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि आबियाना (टैक्स) जो लगाया जावेगा वह पंजाब के मुताबिक ही होगा। इतना भारी विरोध करने के बावजूद व आम किसानों के विरोध करने के बावजूद और बच्चे बच्चे के विरोध करने के बाद भी पंजाब से कहीं ज्यादा आबियाना मद-मालगुजारी-औसतन बढ़ा है। हमने यहाँ तक कहा कि अगर आबियाना बढ़ाते हैं तो पंजाब के मुकाबले में आबियाना कर

[श्री हंसराज]

दीजिये और मालगुजारी कर दीजियेगा किन्तु इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और १० लाख रुपयों का आगियाना बढ़ा दिया गया है। अब कुछ कम किया है मगर फिर भी ज्यादा है। उसका नतीजा यह हुआ है कि वहाँ आन्दोलन शुरू हो गया है, वहां पर लोगों ने भूख-हड़ताल शुरू कर दी है, सत्याग्रह शुरू हो गया है और ऐसा लगता है कि गवर्नमेन्ट को उस आगियाने को मंसूख करना पड़े और ऐसी हालत में काफी लोगों को नुक्सान होगा। जयपुर में हड़ताल हुई, गवर्नमेन्ट को कितना पैट्रोल जलाना पड़ा, अन्य-नुकसान हुए और वेही टैक्स वापिस लेना पड़ा और अगर वही चीज फिर हुई तो न सिर्फ सरकार को नुक्सान उठाना पड़ेगा बल्कि आगियाना वापिस लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ की जनता आन्दोलन के पक्ष में है और वहाँ अधिकारियों का पहुँचना मुश्किल हो जायगा।

(विरोधी दल के नेता कुँ० श्री जसवन्तसिंह द्वारा 'हियर हियर')

मैं इन शब्दों के साथ उस बढ़े हुये आगियाना का विरोध करता हूँ। अब भी अच्छा है, उस इलाके की स्थिति को देखते हुए सरकार संभले। गंगानगर पंजाब की सीमा से मिले हुये होने पर भी पंजाब के मुकाबले में वहाँ जमीन की पैदावार कम है, सुधार कम हैं, सड़कें कम हैं आदि। इन बातों को देखते हुए, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर वह आगियाना वापिस ले ले तो अच्छा होगा। इसके साथ ही यह भी प्रार्थना करूँगा जैसी कि यह कहावत है कि "मीठे मीठे गप्प और कड़वे कड़वे थू"। यदि कोई आफत सरकार के सामने आ जाती है तो गंगानगर को याद किया जाता है किन्तु जब वहाँ पर पैसा लगाने का सवाल होता है तो बीकानेर को आँखों से ओझल कर दिया जाता है।

(विरोधी पक्ष के नेता द्वारा "हियर हियर")

माननीय अध्यक्ष, वास्तव में बीकानेर के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है, न केवल एक काम में बल्कि सभी कामों में। सिंचाई का पैसा है वह भी विशेष स्थानों पर लगाया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें भी विशेष स्थानों पर बनाई जाती हैं तथा और और कामों में भी पक्षपात किया जाता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमें राजस्थान सरकार से पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करनी है कि आगियाना जो बढ़ाया गया है उसको वापिस ले लिया जाय, आगे सरकार की इच्छा।

श्री खेतसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भैरूँसिंहजी ने कटौती का प्रस्ताव नं० १३१ रखा है उसी के समर्थन में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यों तो सिंचाई विभाग में तीन प्रकार के वर्क्स होते हैं--मेजर, माइनर, और मीडियम इरीगेशन। इस प्रकार तीन प्रकार के वर्क्स सिंचाई विभाग द्वारा होते है। मैं इस विषय में इतने संकुचित विचार नहीं रखता कि यह कहा जाय कि सड़कें सारी एक ही जगह बनती हैं, सारे के सारे बान्ध एक ही क्षेत्र में बनते हैं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके ज़रिये माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान का ऐसा इलाका बहुत है जहाँ मेजर इरीगेशन नहीं हो सकते वहाँ मीडियम इरीगेशन

[श्री खेतसिंह]

के लिये काफी स्कोप है, वहाँ कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। किन्तु दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि तीन वर्षों में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ने कुछ भी उन इलाकों की ओर ध्यान नहीं दिया। अगर सरकार उन इलाकों में कुछ कार्य करती तो उनको दो फायदे हो सकते थे, एक तो वहाँ जो हमेशा अकाल पड़ा करता है वह समस्या हल हो सकती थी और अन्न की समस्या भी कुछ हद तक हल हो सकती थी तथा दूसरी, वहाँ की जमीन की प्रोडक्टिवीटी (उत्पादन-शक्ति) बढ़ती और उससे अनाज की भारी सहूलियतें बढ़ जातीं और अनाज की पैदावार काफी होनी शुरू हो जाती। इसके अलावा, जिस वक्त जोधपुर रियासत थी उन दिनों में कुछ ऐसे मीडियम इरिगेशन के विकास की स्कीम्स सरकार के सामने थीं, उस वक्त की सरकार के सामने अगर उन स्कीम्स के अनुसार राहत का कार्य शुरू हो जाता; लेकिन जब से यह राजस्थान बना है तब से न मालूम वे स्कीम्स के कागजात कहाँ गुम हो गये, उनका कहीं पता तक नहीं। हमने कई दर्खास्तें दीं लेकिन आजतक उनका कोई जवाब नहीं मिला। माननीय मन्त्री महोदय का मैं ध्यान इस ओर खास तौर से दिलाऊँगा कि शेरगढ़ में एक बस्तुआ नाम का स्थान है, वहाँ इतना अच्छा बन्ध बंध सकता है कि जिसके बनने पर काफी हद तक बेकारी की समस्या का हल हो सकता है और साथ में अनाज की समस्या का भी हल हो सकता है। इसके लिए जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ पर इन्जिनियर लोग कई दफा गये हैं और इन्क्वायरी की है और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वहाँ पर बान्ध बांध दिया जाय तो खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा और उसके साथ-साथ वहाँ की जनता को राहत मिलेगी।

इसके अलावा बीच में हमने सुना था कि सर्वे वगैरह का काम हरिका प्रोजेक्ट का हो चुका है और उससे जो नहरें निकलेंगी वे जैसलमेर से होती हुई जोधपुर के इलाके की सिंचाई करेंगी। उसका नाम तक राजस्थान नहर रख दिया गया था और लोगों ने वहाँ बसने के लिए जमीनें भी खरीद ली थी और अपनी-अपनी योजनायें शुरू कर दी थी, किन्तु उस नहर के आने का क्या हुआ, कैसे आयगी, कब आयगी कुछ पता नहीं। अब तो ऐसा मालूम हो रहा है कि राजस्थान सरकार की लापरवाही की वजह से नहरें नहीं आ सकेंगी, ऐसा मालूम हुआ है। इसका माननीय मन्त्री अवश्य जवाब देंगे। वास्तव में वह स्कीम सफलता पाने के योग्य है या नहीं, यह कह नहीं सकता। सरकार इस विषय में क्या सोच रही है या सिर्फ सर्वे होकर ही वह खत्म हो गई, इस बारे में जानकारी अवश्य मिलनी चाहिये।

इसके अलावा जो इलाका हमारे उधर आया हुआ है, जो नखलिस्तान आया हुआ है उसकी सिंचाई के लिए पैसा दिया जाय तो मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि वहाँ जो अकाल की समस्या बनी रहती है वह काफी सुलझ जायगी।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्रों ने सिंचाई के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। सिंचाई विभाग की हमेशा यह नीति रही है और विचार रहा है कि जो कोई भी सिंचाई के विषय में अच्छे सुझाव दें उन पर खूब गम्भीरता पूर्वक विचार करें और उन्हें अमल में लाने की कोशिश करे। वैसे तो इसमें जो वाद-विवाद की बातें हुई है उनमें से थोड़ी सी बातें

[श्री भोगीलाल पंड्या]

ऐसी हैं जो भ्रम फैलाने वाली हो सकती हैं, उनका मैं संक्षेप में जवाब दूँगा, बाकी की जो बातें हैं वे ठीक हैं।

सबसे पहले मेरे एक माननीय मित्र ने बतलाया कि एस्टीमेट्स के सेंक्शन कराये बगैर ही काम शुरू कर दिये जाते हैं, न मालूम उन्होंने यह कैसे कहा ? उन्हें यह कैसे मालूम हुआ ? सिंचाई विभाग का तो यह नियम है कि वह पहले एस्टीमेटस सेंक्शन करवाये और बाद में काम शुरू होता है। अगर कोई अनिवार्य कारण हो तो उस काम के शुरू करते ही अकाउन्टेन्ट जनरल को सूचना दे दी जाती है और पैसा तब तक नहीं देते जब तक कि उसकी पूरी-पूरी मन्जूरी की कार्यवाही नहीं हो जाती। यह तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने यह बात कैसे कही ? यह बात अलग है कि पुराने कोई काम बिना एस्टीमेट के शुरू हो गये होंगे, उनको रेगुलराइज़ (नियमित) कराने का सिंचाई विभाग प्रयत्न कर रहा है। उनको रेगुलराइज़ कर दिया गया है और जो कोई बाकी होगा उसको भी रेगुलराइज़ कर दिया जायगा।

दूसरी बात जवाई के बारे में कही गई कि वहां पर ऐसी व्यवस्था है कि जागीरी और खालसा दोनों में सिंचाई की दर अलग-अलग ली जाती है। इस पर भी मेरा यह कहना है कि मेरे माननीय मित्र को भ्रम हो रहा है। ऐसा नहीं है। जोधपुर रियासत के वक्त और जयपुर रियासत के वक्त के ऐसे नियम बने हुए हैं क्योंकि खालसा पर गवर्नमेंट खर्च करती है, उसको लगान मिलता है और सिंचाई की दर भी मिलती है। इस तरह से अनाज वगैरह का भी लाभ मिलता है। इस समय जयपुर और जोधपुर रियासतों के वक्त के रेट्स बने हुए हैं उन पर सरकार विचार कर रही है कि दोनों में जो अन्तर है वह मिटा दिया जाय और इधर जागीरी रिज़म्प्शन का काम भी चल रहा है। इस तरह से जल्दी ही तय हो जायगा, फिर इस प्रकार का कोई अन्तर नहीं होगा। ऐसी बात नहीं कि जवाई में दो प्रकार की रेटस ली जाती हो। शुरू-शुरू में जरूर दोनों में अन्तर था किन्तु अब दोनों की एक ही रेटस से वसूली की जाती है।

तीसरी बात यह बतलाई गई कि गंगानगर में सिंचाई के रेट्स सौ फी सदी बढ़ गये हैं, यह बात ऐसी नहीं। गंगानगर में अमुक-अमुक जिन्स पर ड्योढ़े लिए गए और किसी-किसी पर ड्योढ़े से भी कम है। पहले जो सिंचाई के रेट्स थे उनसे कहीं-कहीं ड्योढ़े से भी कम हैं। अगर सही हालत को देखा जाय तो पंजाब में हमारे से पहले डेढ़े रेट्स हो चुके थे, उसके बाद हमारे यहाँ गंगानगर इलाके में वैसे किये गये। हमने वहाँ के मुकाबले कुछ विशेष बात की हो, यह बात नहीं है। यह सही है कि जमीन के जो रेट्स यहाँ लिये जाते हैं वे पंजाब के मुकाबले कहीं-कहीं ज्यादा हैं। उसी तरह से पटवार भी नहीं लिया जाता, यहाँ लिया जाता है। अगर इन सबको मिला देते हैं तो एक-दो जिन्स में भले ही फर्क रह जाता हो, पंजाब के मुकाबले में यहाँ ज्यादा योग नहीं रहता है। सरकार के सामने यह सब परिस्थिति रखी थी। सरकार ने इस पर विचार करके कुछ जिन्स पर रेट्स कम कर दिये हैं।

उन माननीय सदस्य ने यह भी बतलाया कि पानी में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। न मालूम उन्होंने गंग कैनाल के बारे में यह बात कैसे कह दी ? पानी ज्यादा मिलने के कारण आबपाशी ५०

[श्री भोगीलाल पंड्या]

हज़ार एकड़ ज्यादा बढ़ा दी गई है। कम पानी था तब आबपाशी जरूर कम होती थी। मोखे बने हुए हैं, उसमें पानी ज्यादा-कम का सवाल ही नहीं उठता। मोखे बने हुए हैं और फसल पकने के बाद चार्जेज़ किये जाते हैं। माननीय सदस्य ने जो बात कही, उस बात से भ्रम दूर हो जायगा।

एक माननीय मित्र ने बताया कि सिंचाई का काम ठेकेदारी के द्वारा होता है और उसमें फिर जो तालाब बनते हैं, बाँध बंधते हैं, वे तुरन्त ही टूट जाते हैं। यह भी उनका खयाल गलत है। जितने तालाब बनते हैं वे सभी टूट ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। तुरन्त टूट जाते हैं तो उसका तो पैसा ही नहीं दिया जाता है और तालाब बनते हैं उनके लिए टेन्डर माँगे जाते हैं जिसका नीचा टेन्डर होता है उसी को दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मर्जी माफिक किसी भी आदमी को बाँध बाँधने या तालाब बनाने का काम दिया जाता हो।

आपने कुछ ऐसे भी उदाहरण बताए कि दूसरी जगह ज्यादा काम होता है, आपके यहाँ नहीं। पर भीलवाड़ा जिले में कुछ तालाब बने हैं, यह नहीं बताया। माइनर इर्रिगेशन का काम वहाँ चल रहा है यह बताया होता तो शायद सरकार की प्रशंसा होती। आपने केवलिया तालाब के बारे में बहुत बताया और एक तालाब के बारे में और बताया पर मैं निवेदन कर दूँ कि जितना काम आपके ध्यान में है वह सब नहीं बन सकता, पर फिर भी एक खुश खबरी आपको सुना दूँ कि आपका देवरिया तालाब जो है उसका एस्टीमेट तैयार हो चुका है और २॥ करोड़ की मीडियम इर्रिगेशन स्कीम में वह ले लिया गया है।

इसके बाद एक मित्र ने बताया कि जयसमन्द पर जैसा चाहिये वैसा ध्यान नहीं दिया जाता। पर यहाँ भी ऐसा नहीं है। इस पर भी सरकार द्वारा पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है। इसका अनुमान आपको इस सूचना से हो सकता है कि राजस्थान बनने से पहले ३५०० एकड़ की सिंचाई इससे होती थी, पर अब राजस्थान बनने के बाद वह सिंचाई बढ़कर १२ हजार एकड़ की हो गई है। इसमें अब भी गुँजाइश है और इस ओर सरकार बराबर प्रयत्नशील है। यह बात सही है कि पिछले साल कुछ कठिनाइयाँ ऐसी आ गई थीं और एक ऐसी पहाड़ी आ गई थीं बीच में कि इससे जितना चाहिये उतना काम नहीं बढ़ सका, पर दूसरी बाजू काफी काम हुआ है यह मेरे मित्र को मालूम था, फिर भी इसके लिए उन्होंने नहीं कहा। आगे इसका ४,२५,००० रु० का एस्टीमेट बन चुका है और इसे लघु सिंचाई योजना में रख दिया गया है, यह भी उनको मालूम है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाता, सब पर यथा-योग्य ध्यान दिया जाता है और आगे भी दिया जाता रहेगा।

एक मित्र ने बताया कि लसाड़िया में काम नहीं हो रहा है। इसके बारे मैं बताऊँ कि वास्तव में वह पिछड़ा क्षेत्र है, भील वहाँ रहते हैं और लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहाँ अकाल के कारण कुछ रुपया खर्च करना पड़ा है और माननीय सदस्य भी इन सारी बातों को जानते हैं। वहाँ इन कारणों से भी काम नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर भी तीन तालाब

[श्री भोगीलाल पंड्या]

तो बन चुके हैं; पोकर, भावरी और बावड़ी बन चुकी हैं। गरधाना तालाब का काम चल रहा है। इसके बाद और भी काम बनेगा, माइनर इरिगेशन का काम बनेगा तथा और-और भी काम बनेंगे।

एक मित्र ने बताया और दो एक उदाहरण भी दिये कि कहीं दो तालाब बने हैं और उनमें पानी नहीं टिकता। क्या ही अच्छा होता क्योंकि वे बार-बार मुझे से मिलते भी रहते हैं, यदि वे मुझे बताते उन तालाबों को और बात करते; वहाँ ले जाते तो अच्छा होता। वैसे मेरे खयाल से तो वहाँ पानी टिकता ही होगा। पर चूँकि उन्होंने इस समय सदन के सामने सूचना दी है तो मैं उनको विश्वास दिला देता हूँ कि अगर पानी कम होगा तो पानी टिकने का इन्तजाम कर दिया जावेगा।

यह भी कहा गया कि पहले सर्वे काम का नहीं होता, ऐसा नहीं है। बराबर योजना बनती है इसके लिए और उसके अनुसार ही काम होता है। बाद में उन्होंने कहा कि राऊवास के बन्ध पर मोरी ऊँची रक्खी गई; तो मोरी तो बिल्कुल हिसाब से ही बनाई गई है, डिज़ाइन जैसी थी वैसी ही हिसाब से बनाई गई है। अब पानी ही उसमें कम आया और इस कारण नीचे के खेतों में नहीं पहुँच पाया हो, तो यह अलग बात है। अगले साल पानी से भर जावेगा तो यह शिकायत भी नहीं रहेगी। पर अगर लगातार तीन-चार साल भी पानी नहीं आ सकने की सम्भावना रही तो अगले साल नीची मोरी बना दी जावेगी। इसके लिए उन्होंने, भ्रष्टाचार हुआ, रिश्वतखोरी का बाज़ार गरम रहता है, गड़बड़ियाँ हुईं आदि अनेकों बातें कह दीं। इसके लिए मैं निवेदन कर दूँ कि यह एक ही काम नहीं है, सैकड़ों जगह ऐसी ही काम चल रहे हैं और वे सभी योजना के अनुसार, डिज़ाइनों के हिसाब से ही चल रहे हैं और हरेक का बराबर हिसाब से काम होता है। यदि हम डिज़ाइन के अनुसार काम नहीं करे तो भारत सरकार हमें रुपया ही न दे, यह हमारी बड़ी कठिनाई है; इसको तो आप समझ लीजिये।

एक और बात बताई गई कि ये मिनिस्टर जो हैं उदयपुर डिवीज़न के हैं, इसलिए उदयपुर डिवीज़न में ही ज्यादा काम कराते हैं तथा और कहीं होता ही नहीं है; माइनर, मीडियम और लांग इरिगेशन का काम, सभी प्लान का काम वहीं होता है। मेरे माननीय मित्र ने थोड़ा-सा भी अगर ध्यान दिया होता तो उन्हें मालूम होता कि जितने सारे मेजर वर्क हो रहे हैं वे अधिकतर या तो जोधपुर डिवीज़न में हो रहे हैं, दूसरे बीकानेर डिवीजन में हो रहे होंगे या कोटा डिवीजन में हो रहे होंगे और साथ ही उनको यह भी खयाल नहीं रहा कि सिंचाई मन्त्री उदयपुर डिवीजन के नहीं हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हें इसका ध्यान नहीं रहा और वे सब बातें कह गये।

इसी तरह से मीडियम योजना के कामों के बारे में मैं कह दूँ कि जहाँ उपयोगी स्थान होता है और जितना खर्चा होता है उस हिसाब से रिटर्न जो देता है तो वहाँ यह काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सिंचाई का मन्त्री हुआ तो अपने घर में या अपने गाँव में ही सब सिंचाई

Page No.124

[श्री भोगीलाल पंड्या]

का काम करा लेता है। ऐसी बात नहीं है। जो उपयुक्त स्थान होता है, रिटर्न जहाँ से निकल सकता है वहीं काम होता है।

एक मित्र ने बताया कि सीकर के पास, उधर कोई गाँव है वहाँ पर भी कोई तालाब पर बाँध नहीं बन रहा है। मेरा खयाल है कि अगर वहाँ भी ऐसा मौका होगा तो जरूर वहाँ हम जावेंगे। अभी तक तो ऐसा कोई मौका मेरे ध्यान में नहीं है और माननीय मित्र ने इससे पहले तो नहीं बताया, अब ही बताया है। अगर पहले बताते तो मैं सर्वे में प्राथमिकता देता। अगर ऐसा स्थान कहीं है तो माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि वे मुझे बताएँ। ऐसा मुझे स्मरण है कि एक-आध योजना उधर की तरफ थी सरदार पटेल के समय में और उन्होंने उस योजना का सर्वे भी कराया था, पर वह स्थान भी उपयुक्त साबित नहीं हुआ, और पानी भी पूरा नहीं होता था, रिटर्न भी नहीं मिलता था, कम होता था इसलिए उसे स्थगित कर दिया गया था।

इसके आगे यह बताया गया कि भाखरा का जो काम चल रहा है, वह काफी आगे बढ़ गया है और जून तक हमें उसका पानी भी मिलने लग जावेगा; पर पता नहीं राजस्थान सरकार क्या कर रही है इसके लिए, वह पानी जो आने वाला है उस पानी को ले भी सकेगी या नहीं; तथा यह भी बताया कि पंजाब सरकार की कृपा हुई तो मिलेगा। इसमें कृपा का सवाल नहीं है। इस भाखरा-नांगल के काम में से हमें हमारे अधिकार के तौर पर १५ प्रतिशत मिलने वाला है, वह मिलेगा। इसमें कृपा कैसी ? किसी से भिक्षा थोड़े ही माँग रहे हैं। हमें १५ प्रतिशत मिलेगा और हम उसका उपयोग करेंगे।

और आगे यह बात भी बताई कि काम जो है; जिस ढङ्ग से चाहिये वैसा नहीं हो रहा है। इस बारे में मैं निवेदन कर दूँ कि इसका एक बोर्ड बना हुआ है। उसके पास हर दिन और हर सप्ताह काम की प्रगति की रिपोर्ट जाती है और इससे उनको सन्तोष है। यदि कमी होती है तो तुरन्त वे बता देते हैं कि अमुक काम में क्यों इतनी कमी हुई। तो योजना के अनुसार काम होता है। अगर जून-जुलाई में पानी मिलने वाला है तो हम निश्चित रूप से उसका उपयोग करेंगे और सिंचाई होगी उससे। यह मैं पहले कह चुका हूँ कि जो रेटस गंग नहर की हैं वह आबपाशी की जो रेट्स पंजाब की है उनसे ज्यादा नहीं हैं। पहले पंजाब में जो रेट्स थीं उन्होंने उससे ड्योढ़ी की हैं इसी तरह से हमने भी ड्योढ़ी की हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिंचाई की रेट ज्यादा नहीं है। बल्कि पंजाब से भी किसी सूरत में हमारे यहाँ कम हैं और राजस्थान के दूसरे हिस्सों से भी कम हैं। ये रेट्स, करौली, उदयपुर और जोधपुर डिवीजन में भी जो रेट्स हैं, उनसे भी कम हैं।

आगे एक मित्र ने बताया कि उनके जोधपुर राज्य में योजना बनाई थी और उसको कार्यान्वित नहीं किया और खर्चा नहीं किया गया। न मालूम मेरे उन मित्र को कैसे मालूम हुआ कि वहाँ खर्चा नहीं हो रहा है और योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। वहाँ तो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जोधपुर में जवाई का काम तो हो ही रहा है इसके अलावा भी और क्या-क्या नाम गिनाऊँ, जोधपुर डिवीजन में होने वाले कामों की बड़ी लिस्ट है और इसको अच्छी तरह से जानते हैं वे। पर

[श्री भोगीलाल पंड्या]

जानते हुए भी यह बात अलग है कि वे अनजान बनें। आपके शेरगढ़ में विलाड़ा नामक ग्राम का सर्वे हुआ था। इसका काम नहीं हुआ तो इसकी भी जाँच करावेंगे।

यह भी मैं अब आपको एक खुश खबर सुना दूँ कि हमें काफी रुपया और मिला है जिसको हमें, जहाँ पर कम रिटर्न मिलेगा वहाँ भी खर्च करना है और वह अच्छी खासी बड़ी रकम है। हम इसका उपयोग करेंगे।

इस समय में, अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सभी मित्रों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि वे सब ऐसी जितनी भी योजनाएँ हों कि जिसका रिटर्न कम भी आवे तो वे उन्हें सिंचाई विभाग को बतावे। हम उसका सर्वे करके जल्दी से जल्दी सिंचाई की व्यवस्था के लिए उचित कार्यवाही करेंगे। उसके बाद में एक मित्र ने बताया कि कोई एक योजना ऐसी थी कि जिसके आधार पर लोग बस गये, लेकिन अब बेचारे उजड़ रहे हैं; क्या करें, न करें। मुझे ध्यान नहीं है कि ऐसी योजना के कारण गाँव जो बस गये थे, वे उजड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है।

अलावा मैं जानता हूँ कि हरिका प्रोजेक्ट की बात आपने पूछी, तो हरिका प्राजेक्ट एक बहुत बड़ी योजना है। इससे करीब-करीब ३८ लाख एकड़ जमीन को सिंचाई होगी। जैसा कि आपने बताया कि जोधपुर के बहुत सारे हिस्से में सिंचाई होगी, ऐसा नहीं है; लेकिन फिर भी जैसलमेर का काफी हिस्सा उसमें आ जाता है और बहुत बड़े हिस्से में इससे सिंचाई होगी ३८ लाख एकड़ भूमि पर। इसके लिए भी कहा गया है कि राजस्थान सरकार की लापरवाही से वह योजना खत्म हो गई और राजस्थान को पानी नहीं मिलेगा। राजस्थान सरकार ने बराबर प्रयत्न किया है, और उसके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही उस योजना का कार्य निश्चित होने जा रहा है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में नदियों के पानी के बारे में झगड़ा था और उस झगड़े का फैसला आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ऊपर की तीन नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलेगा और बाकी तीन नदियों का, सतलज आदि का पानी हम को मिलेगा। इस तरह की केन्द्र के द्वारा व्यवस्था हो रही है। इस तरह का समाचार आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। जब यह व्यवस्था हो जायगी तो उसका लाभ मिलेगा, और राजस्थान सरकार उसमें जरा भी प्रयत्न करने में कमी नहीं कर रही है। वह लगातार प्रयत्न कर रही है और बहुत जल्दी ही पानी राजस्थान को मिलेगा और राजस्थानी जनता को उससे लाभ मिलेगा। इसलिए हमको धीरज रखना चाहिए कि वह पानी हमको मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो कुछ आवश्यक बातें उठाई थीं, उसका जवाब दे दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि सब उसको एकमत से स्वीकार करेंगे, जो माँग की गई थी उसको।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जवाई के सिलसिले में इरिगेशन रेट के बारे में जो मैंने बयान दिया था वह पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय माननीय श्री जयनारायणजी व्यास की स्पीच में से कोट करके दिया था। अगर वह गलत है, तो उसकी जिम्मेवरी उन पर डाइरेक्ट कर दी जाय।

Page No.126

श्री जयनारायण व्यास—मैं उसका उत्तर दे देना ठीक समझता हूँ। यह बात ठीक है कि पुरानी जोधपुर रियासत के जमाने में यह रेट्स चली आ रही हैं, लेकिन अब वह रेट्स बराबर कर दी गई हैं। यह सूचना सुनकर माननीय सदस्य को खुशी होगी।

श्री कँवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, मंत्रीजी अगर चम्बल के कार्य पर प्रकाश डालें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—Should I put all these cut motions to vote now ?

(विराम)

The question is that the cut motions moved by shri H. K. Vyas, No. 124, 126 and 127, be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motions fail.

(विराम)

The question is that a cut motion by Shri Shambhu Singh be accepted.

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कट मोशन को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Shambhu Singh to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई, वापिस लीजिये।

श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर—Mr. Speaker, Sir, I beg leave to withdraw my cut-motion.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Bhatnagar to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई।

श्री सोहनलाल भटनागर—I withdraw.

श्री उदयलाल वर्दिया—माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से सूचना चाहता हूँ कि मेरी दो शिकायतें हैं एक तो सरवे के बारे में...

श्री अध्यक्ष—आप विथड्रा करते हैं या नहीं?

श्री उदयलाल वर्दिया—मैं विथड्रा करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri Wardi to withdraw his cut motion.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान हुई।

श्री उदयलाल वर्दिया—मैं विथड्रा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut-motion by Shri Bhairon Singh (16) be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut motion fails.

(विराम)

The question is, "That a sum not exceeding Rs. 83,13,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. VIII, Major Head XVII—Irrigation Works etc."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

भारतीय शासकों को प्रिवी पर्स तथा भत्ते—२६

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 17,36,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955 in respect of Grant No. XXIX, Major Head 54-B-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers."

Cut motion by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Both together?

श्री अध्यक्ष—Both.

श्री हरिकृष्ण व्यास—1. Economy-Retrenchment of charity grant to His Highness Udaipur.

2. Economy-Retrench—facility for free supply of water and electricity.)

माननीय अध्यक्ष, इस माँग के सिलसिले में मेरे २ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

५ लाख का और वह यह है कि महाराजा उदयपुर का चेरिटी का काम चलता रहे, ऐसा कहकर जो ५ लाख की रकम सालाना दी जाती है और जो वोटेड है वह रकम अब उनको देना बन्द कर दी जाय। उसकी न कोई आवश्यकता है, न उसके देने के लिए न्यायोचित आधार है और न ही यह कहा जा सकता है कि यह कोई समझौते का या कोई बड़ी दूरदर्शिता का या इस प्रकार का कोई कदम था जिसे आज भी चालू रखने की आवश्यकता है। न मालूम इस प्रकार की विशेष चीज़ इस सिलसिले में क्यों की गई और न ही कोई कारण है कि आज भी उसे चालू रखा जाय। भारत में विभिन्न रियासतों के उस समय के जो राजा थे उनसे एग्रीमेंट हुए हैं या प्रिवीपर्स के बारे में जितने फैसले हुए हैं एक भी ऐसी दूसरी मिसाल हमें देखने को नहीं मिलेगी कि जहाँ प्रिवी पर्स की रकम मिलते हुए भी उससे अलग उनके ५ लाख रुपये चेरिटी करने की उनकी आदत थी, तो उस आदत से कहीं महरूम न हो जाँय इस आधार पर ५ लाख की मन्जूरी दी गई हो। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि यह ५ लाख रुपये की मन्जूरी न दी जाय।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव जो है, माननीय अध्यक्ष, वह है, बिजली की और पानी की जो सहूलियतें दी गई हैं तीन जगह के भूतपूर्व राजाओं को उसके बारे में। वे सहूलियतें अब रद्द कर दी जाँय। उससे वैसे ही लाखों रुपयों का नुकसान राजस्थान की जनता का हो रहा है और यह बिजलीघर घाटे में जाते हैं उसका कारण एक यह भी है कि जितनी बिजली इनके पेलेसेज में दी जाती है उनकी कोई आमदनी सरकार के खजाने में जमा नहीं होती है। वास्तव में यह एग्रीमेंट किया गया था कि सन् ५० तक उसमें जितना खर्चा होता था बिजली का उसकी मियाद मुकर्रर कर दी जायगी, लिमिट मुकर्रर कर दी जायगी कि एक लिमिट तक वह फ्री दिया जायगा और उस लिमिट के ऊपर खर्चा हुआ तो उसके लिए पैसा लिया जायगा। लेकिन सन् ४९-५० के बाद आज ४ साल होने आये, किन्तु अभी तक भी सरकार के द्वारा वह मयाद मुकर्रर नहीं हो पायी है, वह लिमिट भी तय न हो पायी है। इस वजह से इतना खर्चा बिजली और पानी पर हो रहा है व सब किया गया है वह फ्री सप्लाई हो रहा है। एक पैसा भी सरकार के इस विभाग को नहीं मिल रहा है और यह खर्चे की तादाद है वह लाखों के ऊपर जायगी, माननीय अध्यक्ष। मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि इन तीन राजाओं को बिजली और पानी की मुफ्त सप्लाई बन्द कर दी जाय तो कम से कम २ लाख रु० या हो सकता है इससे भी ज्यादा रुपयों की बचत और हो सकती है। पाँच और दो सात लाख रुपये जो इस तरह से बच सकते हैं वे राष्ट्र-निर्माण के कार्य में या कल्याणकारी कार्यों में खर्च किये जा सकते हैं। इस आशय के मेरे दोनों कटौती प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

Any other member who wants to Participate ?

(विराम)

None (श्री मुख्य मन्त्री को संकेत करके) Reply.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, श्री एच. के. व्यास ने दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उनमें से एक तो ५ लाख रुपये की उस रकम के मुत्तल्लिक है जो महाराज प्रमुख को चेरिटी चालू रखने के लिये दी जाती है और दूसरी जो तीन राजाओं को बिजली और पानी की रियायत दी गई है उसके सम्बन्ध में है। इसमें कोई शक नहीं कि दान-पुण्य के लिये रकम अभी देना कई लोगों के दिमाग में अच्छा नहीं लगता है। वह जिस तरह से दी जा रही है दान-पुण्य की प्रणाली में मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ; लेकिन शायद श्री एच. के. व्यास उन सेन्टिमेन्ट्स को, उन भावनाओं को समझने में इतने समर्थ नहीं हैं जितने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गये थे। उनके हाथ में था कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के राजा भारत के साथ सम्बन्ध करते या पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध करते या स्वतन्त्र रहते, लेकिन देश की भावनाओं को उन राजाओं ने समझा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थोड़े से रुपयों के लिये उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना उचित नहीं समझा। महाराजप्रमुख, जिनकी उम्र काफी है अब आदत बदलने के लिये कहना उनके साथ न्याय करना नहीं है। अतः ५ लाख रुपये सालाना देना स्वीकृत किया गया था। मैं समझता हूँ कि सरकार ने उनकी जिन भावनाओं और उनके जिन सेन्टिमेन्ट्स को लेकर दान-पुण्य की प्रणाली चालू रखी उनको देखते हुए यह रकम फिलहाल रहनी चाहिये और जब आवश्यकता होगी उस रकम को न देने की, तब हम इसको वोट न करेंगे।

दूसरा बिजली और पानी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। यह प्रसंग भी राजाओं के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें तय किया गया था कि उन राजाओं को बिजली-पानी मिलेगा। लेकिन सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो अनियंत्रित पानी और बिजली का खर्चा है उसको रोकने का प्रबन्ध कर लिया गया है और कुछ रुक भी गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी किसी प्रश्न के उत्तर में सूचना दे सकूँगा कि इसको किस तरह से रेगुलेट किया गया है? यह सही है कि इसमें कुछ रकम सरकार को देनी पड़ती है और वह इसलिये कि हमने एक वचन दिया था, एग्रीमेंट किया था। जो सरकार अपने वचन और एग्रीमेन्ट की इज्जत नहीं कर सकती, चाहे उसको ५ पैसे की कमी पड़ती है तो वह आगे जाकर कई तरह के असमन्जस में पड़ जाती है। यदि राजाओं ने हमारे साथ समझौता किया है, भारत के साथ आना तय किया है तो यह ख्याल करके तय किया है कि हम ऐसे लोगों के साथ तय कर रहे हैं जो वचन का मूल्य जानते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारे वचनों का हमारा सदन सम्मान करेगा। ७ लाख रुपये राजस्थान जैसी बड़ी रियासत के लिये छोटी रकम है, इसलिये मैं प्रार्थना करूँगा कि इस ग्रान्ट को मन्जूर कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—I put it to vote. The question is that both the cut-motions moved by Shri H. K. Vyas be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motions fail.

(विराम)

The question is that the Demand be accepted.

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

The Demand is passed.

उद्योग तथा रसद—२३

Now we come to Industries and Supplies. The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 47,54,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXIII, Major Head 43—Industries and Supplies."

There are four cut-motions by Shri H. K. Vyas : two Economy cuts and the other Token cuts. They are all to be moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't want to move my cut-motions.

श्री अध्यक्ष—Shri Kapil Deo Agarwal.

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह—I also don't want to move,

श्री खेतसिंह—I am not in a mood to move.

श्री तेजमल बापना—When nobody is going to move I also don't want to move my cut-motions.

श्री चांदमल मेहता—(1. To discuss the failure of the Government in the development of soap and Khursd industry.

2. To discuss the failure of the Government in making sufficient provision for the development of large scale industries.)

अध्यक्ष महोदय, मैंने इंडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में २ कट मोशन्स रखे हैं, एक है लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ के बारे में और दूसरा है खर्ड और सोप इन्डस्ट्रीज़ के बारे में। मैं पहले सोप और खर्ड इन्डस्ट्रीज के बारे में निवेदन करूंगा। विभाजन के पूर्व जयपुर नगर राजस्थान में खर्ड इन्डस्ट्रीज़ के लिए विश्व में खास स्थान रखता था। विभाजन के पूर्व जयपुर में पन्ना, नीलम और माणक सीलौन, बरमा और श्याम से मंगाये जाते थे और इन रफ स्टोन्स को जयपुर में मेनुफेक्चर किया जाता था और फिर अमेरिका, फ्रान्स आदि विदेशों को भेजा जाता था। इस इन्डस्ट्री पर जिन लोगों का निर्वाह चलता था उनकी संख्या लगभग २५००० थी। उनमें से १५ पर्सेन्ट व्यापारी या दलाल थे और बाकी मजदूर थे। विभाजन के बाद भारत सरकार ने इम्पोर्ट बंद कर दिया, शायद यह सोच कर कि यह लग्ज़री में शामिल है। इसके बाद इम्पोर्ट में कुछ सहूलियतें दी गई लेकिन कई तरह की बन्दिशे लगा दी गई

[श्री चाँदमल मेहता]

और इस वजह से यह धंधा पहले की तरह आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ के कारीगर इतने कुशल थे कि वे एक रत्ती में १५० नग तक मेनुफेक्चर करते थे और बाहर भेजते थे। ऐसे कारीगरों की अभी भी कमी नहीं है। इसके बाद चन्द दिनों से तो यह उद्योग एक तरह से समाप्त-सा हो गया है। अभी एक नई स्थिति पैदा हो गई है और वह यह कि भारत सरकार के कुछ आदमी यहाँ आये हैं और उन्होंने कई व्यापारियों का माल जब्त कर लिया है। इसका कारण यह बताया जाता है कि उनके पास जो माल है वह चोरी से आया है। रफ स्टोन्स के मेनुफेक्चर का जहाँ तक संबंध है, एक व्यापारी कच्चा माल खरीद करता है और उसे अपने ढङ्ग से धीरे-धीरे तैयार कराता है और फिर दूसरे के पास पहुँचता है वह अपने ढंग से तय्यार कराता है और तीसरा अपने ढङ्ग से तैयार कराता है। इस तरह से जैसे-जैसे व्यापारियों के हाथ में वह जाता है तब्दील होता जाता है। तो आज भारत सरकार के आदमी जो यहाँ आये हुए हैं, वे इन व्यापारियों से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पास यह माल कहाँ से आया ? क्योंकि जैसा कि मैंने निवेदन किया उस माल की शक्ल तब्दील होती रहती है, वह माल एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पाँचवें के पास और फिर आगे से आगे कई दूसरे व्यापारियों के पास जाता रहता है, कई व्यापारियों के हाथ से निकलते रहता है, उसकी शक्ल तब्दील होती रहती है; तो ऐसी सूरत में यह बताना मुश्किल है कि वह माल कहाँ से आया ? इस प्रकार १५००० आदमी जो इस काम पर आश्रित थे वे आज बेकार हो गये हैं और उनका काम ठप्प हो गया है। यद्यपि इस काम के बारे में कहा जा सकता है कि यह काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है परन्तु मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि यह एक ऐसा धन्धा है जिससे थोड़ी कीमत में माल विदेशों से आता है और इससे तैयार होकर जो माल बाहर विदेशों में जाता है वह बहुत ज्यादा कीमत पर जाता है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें और इस खर्ड उद्योग की जो गिरती हुई हालत है इसके बारे में यहाँ के व्यापारियों को मौका दें कि वे अपनी कठिनाई आपके सामने रखें और आप फिर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात-चीत करके उसे बतला दें कि यह एक बहुत ही अहम उद्योग है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। जयपुर पहले भी विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान इस काम के लिये रखता था और अगर इस उद्योग को फिर से आगे बढ़ने का मौका दिया गया तो आगे भी इसका वही स्थान रहेगा।

दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है वह साबुन के उद्योग के बारे में है। वैसे तो छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के बारे में बहुत कम ख्याल किया जाता है, परन्तु साबुन के उद्योग के लिये भी कुछ नहीं किया है। साबुन के उद्योग के लिये राजस्थान सरकार ने जो कुछ किया है वह यह है कि साबुन के कारखानों को जितनी कस्टम की रियायत वगैरह की सुविधाएं स्टेटों के समय में प्राप्त थीं उनको भी छीन लिया गया है, यह किया है।

साबुन में खोपरे का तेल और मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है। आज खोपरे के तेल पर १० रुपया फी मन की ड्यूटी है। जनवरी महीने में आदेश निकला है कि जिन साबुन के कारखानों और तेल को रिफाइन करने वाले कारखानों को कस्टम ड्यूटी की रियायत की सुविधाएं थीं उनका सस्पेन्शन कर दिया गया है। इससे कारखाने खत्म हो गये हैं। राजस्थान का एक बड़ा कारखाना हंसा केमिकल फार्मेसी, जिसके बारे में बड़े-बड़े व्यक्तियों ने, माननीय पालीवालजी, माथुर साहब

Page No.132

[श्री चाँदमल मेहता]

आदि और भी कई बड़े-बड़े व्यक्तियों ने यह विचार प्रकट किया था कि राजस्थान में यह अपनी शान का एक ही कारखाना है, इसको अगर और बढ़ाया जाय तो यह हिन्दुस्तान के कौने में एक बहुत बड़ा कारखाना हो सकता है। उस हंसा केमिकल फार्मेसीं में पिछले वर्ष में जितना माल आया उसकी कस्टम की रकम आज की कस्टम की तरह से १५,०००) रुपया होगी। कोई भी कारखाना १५,०००) रुपया सालाना कस्टम का देकर जिंदा नहीं रह सकता। उस कारखाने की ऑडिट रिपोर्ट से नफा और नुकसान के बारे में जानकारी हो सकती है।

मैं मानता हूँ कि यह इस तरह का आदेश इसलिये दिया गया है कि कुछ आदमी कारखानों के नाम से कस्टम-मुक्त रहने के नाते सामान ले आते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं, उनकी सजा इन कारखानों को दी जाती है। अगर कोई अपराध करते हैं तो उन अपराध करने वाले लोगों को सजा देनी चाहिये, न कि उनके बदले इन कारखाने वालों को। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये कारखाने टप्प हो जायेंगे।

दूसरा मेरा कट मोशन है बड़े उद्योग-धंधों के बारे में। पहली बात तो यह है कि राजस्थान में बड़े उद्योग-धंधे हैं ही नहीं और अगर कहीं हैं भी तो उनकी हालत बड़ी ही सोचनीय है। हमारे प्रान्त में रॉ मैटिरियल (कच्चा धातु) बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होता है। हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों के मुकाबले में हमारे यहाँ राजस्थान में ऊन सब से ज्यादा पैदा होती है। उसका सबसे बड़ा हिस्सा हमारे राजस्थान से बाहर जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारे राजस्थान में एक भी वूलन मिल (woolen mill) नहीं है। वूलन मिल आज के जमाने में कोई उद्योगपति खोलने को तैयार नहीं होगा। आज जो सम्पदा कर लगा हुआ है उसकी स्थिति को देखते हुए जिनके पास पैसा हैं वे भी कभी पसन्द नहीं करते कि पैसा बाहर निकालें। कोई लिमिटेड कन्सर्न भी वूलन मिल खोलने में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि आम लोगों का विश्वास लिमिटेड कम्पनियों से उठ गया है क्योंकि जो मैनेजिंग डाइरेक्टर होते हैं वे मलाई-मलाई तो स्वयं खा जाते हैं और शेयर होल्डर्स को विशेष फायदा नहीं होता।

ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार को खुद को ऐसा कारखाना खोलना चाहिये चाहे इसके लिये कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। राजस्थान की बहबूदी के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजस्थान में वूलन मिल खुले और वह राजस्थान सरकार द्वारा खोला जाय।

इसके अलावा और भी कई कारखाने हो सकते हैं। इसके बारे में जाँच करने के लिये एक कमेटी बिठाई जाय जो यह मालूम करे कि किस तरह के उद्योग-धंधे पनप सकते हैं। उस कमेटी में सरकारी आदमियों के साथ-साथ जनता के भी आदमी हों।

अब मैं, हमारे यहाँ के बड़े-बड़े कारखानों के बारे में अर्ज करूँगा। अजमेर-मेरवाड़ा जैसे छोटे से हमारे पड़ौसी इलाके में हमारे प्रान्त के मुकाबिले में कितने टैक्सटाइल मिल्स हैं। हमारे

[श्री चाँदमल मेहता]

यहाँ जो एक दो टैक्सटाइल मिल्स हैं उनकी हालत बड़ी ही सोचनीय है। हमारे किशनगढ़ टैक्सटाइल मिल के १७००० स्पिन्डल्स जल गये। वहाँ के सेठ की अब ऐसी हालत नहीं रही कि वह इसे चला सके। वह मिल बन्द रहा। राजस्थान सरकार ने वहाँ के सेठ की मजबूरी को देख कर इस मिल को चालू करवाया, परन्तु इस मिल की हालत वैसी की वैसी है। जिस मजदूर को दूसरी मिलों में ५४) रुपये मिलते हैं वहाँ इस मिल में ३५) ही मिलते हैं। यदि इस बारे में इस मिल को सहायता नहीं दी गई तो यह जो कुछ मिलता है वह भी बन्द होने वाला है। जो मजदूरों और मिल मालिक के बीच एक एवार्ड (award) मन्जूर किया गया था उसमें इस तरह की चीज़ रखी गई है कि फिलहाल मजदूरों का २५ पर्सेंट रुपया जमा रहेगा, सरकार लोन (ऋण) दिलाने की व्यवस्था करेगी। अभी तक लोन दिलाने की व्यवस्था नहीं की गई है। परन्तु इस एवार्ड के मुताबिक जो जमा होता है उसके कट जाने के बाद मजदूर को ४०) भी नहीं मिलता। प्रोडक्शन (उत्पादन) के आधार पर इनको तनख्वाह मिलती है पर इस मिल की मशीनों के पुर्जे इतने घिसे हुए हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूँगा कि या तो ऐसे कारखानों को मुआवज़ा देकर सरकार अपने कब्जे में कर ले और उन्हें सरकार खुद चलावे; अगर सरकार मुआवज़ा देकर अपने कब्जे में नहीं ले तो फिर इन्हें लोन दे, या दूसरों से लोन दिलाये जायँ ताकि ये कारखाने अच्छी तरह चलें, मजदूरों को राहत मिले और राजस्थान का प्रोडक्शन बढ़े।

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री इस पर ध्यान देंगे।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझ रहा था कि इस विषय पर कोई कट मोशन नहीं आवेगा लेकिन चाँदमलजी ने कुछ कट मोशन लाने का प्रयास किया है। एक कट मोशन है उन लोगों के बारे में जो नगीनों को काट कर अपना काम चलाते हैं। आपने इस बात पर अफसोस ज़ाहिर किया कि उनकी तादाद कम हो गई है, इससे मजदूरों को बहुत नुकसान हुआ तथा क्योंकि १५ प्रतिशत पैसे वालों को इससे फायदा होता था और बाकी मजदूरों को फायदा होता था; मैं यह कहूँगा कि जब कोई उद्योग चलता है और कोई न कोई उसको चलाता है तो फायदे के लिए चलाता है। चाँदमलजी ने १५ प्रतिशत और ८५ प्रतिशत के आँकड़े बताये है उनको मैं उलटा करके बता सकता हूँ। इसमें १५ प्रतिशत धनवानों को फायदा होता था और ८५ प्रतिशत मजदूरों को या ८५ प्रतिशत मालिकों को और १५ प्रतिशत मजदूरों को, यह थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मगर यह सब होते हुए भी उद्योग-उद्योग है, चले तो हमें उससे खुशी है। उद्योग में कुछ कायदे-कानून बने हुए होते हैं। हमारे राजस्थान में भी स्थानीय उद्योगों के लिये सेन्टर ने कुछ कायदे-कानून बनाये हैं और उन्हीं कानूनों के आधार पर उन्होंने तलाशी ली। मेरे भी ध्यान में आया था कि सेन्टर के कुछ आदमी यहाँ पर आये थे और उन्होंने तलाशियें लीं। यह बात मुझे उद्योगपतियों से मालूम हुई थी। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूँ कि बिना बुनियाद के ये तलाशियें हुई हों, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि "गौयड़ के पाप से पीपली जल

[श्री जयनारायण व्यास]

जाय"। ऐसा ही हुआ होगा। कुछ गलत आदमियों के साथ रहने की वजह से सच्चे आदमियों को भी तकलीफ हुई हो। हो जाती है कभी-कभी। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे व्यापारी समाज में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो अपने थोड़े से फायदे के लिये कानून-कायदों को तोड़ देते हैं और गलत काम करते हैं। इससे व्यापारी समाज के दूसरे लोगों को तकलीफ होती है। जब ऐसी बात होती है तो हम तलाशियों को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर हमको विश्वास हो जाए कि कुछ ए० बी० सी० व्योपारी ऐसे हैं जो गड़बड़ नहीं करते हैं तो हम सेन्टर से बात-चीत भी कर सकते हैं।

अभी साबुन के बारे में कहा गया था कि कन्सेशन कम कर दिये गये हैं। सम्भव है और भी कुछ उद्योगों के कन्सेशन कम कर दिये गये हों। सरकार की हमेशा यही नीति रही है कि चाहे बड़े हों, चाहे छोटे उद्योग हों तथा चाहे साबुन का हो और चाहे तेल का उद्योग हो या जिनिंग प्रेस ही क्यों न हो; यदि उनकी वजह से दूसरे उद्योग पनपने नहीं पाते हों तो उनको बराबर लेबल में लाने के लिये कन्सेशन और कस्टम आदि में समानता लाएँ। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ है तो राजस्थान में इनका भी एकीकरण होना जरूरी है। मैं कह सकता हूँ कि हमारी सब स्टेटों को मिला कर राजस्थान बना। उससे कुछ दिन पहले कई तरह के कन्सेशन अलग-अलग रियासतों में लोगों को दिये गये थे। कुछ पहले से दिये हुए थे और कुछ रियासतों में राजस्थान बना उससे कुछ दिन पहले दे दिये गये थे। इसलिये आज राजस्थान में सब जगह कन्सेशन एक से नहीं होने से राजस्थान सरकार को इस असमानता को मिटाना पड़ेगा। हमको तो इस बात का अफसोस है कि अभी तक हम इस असमानता को नहीं मिटा सके और यह असमानता चली आ रही है। फिर भी मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कन्सेशनों में सब जगह समानता लाने की भावना से ही यह कन्शेसन कम किया गया है।

आगे आपने बड़े-बड़े उद्योगों की बात कही। इसमें कोई शक नहीं कि वे चलाए जावें। मैं चाहता हूँ कि वे चलें। मगर इसके लिये योजना कमीशन, सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार की तरफ से जब कुछ नियम बने उस समय कुछ ऐसे उद्योग रखे गये जो प्राइवेट सेक्टर में हैं। प्राइवेट सेक्टरों में हम दखल करें, यह बात ठीक नहीं। आपने कहा कि किशनगढ़ में मिल के स्पिन्डल्स जल गये। हो सकता है कि जिस प्रकार मोटरें आदि इन्स्योर्ड होती हैं उसी प्रकार ये स्पिन्डल्स भी जो जल गये हैं मिल द्वारा इन्स्योर्ड कराये हुए हों और उसके रुपये कम्पनी से वसूल हो गये हों।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इन्स्योर्ड किये हुए थे और कम्पनी से रुपये मिल गये हैं।

श्री जयनारायण व्यास--मेरे कॉम्युनिस्ट दोस्त को सब मालूम है। वे सब बही-खाते रखते हैं।

जो पैसा कम्पनी से मिला है वह काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा चाँदमलजी ने अपने भाषण में यह कहा है कि इस मिल की ऐसी दयनीय हालत हो रही है कि मिल के मजदूरों को २५), ३०) रुपया माहवार भी दे सकेंगे या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता इसलिये उसको सरकार

[श्री जयनारायण व्यास]

को सहायता देनी चाहिये। अगर उसकी बहुत अच्छी हालत नहीं है और सहायता देकर भी बहुत अच्छी हालत उस मिल की नहीं बन सकती है तो हम उसको सहायता देकर अपने आपको जोखम में डालना नहीं चाहते। अब रहा सवाल यह कि हम उस मिल को चलावें, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कई कम्पनियों के हिसाब-किताब देखे हैं। होता यह है कि रुपया-पैसा तो मैनेजिंग डाइरेक्टर खर्च कर देते हैं और ऐसी दयनीय हालत होती है तो सरकार से मदद के लिये कहते हैं। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है "बूढ़ी गाय बामण को दीजे" अर्थात बुड्ढी गाय ब्राह्मण को देने की बात सोची जाती है। मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ जो बुड्ढी गायों को इकट्ठी करके गोशाला या 'पोकर पोल' बनाऊँ। अगर वह कम्पनी चलने लायक है तो चलेगी। यह प्राइवेट सेक्टर का कन्सर्न है, उनको ही चलाना चाहिये। इसके अलावा सावधानी की बात यह है कि अगर उनको बचाया जा सकता हो तो सहायता दी जा सकती है। हम खुद उनको चलावें इस स्थिति में हम खुद अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने आपको नहीं पाते हैं।

चाँदमलजी ने उनके बारे में कहा। मैं यह कहूँगा कि हमारे यहाँ की ८५ प्रतिशत ऊन बाहर जाती है। अगर हमारे यहाँ कोई ऊन का कारखाना खोले तो मैं उसका स्वागत करूँगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के व्योपारी समाज ने ऊन की इज्जत को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हम ऊन को यहाँ से ब्यावर और उसके पहले फजलुका भेजते थे। हमारे यहाँ जब ऊन प्रेसिंग के लिये जाती है तो कम हो जाती है क्योंकि लोग जितना ध्यान इधर देना चाहिये नहीं देते हैं। अगर थोड़े से व्योपारियों की दिलचस्पी इस ओर हो और वे आगे बढ़ कर कारखाने खोलें तो खोल सकते हैं। सरकार ने ऊन के काम की तरफ ध्यान दिया है। जहाँ तक हो सका है सरकार ग्राम-उद्योग की तरफ कदम बढ़ा रही है। छोटे-छोटे उद्योगों में हम ऊन का उपयोग जरूर करेंगे।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के ध्यान में लाना चाहता हूँ जो यह है कि आज यदि उद्योग में गिरावट आई है तो सरकार की उपेक्षा की वजह से नहीं आई है; मगर कहा यही जाता है कि सरकार की उपेक्षा से यह गिरावट आई है। गिरावट है वह वर्ल्ड सिचुएशन (world situation) से आ रही है। यह गिरावट सारी जगह आ रही है। आप अभ्रक को ले लीजिए। इसमें भी हमारा बहुत सारा माल इंग्लेण्ड में पड़ा हुआ है जिसको यू. एस. ए. ने इकट्ठा किया था। हम उसको निकालने की व्यवस्था करना चाहते हैं और उसके बेचने का भारत सरकार पर थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं। वहाँ पर माल तालों में बन्द पड़ा है। इसी प्रकार दूसरी चीजों का उत्पादन भी काफी कम होने लग गया है। जहाँ उत्पादन बहुत होता है वहाँ तालों में बन्द रहता है। यह सब कुछ व्यापारियों में व्यवहार और दुनियाँ की स्थिति की वजह से उद्योग में गिरावट आई है। फिर भी मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जो आर्थिक मर्यादायें हैं उनमें रहते हुए हम बड़े व्यापारियों की मदद नहीं कर सकते हैं, यह हमारी लाचारी है। इसके अलावा कभी किसी के गलती करने पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी की पकड़-धकड़ हो जाती है और उसमें झूठों के साथ सच्चे आदमी भी आ जावें तो बड़े अफसोस की बात है। कभी-कभी मदद ढिली हो जाती है और कभी

[श्री जयनारायण व्यास]

सच्चे और ईमानदार आदमी भी पकड़े जाते हैं, इसमें सरकार कहाँ तक कोशिश करे । इसमें थोड़ा व्यापारियों को और उद्योगपतियों को अपने स्तर को ऊँचा करना पड़ेगा । तभी जाकर हमारे उद्योग और व्यापार पनप सकेंगे । मैं आशा करता हूँ कि यह कट मोशन वापिस ले लिया जावेगा और यह माँग स्वीकार कर ली जावेगी ।

श्री चाँदमल मेहता–इस आशा के साथ कि खरड़ के व्यापारियों और साबुन के व्यापारियों को मिलने का मौका माननीय मुख्य मन्त्रीजी अवश्य दे देंगे, मैं मेरे कट मोशन को सदन से लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Has it the leave of the House ?

(विराम)

Yes.

श्री चाँदमल मेहता—मैं मेरे कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

इसी तरह से दूसरे कटौती प्रस्ताव को सदन से लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—Has it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Yes, yes.

श्री चांदमल मेहता—मैं मेरे दूसरे कटौती प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—The question is, "That a sum not exceeding Rs. 47,54,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1955, in respect of Grant No. XXIII, Major Head 43-Industries and Supplies."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

Now, we come to the Veterinary and Stationery and after that we will have Revenue.

[श्री अध्यक्ष]

माँग संख्या २१–पशु-चिकित्सा

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 20,66,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXI, Major Head 41—Veterinary."

(विराम)

Cut-motions to be moved by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(1. To discuss the economy and reduction of expenditure on establishment.

2. Economy retrenchment of provision for poultry farms.
3. To discuss the failure to make use of Government of India schemes.
4. To discuss the high expenditure on travelling allowance.)

माननीय अध्यक्ष, मैंने इस माँग के सिलसिले में जो कट मोशन्स प्रस्तुत किये हैं उनमें पहला कट मोशन इस बात से ताल्लुक रखता है कि इस विभाग का ढांचा टोप हेवी (top heavy) है और यह कुछ एग्रीकल्चर विभाग की खासियत मालूम होती है कि वह प्रशासनीय और विभागीय खर्चों में ही ज्यादा पैसा खर्च करने की प्रथा डालती जा रही है। वेटरनरी में तो दो लाख के ऊपर खर्चा है। माफ कीजिए, वेटेरेनरी में जो ब्रीडिंग ऑपरेशन (breeding operation) नाम से विभाग है, बजट के पेज नं० १८६-१६० पर, इस एक विशेष मद के लिए भी २ लाख से कुछ ऊपर खर्चा रखा गया है। उसमें अफसरों की तनख्वाहें हैं, स्टाफ है और सब कुछ है और वास्तविक कार्य ब्रीडिंग ऑपरेशन का जो है और जिसके लिए खर्चे का प्रोवीजन किया गया है वह ६० हजार से ज्यादा नहीं जाता है। तो करीब-करीब ६० पर्सेन्ट खर्चा एस्टेब्लिशमेंट पर हो रहा है और ब्रीडिंग ऑपरेशन्स में भी अगर यह हाल हो तो फिर पूरे के पूरे विभाग के बारे में यह चीज लाजमी तौर पर लागू होगी। और यह क्यों हो रहा है, इसके कारणों से ताल्लुक रखने वाला मेरा कटौती का प्रस्ताव है। वह यह है कि यह एक विभाग ऐसा है जिसमें भारत सरकार मदद देने के लिए तैयार रहती है और अलग-अलग स्कीमों के लिए कभी ५०–५० बेसिस पर और शायद पूरी की पूरी रकम भारत सरकार मन्जूर करती है। इस वर्ष तक तो एक भी स्कीम के मातहत रकम उपलब्ध नहीं की गई। इस वर्ष सुना है कि एक स्कीम की मन्जूरी प्राप्त हुई है, लेकिन यह भी सुना है कि ३१ मार्च के पहले-पहले राजस्थान सरकार यदि भारत सरकार को सूचना देगी तो वह पैसा मिलेगा। आज तक की जैसी रफ्तार इस विभाग की रही है उसको देखते हुए यदि चार-पाँच दिन निकल भी जाँय और इस साल कोई स्कीम भारत सरकार मन्जूर न कर पाये, ऐसी हालत पैदा होने का अन्देशा है माननीय अध्यक्ष। भारत सरकार अपनी ओर से सुझाव भेजती है, वहाँ के अधिकारी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि ऊँट, जो कि इस मरुस्थल की विशेषता है, की बीमारियाँ की देख-माल के लिए आप

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

स्कीम क्यों नहीं तैयार करते और ऐसे सुझाव और आश्वासन देकर वे गये हैं कि आप स्कीम भेजें, हम मन्जूर करेंगे। ५०-५० होने पर खर्चा देने के लिए सब सहूलियतें देंगे, किन्तु अभी तक स्कीम तैयार नहीं हुई है और यह साल फिर बीत गया। कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के साथ में वेटेरिनरी के कार्य का ताल्लुक जोड़ा जाय और उसके सिलसिले में आवश्यकता हो तो भारत सरकार मदद दे सकेगी। इस ओर राजस्थान सरकार को भारत सरकार खास रियायतें देंगी और एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा भी देगी किन्तु अभी तक वह स्कीम नहीं बन पाई है, पशु-धन में उन्नति करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। नागौर, मालानी और अन्य स्थानों के पशु हिन्दुस्तान भर में मशहूर हैं और वे हिन्दुस्तान की नाक रखने वाले हैं। उनकी ब्रीड्स की उन्नति के लिये, न केवल भारत सरकार ने बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की यह राय है कि इनकी उन्नति की राजस्थान में बहुत गुन्जाइश है और उन्होंने सुझाव भेजे हैं भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को कि कुछ कदम उठावें, लेकिन अब तक जैसे कोई आँख पर पट्टी बांधे रहता है इसी प्रकार की हालत यहाँ है और मेरा खयाल है कि सबसे बड़ा कीमती और बेश कीमती जो यहाँ का पशुधन है और जिसका शायद भारत में सबसे उव्वल नम्बर नहीं तो तीसरा या चौथा नम्बर अवश्य आता होगा, उस पशुधन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए कोई कदम वेटेरिनरी विभाग की ओर से नहीं उठाया जा रहा है और न ही इस बजट में कोई प्रोविजन देख रहे हैं। इस काम की ओर भारत सरकार की मंजूरी होने की गुन्जाइश है और राजस्थान सरकार पर आर्थिक बोझा भी नहीं पड़ेगा। अतः स्कीम न होने के कारण और पशुधन की ओर कोई उन्नति का कदम न उठाने के कारण ही इसी आशय से कि इनकी उन्नति की ओर ध्यान दिया जाय; इसीलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है और उनको सदन के सामने मंजूरी के लिए प्रस्तावित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—श्री कपिलदेव।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, वेटरनरी डिपार्टमेन्ट के बारे में मुझे कुछ खास सुझाव रखने हैं। और बातों के लिए कुछ कहूँ इससे पहले मैं आपको यह निवेदन करूँगा कि राजस्थान में जो कुक्कुड़ शालाओं की हालत है वह बड़ी ही दयनीय है।

श्री अध्यक्ष—कुकर ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुर्गी से मतलब है।

श्री अध्यक्ष—क्या कुक्कुड़ ?

श्री मानसिंह महार—मुर्गी समझ लीजिये।

माननीय अध्यक्ष, आज जो हमारे यहाँ कुक्कुड-खाने की हालत है उसके ऊपर सरकार द्वारा हजारों रुपयों का खर्च होता है लेकिन जब वहाँ जाकर देखते हैं तो कुल मुर्गे-मुर्गियों की संख्या

[श्री मानसिंह महार]

१०० के आसपास है। तो जिस मुर्गीखाने पर २५-३० हजार रुपये खर्च किये जाँय और उसमें केवल ६० मुर्गे और २०-२५ मुर्गियाँ हों, ऐसी हालत में यही कहा जा सकता है कि वहाँ ठीक व्यवस्था नहीं है।

इस बारे में मैं माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूँ ताकि राजस्थान में मुर्गियों की नस्ल सुधर सके। जो टेनी मुर्गे हैं वे बदल कर अच्छे रेड होर्न्स के बन सकें, इसके लिए मैं कुछ सुझाव आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ।

जब जयपुर में सर मिर्जा आये थे तो उन्होंने कोशिश की थी। वह कोशिश इस प्रकार से की गई थी कि बाहर देहातों में जो टेनी मुर्गे होते हैं उनको खरीदा जाय। जिस आदमी के पास दो या दो से ज्यादा मुर्गे हों वे एक मुर्गा यहाँ कुक्कुड शाला में भेज दे और एक अच्छी नस्ल का मुर्गा ले जा सकता है। इस प्रकार से सरकार को भी ज्यादा घाटा नहीं होता था और मुर्गों की नस्ल भी बदल जाती थी। एक तो तरीका नस्ल बदलने का यह है। इस प्रकार टेनी मुर्गे लाकर रेड होर्न्स वाले मुर्गे सरकार देने लगे तो गाँव के आदमी कुक्कुड़ शाला में देकर यहाँ से अच्छी नस्ल के मुर्गे गाँवों में ले जाँय। इससे वहाँ जो हमारी मुर्गियों की नस्ल है सुधर जायगी। यह एक मेरा सुझाव है। इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारी कुक्कुड़ शालाओं में ऐसा होता है कि जो अंडे होते हैं उनके बारे में मैं यह कह सकता हूँ कि वे अन्डे पैसे से दिये जाते हैं। देहात के जो गरीब आदमी हैं उनके पास पैसे नहीं होते और उनके अन्डों को बेचने के लिए मार्केट नहीं मिलता तो जैसे हमारे सरकारी मुर्गीखाने में हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय और नये एग्रीकलचर सेक्रेटरी महोदय अन्डों के ग्राहक हैं, तो उनको एक अच्छी नस्ल का अन्डा देकर गाँव वालों से उनके बदले चार छोटे अन्डे ले लिये जाँय, इससे सरकार को नुकसान नहीं होगा। इससे आसानी से नस्ल सुधर जायगी। यह तजवीज मैं मुर्गीखाने के बारे में रखना चाहता हूँ। अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो मैं आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से हमारे यहाँ मुर्गीखाने वगैरह खोले जाते हैं उसकी पूर्ति हो सकेगी। यह जो गाँव के अन्दर सफेद टेनी मुर्गी हैं उनकी भी नस्ल सुधर सकेगी। यह मेरा मुर्गीखाने के बारे में सुझाव है। इस ओर अवश्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

अब मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वह है मुर्गे-मुर्गियों के इलाज के बारे में। उनके इलाज के लिए कोई इन्तजाम नहीं। यह बात मैं पर्सनल एक्सपीरिएन्स से कहना चाहता हूँ। हम लोगों को इस प्रकार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद सफेद मुर्गियें मुर्गे पाला करता हूँ......

श्री खेतसिंह—सफेद मुर्गियों के लिए काले मुर्गे सरकार दे देगी।

श्री मानसिंह महार—उनमें से एक मुर्गी की आँख में एक प्रकार की तकलीफ हो गई। मैंने उसको वेटरनरी अस्पताल में इलाज करवाने भेजा। डाक्टर साहब ने न मालूम क्या दवाई दी कि

[श्री मानसिंह महार]

जिससे वह पन्द्रह मिनिट के बाद मर गई। यह हमारे सफाखानों की हालत है। जब दूसरी बार मेरी मुर्गियों में इस प्रकार की बीमारी फैली तो मैंने उन्हें घर पर ही ठीक कर लिया। मामूली घरेलू दवा से ही वे ठीक हो गयीं। यह मैं सही मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ।

मेरे एक मित्र ने फरमाया कि सरकार सफेद मुर्गियों के लिए काला मुर्गा दे सकती है, लेकिन मेरा निवेदन है कि असली जो नस्ल होती है वह सफेद व्हाइट होर्न मुर्गे की ही होती है। शेरगढ़ में काली मुर्गियाँ बहुत हैं, वे वहाँ के लिए मेरे पास से व्हाइट लोंग होर्न्स के मुर्गे ले जा सकते हैं......

श्री खेतसिंह—शेरगढ़ में टर्किश प्लेग है......

श्री मानसिंह महार—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अब मैं कुछ साण्डों के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। हमारी सरकार के पास साण्ड बहुत कमजोर हैं, जो साँड हमारे राजस्थान में छोड़े जाते हैं वे बहुत कमजोर हैं। इसलिए साण्डों की नस्ल-सुधार के लिए जैसा कि अभी बम्बई सरकार ने एक मशीन मँगाई है, उन मशीनों के जरिये गायों के लिए साण्ड का काम चलाया जा सकता है। अगर वह पद्धति यहाँ भी राजस्थान में अपनायी जाय तो राजस्थान में गायों की नस्ल सुधर सकती है और जो इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा खर्च किया जाता है उससे इस विभाग में आधुनिक तरीके के औजार तथा और तरीके अपनाये जाँय तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि वेटरनरी के जो डॉक्टर वगैरह हैं उनका यह हिसाब है कि एक तो डॉक्टर जयपुर में है और दूसरा बाहर। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिए मूविंग डिस्पेन्सरीज़ हों। डॉक्टर लोग मोटरों में गाँवों में जाँय और गाँवों में जो जानवरों में बीमारी हो जाती है उसकी रोक-थाम करें। पिछले साल भी हमारे यहाँ भैंसों में एक प्रकार की बीमारी फैल गई थी, इससे कई भैंसें भी मर गई थीं। आप भी सोचिये पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस मील गाँव वाले इलाज कराने कैसे आ सकते हैं? ऐसी हालत में मोटरों में यदि डिस्पेन्सरीज़ चलती रहें तो गाँव की जनता को काफी फायदा हो सकता है।

पिछले वर्ष कुछ ऊँटों में भी एक प्रकार का रोग फैल गया था। उनको इलाज के लिए जयपुर लाया गया, क्योंकि यह एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जो तीन साल में हुआ करता है। उसमें एक इन्जेक्शन लगाया जाता है। उन ऊँटों को यहाँ लाया गया। किसी ने इन्जेक्शन के लिये दो रुपये माँगे, किसी ने चार माँगे; आखिर बेचारे एक डॉक्टर साहब मिले जिन्होंने काफी रियायत करके इन्जेक्शन लगाये तो, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूँगा कि इस प्रकार जो हम देहातियों को जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको दूर करें। एक जयपुर में वेटरिनरी होस्पिटल के खोल देने से या एक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में अस्पताल खोल देने से कोई काम नहीं चल सकता, जब तक कि मूविंग वेटरनरी अस्पताल न हों: तब तक इसका इन्तजाम ठीक तरह से नहीं हो सकेगा।

[श्री मानसिंह महार]

इसके अलावा हमारे यहाँ जो देशी तरीके से इलाज की पद्धति है वह भी हमारे डॉक्टरों को सिखायी जाय, जिससे वे पाश्चात्य और कुछ हमारी देशी-पद्धति दोनों को मिलाकर काम करें। इससे बहुत फायदा हो सकता है और वह इलाज सस्ता भी उपलब्ध हो सकता है। गाँव के अन्दर कई मवेशियों के इलाज के ऐसे तरीके हैं कि जिससे वाकई में बहुत अच्छा लाभ होता है। यह सजेशन देते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्रीजी से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे यहाँ के मुर्गीखाने तथा और अन्य बातों की ओर अवश्य ध्यान दें।

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, श्री एच० के० व्यास ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, कल जब मेडिकल विभाग पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त ऐसा सुनने में आ रहा था और बजट देखने से ऐसा मालूम होता था कि सरकार ने इस विभाग पर काफी खर्च बढ़ाया है। जिस प्रणाली के अनुसार खर्च बढ़ाया गया उस प्रणाली के अनुसार मेडिकल एड ज्यादा से ज्यादा देने की सरकार ने योजना बनायी है और उसके लिए सरकार ने बजट में प्रोवीजन रखा है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह मानव जाति के लिए मेडिकल एड की सहायता अनिवार्य है उसी प्रकार पशु-जाति के लिए भी मेडिकल एड के लिए विचार किया जाय तो वह किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। लेकिन जब राजस्थान के बजट को देखा जाता है तो यह साफ जाहिर होता है कि सन् ५३-५४ के बजट एस्टीमेट्स में वैटरनरी होस्पिटल के लिए ८ लाख २० हजार ७०० रुपये रखे गये थे, उसमें से ७ लाख ३७ हजार के करीब रुपया खर्च किया गया तथा उसमें से भी करीब एक लाख रुपये की बचत कर दी गई। ब्रीडिंग के लिए सन् ५४-५५ के लिए २ लाख २६ हजार २०० रुपये का एस्टीमेट रखा गया था, रिवाइज्ड एस्टीमेट में १ लाख ४७ हजार ७०० रुपया कर दिया गया; इस तरह से २० हजार की कमी दिखाई गई है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना यह है कि अगर हम यह मान कर चलें कि गाँवों में जानवरों में बीमारी नहीं है तो बहुत मुमकिन है कि किसी प्रकार की कटौती की जावे। लेकिन जब हम बाहर गाँवों में जाते हैं या गाँव-गाँव में घूम-फिर कर तजुर्बा हासिल करते हैं तो हमें सुनने और देखने को यह मिलता है कि जानवरों में कई प्रकार की भयंकर बीमारियाँ फैली रही हैं और इसके निवारणार्थ जो होस्पिटल्स सरकार के हैं वे, बिल्कुल अल्प मात्रा में होने के कारण, मेडिकल एड देने में सफल नहीं होते। और जब इस प्रकार की माँग रक्खी जाती है तो उसको यह कह कर टाल दिया जाता है कि आर्थिक संकट है सरकार पर, इस कारण इस प्रकार की कोई योजना व्यापक रूप से प्रचारित नहीं की जा सकती। मैं मानता हूँ कि ऐसा करने में सरकार को कई बाधाएँ आती होंगी, पर हमारे पास इस प्रकार की भी योजना है कि मामूली से खर्चे में भी, जो अभी बजट एस्टीमेट्स से रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से बची हैं, उसमें ही हम अपनी यह योजना चला सकते हैं। इस बीच की बची हुई रकम ही अगर ठीक प्रकार से गाँवों में खर्च की जावे, तो एक प्रकार का इस बीमारी से जानवरों को और इनके मालिकों दोनों को छुटकारा मिल सकता है।

[श्री भैरूँ सिंह (दांता रामगढ़)]

अभी जिस तरह से मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे यहाँ इस तरह के लोकल इलाज भी हैं जिनको यदि ठीक ढंग से प्रोत्साहित किया जावे तो इन वेटेरिनरी अस्पतालों की विशेष आवश्यकता नहीं रहेगी।

अभी गाँवों में बछड़ों की नस्ल सुधारने की योजना, जिसके लिए गवर्नमेन्ट भी प्रयत्नशील है तथा और भी जितने भी राजनैतिक दल हैं वे भी प्रयत्नशील हैं; पर जो विरोधी राजनैतिक दल है सिवाय अर्थाभाव के कारण पूर्ण रूप से किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। सरकार के पास ही ज्यादा मदद करने का सवाल आता है। पर उसके दिमाग में पाश्चात्य प्रणाली ही घुसी हुई है, उसी के आधार पर वह कार्य कर सकती है और जो हमारी राजस्थान की प्रचीन प्रणाली है उसको किसी प्रकार से प्रोत्साहन देने को तैयार नहीं होती। आज गाँवों में जाकर हम देखते है तो जब बछड़ों को बाधी किया जाता है तो उसमें इतना नृशंस अत्याचार उसके साथ होता है कि यदि उसका दृश्य अपनी आँखों से आप देख लें तो ऐसा कोई भी मानव नहीं, जिसमें थोड़ी बहुत भी मनुष्यता का लक्षण है, वह उसे बर्दाश्त कर सके अथवा देख सके। पर मजबूर होकर ऐसा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि यदि इस प्रकार की चीजें वह यदि नहीं करते हैं तो वह जानवर खेती के काम के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता।

तो सरकार अगर चाहे इसमें तो बहुत अच्छा सुधार हो सकता है और खर्चा भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा उसे। पिछले एस्टीमेट रकम में से जो बची हुई रकम है उससे इस प्रकार के औजार सरकार खरीद करे। इन औजारों में किसी विशेष प्रकार का खर्चा भी नहीं है। उनको लेकर राजस्थान की सभी तहसीलों में वे तकसीम कर सकते हैं, जहाँ ज्यादा कृषक लोग बसते हैं। वे उनमें तकसीम कर सकते हैं और वहाँ पर जितने सरकारी वेटेरिनरी डाक्टर हैं उनको अलग-अलग गाँवों में भेजकर वहाँ के खास-खास मुखियाओं को इकट्ठा करके, काश्तकारों को इकट्ठा करके उनके फायदे के बारे में उनको समझावें और यह बतावें कि इनका किस प्रकार से कैसा उपयोग हो सकता है। अगर इन डाक्टर लोगों के द्वारा उनको सिखाया जावेगा तो वे भी कुछ सीखेंगे और वहाँ के लोगों के द्वारा बीमारी के बारे में डाक्टरों को जानकारी प्राप्त होगी और वे स्थानीय लोग स्वयं इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको थोड़ा-सा सिखाने और अनुसन्धान की जरूरत है, थोड़े से हेरफेर की जरूरत है। डाक्टरों को वे प्राचीन पद्धति भी बताएंगे जिनमें कई प्रकार की छूआछूत की बीमारियों के बारे में भी उपयोगी बातें हैं। यह छूआछूत की बीमारी एक दम नहीं रोकी जाती है, तो जानवरों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार अगर वेटेरिनरी डाक्टर हर स्थिति से वाकिफ रहता है और जागरूक रहता है तो वह वहाँ के लोगों से भी कुछ सीखकर ही अपने डिपार्टमेंट में ही उस बीमारी को रोकने के लिए विशेष प्रकार की योजना भी बना सकता है और एक विशेष प्रकार की दवाई का भी निर्माण कर सकता है। पर, खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये डाक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट वेटेरिनरी हॉस्पिटलों में बैठे रहते हैं और खास तौर से शहरों में ही जो कुछ थोड़ी बहुत इस बीमारी के शिकार जानवर आते हैं उनका जैसा-तैसा इलाज करके सन्तोष कर लेते हैं। जानवरों में छूत की बीमारी आ गई हो तो जब तक डाक्टर साहब को इत्तला की जावेगी और वहाँ जाने के लिए उनकी पूरी-पूरी खुशामद

[श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)]

की जावेगी, या मोटर या ताँगे का इन्तजाम किया जावेगा उस वक्त तक तो वह जानवर भी खतम हो जावेगा और अगर किसी जानवर को छूत की बीमारी है तो वह आसपास में जोरों से फैल जावेगी, भीषणरूप धारण कर लेगी, पर इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा। यह डिस्ट्रिक्ट के आँकड़े लेकर सिद्ध किया जा सकता है।

दूसरी बात शहरों में कई भूखे जानवर हैं और इस कारण भूख से एपीटाइट के रोग में फंस जाते हैं। उनका इलाज वेटेरिनरी अस्पताल में करते हैं, पर उससे वहाँ की जनता को कोई फायदा पहुँचता हो ऐसा देखने में नहीं आता। इसमें यदि रुपये-पैसे खर्च करने की जरूरत हो तो एक कमेटी बिठाई जावे, जो गाँव-गाँव में चक्कर लगाए। राजस्थान में बजाय शहरों के गाँवों में अधिक बीमार हैं और प्राचीन पद्धति के अनुसार कौन-कौन से ऐसे इलाज है, उनका पता लगाया जावे, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और पाश्चात्य पद्धति का अन्ध अनुकरण करने के स्थान पर इन देशी पद्धतियों को सहयोग दिया जावे तो हम निश्चय ही सफतापूर्वक और कम खर्चे में इन बीमारियों पर नियन्त्रण पा सकते हैं और अपनी अनमोल पशुनिधि की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। यह पाश्चात्य पद्धति इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकती। हाँ, उस पद्धति के कुछ औजार बहुत उपयोगी हैं। हम इनका उपयोग कर सकते हैं जैसा कि इसके बारे में मैंने अभी कहा भी है कि हम इनका उपयोग ग्रामीणों को सिखा सकते हैं और उनसे बदले में देशी इलाज की पद्धति मालूम कर सकते हैं जिसे अगर ठीक ढङ्ग से, व्यवस्थित रीति से अनुसन्धान आदि करके प्रोत्साहित किया जावे तो इस राजस्थान के जानवरों की रक्षा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अभी साँडों की बात को लेकर एक बात कही गई। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूँगा कि इन साँडों के सिलेक्शन (Selection) में जो एक्सपर्ट रक्खे जाते हैं उनको केवल किताबी ज्ञान ही अधिक होता है प्रेक्टिकल अनुभव नहीं होता। अतः हमें ऐसे एक्सपर्ट ही रखने चाहिये जो यह भी बखूबी जानते हों कि साँड ही अच्छा देखने से कोई लाभ नहीं है, यह भी देखना चाहिये कि इनका किस तरह से पालन-पोषण होता है, कौन-कौन से गुण किस-किस बात के लिए जरूरी हैं और किस-किस दृष्टि या लाभ के लिए कौन-कौन से गुण होना हितकर है, किस नस्ल का साँड किस नस्ल की गाय के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, किस साँड से बलवान बैल पैदा होगा; हमें अगर अधिक और पौष्टिक दूध की आवश्यकता है तो इसके लिए कौन सी नस्ल का साँड चाहिये जिससे किसी खास नस्ल की गाय का दूध अधिक पैदा हो। ऐसा न हो कि नस्ल की पहचान ही न हो और दूध बढ़ने के बजाय घट जावे या जिस नस्ल की गाय के लिए हमें चाहिये कि इससे खेती के लिए उपयोगी बैल पैदा हों, पर नतीजा दूसरा निकले। इस तरह की ये सारी बातें बताने के लिए हमारे पास, मेरा ऐसा खयाल है कि एक्सपर्ट नहीं हैं। वे तो यह देख लेते हैं कि नागौरी साँड अच्छे होते हैं, हरियाणा के साँड़ और गाय अच्छे होते हैं। यह "अच्छा होने से" कोई अधिक लाभ नहीं है। देखना तो हमें यह है कि हम किस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की खास नस्ल का साँड़ चाहते हैं। देखना यह है कि किस नस्ल के साँड से किस जगह की ब्रीड अच्छी हो सकती है। जिस जगह की ब्रीड जिस जगह के और जिस किस्म के साँड से अच्छी हो सकती है, दूध बढ़ाने की दृष्टि से या अच्छे

[श्री भैरूँ सिंह (दाँता रामगढ़)]

ताकतवर बैल पैदा करने के लिए, तो उस किस्म के साँड को उस एरिया में भेजना चाहिये। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हम सिलेक्शन करेंगे तो ठीक होगा और इस प्रकार के सिलेक्शन से ही हम अपनी ब्रीड को सुधार सकते हैं। ऐसे ही एक्सपर्ट हमें चाहिये। यह नहीं कि एक ही मशहूर नाम के कारण, किसी प्रकार की नस्ल के साँड को मशहूर नाम होने से ही एक दूसरी जगह भेज दिया जाता हो, चाहे उससे हमारा लक्ष्य पूरा होता हो या न होता हो; तो यह किसी भी तरह से योग्यता नहीं समझी जावेगी।

दूसरी चीज़, मुझे गौशालाओं के बारे में कहनी है। राजस्थान में यह सौभाग्य की बात है कि गोवध को कनूनन बन्द कर रक्खा है, पर इसके साथ कहना पड़ता है कि यहाँ राजस्थान के बड़े-बड़े शहरों में विशेष तौर पर और बाहर गाँवों में ऐसा देखने में आया है कि जो लूले हैं, लंगड़े हैं, अपंग और रोगग्रस्त जानवर हैं, उनकी कोई देख-भाल नहीं करता और जितने भी उनके मालिक हैं उन्होंने महज, जब तक उनका उनसे स्वार्थ था, उनसे दूध मिलता था या खेती का काम चलता था या ऐसा ही अन्य काम उनसे चलता था, तब तक तो उनकी सेवा की, लेकिन जिस वक्त उनका स्वार्थ उनसे सधना बन्द हो गया और वे किसी कारणवश या अवस्थावश लूले, लंगड़े अपंग या बेकार और रोगग्रस्त हो गये तो उनको छोड़ दिया। इस पर अगर उनमें भूख के कारण छूत जैसी बीमारी आ गई तो इससे दूसरे सबल, सशक्त जानवरों को भी नुकसान पहुँचने की सम्भावना बहुत प्रबल रहती है और यहाँ पर आकर तो हमारी इस धर्म-प्रिय जनता को भी इस कारण अत्यन्त ठेस पहुँचेगी, पर उन लूली-लंगड़ी गायों और अन्य जानवरों के लिए उनके मालिकों को कोई ठेस नहीं पहुँचती, यह बड़े दुख की बात है। साथ ही दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए कुछ नहीं किया और न उसने इस प्रकार का कोई कानून ही बनाया है कि जिसके द्वारा ऐसा करने पर उनके मालिकों का प्रोसीक्युशन किया जा सके। इस कानून में ऐसा करने का तो प्रोवीजन होना ही चाहिये, पर साथ ही साथ इस प्रकार का भी प्रोवीजन होना चाहिये कि ऐसी लूली, लंगड़ी और बेकार गायों को खास तौर से गौशालाओं में भेजा जावे; उस स्थिति में जब कि उनका मालिक किसी विशेष परिस्थिति और कठिनाइयों के कारण उसको रखने और उसकी परवरिश करने से बिल्कुल ही इन्कार हो जावे। ऐसी सूरत में इन गायों को ईश्वर के भरोसे न छोड़कर उनको थोड़ी बहुत राहत देनी चाहिये। इससे छूत जैसी बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा और मनुष्यता का भी यह तकाजा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इससे राजस्थान की जनता का भी फायदा होगा। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान-ग्रहण करता हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, वेटरनरी के बारे में जो कटौती प्रस्ताव आये हैं, इस वेटरनरी का जो बजट पेश हुआ है उसके अन्दर जो गौशालाएं राजस्थान के अन्दर हैं, उन गौशालाओं की हालत को देखते हुए वेटरीनरी का जो बजट पेश हुआ है वह कुछ भी नहीं है।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

राजस्थान में आज भी करीब २०० से अधिक गौशालाएं हैं और उन गौशालाओं के अन्दर सरकार की तरफ से सहायता नहीं दिये जाने के कारण उनकी हालत दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही हैं। उन गौशालाओं में पब्लिक की तरफ से लाखों रुपया खर्च किया गया है, परन्तु आज आर्थिक स्थिति खराब होने से वे गौशालाएं जो चलती थीं दिन पर दिन बिल्कुल बन्द होती जा रही हैं। इसका कारण एक यह भी है कि उन गौशालाओं को जो चारागाह जागीरदारों की तरफ से या सरकार की तरफ से दिये गए थे वे चरागाह अब दिन पर दिन, खास करके खेती के काम में लाये जा रहे हैं। यह चरागाह अगर उन गोशालाओं के अन्दर रहते तो आज उन गोशालाओं की जो बन्द होने की सूरत पैदा हुई है वह न होती। सरकार उन गोशालाओं के लिए ध्यान दे और उनकी कुछ मदद करे। आज गायों की जो हालत राजस्थान में है वह दूसरे प्रान्तों में कम है। दूसरे प्रान्तों में गोवध जरूर होता है, परन्तु राजस्थान से हजारों गाएं वहाँ जाकर उनका गौवध होता है। तो उसको एक ही सी बात समझना चाहिये क्योंकि राजस्थान में गायों को पेट-भर के चारा नहीं मिलता है और जो मालिक हैं वे उनकी देख भाल अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं।

राजस्थान के अन्दर वेटरनरी के ५० डाक्टर हैं। एक-डेढ़ करोड़ की जनता जो कि राजस्थान की है उसके अन्दर ५० डाक्टरकम हैं। जब कि राजस्थान गवर्नमेंट का आज करोड़ों रुपयों का बजट है, परन्तु वेटरनरी के डाक्टरों के लिए, माननीय अध्यक्ष, एक-एक कस्बे में उनको रखने के लिए, आज पैसे की बहुत तंगी की हालत उनको दिखाई देती है।

दूसरी बात है कि जो गौ-सेवा संघ की तरफ से राजस्थान गवर्नमेंट को बार-बार लिखा भी और उनको सुझाव दिया कि राजस्थान में अन्धी-लूली जो गायें हैं और गौशालायें हैं उनके लिए अगर सरकार प्रबन्ध कर दे और जो कमी मदद में दिखलाई गई है उस कमी को हटवाने का प्रबन्ध कर दे तो उन गायों की जो जिन्दगानी है वह किसी तरह से पूरी हो सकती है, परन्तु सरकार की तरफ से इस तरह की कोई भी मदद देने का प्रयत्न नहीं हुआ है जिससे कि आज उनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। इसके कारण कई गौएं बेचारी परेशान होकर और दुख पाकर मर जाती हैं।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ राजस्थान में वेटरनरी डाक्टर हैं उन डाक्टरों की तनख्वाह वही होनी चाहिये जो कि आज दूसरे राज्यों के अन्दर उन डाक्टरों की तनख्वाह है। उनकी तनख्वाह वही होनी चाहिये जो कि मनुष्यों के अस्पतालों के डाक्टरों की होती है, क्योंकि उनका कोर्स वैसा ही होता है जैसा कि मनुष्यों के डाक्टरों का होता है। उस कोर्स में कोई ४—५ साल लगते हैं तो उस कोर्स में भी ४—५ साल लगते हैं फिर भी इस तरह के भेदभाव से उन्हें देखा जाता है। मनुष्यों के डाक्टरों की तनख्वाह २५०) से ५००) के ग्रेड की होती है और उनकी तनख्वाह १५०) से ३००) के ग्रेड की होती है। इसलिए इस बारे में सरकार को देखना चाहिये, इनके ग्रेड के बारे में भी जोर देना चाहिये......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

Page No.146

श्री अध्यक्ष—गोशालाओं पर बोलते-बोलते तनख्वाह पर आ गए हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, एक मिनट।

जो वेटरनरी के डाक्टर हैं वे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाँय और गौशालाओं की जो हालत हो रही है उसको सुधारने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करे।

गाँवों में साँड नहीं मिलते हैं और साँड न होने से गाँव वाले परेशान होते हैं और गायों को वे दूर-दूर ले जाते हैं। इसके लिए भी सरकार साँडों का सब गाँवों में प्रबन्ध करे जिससे कि गाँव वालों को सुविधा मिल सके। इतना ही कहूँगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्षजी, वेटरनरी विभाग के सम्बन्ध में जो चर्चाएँ अभी सदन में की गई हैं उसमें सबसे पहले मैं इस बारे में कहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं अब तक चलती हैं उनका राजस्थान सरकार ने लाभ नहीं उठाया है। यह एक हद तक सही है क्योंकि उसमें अधिकतर योजनाओं में ५० प्रतिशत राजस्थान सरकार के खर्च करने का प्रश्न था और ५० प्रतिशत भारत सरकार की तरफ से देने की बात थी। पिछले वर्षों में राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन योजनाओं का हम लाभ नहीं उठा पाये, लेकिन इस वर्ष उस योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान के अन्दर भी रुपया रखा गया है और समय पर वह योजना तैयार भी हो गई है और वह भेज दी जायगी, यह मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूँ।

राजस्थान सरकार इस वर्ष राजस्थान में यह चाहती है कि इस वक्त एक गौ-सदन जो सवाई माधोपुर में चलाती है उसके बजाय एक और पश्चिमी हिस्से में बढ़ाया जाय और जिन लूली-लंगड़ी और बेकार गायों के बारे में जिक्र किया गया है उस प्रकार की गायों को गौ-सदन में रखा जायगा जिससे कि गौशालाओं के ऊपर जो आर्थिक भार रहता है और जिसके कारण गोशालाएं अधिक उपयोगी साबित नहीं हो पाती हैं, वह उनके ऊपर जो भार है उससे हटाकर गौशालाओं को आगे के लिए एक अच्छी नस्ल के साँड तैयार करने के कार्य में उनका उपयोग किया जायगा। उस काम के लिए गौशालाओं को मदद, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो योजना है जिसके द्वारा ५० प्रतिशत गौशालाओं को मदद दी जा रही है, दी जायगी। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं राजस्थान के जो गौशालाओं के मामले में अधिक से अधिक दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति हैं और बहुत से लोग, मैं समझता हूँ, उनको जानते हैं, श्री बलवन्तसिंहजी काफी काम करते हैं, उन्होंने सारी योजना पेश की है और वह योजना पूरी तरह से बातचीत करके तैयार की है और हम चाहते हैं कि अलग जगह उनके और सरकार के सहयोग से इस योजना को हम अधिक से अधिक क्रियान्वित करने के अन्दर प्रयत्न करें। मैं इस बात को मानता हूँ कि राजस्थान हमारे देश के अन्दर प्रमुख राज्य-सा है, जहाँ कि अच्छी प्रकार की गायें उपलब्ध होती हैं; उसमें अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए। उस प्रयत्न करने में कठिनाइयाँ भी आवेंगी और आसानी भी बहुत जल्दी नजर आती है। उसका परिणाम भी अभी जल्दी नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी काफी चर्चा के बाद इसकी योजनाएं तैयार की हैं, मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष निश्चित-तौर से काफी सुधार होगा। कई

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

गौशालाओं को अपना केन्द्र बनाना चाहता हूँ और आगे के विकास के लिए इन चीजों को विकसित करना चाहता हूँ।

हम गौशालाओं को भी कुछ गायें देना चाहते हैं इसलिए कि उनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और अच्छी नस्ल तैयार हो सके और अच्छे साँड तैयार किये जा सकते हैं। साँड तैयार करने के लिए हम सहायता देंगे। इसी तरह से गाँवों में भी गाँव वाले यदि उनको संभालने के लिए तैयार होंगे तो हम उनको मदद देंगे। यह सही है कि इस वक्त जितना बड़ा राजस्थान है उनके लिए वेटरनरी डाक्टरों की कमी है। वेटरनरी डाक्टरों की तादाद बढ़ाने के लिए इस साल बजट में प्रोवीजन रखा है जैसा कि आपने बजट के आँकड़ों से देखा होगा। इस साल हम ८ लाख रुपये ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। राजस्थान में वेटरनरी स्कूल खोलने की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति करने के लिए भारत सरकार के सामने एक योजना भेजी गई है, मन्त्रीजी से बात कर ली है। ढाई लाख रुपये वेटरनरी कॉलेज के लिए रखे हैं जिसमें वेटरनरी डाक्टर और स्टोकमेन तैयार किये जायेंगे।

Key Village Scheme के बारे में एक मित्र ने कहा कि गाँव-गाँव में सप्लाई करनी चाहिये। इतने लंबे राजस्थान में नहीं कर पाये हैं, इसका कारण यह है कि अच्छे साँड अधिक उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच में जो हैं उनसे भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। जितना अधिक लाभ मिल सके उतना लाभ लेना चाहते हैं। ये योजनाएं अधिक से अधिक इस वर्ष आपके सामने आवेंगी और वर्ष के अन्त में हमें इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि हम इस दिशा में प्रगति नहीं कर रहे हैं।

गायों के बारे में कहा गया कि हजारों गायें राजस्थान के बाहर जाकर कटती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर विश्वास इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि राजस्थन के बाहर गायें जाने का प्रश्न ही नहीं आता। सिर्फ अकाल के जमाने में गायें बाहर जाती हैं, लेकिन बिक कर गायें बाहर नहीं जा सकतीं, इसके लिये इजाजत नहीं है। खास खास बातें मैंने आपके सामने रखीं, लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, बिना कुरकुटखाने के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे इसे खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे मित्र का व्यक्तिगत ज्ञान मुर्गा-मुर्गी के बारे में बहुत है। उन्होंने मुर्गा-मुर्गी के बारे में बहुत सी बातें कहीं और उनके सुधार के बारे में भी काफी चर्चा की। मैं समझता हूँ सदन में एक ऐसे अनुभवी सदस्य मौजूद हैं तो उनसे हमें काफी मदद मिलेगी। इस समय तो उनके ज्ञान का फायदा मिला ही है लेकिन मैं आशा करता हूँ कि समय-समय पर हम उनके ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं और इससे उन 'मुर्गा-मुर्गियों' की प्रगति अधिक से अधिक हो सकेगी।

मैं निवेदन करूँगा कि मैंने जो बातें कहीं हैं उनको ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने-अपने कट मोशन्स वापिस लेकर मूल माँग को पास करावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to withdraw my cut-motion.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to allow Shri H. K. Vyas to withdraw his Cut-motion.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I withdraw.

श्री अध्यक्ष—The question is that the Demand be passed.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—There are some more cut-motions.

श्री अध्यक्ष—No.

(स्वीकृत)

The Demand is passed.

श्री मानसिह महार—We should now adjourn; because there are elections tomorrow for the financial committees and we have to canvass.

श्री अध्यक्ष—I have no ears, I have only eyes.

माँग संख्या ३१-लेखन-सामग्री तथा मुद्रण

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 37,10,000/- be granted to His Highness the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. XXXI, Major Head 56-Stationery and Printing."

Cut-motion by Shri Tejmal.

(अनुपस्थित)

There was only one Cut-motion, so I put the question.

(विराम)

The question is that the Demand be passed.

(स्वीकृत)

The Demand is passed.

माँग संख्या १-भू-राजस्व

The motion is, "That a sum not exceeding Rs. 2,08,00,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1955, in respect of Grant No. I, Major Head 7-Land Revenue."

[श्री अध्यक्ष]

I wanted to know how much time the Hon'ble Members will like to have over this Demand.

श्री चांदमल मेहता—I will require half an hour.

श्री अध्यक्ष—No, Land Revenue—it is a very important Demand. There are some 17 cut-motions over this Demand. Now, we have got only 45 minutes at our disposal. I think we should sit for some time more. We might not finish this Demand, but we can discuss. Yes, Mr. Vyas; even un-riped, I allow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are only 10 minutes left for today's sitting.

श्री अध्यक्ष—45 minutes. You know the rule.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I personally like to have it tomorrow.

श्री अध्यक्ष—Any other Member in the mood of speaking ? Mr. Mehta.

श्री चांदमल मेहता—I will speak tomorrow.

श्री अध्यक्ष—Then we will sit both the times tomorrow and we adjourn.

[सदन की कार्यवाही ७ बज कर २० मिनिट (मध्यान्होत्तर) पर, दिनाँक २५ मार्च, १९५४ के ८-३० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई ।]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—२४ मार्च, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।